



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 397]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 14, 2018/अग्रहायण 23, 1940

No. 397]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 14, 2018/AGRAHAYANA 23, 1940

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 2018

अंतिम जांच परिणाम

विषय: चीन जन. गण., यूरोपीय यूनियन, केन्या, पाकिस्तान, ईरान, यूक्रेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सोडा ऐश" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी निर्णायक समीक्षा जांच।

फा. सं. 7/5/2017-डीजीएडी .—क. मामले की पृष्ठभूमि

- जबकि, निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) ने चीन जन. गण., यूरोपीय यूनियन, केन्या, पाकिस्तान, ईरान, यूक्रेन और संयुक्त राज्य अमेरिका (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सोडा ऐश" (जिसे आगे "संबद्ध वस्तु" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करते हुए दिनांक 17 फरवरी, 2012 की अधिसूचना संख्या 14/17/2010-डीजीएडी के द्वारा अंतिम जांच परिणाम अधिसूचित किए थे। केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 03 जुलाई, 2012 की अधिसूचना संख्या 34/2012-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा निश्चयात्मक शुल्क लगाए गए थे।
- और जबकि, प्राधिकारी ने मध्यावधिक समीक्षा पूरी करने पर 22 जुलाई, 2017 के अंतिम जांच परिणाम संख्या 15/28/2014-डीजीएडी द्वारा संबद्ध सामानों पर पाटनरोधी शुल्क वापस लिए जाने की सिफारिश की और तदनुसार, दिनांक 22 जुलाई, 2017 की अधिसूचना संख्या 7/5/2017-डीजीएडी द्वारा भी साथ-साथ निर्णायक समीक्षा को रद्द किया।
- और जबकि, याचिकाकर्ताओं ने उपर्युक्त मध्यावधिक समीक्षा के अंतिम जांच परिणाम और निर्णायक समीक्षा को रद्द किए जाने के आदेश को अहमदाबाद में गुजरात के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी। विशेष सिविल आवेदन 2017 के संख्या 14202 से 14207 और 2018 के विशेष आवेदन संख्या 14202 में 2018 के विविध सिविल आवेदन संख्या 2 में 11 जून, 2018 के आदेश और 2018 के विशेष सिविल आवेदन संख्या 14204 में 2018

के विविध सिविल आवेदन संख्या 3 में 15 जून, 2018 के अंतिम आदेश के अनुसरण में गुजरात के माननीय उच्च न्यायालय ने उपर्युक्त मध्यावधिक समीक्षा के अंतिम जांच परिणामों और निर्णायक समीक्षा को रद्द करने के आदेश को अलग कर दिया। माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णायक समीक्षा 6 माह तक पूरी करने की समय-सीमा भी बढ़ा दी और प्राधिकारी को निर्देश दिया कि वे प्रक्रिया के अनुसार निर्णायक समीक्षा पूरी करें।

4. जबकि, यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1995 की धारा 9क(5) के अनुसार, लगाया गया पाटनरोधी शुल्क जब तक कि पूर्व में हटाया न गया हो, उसे लगाए जाने की तारीख से 5 वर्षों की समाप्ति पर अप्रभावी हो जाएगा और प्राधिकारी को यह समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है। उपर्युक्त के अनुसार, प्राधिकारी को घरेलू उद्योग द्वारा किए गए विधिवत सिद्ध अनुरोध अथवा घरेलू उद्योग की ओर से किए गए अनुरोध के आधार पर यह समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है।
5. जबकि, मैसर्स निरमा लि. और मैसर्स डीसीडब्ल्यू लि. (जिन्हें यहां आगे याचिकाकर्ता कहा गया है) ने चीन जन. गण., यूरोपीय संघ, केन्या, पाकिस्तान, ईरान, यूक्रेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना का आरोप लगाते हुए शुल्क 5 वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ाए जाने हेतु "सोडा ऐश" के आयात पर लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा शुरू किए जाने की मांग करते हुए अधिनियम और नियमावली के अनुसार संयुक्त रूप से याचिका दायर की थी।
6. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित 16 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 7/5/2017-डीजीएडी द्वारा निर्णायक समीक्षा यह जांच करने के लिए शुरू की कि क्या पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन अथवा क्षति जारी रहेगी अथवा बार-बार होगी। तथापि, निर्णायक समीक्षा की शुरुआत मध्यावधि समीक्षा के अंतिम परिणाम के अध्यधीन थी जो चल रही है।

ख. प्रक्रिया

7. इस जांच के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई है:
 - i. प्राधिकारी ने जांच शुरू करने संबंधी 16 जुलाई, 2017 की अधिसूचना की प्रतियां भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, संबद्ध देश के ज्ञात निर्यातकों, ज्ञात आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों तथा उपलब्ध सूचना के अनुसार घरेलू उत्पादकों को भेजीं। ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत कर दें और अपने विचारों से लिखित में अवगत करा दें।
 - ii. निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावलियों की प्रतियां संबद्ध देशों के दूतावासों को ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों की सूची के साथ इस अनुरोध के साथ भेजी गई थीम कि वे संबद्ध देशों के निर्यातकों/उत्पादकों को यह सलाह दें कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने उत्तर प्रस्तुत कर दें।
 - iii. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार आवेदक की ओर से दायर की गई याचिका के अगोपनीय रूपांतर की प्रति ज्ञात निर्यातकों, घरेलू उत्पादकों और संबद्ध देश के दूतावासों को उपलब्ध करा दी गई थी।
 - iv. प्राधिकारी ने निर्णायक समीक्षा शुरू करने संबंधी सार्वजनिक अधिसूचना की एक प्रति संबद्ध देश के निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को भेजी थी और नियमावली के नियम 6(2) और 6(4) के अनुसार उन्हें पत्र की तारीख से चालीस दिनों के भीतर लिखित रूप से अपने ज्ञात विचारों से अवगत कराने का अवसर प्रदान किया था:

शानडोंग हाईहुआ ग्रुप, शानडोंग हाईहुआ ग्रुप कंपनी लिमिटेड, डेवलप जोन आफ हाईहुआ बेफेंग सिटी शानडोंग, चीन
क्विंगहाई अल्काली प्लांट (झेझियांग ग्लास चार्इनाजिक्वगटल अल्काली प्लांट) जेझियांग ग्लास चार्इनाजिक्वगहाई डिलिंघा इंडस्ट्रियल पार्क, जिप : 817000 चीन
जिनशान केमिकल कंपनी, हेनन प्रांत में चार्इनाज जेंगझाऊ सिटी, जेंगझाऊ सिटी, फुशोऊशान स्ट्रीट 87, चीन
हेबेई टांगशान सानयु अल काली इंडस्ट्री कंपनी, नानपु डेवलेपमेंट एरिया, टांगशान, हेबेई, चीन
टिआन्जिन सोडा एश प्लांट, नंबर 87 किसनहुआ रोड टंगू, जिला - टिआन्जिन, चीन

सिमान लिमिटेड, पोस्ट बॉक्स 29, कजानलक एसएल, जगोरा, बल्गारिया-6103
सोलवाई सोडी एडी, जिप कोड : 9160, बोसनिया और हेरजेगोविना, ब्रूनर मंडे विन्निंगटन लेन, मोंड हाऊस, नोर्थविच, चेथायर, यूके, सीडब्ल्यू 8 4 डीटी
स्पिन इंटरनेशनल, 13 रयू डे पेस्सी, पेरिस 75016
बेलवेडेरे एसआरएल रोमानिया, सेटेटिआनू लोन, गलाटी, रोमानिया 800198
आशा ट्रेड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, मंगालियर एनआर 71 बीएल पीआईएस डी एपीटी 36, कोन्सटाना 900116, रोमानिया
जीएचसीएल रोमानिया, जीएचसी अपसोम ओईना म्यूस अल्बा काउंटी, रोमानिया 515700
सिसक्केम सोडे लूकोवेक" दि फर्स्ट स्ट्रीट 1 75300 ल्यूकंवा, बोसानिया और हेरजेगोविना
मगडी सोडा कंपनी, पी ओ बॉक्स 1 - 00206, मगडी, केनिया
अलाईड नेटवर्क कंपनी लिमिटेड, असिली को-ओप हाऊस मोई एवन्यू, नेरोबी, केनिया-72964 00200
एफएमसी इंडस्ट्रियल केमिकल्स, 1735 मार्किट स्ट्रीट, फिलाडेलफिया, पीए 19103, संयुक्त राज्य अमरीका
ओसीआई केमिकल कार्पोरेशन, 1800 वेस्ट ओक कोमन कोर्ट सूट 100, मेरिएट्टा, जीए 30062
सोलावे सोडा एश, मुख्यालय, 5333 रिचमोंड एवन्यू, हाऊसटन, टीएक्स 77098, डाक का पता: पी.ओ. बाक्स 27328, हाऊसटन, टीएक्स 77227
जनरल केमिकल्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, 120 ईगल रोक एवन्यू, ईस्ट हेनोवर, न्यू जर्सी, संयुक्त राज्य अमरीका
एएनएसएसी, 15 रीवरसाईड एवन्यू, दूसरा तल, वेस्टपोर्ट, सीटी 06880, संयुक्त राज्य अमरीका
एफएमसी कार्पोरेशन, वेल्स फ्रेगो बैंक एन.ए., शेयरओनर सर्विसिज, पी.ओ. बाक्स 64854, सेंट पोल, एमएन 55164-0854, ओआर 161 एन. कोन्कोर्ड एक्सचेंज साउथ इट, पोल, एमएन
सोडा एश, सोडा एश बिजिनेस आईसीआई पाकिस्तान लिमिटेड 63 - मोजांग रोड, लाहौर, पाकिस्तान
ओलम्पिया केमिकल्स लिमिटेड, 23-डेविस रोड, लाहौर, पाकिस्तान
सिरिना ट्रेड कंपनी, अरुम्स 88 आफिस 25 ला, डोनेट्स्क, यूक्रेन

- v. निर्णायक समीक्षा शुरू करने के उत्तर में संबद्ध देशों के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत नहीं किए हैं अथवा कोई अनुरोध नहीं किया है।
- vi. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार, आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को प्रश्नावलियां भेजी गई थीं:

गुजरात गारजियन लिमिटेड, ग्राम - कोंध, बालिया रोड, प्लांट स्टेट हाईवे नंबर 13, अंकलेश्वर, भडौच - 393001
फ्लोट ग्लास इंडिया लिमिटेड, टी-7 मिडक, इंडस्ट्रियल एरिया, टालोजा, महाराष्ट्र।
हिन्दुस्तान नेशनल ग्लास एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिशरा, पश्चिम बंगाल।
प्रोक्टर एंड गेम्बल हाईजीन एंड हेल्थ केयर, मंडीदीप प्लांट एलएंडसी-एमएफजी, प्लाट नंबर 182, मंडीदीप, मध्य प्रदेश।
एडवाटेज इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड, धनाली, ग्राम - धनाली, अल-कादिल जिला, मेहसाना,

गुजरात।
यू.पी. ग्लास मैनुफैक्चरर्स, सिंडीकेट, 14- मोनापुरम, निकटस्थ गणेश नगर - फिरोजाबाद - 283203, उत्तर प्रदेश।
फेना (प्राईवेट) लिमिटेड, ए-237 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-20
पोल्लाची चेम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री , आर पी काम्पलेक्स , दूसरा तल, 14, बालागोपालापुरम स्ट्रीट, पोल्लाची-642001
पावर सोप लिमिटेड , 62-बी, नॉर्थ बोआग रोड, टी. नगर, चेन्नई-600017
अलेम्बिक ग्लास इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अलेम्बिक रोड, बडोदा (बड़ोदरा) गुजरात।
दीपक नाईट्राईट लिमिटेड, 4/12, केमिकल कॉम्पलेक्स, जीआईडीसी, नानफेसारी, बडौदा (बड़ोदरा) गुजरात।
हिन्दुस्तान यूनीलाईव लिमिटेड, पार्टी का पता, दक्षिण बिल्डिंग, 8वां तल, प्लॉट नंबर-2, सेक्टर-11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई।
अल्ब्राईट मोरारजी एंड पंडित लिमिटेड, अम्बरनाथ, जिला - थाणे, महाराष्ट्र।
सेंट-गोबाइन ग्लास इंडिया, मुख्यालय और संयंत्र: ए-1 सिपकोट इंडस्ट्रियल पार्क, श्रीपेरुम्बदुर-602105, कांची पुरम जिला, तमिलनाडु।
आशी इंडिया ग्लास लिमिटेड , 5वां तल, टावर-बी, ग्लोबल बिजिनेस पार्क, महरौली-गुरुग्राम रोड, गुरुग्राम-122002 (भारत)।
श्री यूनिग्रन आर्गेनिक्स प्राईवेट लिमिटेड, बीएस-3, अपीजे, 130 बम्बई समाचार मार्ग, मुंबई-23
वसुन्धरा रसायन लिमिटेड, सी-104, एमआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया, माहेड, जिला - रायगड, महाराष्ट्र।
शान्तिनाथ डिटर्जेंट प्राईवेट लिमिटेड, पी-15, कलाकार स्ट्रीट, कोलकाता-700007
एडवांस होम एंड पर्सनल केयर प्राईवेट लिमिटेड, एडवांस सर्फेक्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, 511/2/1, ग्राम - रजोकडी, नई दिल्ली-38
एस कुमार डिटर्जेंट प्राईवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 34, सेक्टर-2, इंडस्ट्रियल एरिया, पीथमपुर-454775, जिला - धार, मध्य प्रदेश।
हिन्द सिलेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड, 3ए, ऑकलैंड प्लेस, 5वां तल, कोलकाता-17
पी एंड जे क्रेटकेम (प्राईवेट) लिमिटेड, 318, स्वपन लोक, 92/93, एसडी रोड, सिकन्दराबाद-500003, आन्ध्र प्रदेश (भारत)।
जे.जे. पटेल इंडस्ट्रीज, गोंडल रोड, बी/एच राजकमल पेट्रोल पम्प, वावडी, राजकोट-360004
मार्डन ग्लास इंडस्ट्रीज, कोल सार्डिंग रोड, एस.एन. रोड, फिरोजाबाद-283203
सन्दीप आर्गेनिक्स प्राईवेट लिमिटेड, 104, नैन कूपा, 118/122, काजी सईद स्ट्रीट, मस्जिद बंदर (पश्चिम), वाडगाडी, मुंबई-400003
एलंबिक ग्लास इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एलंबिक रोड, बडौदा (बड़ोदरा) गुजरात।
रोहित सर्फेक्टेंट्स (प्राईवेट) लिमिटेड, 117/एच-2/202, पांडु नगर, कानपुर-05
बीडीजे ग्लास इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड, 1 कईद स्ट्रीट, प्लेस कोर्ट, 1ला तल, सूट-14-ए, कोलकाता-700016
जगजीत इंडस्ट्रीज लिमिटेड, प्लॉट नंबर 78, सेक्टर-18, इंडस्ट्रियल एरिया, गुरुग्राम-122001

हिल्डन ग्लास गुजरात लिमिटेड, 9, गायत्री कमर्सियल काम्पलेक्स, मित्तल इंडस्ट्रियल एरिया इस्टेट नंबर 5 के पीछे, अंधेरी रोड, मारोल नाका, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400059
हिपोलीन लिमिटेड, मधुबन, 4था तल, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-380006
मॉडर्न ग्लास इंडस्ट्रीज, कोल साईडिंग रोड, एस.एन. रोड, फिरोजाबाद-283203
डिटरजेंट मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (दिल्ली क्षेत्र), 148, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल काम्पलेक्स-1, नई दिल्ली-110020
मौली एक्सपोर्ट्स, प्लाट नंबर 97-98, सेक्टर-25, पार्ट-2, इंडस्ट्रियल एरिया, हूडा, पानीपत-132104 (हरियाणा)।
मेसर्स चेम्पेक्स इंटरनेशनल, 393/III/6 बाजेर, बीकानेरियन, कटरा, आहलूवालिया, अमृतसर, पंजाब।
टाटा केमिकल्स लिमिटेड, लीला बिजिनेस पार्क, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-59
मेसर्स टूटीकोरिन अल्काली केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, 534, अन्ना सलई, तेईनामपेट, चेन्नई-18
एजीआई ग्लासपेक, ग्लास फैक्टरी रोड, मोती नगर, पोस्ट बाक्स 1030, शांत नगर, हैदराबाद-500018
पावर सोप्स लिमिटेड, ए-8 प्रथम मेन रोड, अम्बादुर इंडस्ट्रियल इस्टेट, चैन्नई-600 058
हिंडकोन केमिकल्स (प्राईवेट) लिमिटेड, 62/बी, ब्रोनफ्लेड रोड, 1ला तल, कोलकाता-700 027
एम्पायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एम्पायर हाऊस, 414, सेनापति बापत, लोअर पारेल, मुंबई-13

- vii. उपरोक्त अधिसूचना के उत्तर में किसी भी आयातक/प्रयोक्ता ने प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत नहीं किए हैं अथवा कोई अनुरोध नहीं किया है।
- viii. आवश्यक सूचना मंगाने और उत्तर प्राप्त करने के लिए भारत में संबद्ध वस्तुओं के ज्ञात घरेलू उत्पादकों को भी प्रश्नावलियां भेजी गई थीं:

क्रम सं.	घरेलू उत्पादक का नाम
i.	मैसर्स जीएचसीएल लिमिटेड
ii.	मैसर्स टाटा केमिकल्स लिमिटेड
iii.	मैसर्स सौराष्ट्र केमिकल्स लिमिटेड

- ix. जांच शुरू करने संबंधी अधिसूचना निम्नलिखित एसोसिएशनों को भी भेजी गई थीं:

डिटरजेंट मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (दिल्ली क्षेत्र)
इंडियन केमिकल मर्चेन्ट्स एंड मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन
बल्क ड्रग मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (इंडिया)
इंडियन ग्लास मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन
दि डायर्स एंड केमिकल मर्चेन्ट्स एसोसिएशन
आल इंडिया ग्लास मैनुफैक्चरर्स फेडरेशन

अल्काली मैनुफेक्चरर्स एसोसिएशन आफ इंडिया
इंडियन सोप्स एंड टोईलेटरीज मेकर्स एसोसिएशन

- x. निम्नलिखित पक्षकारों ने इस जांच के दौरान अपने अनुरोध प्रस्तुत किए हैं:
- यूक्रेन दूतावास
 - डिटरजेंट मैनुफेक्चरर्स एसोसिएशन आफ इंडिया
 - ऑल इंडिया ग्लास मैनुफेक्चरर्स फेडरेशन
 - सेंट गोबार्डन ग्लास इंडिया लिमिटेड
 - हिन्दुस्तान यूनीलीवर लिमिटेड
 - ओलंपिया केमिकल्स लि., पाकिस्तान
- xi. जिन निर्यातकों, उत्पादकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने प्राधिकारी को कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है और न ही इस जांच से संबद्ध कोई सूचना प्रस्तुत की है, उन्हें असहयोगी हितबद्ध पक्षकार माना गया है।
- xii. वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से अनुरोध किया गया था कि वे जांच की अवधि और विगत तीन वर्षों के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयातों के विस्तृत आंकड़े उपलब्ध कराएं। इसलिए प्राधिकारी ने आयातों की मात्रा का परिकलन करने और अन्य मानदंडों का विश्लेषण करने के लिए डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों पर विश्वास किया है।
- xiii. सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत और निर्माण एवं बिक्री की लागत का आकलन किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यदि पाटनरोधी शुल्क पाटन मार्जिन से कम लगाया जाता है तो क्या वह घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा। प्राधिकारी द्वारा एनईपी का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के तहत निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार किया गया है।
- xiv. यह जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि अप्रैल, 2016 से मार्च, 2017 (जिसे यहां जांच की अवधि कहा गया है) तक है। तथापि, क्षति जांच में वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 और जांच की अवधि शामिल है।
- xv. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को अपने मौखिक विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने के लिए 5 नवंबर, 2018 को एक सार्वजनिक सुनवाई की थी। जिन पक्षकारों ने इस सार्वजनिक सुनवाई के समय अपने मौखिक विचार प्रस्तुत किए थे, उनसे अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए अपने विचारों को लिखित रूप में भी प्रस्तुत करें और साथ ही अपने प्रत्युत्तर भी दें।
- xvi. जांच के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर प्राधिकारी द्वारा जहां भी संगत पाया गया, वर्तमान जांच परिणाम में विचार किया गया है। घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना और आंकड़ों के संबंध में आवश्यक समझी गई सीमा तक सत्यापन किया गया था।
- xvii. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना की गोपनीयता के दावों की उनकी पर्याप्तता के संदर्भ में जांच की गई। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहीं भी उचित था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा है और उसे अन्य पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले हितबद्ध पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर भी प्रस्तुत करें।
- xviii. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने मौजूदा जांच की कार्रवाई के दौरान आवश्यक सूचना देने से मना कर दिया है अथवा ऐसी सूचना अन्यथा प्रदान नहीं की है अथवा जांच में अत्यधिक अड़चन डाली है, वहां प्राधिकारी ने "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम रिकार्ड किए हैं।

- xix. प्राधिकारी ने दिनांक 27.11.2018 के प्रकटन विवरण द्वारा सभी पक्षकारों को विचाराधीन अनिवार्य तथ्य प्रकट किए। प्रकटन विवरण पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए सभी पक्षकारों को पर्याप्त समय दिया गया था। प्रकटन विवरण पर सभी पक्षकारों के अनुरोधों को रिकॉर्ड किया गया है और इस वर्तमान जांच परिणाम में उपयुक्त स्थानों पर उनकी जांच की गई है।
- xx. *** किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई तथा प्राधिकारी द्वारा नियमावली के तहत मानी गई सूचना दर्शाते हैं।
- xxi. प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई जांच की अवधि के दौरान प्रचलित औसत विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 67.95 रुपए है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए अनुरोध

- विचाराधीन उत्पाद डाइ सोडियम कार्बोनेट है जिसे सोडा ऐश के रूप में भी जाना जाता है और जिसका रासायनिक सूत्र इसके सभी रूपों में Na_2CO_3 है और किसी भी प्रक्रिया के माध्यम से उत्पादित किया जाता है।
- सोडा ऐश दो रूपों में उत्पादित किया जाता है – लाइट सोडा ऐश और डैस सोडा ऐश।
- इसे सिंथेटिक प्रक्रिया के माध्यम से उत्पादित किया जाता है जैसा कि प्राकृतिक स्रोतों से भी लिया जाता है।
- जांच का क्षेत्र वही है जो मूल जांच में है।
- सोडा ऐश सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अंतर्गत सीमा शुल्क उप शीर्ष संख्या 2836.20 के तहत वर्गीकृत है और इसमें प्रशुल्क शीर्ष 28362010, 28302020, 26362090 शामिल हैं।
- घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान और संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध सामानों में कोई ज्ञात अंतर नहीं है।
- घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामानों और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध सामानों की भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी, प्रकार्य एवं प्रयोग, उत्पाद विशिष्टि, कीमत, वितरण और विपणन तथा सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण जैसे मानदंडों के संदर्भ में तुलनीय विशेषताएं हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सोडा ऐश और संबद्ध देशों से आयातित सोडा ऐश इस प्रकार समान वस्तु मानी जाती है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

8. मूल जांच में तथा वर्तमान निर्णायक समीक्षा में विचाराधीन उत्पाद "सोडा ऐश" है। मूल जांच में उत्पाद का क्षेत्र निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया था:

"i. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद डाइ सोडियम कार्बोनेट है जिसे सोडा ऐश के रूप में भी जाना जाता है जिसका रासायनिक सूत्र Na_2CO_3 है। सोडा ऐश दो रूपों – लाइट सोडा ऐश और डैस सोडा ऐश में उत्पादित किया जाता है। दोनों किस्मों में अंतर बल्क घनत्व का है। इसे सिंथेटिक तरीके तथा प्राकृतिक तरीके से उत्पादित किया जा सकता है जिसे डिसॉल्यूशन प्रक्रिया जाना जाता है। वर्तमान जांच में सोडा ऐश की सभी किस्में और रूप शामिल हैं।

सोडा ऐश डिटर्जेंट, साबुनें, क्लीनिंग कंपाउंड, सोडियम आधारित रसायनों, फ्लोट ग्लास, कंटेनर और विशेष ग्लासों, सिलिकेट्स और अन्य औद्योगिक रसायनों के विनिर्माण में एक अनिवार्य घटक है। इसका प्रयोग वस्त्र, कागज, धातु निष्कर्षण उद्योगों, डिसेलेशन संयंत्रों में व्यापक रूप से किया जाता है। सोडा ऐश उप शीर्ष संख्या 2836.20 के तहत सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अध्याय 28 के अंतर्गत वर्गीकृत है। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और वर्तमान जांच के क्षेत्र पर किसी भी तरह बाध्यकारी नहीं है।"

9. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और समान वस्तु के संबंध में कोई मुद्दा नहीं उठाया है।
10. प्राधिकारी इस बात की पुष्टि करते हैं कि इस निर्णायक समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद वही है जो मूल जांच में परिभाषित किया गया है। प्राधिकारी यह भी मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु है।

घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार

याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए अनुरोध

- i. जीएचसीएल और टाटा केमिकल्स को छोड़कर किसी भी कंपनी ने स्वयं जांच की अवधि के दौरान संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है।
- ii. टाटा केमिकल्स के केन्या, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में संबंधित उत्पादक हैं। केन्याई और संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनियां टाटा केमिकल्स की सहायक कंपनियां हैं जिन्होंने भारत को सामानों का निर्यात किया है। मूल जांच में प्राधिकारी के निर्णय के मद्देनजर, याचिकाकर्ताओं ने टाटा केमिकल को एक अपात्र घरेलू उद्योग माना है।
- iii. जीएचसीएल ने संबद्ध देशों में से विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है। तथापि, इसके ब्यौरे याचिकाकर्ताओं को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हैं। यदि उपयुक्त माना जाए तो जीएचसीएल को अपात्र घरेलू उद्योग माना जाए।
- iv. मैसर्स निरमा का संयुक्त राज्य अमेरिका में एक संबंधित उत्पादक है जिसने मार्च, 2016 तक भारत को सोडा ऐश का निर्यात किया है। जांच की अवधि में इस कंपनी द्वारा कोई आयात नहीं किए गए हैं।
- v. यह अनुरोध किया गया है कि निर्णायक समीक्षा जांच में आधार कोई अनिवार्य अपेक्षा नहीं है। नियम 23 विशेष रूप से नियम 5 को अलग करता है।
- vi. पाटनरोधी शुल्क बढ़ाए जाने का अनुरोध क्षति के बार-बार होने की संभावना पर आधारित है।
- vii. चूंकि, किसी क्षति का दावा नहीं किया गया है, अतः सभी घरेलू उत्पादकों के लिए आंकड़ों के विश्लेषण की अपेक्षा का कोई कारण नहीं है।
- viii. याचिकाकर्ता कंपनियों के उत्पादन का भारतीय उत्पादन में प्रमुख अनुपात है।
- ix. याचिकाकर्ताओं को केवल इसलिए राहत से इंकार नहीं किया जा सकता कि अन्य भारतीय उत्पादकों ने संगत सूचना प्रस्तुत नहीं की है।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

- i. मैसर्स निरमा लि. का संबद्ध देश अर्थात् संयुक्त राज्य अमेरिका में एक संबंधित उत्पादक है और यह कि जांच की अवधि के दौरान उस संबंधित उत्पादक ने भारत को कोई निर्यात नहीं किए।
- ii. केवल आयातों की मौजूदगी पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के तहत किसी घरेलू उत्पादक को स्वतः अपात्र नहीं मानती। प्राधिकारी को घरेलू उद्योग का क्षेत्र निर्धारित करने का विवेकाधिकार है।
- iii. अनुरोध है कि घरेलू उद्योग जीएचसीएल को केवल इसलिए अलग करे क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में उसका सकारात्मक निष्पादन था।
- iv. मैसर्स निरमा लि. की संयुक्त राज्य अमेरिका में एक संबंधित कंपनी है जो संबद्ध सामानों के विनिर्माण में तथा भारत को संबद्ध सामानों के निर्यात में लगी हुई है। इस संबद्ध कंपनी ने पूरी क्षति अवधि के दौरान संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग को उन उत्पादकों से समझौता नहीं करना चाहिए जो संबद्ध सामानों के निर्यातकों से संबंधित हैं।
- v. याचिकाकर्ताओं के उत्पादन का पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार, कुल भारतीय उत्पादन में प्रमुख अनुपात नहीं है।
- vi. याचिकाकर्ताओं और अन्य भारतीय उत्पादकों के बिक्री आंकड़ों से उत्पादन आंकड़ों की तुलना पर अन्य भारतीय उत्पादकों के वार्षिक उत्पादन और उनकी घरेलू बिक्री में पूर्णतः बेमेल स्थिति है।
- vii. यद्यपि, घरेलू उद्योग का उत्पादन उसकी घरेलू बिक्री से अधिक है, तथापि, दूसरी ओर अन्य भारतीय उत्पादकों का वार्षिक उत्पादन उनकी वार्षिक घरेलू बिक्री का लगभग आधार प्रतीत होता है।
- viii. अन्य भारतीय उत्पादकों के वार्षिक उत्पादन आंकड़ों और अन्य भारतीय उत्पादकों के वार्षिक घरेलू बिक्री के आंकड़ों में पूर्णतः बेमेल स्थिति है।

- ix. प्रस्तुत किए गए आंकड़े घरेलू उद्योग द्वारा पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के तहत इस मामले में झूठा आधार सिद्ध करने के लिए पूर्णतः तोड़े-मरोड़े गए हैं।
- x. यदि अन्य भारतीय उत्पादकों के सही-सही उत्पादन आंकड़ों का प्रयोग किया जाए तो याचिकाकर्ताओं का कुल भारतीय उत्पादन में कहीं भी प्रमुख उत्पादन नहीं होगा, इस प्रकार वे नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग की योग्यता रखने में विफल होते हैं।
- xi. मैसर्स टाटा केमिकल्स लि. की केन्या में एक संबद्ध कंपनी है और मैसर्स जीएचसीएल ने संबद्ध सामानों का आयात किया था तथा याचिकाकर्ताओं द्वारा उन्हें घरेलू उद्योग से अलग किए जाने का दावा किया गया है। इसी तर्क को लागू करते हुए मैसर्स निरमा लि. को भी अलग किया जाना चाहिए क्योंकि उसकी संयुक्त राज्य अमेरिका में एक संबद्ध कंपनी है।
- xii. टाटा केमिकल्स लि. और मैसर्स जीएचसीएल लि. को याचिका के अनुबंध-1.4 में आयातकों की सूची में उल्लिखित नहीं किया गया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

11. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) निम्नानुसार में (पढ़ा जाता है:

"घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से हैं जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।

12. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में यह प्रावधान है कि जो घरेलू उत्पादक निर्यातकों/आयातकों से संबद्ध हैं अथवा जो तथाकथित पाटित आयातों के खुद आयातक हैं, उन्हें घरेलू उद्योग निर्धारित करते समय अलग किया जाए।
13. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मूल जांच में घरेलू उद्योग के घटक संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों में शामिल थे अथवा संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के निर्यातकों/ आयातकों से संबद्ध थे। मूल जांच के अंतिम जांच परिणाम में प्राधिकार ने अंतिम जांच परिणाम संख्या 14/17/2010-डीजीएडी दिनांक 17.02.2012 में निम्नलिखित नोट किया था:

"49. प्राधिकारी मानते हैं कि जो घरेलू उत्पादक पाटित सामानों की अपर्याप्त मात्रा का आयात करते हैं अथवा जिनके संबद्ध निर्यातक पाटित सामानों का निर्यात करते हैं अथवा जिनके संबद्ध आयातक पाटित सामानों का आयात करते हैं, वे पाटन की परिपाटियों से अनुचित लाभ नहीं लेते, यदि ये आयात उनकी बिक्री अथवा बाजार आकार का महत्वपूर्ण भाग नहीं दर्शाते। वस्तुतः बाजार में अन्य आपूर्तिकर्ताओं से प्रतिस्पर्धा के कारण इन घरेलू उत्पादकों को कोई लाभ नहीं होता। प्राधिकारी यह निर्णय लेते समय कि क्या घरेलू उत्पादक को अलग कर दिया जाना चाहिए, क्या घरेलू उत्पादक केवल कुछ पाटित आयातों के साथ अपने घरेलू उत्पादन में सहायता ही कर रहा है अथवा क्या यह प्राथमिक रूप से अपेक्षाकृत रूप से सीमित उत्पादन के साथ एक आयातक है, यह नोट करते हैं कि अन्य देशों के जांचकर्ता अधिकारियों द्वारा लिया गया दूसरा अंतर है। प्राधिकारी मानते हैं कि दूसरे मामले में ऐसी कंपनी को घरेलू उद्योग के क्षेत्र से अलग किया जाना चाहिए। दूसरा तत्व जिस पर विचार किया जा सकता है, वह यह है कि क्या प्रश्नगत घरेलू उत्पादक आयातों के देश में उत्पादन के लिए प्रतिबद्ध है अथवा नहीं।

50. उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी मानते हैं कि निश्चरण के लिए एक मात्र संगत मुद्दा यह है कि क्या जीएचसीएल, निरमा, एससीएल और टाटा केमिकल्स को पात्र घरेलू उद्योग माना जाना चाहिए अथवा नहीं, इस मामले में कोई आरोप नहीं है कि कोई भी घरेलू उत्पादक दूसरे आयातक से संबद्ध है। हितबद्ध पक्षकारों के तर्क हैं कि एससीएल, निरमा और जीएचसीएल को संबद्ध देश में विदेशी उत्पादकों/निर्यातकों के साथ उनके संबंध के मद्देनजर अपात्र घरेलू उद्योग माना जाना चाहिए अथवा निरमा के मामले में अतिरिक्त रूप से निरमा द्वारा किए गए आयातों के कारण अपात्र घरेलू उद्योग माना जाना चाहिए।

51. प्राधिकारी ने वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के उपर्युक्त सिद्धांतों को लागू कर आवेदक कंपनियों की पात्रता के मुद्दे की जांच की है। वर्तमान मामले के तथ्य जहां तक आवेदक कंपनियों के संबंध और पात्रता के मुद्दे का संबंध है, निम्नलिखित है:

- i. यह आवेदन पत्र अलकाली मैनुफैक्चर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एएमएआई) द्वारा दायर किया गया था। एएमएआई कास्टिक सोडा (क्लोरीन सहित) और सोडा ऐश के उत्पादकों की एसोसिएशन है।
- ii. डीसीडब्ल्यू, जीएचसीएल, निरमा और साँकेम ने घरेलू उद्योग को क्षति से संगत सूचना प्रदान की है और वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए "घरेलू उद्योग" के रूप में माने जाने के लिए अनुरोध किया है। इन कंपनियों को "भागीदार कंपनी" के रूप में माना जा रहा है। इस याचिका को जांच की अवधि के दौरान टाटा केमिकल्स को छोड़कर सोडा के सभी भारतीय उत्पादकों का पूर्ण समर्थन है। टाटा केमिकल्स ने न तो पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का समर्थन किया है और न विरोध किया है। तथापि, यह नोट किया जाता है कि मेगाडी सोडा कंपनी, केन्या (जिसे पुनः टाटा केमिकल्स मेगाडी लि. नाम दिया गया था) टाटा केमिकल्स की 100 प्रतिशत सहायक कंपनी है और यह कंपनी नियमित प्रश्रवावली का उत्तर दायर करके वर्तमान जांच में भाग ले रही है।
- iii. जांच की शुरुआत के बाद और पहली मौखिक सुनवाई आयोजित करने के बाद तृतीकोरिन अलकाली केमिकल्स (टीएसी) ने आवेदन पत्र का समर्थन करते हुए और निर्दिष्ट प्राधिकारी से पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का अनुरोध करते हुए दिनांक 23 मई, 2011 के पत्र द्वारा अपने लिखित अनुरोध दायक किए हैं। यह नोट किया जाता है कि टीएसी ने जांच की शुरुआत की अधिसूचना का उत्तर देकर के कार्यवाहियों में भाग नहीं लिया है। यह भी नोट किया जाता है कि वे जांच की अवधि के दौरान संबद्ध सामानों का उत्पादन नहीं कर रहे थे। अतः प्राधिकारी ने इस देरी के स्तर पर टीएसी के अनुरोधों पर विचार नहीं किया है।
- iv. याचिकाकर्ताओं की कोई भी कंपनी भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी भी आयातक से संबद्ध नहीं है।
- v. डीसीडब्ल्यू लि. का भारत से बाहर कोई संबद्ध उत्पादक-निर्यातक नहीं है। कंपनी ने विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है और न ही कंपनी किसी निर्यातक अथवा आयातक से संबद्ध है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि डीसीडब्ल्यू "घरेलू उद्योग" बनते हुए एक पात्र घरेलू उत्पादक है। याचिकाकर्ता ने सशक्त रूप से यह तर्क दिया है कि प्राधिकारी द्वारा यह माने जाने की स्थिति में कि जीएचसीएल, निरमा और एससीएल अपात्र घरेलू उद्योग हैं, डीसीडब्ल्यू अकेले घरेलू उद्योग होगा क्योंकि उस स्थिति में कंपनी का उत्पादन "घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन" का 100 प्रतिशत होगा।
- vi. एससीएल और निरमा निर्विवाद रूप से संबद्ध कंपनियां हैं।
- vii. निरमा ने संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने संबद्ध आपूर्तिकर्ता से सोडा ऐश का आयात किया है। निरमा को छोड़कर किसी भी याचिकाकर्ता कंपनी ने खुद पूरी क्षति अवधि के दौरान किसी भी संबद्ध देश से सामग्री का आयात नहीं किया है।
- viii. जीएचसीएल की रोमानिया में एक संबद्ध कंपनी है जिसका नाम एस. सी. जीएचसीएल अपसोम है। जीएचसीएल के संबद्ध निर्यातक ने वर्तमान क्षति अवधि में भारत को सोडा ऐश का निर्यात किया है। जीएचसीएल ने उत्पादन तथा भारत को निर्यात (मात्रात्मक सूचना केवल) के संबंध में रोमानिया में अपनी संबद्ध कंपनी के ब्यौरे भी दिए हैं। क्षति की अवधि में संबद्ध निर्यातक द्वारा किए गए निर्यातों के ब्यौरे यह दर्शाते हैं कि (क) ये निर्यात जांच की अवधि के दौरान असंबद्ध भारतीय ग्राहकों को रोमानियन कंपनी द्वारा सीधे ही किए गए हैं, और (ख) कंपनी के निर्यात की मात्रा में क्षति की अवधि में भारी गिरावट आई। निम्नलिखित तालिका रोमानिया से निर्यातों की मात्रा, जीएचसीएल अपसोम द्वारा निर्यात तथा अन्य संबंधित ब्यौरे दर्शाती है।

क्रम सं.	विवरण	यूनिट	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
क	(क) एस. सी. जीएचसीएल अपसोम द्वारा निर्यात	मी. टन	17,356	51,353	6,489	4,101
ख	संबद्ध पक्षकारों को निर्यात	मी. टन	11,082	-	-	-
ग	असंबद्ध भारतीय पक्षकारों को निर्यात	मी. टन	6,274	51,353	6,489	4,101

घ	(ख) रोमानिया से कुल आयात	मी. टन	46,594	67,121	7,652	47,148
2	के अनुपात में एस. सी. जीएचसीएल अपसोम द्वारा किए गए निर्यात	मी. टन	17,356	51,353	6,489	4,101
क	भारतीय उत्पादन		0.85%	2.54%	0.32%	0.20%
ख	भारतीय खपत		0.80%	2.33%	0.29%	0.17%
ग	जीएचसीएल का उत्पादन		3.31%	8.68%	1.05%	0.61%
घ	के अनुपात में जीएचसीएल द्वारा किए गए आयात					
क	जीएचसीएल का उत्पादन		2.11%	0.00%	0.00%	0.00%
ख	भारतीय उत्पादन		0.54%	0.00%	0.00%	0.00%
ग	भारतीय खपत		0.51%	0.00%	0.00%	0.00%
3	रोमानिया से सकल आयात	मी. टन	46,594	67,121	7,652	47,148
क	• जीएचसीएल अपसोम द्वारा निर्यात	मी. टन	17,356	51,353	6,489	4,101
ख	• अन्य निर्यातकों द्वारा निर्यात	मी. टन	29,238	15,768	1,163	43,047
ग	रोमानिया से कुल निर्यातों में जीएचसीएल का हिस्सा		37.25%	76.51%	84.80%	8.70%

52. प्राधिकारी मानते हैं कि:

- (i) जीएचसीएल अपसोम रोमानिया से सोडा ऐश का प्रमुख निर्यातक नहीं है। रोमानिया के अन्य निर्यातकों का रोमानिया से प्रमुख निर्यात है।
- (ii) जीएचसीएल अपसोम द्वारा निर्यातों में पूर्ण दृष्टि से और रोमानिया से आयातों के अनुपात में भी काफी गिरावट आई।
- (iii) जीएचसीएल अपसोम द्वारा निर्यात भारत में सोडा ऐश के कुल आयातों, जीएचसीएल द्वारा सोडा ऐश के उत्पादन और भारत में सोडा ऐश की खपत से तुलना करने पर काफी अधिक हैं।
- (iv) जीएचसीएल, इंडिया द्वारा आयात नहीं किए गए थे। आयात सीधे ही असंबद्ध उपभोक्ताओं द्वारा किए गए थे।
- (v) जीएचसीएल अपसोम द्वारा निर्यातों की मात्रा इतनी अधिक नहीं है कि वह घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाए अथवा बढ़ाए।
- (vi) जीएचसीएल का जोर उत्पादन पर जारी है। कंपनी ने व्यापारी नहीं बदला है। न ही कंपनी अनुचित रूप से पाटन से लाभान्वित हुई है। वस्तुतः पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का अर्थ जीएचसीएल अपसोम द्वारा किए गए निर्यातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना होगा। क्षति निर्धारण घरेलू उद्योग के क्षेत्र के अंतर्गत जीएचसीएल को शामिल करके विकृत नहीं होगा।
- (vii) किसी भी विरोधी हितबद्ध पक्षकार ने स्वयं ही संबंध के तथ्य को छोड़कर घरेलू उद्योग के क्षेत्र से जीएचसीएल को हटाए जाने के लिए कोई औचित्य नहीं दिया है।

53. एससीएल और निरमा का संयुक्त राज्य अमेरिका में संबद्ध उत्पादक है जिसका नाम सर्लस वैली मिनरल्स है। क्षति की अवधि में संबद्ध निर्यातक द्वारा किए गए निर्यातों के ब्यौरे यह दर्शाते हैं कि (क) ये निर्यात केवल जांच की अवधि के दौरान किए गए हैं, (ख) निर्यात निरमा को किए गए हैं, (ग) निरमा ने इस सामग्री का प्रयोग अपने खपत के लिए किया है। निम्नलिखित तालिका संयुक्त राज्य अमेरिका से निर्यातों की मात्रा सर्लस वैली मिनरल्स (संयुक्त राज्य अमेरिका में निरमा और एससीएल का संबद्ध उत्पादक) द्वारा निर्यात तथा अन्य संगत ब्यौरे दर्शाती है।

क्रम सं.		यूनिट	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1	(क) सर्लस वैली मिनरल्स द्वारा निर्यात	मी. टन	-	-	-	2,700
	निरमा को निर्यात	मी. टन	-	-	-	2,700
	असंबद्ध भारतीय पक्षकारों को निर्यात	मी. टन	-	-	-	-
	(ख) संयुक्त राज्य अमेरिका से कुल आयात	मी. टन	123	629	830	32,679
	प्रत्यक्ष	मी. टन	123	629	830	17,852
	लदान	मी. टन	-	-	-	14,827
2	के अनुपात में सर्लस वैली मिनरल्स (संयुक्त राज्य अमेरिका) द्वारा किए गए निर्यात					
	भारतीय उत्पादन		0.00%	0.00%	0.00%	0.13%
	भारतीय खपत		0.00%	0.00%	0.00%	0.11%
	निरमा का उत्पादन		0.00%	0.00%	0.00%	0.58%
	के अनुपात में निरमा द्वारा किए गए आयात					
	निरमा का उत्पादन		0.00%	0.00%	0.00%	0.58%
	भारतीय उत्पादन		0.00%	0.00%	0.00%	0.13%
	भारतीय खपत		0.00%	0.00%	0.00%	0.11%
3	भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात	मी. टन	123	629	830	32,679
	निरमा/सॉकेम के संबद्ध पक्षकारों द्वारा निर्यात	मी. टन	-	-	-	2,700
	संयुक्त राज्य अमेरिका से अन्य पक्षकारों द्वारा निर्यात	मी. टन	123	629	830	29,979
	संयुक्त राज्य अमेरिका से कुल आयात में निरमा के संबद्ध उत्पादक द्वारा निर्यातों का हिस्सा		0.00%	0.00%	0.00%	8.26%

54. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

- (i) सर्लस वैली मिनरल्स (संयुक्त राज्य अमेरिका में निरमा और एससीएल की संबद्ध कंपनी) जांच की अवधि के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका से सोडा ऐश का प्रमुख उत्पादक नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका से अन्य निर्यातकों (गैर-संबद्ध) का संयुक्त राज्य अमेरिका से निर्यातों में प्रमुख और काफी अधिक हिस्सा है।
- (ii) सर्लस वैली मिनरल्स द्वारा निर्यात भारत में सोडा ऐश के कुल आयातों, निरमा एवं सॉकेम द्वारा सोडा ऐश के उत्पादन और भारत में सोडा ऐश की खपत से तुलना करने पर काफी अधिक हैं।
- (iii) सर्लस वैली मिनरल्स द्वारा निर्यातों की मात्रा इतनी अधिक नहीं है कि वह घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाए अथवा बढ़ाए।
- (iv) निरमा द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में संबद्ध कंपनी से आयातों का प्रयोग घरेलू बाजार में व्यापार के लिए नहीं किया गया है। इसका प्रयोग निरमा द्वारा कैप्टिव खपत के लिए किया गया है और यह मात्रा निरमा के कुल उत्पादन की तुलना में काफी नहीं है।
- (v) निरमा (अथवा सॉकेम) का जोर उत्पादन पर जारी है। यह उपयुक्त रूप से कहा जा सकता है कि कंपनी ने आयातित सामानों में व्यापार नहीं बदला है। न ही कंपनी को पाटन से अनुचित रूप से लाभ होना कहा जा सकता है। वस्तुतः पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का अर्थ सर्लस वैली मिनरल्स द्वारा किए गए निर्यातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना होगा। क्षति निर्धारण घरेलू उद्योग के क्षेत्र के अंतर्गत सर्लस वैली मिनरल्स को शामिल करके विकृत नहीं होगा।
- (vi) किसी भी विरोधी हितबद्ध पक्षकार ने स्वयं ही संबंध के तथ्य को छोड़कर घरेलू उद्योग के क्षेत्र से सर्लस वैली मिनरल्स को हटाए जाने के लिए कोई औचित्य नहीं दिया है।

55. टाटा केमिकल्स (संबद्ध सामानों का एक घरेलू उत्पादक) का रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार केन्या में एक संबद्ध उत्पादक है और प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान केन्या से काफी आयात हुए हैं। वर्तमान जांच में एक संबद्ध देश के रूप में केन्या शामिल है। क्षति की अवधि में केन्या में संबद्ध निर्यातक द्वारा किए गए निर्यातों के ब्यौरे यह दर्शाते हैं कि (क) केन्याई कंपनी टाटा केमिकल्स की एक सहायक कंपनी है, (ख) रिकार्ड केन्या में सोडा ऐश का कोई अन्य उत्पादक नहीं दर्शाता, (ग) ये निर्यात पूरी क्षति की अवधि में किए गए हैं, (घ) याचिकाकर्ता ने दावा किया कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने ठोस कारणों के साथ विवाद नहीं किया है कि टाटा केमिकल्स को घरेलू उद्योग बनने के लिए नियम 2(ख) के तहत अपात्र घरेलू उद्योग माना जाना चाहिए। निम्नलिखित तालिका केन्या से निर्यातों की मात्रा मेगाडी सोडा ऐश (जिसे टाटा केमिकल्स मेगाडी लि. नाम दिया गया था) द्वारा निर्यात तथा अन्य संगत ब्यौरे दर्शाती है।

क्रम सं.		यूनिट	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1	(क) मेगाडी सोडा द्वारा निर्यात	मी. टन	85,797	1,15,520	1,17,572	1,06,585
	संबद्ध पक्षकारों को निर्यात	मी. टन	-	-	-	2,005
	असंबद्ध भारतीय पक्षकारों को निर्यात	मी. टन	85,797	1,15,520	1,17,572	1,04,580
	(ख) केन्या से कुल आयात	मी. टन	85,797	1,15,520	1,17,572	1,06,585
2	के अनुपात में मेगाडी सोडा द्वारा किए गए निर्यात (केन्या)	मी. टन	85,797	1,15,520	1,17,572	1,06,585
	भारतीय उत्पादन		4.19%	5.72%	5.79%	5.13%
	भारतीय खपत		3.97%	5.24%	5.33%	4.32%
	टीसीएल का उत्पादन		11.33%	16.57%	16.91%	15.32%

56. उपर्युक्त से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि:

- (i) मेगाडी सोडा, केन्या (जिसे टाटा केमिकल्स मेगाडी लि. नाम दिया गया था) केन्या से सोडा ऐश का पूरा निर्यातक है।
- (ii) मेगाडी सोडी (केन्या) द्वारा निर्यात भारत में सोडा ऐश के कुल आयातों, टाटा केमिकल्स द्वारा सोडा ऐश के उत्पादन और भारत में सोडा ऐश की खपत से तुलना करने पर काफी अधिक हैं।
- (iii) मेगाडी सोडा (केन्या) द्वारा निर्यातों की मात्रा इतनी अधिक नहीं है कि घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाए अथवा बढ़ाए।
- (iv) टाटा केमिकल्स का जोर उत्पादन पर जारी है। कंपनी ने व्यापारी नहीं बदला है, तथापि, संबद्ध कंपनी द्वारा पाटन से जांच की अवधि के दौरान केन्या से संबद्ध कंपनी द्वारा निर्यातों की मात्रा को देखते हुए इस कंपनी को अनुचित लाभ होने से नकारा नहीं जा सकता।
- (v) यद्यपि, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि टाटा केमिकल्स को अपात्र घरेलू उद्योग माना जाना चाहिए, तथापि, किसी भी विरोधी हितबद्ध पक्षकार ने टाटा केमिकल्स को घरेलू उद्योग के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए जाने की मांग नहीं की है।

57. इस प्रकार, यह देखा जाता है कि:

- (i) संयुक्त राज्य अमेरिका से 85 प्रतिशत निर्यात और रोमानिया से 93 प्रतिशत निर्यात भारतीय उत्पादकों से असंबद्ध उत्पादकों द्वारा हैं। तथापि, मेगाडी से 100 प्रतिशत निर्यात एक भारतीय उत्पादक से संबद्ध उत्पादक द्वारा है।
- (ii) जहां तक टाटा केमिकल्स का संबंध है, मेगाडी सोडा द्वारा किए गए निर्यात काफी अधिक हैं। मेगाडी सोडा केन्या में सोडा ऐश का एक मात्र उत्पादक है। निर्यात की मात्रा में गिरावट नहीं आई है। मेगाडी सोडा की कम घरेलू मांग है और कंपनी का जोर निर्यातों (कंपनी द्वारा निर्यात उसकी कुल बिक्री के लगभग 90 प्रतिशत हैं) पर है। प्राधिकारी मानते हैं कि यद्यपि, टाटा केमिकल्स एक घरेलू उत्पादक है, तथापि, कंपनी को वर्तमान जांचों के लिए "घरेलू उद्योग" के रूप में माने जाने के लिए अपात्र माना जाना चाहिए।
- (iii) जहां तक जीएचसीएल का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध निर्यातक द्वारा किए गए निर्यातों में क्षति की अवधि में काफी गिरावट आई है, रोमानिया से 93 प्रतिशत निर्यात, रोमानिया में असंबद्ध उत्पादकों द्वारा है। जीएचसीएल का जोर विनिर्माण से व्यापार की ओर नहीं बदला है, और न ही कोई अनुचित लाभ संबद्ध निर्यातक अथवा जीएचसीएल को होना कहा जा सकता है। प्राधिकारी जीएचसीएल को वर्तमान जांचों के प्रयोजन के लिए "घरेलू उद्योग" माने जाने के लिए पात्र मानते हैं।
- (iv) जहां तक निरमा और सॉकेम का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध निर्यातक द्वारा किए गए निर्यात केवल जांच की अवधि में थे। संयुक्त राज्य अमेरिका से 85 प्रतिशत निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका में असंबद्ध उत्पादकों द्वारा हैं। निरमा का जोर विनिर्माण से व्यापार की ओर नहीं बदला है जैसा कि संगत आंकड़े दर्शाएंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका में संबद्ध उत्पादक द्वारा किए गए निर्यातों से भारत में घरेलू उत्पादक अर्थात् निरमा या सॉकेम को अनुचित लाभ होना नहीं कहा जा सकता। इसके बजाए आंतरिक खपत के लिए सामग्री की बहुत कम मात्रा का आयात किया गया है। उपर्युक्त स्थिति के मद्देनजर, प्राधिकारी निरमा और सॉकेम को वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए "घरेलू उद्योग" माने जाने के लिए पात्र मानते हैं।

58. इस प्रकार, प्राधिकारी का यह मत है कि जीएचसीएल, निरमा, सॉकेम और डीसीडब्ल्यू लि. को पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के तहत घरेलू उद्योग माना जाना उपयुक्त है। तदनुसार, प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के साथ पठित नियम 2(ख) की अपेक्षाओं को पूरा करते हुए जीएचसीएल, निरमा, सॉकेम और डीसीडब्ल्यू लि. को "घरेलू उद्योग" के रूप में घटक आवेदक मानते हैं।

14. वर्तमान जांच में, मैसर्स डीसीडब्ल्यू लि. ने न तो संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का आयात किया है और न ही संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातकों या निर्यातकों से संबंधित है। मैसर्स निरमा लि. ने भी संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है। तथापि, संयुक्त राज्य अमेरिका में उनकी संबद्ध कंपनी ने 2014-15 (संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के कुल आयात का *** प्रतिशत और निरमा लि. द्वारा विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन का *** प्रतिशत) तथा 2015-16 (संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के कुल आयात का *** प्रतिशत और निरमा लि. द्वारा

विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन का *** प्रतिशत) के दौरान भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मैसर्स निरमा लि. की संबद्ध कंपनी ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध सामानों का निर्यात नहीं किया है। किसी भी अन्य भारतीय उत्पादक ने याचिकाकर्ताओं के आधार का विरोध नहीं किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै. निरमा लिमिटेड का जोर संबद्ध सामानों के घरेलू उत्पादन पर रहता है।

15. वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग के संघटकों की उत्पादन स्थिति निम्नलिखित है:

विवरण	यूओएम	2013- 14	2014- 15	2015-16	जांच की अवधि
याचिकाकर्ताओं का उत्पादन	मी. टन	925,479	940,319	1,017,741	1,042,246
अन्य भारतीय उत्पादक (जीएचसीएल, टाटा केमिकल्स लि. और तूतीकोरिन अलकालीज से युक्त)	मी. टन	1,410,117	1,477,012	1,492,907	1,568,253
कुल भारतीय उत्पादन	मी. टन	2,335,596	2,417,331	2,510,649	2,610,499
कुल भारतीय उत्पादन (टाटा केमिकल्स लि. को छोड़कर)	मी. टन	1,611,777	1,693,439	1,786,756	1,886,607
याचिकाकर्ताओं का हिस्सा	%	40%	39%	41%	40%
अन्य भारतीय उत्पादकों का हिस्सा	%	60%	61%	59%	60%
याचिकाकर्ताओं का हिस्सा (यदि टाटा केमिकल्स लि. को भारतीय उत्पादकों का भाग नहीं माना जाता है)	%	57%	56%	57%	55%

16. प्राधिकारी मानते हैं कि भारतीय पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5(3) के अनुसार याचिकाकर्ता आधार की आवश्यकता को पूरा करते हैं।

ड. गोपनीयता

अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

- याचिकाकर्ता ने याचिका में कई सूचनाओं और आंकड़ों के संबंध में गोपनीयता का दावा किया है जिससे उत्तरदाताओं की अपने हितों की रक्षा करने की क्षमता में व्यवधान आता है क्योंकि उन्हें अनिवार्य तथ्य ज्ञात नहीं हैं।
- याचिकाकर्ता पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 और पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 6.5 के तहत अपेक्षित कतिपय अनिवार्य तथ्यों के संबंध में गोपनीयता का दावा करने का सही कारण देने में विफल रहे हैं।
- निर्यात बिक्री मात्रा का गोपनीय व्यवहार, संयुक्त राज्य अमेरिका में मैसर्स निरमा लि. की संबद्ध कंपनी द्वारा क्षति की अवधि के दौरान भारत को संबद्ध सामानों के निर्यात, कैप्टिव खपत, मालसूची और रोजगार पाटनरोधी नियमावली के नियम 7(1) और पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 6(5) के उल्लंघन में है।
- उपर्युक्त सूचना उत्तरदाता को काफी प्रतिस्पर्द्धी लाभ नहीं देगी और न ही याचिकाकर्ताओं पर उसका अधिक प्रतिकूल प्रभाव है तथा इसलिए इस सूचना को "प्रकृति में गोपनीय" के रूप में नहीं माना जा सकता।
- याचिकाकर्ताओं ने उपर्युक्त सूचना और आंकड़ों को गोपनीय माने जाने का कोई ठोस कारण नहीं दिया है।
- गोपनीय बनाई गई सूचना विशेष रूप से लागत संबंधी सूचना का कोई अगोपनीय सार नहीं दिया गया है। यह पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 और पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 6.5 के उल्लंघन में है।
- दिनांक 09 दिसंबर, 2013 की व्यापार सूचना संख्या 1/2013 के अनुसार याचिका के अगोपनीय रूपांतर में सूचीकरण और/अथवा गोपनीय आंकड़ों का सार होने की अपेक्षा है।

- viii. अगोपनीय सार पर्याप्त ब्यौरे में होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर दी गई सूचना के सार को उपयुक्त रूप से समझा जा सके।
- ix. व्यापार सूचना के अनुसार गोपनीयता के आधार पर सार्थक अगोपनीय रूपांतर के बिना किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।
- x. अर्जेंटीना-सेरामिक टाइल्स में यह देखा गया था कि अगोपनीय सार का प्रयोजन हितबद्ध पक्षकारों को सूचित करना है ताकि वे अपने हितों की रक्षा कर सकें।
- xi. याचिकाकर्ता उनके द्वारा जिस सूचना पर विश्वास किया गया है, उसका स्रोत देने में विफल रहे हैं।

प्राधिकारी द्वारा जांच

17. सूचना की गोपनीयता के संबंध में, पाटनरोधी नियमावली के नियम में 7 निम्नलिखित प्रावधान है:

(1) नियम उपनियमों के 6(2), (3) और (7) उपनियम के 12 नियम, (2) उपनियम के 15 नियम, (4) और नियम उपनियम के 17 (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम उपनियम के 5 (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में निहित किसी बात को होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि गोपनीयता के लिए अनुरोध न्यायसंगत नहीं अथवा सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा इसको सामान्य तौर पर अथवा संक्षिप्त रूप में उसे प्रकट करने के लिए अनिच्छुक हो। ऐसी सूचना हो तो उपेक्षा की जा सकती है।

18. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना की गोपनीयता के दावों की उनकी पर्याप्तता के संदर्भ में जांच की गई। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहीं भी उचित था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा है और उसे अन्य पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर भी प्रस्तुत करें। प्राधिकारी ने सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराए।

च. विविध अनुरोध

याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए अनुरोध

- i. वर्तमान पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने से निरंतर पाटन होने अथवा पाटन के बढ़ने तथा घरेलू उद्योग को बार-बार क्षति होने की संभावना है।
- ii. सोडा ऐश के आयात इस समय पाटनरोधी शुल्क के अध्यक्षीन हैं जिसके बावजूद वे पाटित कीमतों पर संबद्ध देश से भारत में निर्यात किए जा रहे हैं।
- iii. संबद्ध निर्यातक घरेलू उद्योग के लिए उचित कीमत से कम कीमत पर कई अन्य देशों को उत्पाद का निर्यात कर रहे हैं।
- iv. दिनांक 03.07.2012 की अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार ने पूर्व में संबद्ध देशों से सोडा ऐश के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया था। एक हितबद्ध पक्षकार द्वारा दायर आवेदन पत्र पर एक समीक्षा (मध्यावधिक समीक्षा) 21.07.2015 को शुरू की गई थी। इस मध्यावधिक समीक्षा के परिणामस्वरूप शुल्क समाप्त करते हुए 21.12.2016 की सीमा शुल्क अधिसूचना जारी की गई। मध्यावधिक समीक्षा को पूर्व के 14.09.2016

के प्रकटन विवरण और 23.09.2016 के अंतिम जांच परिणाम के साथ उपर्युक्त सीमा शुल्क अधिसूचना को चुनौती देते हुए घरेलू उद्योग द्वारा दायर 2016 के विशेष सिविल आवेदन संख्या 16426 के लंबित होने के कारण आस्थगित रखा गया था। वे अहमदाबाद के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय और पारित आदेश दिनांक 23.02.2017 द्वारा रद्द और अलग कर दिया।

- v. एक नया प्रकटन विवरण 60 दिन के भीतर जारी किए जाने का आदेश दिया गया था। प्राधिकारी ने उपर्युक्त प्रकटन विवरण 07.06.2017 को जारी किया जबकि 60 दिन की अवधि की समाप्ति की तारीख 30.05.2017 थी। प्राधिकारी ने 16.06.2017 की अधिसूचना द्वारा वर्तमान संबद्ध देशों से सोडा ऐश के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा की शुरुआत की। यह अनुरोध किया गया है कि अनिवार्य तथ्य प्रकट करते समय, जो कि कुछ नहीं बल्कि उन तथ्यों का अंतिम सेट है जिन पर प्राधिकारी ने पाटन एवं क्षति के बार-बार होने की संभावना की स्थिति तथा पाटन जारी रहना दर्शाते हुए और पांच वर्षों के लिए आगे शुल्क लगाए जाने पर विचार करने के लिए निर्णायक समीक्षा शुरू करते हुए अंतिम निर्धारण करेंगे, प्राधिकारी ने मध्यावधिक समीक्षा में पाटनरोधी शुल्क दिनांक 22.07.2017 के अंतिम जांच परिणाम द्वारा समाप्त करने की सिफारिश की। उसी दिन प्राधिकारी ने निर्णायक समीक्षा वापस लेने के एक आदेश भी जारी किया।
- vi. चूंकि, दिनांक 03.07.2012 की अधिसूचना की पांच वर्ष की अवधि 02.07.2017 को समाप्त हो रही थी और चूंकि, मध्यावधिक समीक्षा प्राधिकारी द्वारा पूरी नहीं की गई थी, जबकि निर्णायक समीक्षा पहले ही शुरू कर दी गई थी। अतः पाटनरोधी शुल्क की अवधि 2017 के विशेष सिविल आवेदन सं. 12249 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित 30.06.2017 के आदेश के अनुसरण में जारी दिनांक 30.06.2017 की अधिसूचना के माध्यम से सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9क(5) के तहत एक वर्ष अर्थात् 02.07.2018 तक बढ़ाई गई थी।
- vii. याचिकाकर्ताओं ने 22.07.2017 के अंतिम जांच परिणाम और दिनांक 22.07.2017 के रद्द किए जाने के आदेश को याचिका तथा संबद्ध मामलों के माध्यम से चुनौती दी है। उच्च न्यायालय ने 31.07.2017 के आदेश द्वारा केंद्र सरकार को 22.07.2017 के अंतिम जांच परिणामों और 22.07.2017 के निरस्तीकरण आदेश पर कार्रवाई करने से रोका। इस प्रकार, 31.07.2017 के आदेश के आधार पर वर्तमान मामले का वापसी आदेश "प्रचालन में नहीं" था और जांच यथा तथ्यतः बनाए रखी गई थी।
- viii. प्राधिकारी को निर्णायक समीक्षा पूरी करने के लिए जांच करना अपेक्षित था।
- ix. घरेलू उद्योग ने 26.04.2018 और 02.05.2018 के पत्रों द्वारा जांच पूरी करने का अनुरोध किया।
- x. चूंकि, विषयगत रिट याचिकाएं लंबित थीं और प्राधिकारी ने 22.07.2018 से पूर्व अर्थात् जिस दिन शुल्क की बढ़ाई गई अवधि समाप्त होनी थी, उस दिन तक जांच पूरी करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए, अतः घरेलू उद्योग ने विषयगत याचिका में 2018 की आईए संख्या 1 दायर की।
- xi. उच्च न्यायालय ने 11.06.2018 के निर्णय तथा आदेश द्वारा मध्यावधिक समीक्षा में 22.07.2017 के अंतिम जांच परिणाम को रद्द करते हुए तथा उसे अलग करते हुए और दिनांक 22.07.2017 के निर्णायक समीक्षा के निरस्तीकरण के आदेश को रद्द करते हुए और उसे अलग करते हुए विषयगत रिट याचिका की अनुमति दी।
- xii. न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन करने के लिए प्राधिकारी के लिए यह आवश्यक था कि वे नियमावली के नियम 17(1)(क) के पहले परंतुक के तहत समय बढ़ाए जाने की मांग करें।
- xiii. अलकाली मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने दिनांक 12.06.2018 के पत्र द्वारा प्राधिकारी को 11.06.2018 के निर्णय और आदेश के संबंध में सूचित किया और प्राधिकारी से निर्णायक समीक्षा पूरी करने का अनुरोध किया।
- xiv. याचिकाकर्ताओं ने 13.06.2018 के ई-मेल द्वारा समय बढ़ाए जाने की मांग करने के अनुरोध के साथ इस तथ्य की ओर प्राधिकारी का ध्यान आकर्षित किया।
- xv. यह देखने पर कि कोई अनुपालन नहीं था, घरेलू उद्योग उपर्युक्त आदेशों के लिए 2018 के विविध सिविल आवेदन पत्र संख्या 3 द्वारा उच्च न्यायालय में चला गया। इसकी 15.06.2018 के निर्णय और आदेश द्वारा

- अनुमति दी गई तथा उच्च न्यायालय ने नियमावली के नियम 17(1)(क) के पहले परंतुक के अनुसार 6 माह तक निर्णायक समीक्षा जांच में निष्कर्ष निकालने की अवधि बढ़ा दी।
- xvi. एक समीक्षा जांच 12 माह से अनधिक अवधि के भीतर पूरी की जानी चाहिए, परंतु नियम 23 के अनुसार 6 माह तक बढ़ाई जा सकती है।
- xvii. उपर्युक्त माह की समाप्ति के बाद, निर्णायक समीक्षा पूरी करने के लिए कानून में आगे अवधि बढ़ाना अधिदेशित नहीं है। वह अवधि 15.12.2018 को समाप्त हो रही है।
- xviii. इस संबंध में, अलकाली मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन द्वारा प्राधिकारी को 17.07.2018 के पत्र द्वारा सूचित किया गया था।
- xix. घरेलू उद्योग ने 19.10.2018 के पत्र द्वारा प्राधिकारी का ध्यान पुनः आकर्षित किया।
- xx. दिनांक 02.07.2018 को शुल्क बंद किए जाने के बाद संबद्ध देशों से भारत में सोडा ऐश का आयात काफी बढ़ गया है।
- xxi. अगस्त, 2018 और सितंबर, 2018 माह में आयात जुलाई, 2018 से 23 प्रतिशत की वृद्धि पर रहे हैं।
- xxii. चीन ने जुलाई में 54 प्रतिशत की तुलना में अगस्त में 1718 प्रतिशत तक संबद्ध सामानों का निर्यात बढ़ाया है।
- xxiii. संयुक्त राज्य अमेरिका ने 796 प्रतिशत तक आयातों की मात्रा बढ़ाई है।
- xxiv. मध्यावधिक समीक्षा के तथाकथित जांच परिणाम गलत पाए गए थे और माननीय उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया।
- xxv. हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के प्रति असम्मान दर्शाते हैं।
- xxvi. सोडा ऐश उद्योग का देश में पाटन का इतिहास है।
- xxvii. पूर्व जांचों में निर्धारित पाटन मार्जिन और वर्तमान जांच में प्रस्तावित पाटन मार्जिन काफी अधिक हैं और स्पष्ट रूप से पाटन की संभावना तथा पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में परिणामस्वरूप क्षति दर्शाते हैं।
- xxviii. पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में, ये निर्यातक घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा लेकर भारत में विचाराधीन उत्पाद को पाटित करने का बेहतर स्तर प्राप्त करेंगे।
- xxix. आयात मात्रा जांच की अवधि में और पाटित कीमतों पर बढ़ी है। आयात पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में पाटित कीमतों पर काफी मात्रा में आने की संभावना है।
- xxx. आयातों का ह्रासमान/न्यूनीकरण प्रभाव भारतीय बाजार में नहीं देखे गए थे क्योंकि पाटनरोधी शुल्क मौजूद था। आयात कीमत में काफी गिरावट आनी शुरू हो गई है और घरेलू उद्योग की कीमतों पर ह्रासमान प्रभाव शुरू हो गया है। जैसे ही नई तुर्की क्षमताओं का वाणिज्यिकीकरण हुआ है, जो कि वैश्विक मांग आपूर्ति परिदृश्य को खतरा पैदा कर रहा है।
- xxxi. घरेलू उद्योग संबद्ध उत्पादकों के साथ मालसूची के स्तरों को सुनिश्चित नहीं कर पाया। संबद्ध देशों में उपलब्ध आसन्न क्षमताओं के मद्देनजर यह उचित रूप से कहा जा सकता है कि जैसे ही बाजार उपलब्ध होगा, उत्पादन किया जा सकता है।
- xxxi. संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन संबद्ध सामानों के क्रमशः पहले और दूसरे सबसे बड़े निर्यातक रहे हैं।
- xxxi. तुर्की निर्यातकों के पास *** मिलियन मीट्रिक टन की क्षमताएं हैं जिनमें से उनकी मांग लगभग *** मिलियन मी. टन है जो निर्यात के लिए *** मी. टन छोड़ता है। यह समान यूरोप को भेजे जाते हैं और फिर भारत को भेजे जाते हैं।
- xxxi. चीन, यूरोपीय संघ, यूक्रेन और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा तीसरे देशों में भी पाटन की मौजूदगी है। पिछले एक दशक के आयातों के लिए लेन-देन वार विक्षेपण किया गया है।

- xxxv. पाटित निर्यातों की मात्रा निरंतर बहुत अधिक थी।
- xxxvi. क्षतिकारक निर्यातों की मात्रा पूर्व में बहुत अधिक थी। हिस्से में 2015-16 तक गिरावट आई और उसके बाद वृद्धि हुई।
- xxxvii. कीमत आकर्षक निर्यातों की मात्रा भारत में खपत की तुलना में वर्तमान जांच की अवधि में काफी अधिक है तथा उसके बाद अनुपात जांच की अवधि के बाद बढ़ा।

अन्य हितवद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

- i. गैर-आयातक औद्योगिक प्रयोक्ता के लिए प्रश्नावली का कोई लागू प्रपत्र नहीं है। यह केवल जांच की शुरुआतों के लिए लागू है जो फरवरी, 2018 के बाद हुई।
- ii. वर्तमान मामले के जटिल इतिहास से जांच में किसी समय-सीमा में संदिग्धता जुड़ी है।
- iii. कोई शुल्क मौजूद नहीं है क्योंकि प्राधिकारी ने शुल्कों की अवधि बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से आवेदन नहीं किया। प्राधिकारी के लिए केंद्र सरकार को अपनी सिफारिश देने का कोई अवसर नहीं है।
- iv. राजस्व विभाग फोरेक इंडिया लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी तथा अन्य के निर्णय के अनुसार शुल्क नहीं बढ़ा सकते क्योंकि कोई मौजूदा शुल्क नहीं है। यदि नियम 18 के तहत अवधि में रुकावट आ जाती है तो कोई प्राधिकारी शुल्क नहीं बढ़ा सकता। उपर्युक्त निर्णय को स्थगित नहीं किया गया है और इसीलिए प्राधिकारी पर बाध्यकारी है।
- v. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने जांच के 36 दिन के बाद निर्णायक समीक्षा जांच को रद्द किया है।
- vi. किसी भी हितवद्ध पक्षकार को भाग लेने अथवा अपने अनुरोध देने का अवसर नहीं है क्योंकि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने जांच की शुरुआत से 40 दिन की समाप्ति के पूर्व जांच बंद कर दी थी।
- vii. प्राधिकारी ने उत्तर देने अथवा अनुरोध करने के लिए किसी हितवद्ध पक्षकार को अवसर दिए बिना सुनवाई 16 माह से अधिक की समाप्ति के बाद की।
- viii. किसी भी हितवद्ध पक्षकार को न तो उत्तर देने का समय मिला और न ही प्राधिकारी ने हितवद्ध पक्षकारों को उत्तर प्रस्तुत करने अथवा अपने अनुरोध करने के लिए संशोधित समय-सीमा के संबंध में सूचित किया।
- ix. घरेलू उद्योग अत्यधिक न्यायिक जांच की मांग कर सक्षम प्राधिकारी द्वारा वास्तविक जांच परिणाम के माध्यम से व्यवधान रहित तरीके से शुल्क बढ़ाने में सक्षम था जो यह दर्शाता है कि वर्तमान मामले में पाटनरोधी शुल्क की आवश्यकता नहीं है।
- x. सोडा ऐश उद्योग एक सुसंगठित क्षेत्र है जिसको बहुत लंबी समयावधि से पाटनरोधी शुल्क के लाभ प्राप्त हो रहे हैं।
- xi. जीएचसीएल और टाटा केमिकल्स को सोडा ऐश उद्योग की वास्तविक स्थिति छिपाने के लिए अलग कर दिया गया है।
- xii. सोडा ऐश उद्योग पिछले कई वर्षों से उत्कृष्ट तरीके से निष्पादन करता रहा है जो यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग किसी भी वास्तविक क्षति के लिए सुभेद्य नहीं है।
- xiii. पिछले 8 वित्तीय वर्षों में यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग लगभग 80 प्रतिशत (औसत लगभग 83 प्रतिशत) से अधिक के सुदृढ़ क्षमता उपयोग को बनाए रखने में सक्षम था। यह घरेलू उद्योग की मौलिक रूप से मजबूत स्थिति दर्शाता है और घरेलू उद्योग को कोई खतरा नहीं होता।
- xiv. घरेलू उद्योग उपयुक्त वृद्धि के साथ निरंतर उत्पादन एवं बिक्री की स्थिति दर्शाता है।
- xv. भारतीय उत्पादकों का भारतीय बाजार में 80 प्रतिशत हिस्सा बना रहा है और जो कि भारत में आयातित किया जा रहा है, वह केवल 20 प्रतिशत तक है। अतः बाजार हिस्से में भारी अंतराल है। पाटनरोधी शुल्क जारी रखने से सभी आयात रुक सकते हैं जो कि घरेलू उद्योग का यह इरादा प्रतीत होता है कि वे पूरा एकाधिकार ले सकें।

- xvi. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता लाभ तथा आरओसीई के संदर्भ में अधिक रही है और बढ़ती रही है, आयातों से अप्रभावित रही है।
- xvii. आयातों की पहुँच कीमतों से कुछ समय के लिए घरेलू उद्योग को कोई कीमत ह्रास अथवा न्यूनीकरण प्रभाव तथा कम कीमत पर बिक्री प्रभाव नहीं हो रहा था। यह कीमत प्रभाव स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग की कीमतों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं बनने जा रहा है।
- xviii. सकारात्मक कीमत कटौती ही घरेलू उद्योग द्वारा लगाई गई बहुत अधिक कीमत का परिणाम है और किसी प्रतिकूल कीमत स्थिति को नहीं बताता।
- xix. भारत में बहुसंख्य प्रयोक्ता उद्योग और क्षेत्र हैं जिनके लिए सोडा ऐश एक प्रमुख कच्ची सामग्री है और लागू पाटनरोधी शुल्क का प्रयोग करने वाले घरेलू उद्योग द्वारा लगाई गई अवास्तविक रूप से अधिक कीमतों से ये उद्योग अपने वैश्विक व्यापारियों के विरुद्ध गैर-प्रतिस्पर्द्धी हो गई हैं और इन्हें भारी नुकसान हो रहा है।
- xx. पाटनरोधी शुल्क की मदद से सोडा ऐश उद्योग को लाभ देने से भारत में सोडा ऐश के व्यापार में प्रतिस्पर्द्धा समाप्त हो गई है जो कि पाटनरोधी शुल्क का प्रयोजन नहीं था।
- xxi. घरेलू उद्योग यह प्रचार करने का प्रयास कर रहा है कि लागू पाटनरोधी शुल्क के कारण निष्पादन अच्छा है। इसका अर्थ संभावना का उल्लेख करके शुल्कों को जारी रखने के लिए मांग बताना है।
- xxii. भारत में आयात मात्रा मांग-आपूर्ति अंतराल को पूरा करने के लिए एक स्तर पर रही है। आयात की पहुँच कीमतों से घरेलू उद्योग पर कोई कीमत प्रभाव नहीं बन रहे थे।
- xxiii. संबद्ध देशों से सोडा ऐश के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क जारी रखना पाटनरोधी शुल्क योजना का पूर्णतः दुरुपयोग होगा। यह लाभ कमाने का एक हथियार बन गया है। पाटनरोधी शुल्क न्यायाकि कार्यवाहियों में शामिल तकनीकियों के कारण लागू है और वर्तमान शुल्कों को जारी रखने में कोई औचित्य नहीं है।
- xxiv. रिट याचिका संख्या 4886/2014 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा स्थापित कानूनी स्थिति के अनुसार यहां तक कि यदि प्राधिकारी निर्देशों के अनुसार वर्तमान निर्णायक समीक्षा पूरी भी करते हैं और शुल्क जारी रखने की सिफारिश करते हैं तो शुल्क आगे बढ़ाया नहीं जा सकता क्योंकि 02.07.2018 की तारीख पहले ही निकल चुकी है।
- xxv. घरेलू उद्योग ने माननीय गुजरात उच्च न्यायालय ने अपने याचिका में कोई विदेशी पक्षकार उत्तरदाता नहीं बनाया है जिसमें उनके ज्ञात विचारों को देने से, उन्हें असहयोगी बनाने से ऐसे पक्षकारों को रोका हो।
- xxvi. जीएचसीएल को एक प्रयोजन से घरेलू उद्योग से अलग किया गया है क्योंकि वह भारी लाभ कमाता है। जीएचसीएल से क्षति आंकड़ों की भी जांच की जानी चाहिए। किसी उत्पादक को शामिल करना अथवा हटाना प्राधिकारी के विवेक पर है।
- xxvii. सोडा ऐश के आयात अब पाटनरोधी शुल्क के अध्येधीन नहीं है क्योंकि शुल्क की तारीख 02 जुलाई, 2018 को निकल चुकी है।
- xxviii. फोरेक इंडिया लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी तथा अन्य में दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय ने माना है कि – (i) निर्णायक समीक्षा होने तक पाटनरोधी शुल्क एक वर्ष बढ़ाए जाने तथा निर्णायक समीक्षा के अनुसरण में लगाए गए पांच वर्ष के शुल्क के बीच का अंतराल गैर-कानूनी है; (ii) निर्णायक समीक्षा के अनुसरण में पाटनरोधी शुल्क का पांच वर्ष का विस्तार जो अंतराल के बाद लगाया जाता है, भी गैर-कानूनी है।
- xxix. पाटनरोधी शुल्क को पूर्व प्रभावी रूप से लगाए जाने से उपर्युक्त निर्णय गलत होगा और इस प्रकार गैर-कानूनी होगा।
- xxx. याचिकाकर्ताओं ने यह सिद्ध करने के लिए कोई ठोस अथवा पर्याप्त साक्ष्य नहीं दिया है कि शुल्क की समाप्ति से पाटित आयातों के कारण क्षति बार-बार होगी अथवा जारी रहेगी।
- xxxi. क्षति का बार-बार होना अथवा जारी रहना सिद्ध करने के लिए जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों का विश्लेषण करना व्यावहारिक है जो कि नहीं दिये गए हैं। इन आंकड़ों के अभाव में काफी बड़े हुए आयात की संभावना निर्धारित नहीं की जा सकती।

- xxxii. याचिकाकर्ताओं को हुई तथाकथित क्षति और संबद्ध आयातों के बीच कारणात्मक संपर्क नहीं है। यहां तक कि यदि लगातार पाटन हो रहा है तो भी निरंतर क्षति का अभाव है जिसका अर्थ है कि पाटन और क्षति के बीच अब कोई कारणात्मक संपर्क नहीं है।
- xxxiii. आईएचएस की रिपोर्ट का वर्ष स्पष्ट नहीं है और यदि यह वास्तव में आईएचएस रिपोर्ट है तो सत्यापनीय नहीं है।
- xxxiv. टर्की का याचिकाकर्ता का संदर्भ, जो कि एक संबद्ध देश नहीं है, अनावश्यक है। यह कथन तुर्की में अतिरिक्त क्षमता से तुर्की से यूरोपीय संघ को संबद्ध सामानों का बहिर्प्रभाव होगा जिससे भारत में प्रवाह होगा, यह केवल एक अनुमान है और विधिवत सिद्ध नहीं है।
- xxv. संबद्ध देशों की बढ़ती हुई क्षमताएं सिद्ध करने के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा कोई सत्यापनीय साक्ष्य नहीं दिया गया है। याचिका के अनुबंध-4.3 में दिया गया साक्ष्य भी सत्यापनीय नहीं है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

19. पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 में निम्नलिखित उल्लेख है:

"(1) अधिनियम की धारा 9 क के उपबंध के अंतर्गत लगाया गया कोई पाटनरोधी शुल्क क्षति पहुंचाने वाले पाटन को समाप्त करने के लिए उस अवधि तक और उस सीमा तक लागू रहेगा।

(1क) निर्दिष्ट प्राधिकारी जहां अपेक्षित हो, अपनी खुद की पहल पर या ऐसे किसी हितबद्ध पक्षकार के अनुरोध पर जो ऐसी समीक्षा की जरूरत की पुष्टि करते हुए सकारात्मक सूचना प्रस्तुत करता है और निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बाद उचित समयावधि बीत जाती है, किसी पाटनरोधी शुल्क को निरंतर लागू रखने की जरूरत की समीक्षा करेंगे और ऐसी समीक्षा के उपरांत निर्दिष्ट प्राधिकारी उस स्थिति में उसकी समाप्ति हेतु केन्द्र सरकार को सिफारिश करेंगे जहां वह इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यदि पाटनरोधी शुल्क समाप्त या परिवर्तित कर दिया जाता है तो घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना नहीं है और इसलिए अब इसकी जरूरत नहीं है।

(1 ख) उप नियम (1) या (1क) में किसी बात के होते हुए भी अधिनियम के अंतर्गत लगाया गया कोई निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क उसके लगाए जाने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगा बशर्ते निर्दिष्ट प्राधिकारी उक्त अवधि से पूर्व अपनी खुद की पहल पर या घरेलू उद्योग की ओर से किए गए विधिवत पुष्टिकृत अनुरोध के आधार पर उक्त अवधि समाप्त होने से पूर्व उचित अवधि के भीतर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उक्त शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

(2) उपनियम- (1) के अंतर्गत शुरू की गई कोई समीक्षा ऐसी समीक्षा की शुरुआत की तारीख से 12 माह से अनधिक अवधि के भीतर संपन्न की जाएगी।

(3) नियम 6, 7, 8, 9/10, 11, 16, 17, 18, 19 तथा 20 के उपबंध समीक्षा के मामले में आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

20. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा उठाए गए मुद्दों को रिकार्ड किया है और नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली का नियम 23 प्राधिकारी को पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने का दायित्व देता है।

21. प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित संगत मुद्दे उठाए हैं:

क. रिट याचिका (सी) संख्या 4886/2014 में दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय ने माना है कि निर्णायक समीक्षा के अनुसरण में पाटनरोधी शुल्क के पांच वर्ष के विस्तार और निर्णायक समीक्षा पूरी होने तक पाटनरोधी शुल्क के एक वर्ष के विस्तार के बीच कोई अंतराल नहीं होना चाहिए।

ख. उपर्युक्त निर्णय को एसएलपी (सी) सं. 15859-15861/2018 में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने 09 जुलाई, 2018 के आदेश द्वारा उपर्युक्त एसएलपी में नोटिस जारी किया, परंतु रिट याचिका 4886/2014 में दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय पर कोई स्थगन आदेश नहीं दिया।

- ग. गुजरात के माननीय उच्च न्यायालय ने 2017 के आर/विशेष सिविल आवेदन सं. 14204 में 2018 के विविध सिविल आवेदन संख्या 3 में 15 जून, 2018 के आदेश द्वारा 6 माह तक निर्णायक समीक्षा पूरी करने की समय-सीमा बढ़ाई।
- घ. संबद्ध सामानों पर पाटनरोधी शुल्क की तारीख 02 जुलाई, 2018 को समाप्त हो गई। हितबद्ध पक्षकार तर्क देते हैं कि प्राधिकारी इस निर्णायक समीक्षा के अनुसरण में पांच वर्षों के लिए पाटनरोधी शुल्क आगे बढ़ाने की सिफारिश करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। वे तर्क देते हैं कि पूर्व तारीख से कोई पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से रिट याचिका (सी) संख्या 4886/2014 में दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय गलत हो जाएगा।
- ङ. यदि पाटनरोधी शुल्क जारी रखा जाता है तो भारत में प्रयोक्ता उद्योग को क्षति होगी।
22. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि प्राधिकारी संबद्ध सामानों पर पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की कानूनी तौर पर सिफारिश नहीं कर सकते। यह देखा जाता है कि सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 और पाटनरोधी नियमावली के तहत पाटनरोधी शुल्क लगाने और न लगाने का अंतिम निर्णय केन्द्र सरकार के पास होता है। जहां तक प्रयोक्ता उद्योग के हित से संबंधित अनुरोध का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का प्रयोजन उचित व्यापारिक क्षेत्र सृजित करना है। यह प्रयोक्ता उद्योग के हित में है कि घरेलू उद्योग को उन पाटित आयातों से पर्याप्त संरक्षण दिया जाए जिनके कारण घरेलू उद्योग को क्षति होती है।
23. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों के पास प्रश्नावली का उत्तर देने और अनुरोध करके जांच में भाग लेने का पर्याप्त समय था।
24. पाटन, क्षति, कारणात्मक संपर्क और पाटन एवं क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना से संबंधित मुद्दों को उपयुक्त स्थानों पर अंतिम जांच परिणाम में हल किया जाएगा।

छ. पाटन मार्जिन का निर्धारण

बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी दावे, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन

याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए अनुरोध

- i. पाटन मार्जिन पिछले 10 वर्षों के लिए अलग-अलग आयात लेन-देनों पर विचार करके निर्धारित किया गया है।
- ii. यद्यपि, वर्तमान जांच की अवधि पाटन के जारी रहने को सिद्ध करने के लिए संगत है, तथापि, पाटन की संभावना सिद्ध करने के लिए ऐतिहासिक आंकड़े संगत हैं। यह अनुरोध किया गया है कि यदि जांच की अवधि स्वयं यह दर्शाती है कि पाटन जारी रहा तो वही पर्याप्त है। तथापि, यदि पाटन पूरे पिछले दशक में दर्शाया जा सकता है तो वह पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने पर जारी रहने की संभावना है।
- iii. वर्तमान जांच की अवधि के लिए भारित औसत पाटन मार्जिन पर विचार करने हेतु भारित औसत उपयुक्त पैमाना हो सकता है।
- iv. विभिन्न निर्यात लेन-देनों के माध्यम से दर्शाया गया अलग-अलग निर्यातकों का व्यवहार पाटन की संभावना सिद्ध करने के लिए जांच करने हेतु संगत उपयुक्त और आवश्यक है।
- v. यदि प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि भारित औसत पाटन मार्जिन न्यूनतम है तो फिर प्रत्येक आयात लेन-देन के लिए पाटन मार्जिन की पृथक रूप से जांच करने की आवश्यकता उत्पन्न होती है। पाटित कीमतों पर काफी निर्यातों के मामले में यह सिद्ध है कि पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में पाटित कीमतों पर निर्यात होने की संभावना है।
- vi. चीन जन. गण. के मामले में वर्तमान जांच की अवधि पर अनुच्छेद 15 लागू होगा क्योंकि जांच की अवधि का एक भाग दिसंबर, 2016 की अवधि के अंतर्गत है। चीन को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए। चीन में सामान्य मूल्य अनुबंध-1 के पैरा 7 के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।
- vii. चीन में सामान्य मूल्य भारत में देय कीमत के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए क्योंकि याचिकाकर्ता चीन में सामान्य मूल्य इस कारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में निर्मित मूल्य अथवा कीमत के आधार पर निर्धारित नहीं कर पाए कि संगत, पूर्ण और पूर्ण सत्यापनीय सूचना सार्वजनिक रूप से

उपलब्ध नहीं है तथा प्राप्त नहीं की जा सकती। सामान्य मूल्य घरेलू उद्योग की ही बिक्री कीमत के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है क्योंकि यह कीमत न्यूनीकृत नहीं है और भारत में देय कीमत है।

- viii. घरेलू उद्योग ने संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ के लिए कीमतें आईएचएस केमिकल ग्लोबल सोडा ऐश में सूचित कीमतों के अनुसार मानी हैं। चूंकि, पत्रिका उच्च और कम कीमतों का उल्लेख करती है, अतः घरेलू उद्योग ने औसत कीमत अपनाई है। सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन भी औसत कीमत को मानते हुए निर्धारित किए गए हैं।
- ix. पाकिस्तान के लिए सामान्य मूल्य आईसीआई पाकिस्तान लि., पाकिस्तान में एक सूचीबद्ध कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर परिकलित की गई है।
- x. केन्या के लिए सामान्य मूल्य टाटा केमिकल्स लि. के स्वामित्व वाली मेगाडी, केन्या ने संयंत्र के लिए वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए ब्यौरों के आधार पर निर्मित किया गया है।
- xi. ईरान के लिए सामान्य मूल्य मध्य-पूर्व/उत्तरी अफ्रीका के लिए आईएचएस केमिकल सोडा ऐश में प्रकाशित कीमतों के आधार पर उसे एक तुलनीय प्रतिनिधिकारक कीमत मानते हुए निर्धारित किया गया है।
- xii. निर्यात कीमत संबंधित संबद्ध देशों से सोडा ऐश की भारित औसत आयात कीमत के अनुसार निर्धारित की गई है। यह सीआईएफ स्तर पर परिकलित की गई है।
- xiii. निर्यात कीमत समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, पत्तन व्यय, कमीशन, अंतर्देशीय भाड़ा और अप्रत्यक्ष करों (चीन के मामले में केवल वैट अंतर) के लिए समायोजित की गई है जो कि व्यापार के उसी स्तर पर सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को रखने के लिए भारत को सामग्री का निर्यात करने हेतु निर्यातक द्वारा कर दी गई होती।
- xiv. निर्यात कीमत प्रस्तावित जांच की अवधि के लिए औसत विनिमय दर पर विचार करते हुए अमेरिकी डॉलर में निर्धारित की गई है।
- xv. इस उत्पाद के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत कारखानागत स्तर पर निर्धारित किया गया है जो उस अवधि से संबंधित है, और जिसमें बिक्री की शर्तों तथा शुल्क मुक्ति में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। इस प्रकार, की गई तुलना एक उचित तुलना है।
- xvi. पाटन मार्जिन न्यूनतम नहीं है परंतु काफी है।
- xvii. सभी निर्यातकों और विदेशी उत्पादकों को असहयोगी माना जाना चाहिए। उनमें से किसी ने भी वर्तमान मामले में प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है। प्राधिकारी को इस असहयोग को घरेलू उद्योग के मामले को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करने देना चाहिए। यह अनुरोध किया गया है कि प्राधिकारी को यह मानते हुए निर्यातकों के विरुद्ध प्रतिकूल भाव लेना चाहिए कि निर्यातकों ने असहयोग किया है।
- xviii. तीसरे देशों को निर्यातों के लेन-देन वार ब्यौरे निर्णायक समीक्षा के मामलों के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है और इसका उद्देश्य क्षति के बार-बार होने की जांच करने के लिए विश्लेषण करना है।
- xix. उपर्युक्त सूचना निर्णायक समीक्षा के चरण में सबसे अधिक एकमात्र महत्वपूर्ण सूचना है और विशेष रूप से उन मामलों में जहां विस्तार के लिए अनुरोध क्षति के बार-बार होने पर आधारित हो।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

- i. पाटन मार्जिन वर्तमान जांच में सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा दायर सूचना के आधार पर परिकलित किया जाना चाहिए।
- ii. पाटन मार्जिन जांच की अवधि के दौरान कुल निर्यातों के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए न कि चुनिंदा लेन-देनों के आधार पर।
- iii. भारित औसत आधार पर ही पाटन मार्जिन का निर्धारण कानूनी है।

- iv. घरेलू उद्योग ने अधिक पाटन मार्जिन दर्शाने के लिए बड़ा हुआ सामान्य मूल्य और कम की हुई निर्यात कीमत प्रस्तुत करने का प्रयास किया है जो आधारहीन है।
- v. सचिव (राजस्व), भारत सरकार बनाम डाइस्टप्स मैनुफैक्चर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का मामला यह पुष्ट करता है कि व्यापारिक पत्रिकाओं पर सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन सिद्धांत पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजन के लिए उपलब्ध तथ्यों के अनुसार विश्वास नहीं किया जा सकता।
- vi. याचिकाकर्ताओं ने सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए आईएचएस केमिकल पर विश्वास किया है जो कि एक व्यापारिक लेन-देन है। इस सामान्य मूल्य पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए।
- vii. पाकिस्तान और केन्या के लिए भी सामान्य मूल्य कंपनी की वार्षिक रिपोर्टों को देखकर निर्धारित किया गया है जो कि सही दृष्टिकोण नहीं है।
- viii. याचिकाकर्ताओं ने व्यापार के समान स्तर पर निर्यात कीमत और सामान्य मूल्य की तुलना करने के लिए समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, पत्तन व्यय, कमीशन, बैंक प्रभार, अंतर्देशीय भाड़ा, अप्रत्यक्ष करों के संबंध में किए गए समायोजनों के लिए कोई स्रोत नहीं दिया है।
- ix. इस संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है कि याचिका के प्रयोजन के लिए समायोजनों की गणना कैसे की गई है।
- x. याचिकाकर्ताओं द्वारा याचिका में प्रस्तुत आयात आंकड़ों पर भी प्रश्न उठाया जा सकता है। आयात आंकड़ों के लिए याचिकाकर्ता द्वारा बहु विध स्रोतों पर विश्वास किया गया है। मार्च, 2015 तक याचिका में सभी संबद्ध देशों के लिए डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों पर विश्वास किया गया है। अप्रैल, 2015 – मार्च, 2016 के लिए याचिका में चीन, यूरोपीय संघ, केन्या, ईरान, यूक्रेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए आयात आंकड़े हेतु दूसरे स्रोत आईबीआईएस पर विश्वास किया गया है, परंतु पाकिस्तान के लिए याचिका में डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों पर विश्वास किया गया है।
- xi. याचिका में आंकड़ों के स्रोतों की बहुविधता से एक विश्वास बनता है कि आंकड़ों को तोड़ा मरोड़ा गया है और इस मामले में गलत पाटन एवं क्षति विश्लेषण के परिणाम प्रस्तुत किए गए हैं।
- xii. उत्पादकों/निर्यातकों को समीक्षा एवं जांच से संबंधित गतिविधियों की जानकारी नहीं हो सकती है जिस वजह से ही वे इस समीक्षा में भाग नहीं ले पाए।
- xiii. प्राधिकारी इस चल रही समीक्षा के संबंध में संबद्ध देशों में उत्पादकों/निर्यातकों को सूचित करने पर विचार कर सकते हैं और उन्हें निर्देश दे सकते हैं कि वे अपनी रक्षा में संगत सूचना प्रस्तुत करें।
- xiv. तुर्की एक संबद्ध देश नहीं है और उसकी क्षमता संगत नहीं है।
- xv. घरेलू उद्योग ने अपने लिखित अनुरोधों में यूक्रेन के लिए सामान्य मूल्य हेतु कोई निर्धारण नहीं किया है और इसीलिए यूक्रेन से संबद्ध सामानों के आयातों से क्षति का दावा करने का कोई कानूनी आधार नहीं है।
- xvi. घरेलू उद्योग का यह दावा कि संबद्ध देशों में उत्पादक तीसरे देशों में पाटन कर रहे हैं, किसी साक्ष्य से विहीन है।
- xvii. घरेलू उद्योग की स्थिति में काफी सुधार हुआ है और उसे अब किसी संरक्षण की आवश्यकता नहीं है।
- xviii. यूक्रेन में सोडा ऐश का केवल एक उत्पादक पीजेएससी "क्रीमियन सोडा प्लांट" है जो कि रशियन फेडरेशन द्वारा क्रीमिया को अपने पास लेने के कारण यूक्रेन के नियंत्रण से बाहर है। उत्पादक के पास अब गैर-कानूनी रूसी पंजीकरण है। विश्व में भारत सहित यूक्रेनियन सोडा ऐश का कोई निर्यात नहीं है।
- xix. यूनाइटेड नेशन क्रेडिट डाटाबेस तथा स्टैटिस्टिक्स सर्विस ऑफ यूक्रेन का संदर्भ दिया गया है जो 2014 से आज की तारीख तक यूक्रेन से भारत को जांचाधीन उत्पाद का कोई निर्यात नहीं दर्शाता। यूक्रेन ने अन्य देशों को भी अपने उत्पाद का निर्यात रोक दिया था। सोडा ऐश के आयातों से संबंधित पाटनरोधी शुल्क निर्णायक समीक्षा जांच 16 जून, 2017 को शुरू की गई थी। दिनांक 22 जुलाई, 2017 को न्यायालय के निर्णय के बाद इसे रद्द कर दिया गया था।

प्राधिकारी द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था के दावों की जांच**चीन जन. गण.**

25. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8(3) में उल्लिखित मानदंडों के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की अवधारणा का खंडन करने के लिए चीन जन. गण. में सभी ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को एमईटी प्रभावली की प्रतियां भेजीं। प्राधिकारी ने भारत में संबंधित देशों के दूतावासों से यह भी अनुरोध किया कि वे अपने देश में उत्पादकों/निर्यातकों को सलाह दें कि वे अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराएं। यथासंशोधित पाटनरोधी नियमावली के पैरा 8, अनुबंध-1 के अनुसार, गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की अवधारणा का खंडन किया जा सकता है, यदि निर्यातक पैरा 8 में उप पैरा (3) में निर्धारित मानदंडों के आधार पर सूचना तथा पर्याप्त साक्ष्य दें और उसके विपरीत सिद्ध करें। तथापि, चीन जन. गण. में किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने सहयोग नहीं किया और वर्तमान समीक्षा में निर्यातक प्रभावली तथा एमईटी प्रभावली का उत्तर दायर नहीं किया। उपर्युक्त स्थिति के मद्देनजर और गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की अवधारणा के खंडन के अभाव में प्राधिकारी चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार कार्यवाही करना उपयुक्त मानते हैं।

ज. सामान्य मूल्य का निर्धारण

26. संबंधित संबद्ध देशों से उत्पादकों/निर्यातकों के संबंध में प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के अनुसार सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।

चीन जन. गण.

27. चाइनीज एसेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान है:

"जीएटीटी का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, 1994 ("पाटनरोधी समझौता") के अनुच्छेद-VI के कार्यान्वयन पर समझौता तथा एससीएम समझौता निम्नलिखित के अनुरूप डब्ल्यूटीओ सदस्यों में चीन मूल के आयातों वाली कार्यवाहियों पर लागू होंगे:

(क) जीएटीटी के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी समझौते के तहत मूल्य की तुलना का निर्धारण करने में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित के आधार पर चीन में घरेलू मूल्यों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है:

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

(ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।

- (ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सस्मिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।

आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

28. अनुच्छेद 15 का अर्थ है कि एक उप पैराग्राफ के उपबंध चीन के शामिल होने की तारीख से 15 वर्षों के बाद समाप्त हो जाएंगे। इस पैराग्राफ के उपबंध 11 दिसंबर, के पाटन चूँकि गए। हो समाप्त को 2016 घरेलू उद्योग को क्षति पहचाने का तथ्य जांच की अवधि के आधार पर सिद्ध हो गया है इसलिए जांच की अवधि के दौरान प्रचलित स्थिति ही संगत समुचित है और वर्तमान जांच के लिए आवश्यक है। वर्तमान समीक्षा के लिए जांच की अवधि (पीओआई) अप्रैल 2015 से मार्च 2016 है। चूंकि, अनुच्छेद 15 का उप पैराग्राफ जांच की अवधि के दौरान मौजूद था, प्राधिकारी ऐसी पद्धति का प्रयोग कर सकते हैं जो घरेलू कीमतों या चीन में लागत की कड़ी तुलना पर आधारित न हो यदि जांच के अधीन उत्पादक स्पष्ट रूप से यह नहीं दर्शाते हैं कि उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान उत्पाद का उत्पादन करने में उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं प्रचलित हैं।
29. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पिछले तीन वर्षों में चीन जन. गण. को भारत द्वारा और अन्य डब्ल्यूटीओ सदस्यों द्वारा पाटनरोधी जांचों में गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना गया है। चीन जन. गण. को पाटनरोधी नियमावली के अनुसार निर्यातक देशों अथवा उसके अलग-अलग निर्यातकों द्वारा अवधारणा के खंडन के अध्यधीन गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना गया है।
30. तथापि, चीन जन. गण. से किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने बाजार अर्थव्यवस्था प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है। उपर्युक्त स्थिति के मद्देनजर और किसी भी चीनी निर्यातक कंपनी द्वारा गैर-बाजार अर्थव्यवस्था अवधारणा के खंडन के अभाव में प्राधिकारी वर्तमान जांच में गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में चीन जन. गण. को मानना उपयुक्त समझते हैं और चीन जन. गण. के मामले में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार कार्यवाही करते हैं।
31. इसके अतिरिक्त, चीनी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा असहयोग के मद्देनजर प्राधिकारी सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करना उपयुक्त मानते हैं। पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 में यह प्रावधान है कि:

"गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य, मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं है, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयवधि प्रदान की जाएगी।"

32. तदनुसार, किसी भी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में संबद्ध सामानों के लिए किसी विश्वसनीय कीमत तथा लागत संबंधी ब्यौरों के अभाव में प्राधिकारी ने चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार निर्मित किया है। तदनुसार, चीन जन. गण. से निर्यातों के लिए सामान्य मूल्य संबद्ध सामानों के लिए निर्मित किया गया है और वह निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

यूरोपीय संघ (ईयू)

33. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यूरोपीय संघ से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है, अतः प्राधिकारी ने यूरोपीय संघ के संबंध में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार, सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना पर विश्वास किया है। यूरोपीय संघ के लिए इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित किया गया है।

संयुक्त राज्य अमेरिका

34. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है, अतः प्राधिकारी ने संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंध में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार, सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना पर विश्वास किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित किया गया है।

ईरान

35. प्राधिकारी नोट करते हैं कि ईरान से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है, अतः प्राधिकारी ने ईरान के संबंध में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार, सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना पर विश्वास किया है। ईरान के लिए इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित किया गया है।

पाकिस्तान

36. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाकिस्तान से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है, अतः प्राधिकारी ने पाकिस्तान के संबंध में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार, सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना पर विश्वास किया है। पाकिस्तान के लिए इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित किया गया है।

केन्या

37. प्राधिकारी नोट करते हैं कि केन्या से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है, अतः प्राधिकारी ने केन्या के संबंध में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार, सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना पर विश्वास किया है। केन्या के लिए इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित किया गया है।

यूक्रेन

38. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यूक्रेन से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है, अतः प्राधिकारी ने यूक्रेन के संबंध में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार, सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना पर विश्वास किया है। यूक्रेन के लिए इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित किया गया है।

झ. निर्यात कीमत**चीन जन. गण., यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान, केन्या और यूक्रेन**

39. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन. गण., यूक्रेन, यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान और केन्या से संबद्ध सामानों के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने प्राधिकारी को निर्धारित प्रपत्र में और किसी तरीके से उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। उपरोक्त देशों से उत्पादकों/निर्यातकों से निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर इन देशों के संबंध में निर्यात कीमत निर्धारित की है। प्राधिकारी ने जांच की अवधि के दौरान उपर्युक्त देशों से आयातों के भारित औसत सीआईएफ मूल्य निर्धारित करने के लिए डीजीसीआईएंडएस के आयात आंकड़ों पर विश्वास किया है। समुद्री भाड़ा, बीमा, कमीशन, पत्तन व्यय, अंतर्देशीय भाड़ा और बैंक प्रभार के कारण उपर्युक्त समायोजनों पर इन प्रत्येक देश के संबंध में निवल निर्यात कीमत निकालने के लिए विचार किया गया है। तदनुसार, चीन जन. गण., यूक्रेन, यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान और केन्या के सभी निर्यातकों के लिए कारखानागत

स्तर पर प्रस्तावित निर्यात कीमत निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में दिए गए अनुसार क्रमशः निर्धारित की गई है।

ब. पाटन मार्जिन

40. निर्धारित उपर्युक्त सामान्य मूल्य और निर्यात कीमतों की तुलना करने पर जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन निम्नलिखित हैं:

जांच की अवधि

देश	निर्यातक/ उत्पादक	सामान्य मूल्य अमेरिकी डॉलर/मी. टन	निवल निर्यात कीमत अमेरिकी डॉलर/ मी. टन	पाटन मार्जिनअमेरिकी डॉलर/ मी. टन	पाटन मार्जिन %	पाटन मार्जिन% रेंज
चीन जन. गण.	सभी	***	181.64	***	***	नकारात्मक
यूरोपीय संघ	सभी	***	183.08	***	***	नकारात्मक
केन्या	सभी	***	162.68	***	***	न्यूनतम
पाकिस्तान	सभी	***	212.01	***	***	नकारात्मक
ईरान	सभी	***	149.75	***	***	सकारात्मक
यूक्रेन	सभी	***	167.75	***	***	नकारात्मक
संयुक्त राज्य अमेरिका	सभी	***	150.11	***	***	सकारात्मक

ट. क्षति निर्धारण तथा क्षति की जांच और कारणात्मक संपर्क के लिए सिद्धांत

याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए अनुरोध

- घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार व्यापक रूप से लागू पाटनरोधी शुल्क के कारण है और पाटनरोधी शुल्क के बंद होने की स्थिति में क्षति की संभावना है।
- पिछले 10 वर्षों के लिए अलग-अलग आयात लेन-देनों पर विचार करके क्षति की संभावना निर्धारित करने के लिए विचार किया गया है।
- निवल बिक्री वसूली करें और शुल्कों, छूटों, रियायतों और कमीशनों को छोड़कर पूरी घरेलू बिक्री की मात्रा की बिक्री कीमत पर विचार करके निर्धारित की गई है। आयातों की पहुँच कीमत 1 प्रतिशत पहुँच प्रभार तथा लागू मूल सीमा शुल्क के साथ भारत औसत सीआईएफ आयात कीमत पर विचार करके निर्धारित की गई है। निवल बिक्री वसूली और आयातों की पहुँच कीमत की तुलना करने पर यह पाया गया कि कीमत कटौती पाटनरोधी शुल्क के बंद होने की स्थिति में काफी सकारात्मक है।
- घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत की तुलना आयातों की पहुँच कीमत से तभी की जानी चाहिए जब परिवहन लागतें जोड़ी जाएं क्योंकि संबद्ध सामानों के मामले में उनका उत्पादन लागत में काफी बड़ा भाग होता है।
- नियमों में इस सिद्धांत का कोई प्रावधान नहीं है कि प्राधिकारी को कैसे निर्धारित करना चाहिए, भले ही भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटन आयातों से काफी कीमत कटौती हो रही हो। यह अनुरोध किया गया है कि कीमत कटौती निर्धारित करने के लिए कोई निर्धारित सिद्धांत नहीं है।
- उपयुक्त तुलना के लिए घरेलू कीमत की तुलना व्यापार के समान स्तर पर आयात कीमत से की जाती है। समान उत्पाद की कीमत कारखानागत कीमत नहीं हो सकता जब उद्देश्य उसकी तुलना आयात कीमत से करने का हो। कीमत कटौती भाड़ा जोड़ने के बाद निर्धारित की जानी चाहिए। डब्ल्यूटीओ में भारत की स्थिति भी यह बताती है कि कीमतों की तुलना खपत के निकटतम बिन्दु पर की जानी चाहिए।

- vii. प्राधिकारी द्वारा दर्जनों मामलों में कीमत कटौती का उत्पाद किस्म-वार तथा माह अथवा तिमाही-वार निर्धारण अपनाना और बिक्री के बाद के व्यय के समायोजन – वारंटी, गारंटी, अनिवार्य स्पेयर पार्ट्स, भारतीय कार्यालय व्यय अपनाना स्पष्ट रूप से उचित तुलना के सिद्धांतों को स्वीकार करना तथा मानना सिद्ध करता है।
- viii. कीमत कटौती और क्षति मार्जिन का निर्धारण केवल उन लेन-देनों पर विचार करके किया जाना चाहिए जिनसे घरेलू उद्योग को कीमतों की क्षति हो रही थी अथवा कीमत कटौती हो रही थी। मेलाबेल कास्ट आयरन ट्यूब पर ईसी – पाटनरोधी शुल्क के मामले में डब्ल्यूटीओ की रिपोर्ट पर विश्वास किया जाता है जिसमें यह सिद्ध है कि:
- क. संबंधित उत्पाद और समान उत्पाद को शामिल करके प्रत्येक लेन-देन की जांच के आधार पर केवल एक कटौती मार्जिन सिद्ध करने की अनुच्छेद 3.2 के तहत कोई आवश्यकता नहीं है।
- ख. एक अपेक्षा कि किसी जांचकर्ता प्राधिकारी को उस सिद्धांत पर कीमत कटौती विश्लेषण का आधार बनाना चाहिए जिसमें अधिक कीमतों के साथ कीमत कटौती वाली कीमतों का परिणाम जांचकर्ता प्राधिकारी के लिए यह निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता बनाए कि कोई कीमत कटौती मौजूद नहीं थी जब वस्तुतः पर्याप्त संख्या में बिक्री कीमत कटौती पर हो सकती है जिससे घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।
- ग. घरेलू उद्योग पर किस सीमा तक कीमत कटौती का प्रभाव हुआ होता, दो परिवर्तकों का कार्य होगा – (i) कटौती की कीमतों पर बिक्री की संख्या और, (ii) ऐसी बिक्रियों की कीमत कटौती की मात्रा। पहले वाला विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह घरेलू उद्योग द्वारा खोई बिक्रियों की संभावित संख्या का संकेतक प्रदान करता है।
- घ. सभी बिक्रियों के लिए कीमत कटौती के औसत मार्जिन का परिकलन, भले ही वे कीमत कटौती पर हों या न हों। घरेलू उद्योग पर कीमत कटौती के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका नहीं हो सकता क्योंकि उसने इन दो परिवर्तकों की जांच करने के लिए स्वतंत्र रूप से जांचकर्ता प्राधिकारी की क्षमता सीमित की।
- ix. भारत में भारित औसत निर्यात कीमतें यह निर्धारित करने के लिए पूर्णतः अपर्याप्त हैं कि क्या घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है।
- x. क्षति रहित कीमत और क्षति मार्जिन निर्णायक समीक्षा मामले में निर्धारित किए जाने की आवश्यकता नहीं है जहां विस्तार का अनुरोध घरेलू उद्योग को क्षति के बार-बार होने की संभावना पर आधारित हो। इनका निर्धारण विभिन्न निर्यात लेन-देनों में निर्यातकों के व्यवहार की जांच करने के लिए किया जा सकता है। इस प्रयोजन के लिए प्राधिकारी को केवल यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि क्या एनआईपी से कम कीमत पर अथवा अधिक कीमत पर विशेष निर्यात लेन-देन हुए हैं।
- xi. निर्णायक समीक्षा मामले में नियम 11 विस्तारित नहीं होता तथा प्राधिकारी को केवल क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना की ही जांच करने की आवश्यकता होती है।
- xii. वर्तमान मामले पर "जैसा है आधार पर" अनुबंध-II लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि ये नियम अधिनियम और डब्ल्यूटीओ एडीए के अनुरूप नहीं हैं। ये नियम इस तथ्य के "आवश्यक संशोधनों के बाद" लगाए जाने चाहिए कि ये नियम उस मामले में लागू किए जा रहे हैं जहां पाटनरोधी शुल्क लागू है और जहां याचिका घरेलू उद्योग को क्षति के बार-बार होने की संभावना के आधार पर पाटनरोधी शुल्क बढ़ाए जाने के लिए है।
- xiii. यह अनुरोध है कि निम्नलिखित रूप में कानूनी प्रावधान लागू किए जाने चाहिए:
- क. घरेलू उद्योग को वर्तमान क्षति के घटक को संभावित भावी क्षति में लाया जाना चाहिए।
- ख. आयातों का प्रभाव निर्धारित किया जाना चाहिए; और
- ग. तीसरे देशों से पाटित आयातों की वृद्धि की महत्वपूर्ण दर पर भी विचार किया जाना चाहिए।
- xiv. संभावना निर्धारित करने के लिए विभिन्न देशों द्वारा अपनाए गए मानदंडों की सूची प्रस्तुत की गई है और वे सब प्रकृति में भिन्न हैं। अतः यह अनुरोध है कि नियमावली में सूचीबद्ध मानदंड "ऊपरी सीमा" अथवा "सख्त निर्धारण" के रूप में कठोरता से लागू नहीं किए जा सकते और केवल संकेतात्मक हैं।

- xv. विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग पूरी क्षति की अवधि में बढ़ी है, चाहे वह कैप्टिव खपत को शामिल करके हो या नहीं।
- xvi. आयातों का भारतीय बाजार में काफी मात्रा में स्थान है और पूरी क्षति अवधि में काफी बढ़े हैं। आयातों ने तब काफी वृद्धि दर्शानी शुरू की जब पाटनरोधी शुल्क वर्तमान अधिसूचना के अनुसार जुलाई, 2018 में बंद हो गए।
- xvii. देश में उत्पादन और खपत के संबंध में आयात 2013-14 के स्तरों की तुलना में 2014-15 में बढ़े। इसमें 2015-16 में गिरावट आई, परंतु दोबारा जांच की अवधि में वृद्धि हुई। मौजूदा पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद क्षति जांच अवधि में उत्पादन और खपत के संबंध में आयातों में वृद्धि हुई है।
- xviii. पाटित आयातों की पहुँच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों से काफी कम है और वह पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में संबद्ध देशों से कीमत कटौती के उच्च स्तर दर्शाता है।
- xix. उत्पादन, बिक्री कीमत और आयातों की पहुँच कीमत की तुलना यह दर्शाती है कि यद्यपि घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत और बिक्री कीमत ने सकारात्मक प्रवृत्ति दर्शाई है और आयातों से लागू पाटनरोधी शुल्क से कोई कीमत ह्रास अथवा न्यूनीकरण प्रभाव नहीं हो रहा था, तथापि, यदि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाते हैं, तो बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटन का काफी न्यूनीकरण प्रभाव पड़ेगा।
- xx. 2012 में पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद घरेलू उद्योग में धीरे-धीरे सुधार हुआ और शीघ्र ही बाजार क्षमता विकास में निवेश करने के लिए अर्थक्षम हो गया तथा उसने बाजार विस्तार की योजना बनाई। पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद *** लाख मी. टन तक की नई क्षमता शुरू की गई है। साथ ही, *** लाख मी. टन की क्षमता की योजना बनाई जा रही है। मैसर्स घड़ी ने *** करोड़ रुपये के निवेश पर *** लाख मी. टन की उत्पादन क्षमता का एक नया ग्रीन फील्ड प्लांट शुरू किया है। इन नए निवेशों की अर्थक्षमता दांव पर है।
- xxi. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता कुल मिलाकर सुधरी है, परंतु उसमें जांच की अवधि में गिरावट आई है। नियोजित पूंजी पर आय तथा नकद प्रवाह क्षति की अवधि में बढ़े हैं तथा कीमत मानदंड में पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के कारण सुधार दर्शाया है। पाटनरोधी शुल्क बंद करने से घरेलू उद्योग पर कीमत प्रभाव बनेगा और इससे घरेलू उद्योग के इन मानदंडों में गिरावट आएगी।
- xxii. विचाराधीन उत्पाद की मांग पर्याप्त दर पर बढ़ रही है जिससे आगे क्षमताओं का विस्तार करने के लिए औचित्य बनता है। पहले उल्लेख किए गए अनुसार क्षमता के विस्तार के लिए भारी राशि के निवेश की आवश्यकता होती है जो दांव पर है।
- xxiii. विचाराधीन उत्पाद की घरेलू मांग में संबद्ध देशों का बाजार हिस्सा बढ़ा है जबकि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में क्षति की अवधि में गिरावट आई है। संबद्ध देशों से आयात यदि लागू पाटनरोधी शुल्क बढ़ाया नहीं जाता है तो भारत में और अधिक बाजार पकड़ लेंगे।
- xxiv. घरेलू उद्योग में मालसूची क्षति की अवधि में बढ़ी है।
- xxv. मजदूरी, उत्पादकता और रोजगार स्तर क्षति के अवधि में बढ़े हैं।
- xxvi. विभिन्न मानदंडों के संदर्भ में याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग की वृद्धि सकारात्मक थी।
- xxvii. घरेलू उद्योग ने निरंतर क्षति का दावा नहीं किया है।
- xxviii. घरेलू उद्योग के निष्पादन में दृश्यमान वृद्धि केवल पाटनरोधी शुल्क के उपचारात्मक प्रभावों का परिणाम है।
- xxix. यद्यपि, कुल निष्पादन स्तर वास्तविक क्षति नहीं दर्शाते, तथापि, घरेलू उद्योग की स्थिति स्पष्ट रूप से टूटने की है जो कि जांच की अवधि के बाद लाभ में गिरावट से सिद्ध है।
- xxx. जांच की अवधि के बाद निष्पादन में और अधिक गिरावट आई है।
- xxxi. यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है कि निचले उद्योगों को तथाकथित उच्च कीमतों के कारण गैर-प्रतिस्पर्द्धी रख दिया गया है।

- xxxii. उपभोक्ताओं के निष्पादन में पाटनरोधी शुल्क की अवधि के दौरान ह्रास के बावजूद सुधार हुआ है, जैसा कि एचयूएल द्वारा प्राप्त लाभों से सिद्ध है।
- xxxiii. डिटर्जेंट मैनुफैक्चर्स जो संबद्ध सामानों के प्रमुख प्रयोक्ता हैं, ने लागतों से कहीं अधिक अपनी बिक्री कीमत बढ़ा दी है। अतः निचले उद्योगों का गैर-प्रतिस्पर्द्धी होने का दावा आधारहीन है।
- xxxiv. घरेलू उद्योग के निष्पादन में पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी के कारण व्यापक रूप से सुधार हुआ है।
- xxxv. यह कहने का कोई आधार नहीं है कि उचित मांग एवं आपूर्ति संतुलन है। विश्व में मांग एवं आपूर्ति का स्पष्ट अंतराल है।
- xxxi. पाटन के जारी रहने/बार-बार होने की अत्यधिक संभावना का खंडन करने के लिए हितवद्ध पक्षकारों द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- xxxvii. भारत को काफी पाटित कीमतों पर काफी आयात किए जा रहे हैं।
- xxxviii. तुर्की प्रत्येक देश के लिए एक खतरा बन रहा है और भारतीय बाजार भी और अधिक सुभेद्य बन गया है।
- xxxix. पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी से घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन और बिक्री में वृद्धि हुई है।
- xl. आयात मात्रा 2013-14 से 2014-15 तक काफी बढ़ी और उसने 2014-15 में लिए गए स्तरों को वापस बढ़ाने के लिए ही 2015-16 में गिरावट दर्शाई।
- xli. पूरी क्षति अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी के बावजूद आयात मात्रा ने अपवादात्मक वृद्धि दर्शाई है।
- xlii. आयातों ने जुलाई, 2018 से काफी वृद्धि दर्शाना पहले ही शुरू कर दिया है।
- xliii. जुलाई, 2018 से सितंबर, 2018 तक के महीनों में आयात स्वयं ही 37 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हैं।
- xliv. आयातों की मात्रा पिछले माह की तुलना में 796 प्रतिशत तक बढ़ी है।
- xlvi. निवेश पर अत्यधिक आय इस तथ्य के कारण है कि प्राधिकारी घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेशों, जो व्यापक रूप से मूल्यह्रास पर हैं, पर विचार करके नियोजित पूंजी पर आय निर्धारित कर रहे हैं।
- xlvii. निवेश पर आय का निर्धारण जांचों के निवल वर्तमान मूल्य पर विचार करके निर्धारित किया जाना चाहिए न कि निवेश के निवल मूल्यह्रास, बुक मूल्य पर। यह पूर्णतः अनुचित है और यहां तक कि घरेलू उद्योग के लिए भी अनुचित है कि निवेश पर आय निवेशों के मूल्यह्रास मूल्य विचार करके निर्धारित की जाती है।
- xlviii. कीमतों के वर्तमान स्तर पर नए निवेशों की निवेश पर आय केवल 14 प्रतिशत होगी। यह अच्छी आय नहीं है।
- xlviii. घरेलू उद्योग की मालसूची भी इस अवधि में लगभग दोगुनी हुई है। संबद्ध देशों का बाजार हिस्सा, जैसा कि पाटनरोधी शुल्क लगने वाले देशों में अतिरिक्त क्षमताएं प्रभावी हो गईं, वृद्धिकारक प्रवृत्ति दर्शाता है जबकि घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा लगभग वही रहा। अन्य भारतीय उत्पादकों के बाजार हिस्से में इस अवधि में गिरावट आई।
- xlix. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग द्वारा किए गए नए निवेशों के लिए उपयुक्त रूप से अर्थक्षम होने हेतु न्यूनतम उपयुक्त आय की आवश्यकता होती है। क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित औसत आय काफी कम थी। इस दर पर निवेश की लागत परिसंपत्तियों के जीवन काल के बाद ही वसूल की जाएगी।
- i. आयातों से लागू पाटनरोधी शुल्क से कोई न्यूनीकरण अथवा ह्रासमान प्रभाव नहीं हो रहा था। यदि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क बंद हो जाते हैं तो पाटन से बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर काफी न्यूनीकरण प्रभाव पड़ेगा। कीमत ह्रासमान/ न्यूनीकरण की संभावना की जांच की जानी चाहिए न कि खुद कीमत न्यूनीकरण/ ह्रासमान की।
- ii. बढ़ी हुई पूंजी पर आय और लाभप्रदता संबद्ध देशों द्वारा पाटित किए जाने वाले उत्पादों के लिए आधार नहीं हो सकते।

- lii. अर्जित किए जा रहे लाभ पुनः क्षमता निर्माण में निवेश किए जा रहे हैं।
- liii. शुल्कों को बंद करने के संभावित प्रभाव की जांच करने के लिए विश्लेषण किया गया है और वह स्पष्ट रूप से सिद्ध करता है कि इस अवधि में सामान्य मूल्य, बिक्री कीमत और घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से कम कीमतों पर काफी निर्यात किए गए।
- liv. यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य सामने नहीं लाया गया है कि सीमा शुल्क प्राधिकारी पाटनरोधी शुल्क एकत्रित किए बिना सामानों की संजूरी दे रहे हैं। विगत में ऐसे कई मामले हैं जिनमें निर्णायक समीक्षा जांच परिणाम 18 माह पूरे होने के बाद जारी किए गए थे। अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाया गया यह तर्क इन सभी जांच परिणामों और शुल्कों को गैर-कानूनी बना देता है। उच्च न्यायालय के दिनांक 15.06.2018 के निर्णय और आदेश के अनुसार जांच की जा रही है। याचिकाकर्ता पूर्व तारीख से शुल्क की मांग नहीं कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती दी जा रही है और स्थगन के लिए आवेदन पत्र भी इस आदेश के विरुद्ध दायर कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने आज की तारीख तक पाटनरोधी शुल्क समाप्त नहीं किया है।
- lv. मूल जांच के बाद की गई एक जांच ही यथातथ्यतः है। एमटीआर जांच परिणाम क्षति की संभावना के पर्याप्त विश्लेषण पर आधारित नहीं थे।
- lvi. उत्तरदाता निर्यातकों को यह भी दर्शाना चाहिए कि निरंतर पाटन नहीं होगा अथवा उसके जारी रहने की संभावना नहीं है।
- lvii. प्राधिकारी ने निर्णायक समीक्षा प्रश्नावली भाग-II निर्धारित की है जिसमें निर्यातक से उसकी क्षमताओं, क्षमता विस्तार, लेन-देन वार तीसरे देश को निर्यात, घरेलू बिक्री आदि के संबंध में सूचना पाटन और क्षति के बार-बार होने की संभावना की जांच के लिए मांगी जाती है।
- lviii. उत्तरदाता पक्षकारों ने अन्यथा सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।
- lix. घरेलू उद्योग ने संबद्ध देशों से आयात मात्रा के संबंध में ब्यौरे दायर किए हैं। दायर किए गए आंकड़े केवल क्षति जांच अवधि से संबंधित ही नहीं हैं बल्कि 2006-07 से 2018-19 तक आयात मात्रा का विश्लेषण भी हैं।
- lx. आयातों में आयात कीमत में गिरावट के साथ जांच की अवधि के बाद में काफी उछाल आया है।
- lxi. क्षतिकारक लेन-देन काफी बढ़े हैं और कुल मात्रा का 90 प्रतिशत के आसपास दर्शाते हैं।
- lxii. अन्य विस्तृत और ठोस साक्ष्य घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए हैं।
- lxiii. वर्तमान में आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती हो रही है। आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती होने की उस समय भी संभावना है जब शुल्क लागू न हों।
- lxiv. पाटित एवं क्षतिकारक कीमत पर अन्य देशों को संबद्ध देशों द्वारा निर्यात के संदर्भ में भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता सिद्ध करने वाले सभी आवश्यक साक्ष्य विस्तार से दिए गए हैं।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

- i. याचिकाकर्ताओं को निरंतर क्षति नहीं हुई है और घरेलू उद्योग के निष्पादन में लागू पाटनरोधी शुल्क के कारण वर्तमान अवधि में सुधार हुआ है।
- ii. प्राधिकारी ने इस तथ्य को उचित महत्व दिया है कि घरेलू उद्योग ने काफी वृद्धि की है और अच्छा निष्पादन किया है तथा पाटनरोधी शुल्क से उसका अपेक्षित प्रयोजन सिद्ध हुआ है।
- iii. याचिकाकर्ता भारत में घरेलू उत्पादों के लिए उचित बाजार स्थिति प्रदान करने/ बनाए रखने के अपेक्षित उद्देश्य को प्राप्त करते हुए पाटनरोधी शुल्क के कारण उचित बाजार में अच्छा निष्पादन करने में सक्षम रहे हैं।
- iv. यह विचार करते हुए कि निरंतर कोई क्षति नहीं है और याचिकाकर्ताओं का निष्पादन संतोषजनक है, क्षति के बार-बार होने की कोई संभावना नहीं है।

- v. पाटन/क्षति के बार-बार होने की संभावना के किसी रूप को निर्धारित करते समय जांच की अवधि और जांच की अवधि के बाद की अवधि सहित क्षति की अवधि को छोड़कर किसी अन्य आंकड़े पर विचार करने का कोई कानूनी दायित्व नहीं है।
- vi. याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया है कि बिक्री कीमत की तुलना परिवहन लागतों को जोड़ने के बाद पहुँच कीमत से की जानी चाहिए। एचयूएल ने अनुरोध किया है कि यह दावा त्रुटिपूर्ण है और कारखानागत स्तर पर बिक्री कीमत और पहुँच कीमत की तुलना करने की प्राधिकारी की परिपाटी के विपरीत है।
- vii. एनआईपी पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III उल्लिखित सिद्धांतों के आधार पर निर्धारित की जाती है।
- viii. प्राधिकारी ने नियोजित पूंजी पर आय की दर 22 प्रतिशत दी है।
- ix. एनआईपी का परिकलन भी कारखानागत स्तर अर्थात् कारखाने के बाद के खर्चों के प्रभाव दिए बिना किया जाता है क्योंकि पहुँच कीमत आयात के स्थान पर मानी जाती है। निवल बिक्री वसूली भी इसी सिद्धांत को अपनाती है। याचिकाकर्ता के लिए यह गैर-तर्कसंगत है कि वे स्थापित सिद्धांत में विचलन की मांग करें। इसका उचित तुलना पहलू इस तथ्य में निहित है कि दोनों कीमतों का परिकलन दोनों कीमतों से आवश्यक समायोजन करने के बाद किया जाता है।
- x. याचिकाकर्ताओं द्वारा मांग की गई कीमत कटौती के विषयपरक सिद्धांत इस तथ्य के आलोक में मान्य नहीं है कि एक निर्धारित पूर्वोदाहरण होना चाहिए जिसमें ऐसी जांच में भावी भागीदार विश्वास कर सकें और अपने अनुरोध तैयार कर सकें।
- xi. जब तक दोनों कीमतों में समायोजन करने के बाद कीमतों की तुलना की जाती है, निर्धारण में जोड़ी जा रही भाड़े और अन्य परिवहन लागतों पर विचार करने के लिए विषयपरक सिद्धांत की कोई आवश्यकता नहीं है।
- xii. भाड़ा और परिवहन लागतों को शामिल करने के बाद कम कीमत पर बिक्री का मूल्यांकन करने के अनुरोध याचिकाकर्ताओं द्वारा अपने लाभ के लिए कम कीमत पर बिक्री के निर्धारण को भ्रमित करना है न कि उचित और समानता के हित में।
- xiii. परिवहन लागतों के संबंध में डब्ल्यूटीओ प्रस्ताव केवल एक प्रस्ताव है और डब्ल्यूटीओ में उसे कानून में स्वीकार नहीं किया गया है। प्रस्ताव में भाड़ा/ परिवहन लागतों को शामिल करना नहीं दर्शाया गया है। यह व्यापार के समान स्तर पर कीमतों की तुलना करने की आवश्यकता की पुष्टि करता है और किसी परिवर्तन विशेष की मांग नहीं करता।
- xiv. कीमत कटौती निर्धारित करने के लिए लेन-देन आधारित दृष्टिकोण शून्यकरण के समान है जिसे अनुपयुक्त माना गया है तथा पाटनरोधी करार के उल्लंघन में माना गया है।
- xv. यद्यपि, संभावना के मापदंड पाटनरोधी नियामवली में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं हैं, तथापि, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (vii) में संभावना के लिए कारकों संबंधी शासी प्रावधान के रूप में निर्वचन किया गया है।
- xvi. विगत में प्राधिकारी द्वारा विश्लेषण किए गए मानदंड हैं: (क) बढ़े हुए आयात की संभावना दर्शाने वाले संबद्ध आयातों की वृद्धि, (ख) संबद्ध देश में अतिरिक्त क्षमताएं दर्शाने वाले साक्ष्य जो यदि शुल्क समाप्त किए जाते हैं, भारत को भेजे जाने की संभावना है, (ग) वह साक्ष्य जो न्यूनीकरण/ह्रासमान प्रभाव की मौजूदगी सिद्ध करे, (घ) जांच की जा रही वस्तु की मालसूची संबंधी साक्ष्य, (ङ) पूर्व जांच में पाटन मार्जिन, (च) भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता, (छ) उत्पाद एवं भारतीय बाजार की कीमत संवेदनशीलता के संदर्भ में घरेलू उद्योग की सुभेद्यता।
- xvii. यह सिद्ध करने के लिए कि क्या पाटन आयातों में वृद्धि हुई है, जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों का विश्लेषण करना व्यावहारिक है जो याचिकाकर्ता ने नहीं दिए हैं। जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों के बिना काफी बढ़े आयात की संभावना निर्धारित नहीं की जा सकती। याचिकाकर्ताओं ने पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में कीमत कटौती की संभावना का कोई साक्ष्य नहीं दिया है।
- xviii. पाटनरोधी शुल्क का प्रयोजन घरेलू उद्योग के निवेशों/संभावित निवेशों की रक्षा करना नहीं है।

- xix. घरेलू उद्योग एक पर्याप्त स्तर पर निष्पादन कर रहा है और संबद्ध आयातों से बिल्कुल भी उनके निष्पादन में प्रभाव नहीं पड़ रहा है।
- xx. यदि याचिकाकर्ताओं को संबद्ध आयातों के कारण तथाकथित क्षति हो रही थी, तो याचिकाकर्ताओं को उनके बाजार हिस्से में गिरावट का अनुभव होना चाहिए था और संबद्ध देशों के लिए बाजार हिस्से में समान वृद्धि होनी चाहिए थी। तथापि, वर्तमान वास्तविक मैट्रिक्स में यह स्थिति नहीं है।
- xxi. याचिकाकर्ताओं का बाजार हिस्सा जांच की अवधि में बढ़ा है जबकि आयातों का बाजार हिस्सा वही रहा है।
- xxii. यह दावा कि घरेलू उद्योग में मालसूची क्षति की अवधि में बढ़ी है, याचिका में उनके द्वारा दिए गए आंकड़ों से असंगत है क्योंकि उनकी बिक्री की मात्रा पूरी क्षति की अवधि तथा जांच की अवधि में काफी बढ़ती रही है।
- xxiii. याचिकाकर्ता पूरी क्षति की अवधि में मजदूरी, उत्पादकता और रोजगार काफी बढ़ाने के लिए अच्छा निष्पादन करने में सक्षम रहे हैं।
- xxiv. पाटन मार्जिन सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के आधार पर होना चाहिए, जैसा कि संबद्ध देशों से भागीदार निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा दिया गया है।
- xxv. सकारात्मक आर्थिक मानदंड क्षति के बार-बार होने की कमी निर्धारित करने के लिए पर्याप्त होने चाहिए और इसलिए वर्तमान जांच रद्द की जानी चाहिए।
- xxvi. घरेलू उद्योग को निरंतर कोई क्षति नहीं हुई है। घरेलू उद्योग का निष्पादन सभी मानदंडों पर असाधारण रहा है और यह उत्कृष्ट निष्पादन स्पष्ट रूप से दर्शाता है। वर्तमान शुल्कों की समाप्ति से बार-बार कोई क्षति नहीं होगी।
- xxvii. आयातों में निरंतर कोई वृद्धि नहीं थी और आयातों में संचलन को देश में उत्पाद के लिए मांग आपूर्ति की स्थिति से जोड़ा जा सकता है।
- xxviii. भारतीय उत्पादकों का समग्र रूप से बाजार हिस्से में 80 प्रतिशत हिस्सा रहा है जो कि एक काफी बाजार हिस्सा है।
- xxix. याचिकाकर्ता आयातों पर प्रतिबंध लगाकर उचित प्रतिस्पर्द्धा को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं।
- xxx. घरेलू उद्योग को कोई मात्रात्मक अथवा कीमत संबंधी क्षति नहीं हुई है। उनके पूर्ण बिक्री के आंकड़े और उत्पादन काफी बढ़े हैं। जांच की अवधि में बढ़ी हुई क्षमता के बावजूद क्षमता उपयोग भी बढ़ा है।
- xxxi. कीमत के स्तर पर भी कोई क्षति नहीं हुई है क्योंकि आयातों से वे कीमतें घटाने के लिए मजबूर नहीं हुए हैं। घरेलू उद्योग बिक्री की लागत में वृद्धि की तुलना में काफी अधिक कीमत बढ़ाते रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप उनके लाभ में काफी वृद्धि हुई है।
- xxxii. घरेलू उद्योग द्वारा प्राप्त कीमत वृद्धि स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि वर्तमान मामले में कोई कीमत न्यूनीकरण/ह्रासमान प्रभाव नहीं है।
- xxxiii. घरेलू उद्योग अपनी मजदूरी बढ़ा पाया है और प्रत्येक मानदंड वृद्धि की दृष्टि से भी काफी सकारात्मक था।
- xxxiv. संबद्ध देशों से आयात कीमत में आधार वर्ष में जांच की अवधि लगभग 6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई। घरेलू उद्योग का एनएसआर भी इस अवधि में लगभग 7 प्रतिशत तक बढ़ा, परंतु लागत लगभग 70 प्रतिशत तक कम की गई थी। घरेलू उद्योग अपनी कीमतें काफी बढ़ाने में सक्षम रहा जो आयातों से कोई कीमत प्रभाव तथा घरेलू उद्योग का कीमत व्यवहार नहीं दर्शाता।
- xxxv. यह तथ्य कि जब कीमत में काफी कमी थी, तो आयात कीमतें बढ़ीं, यह दर्शाता है कि निर्यातकों ने भी उत्पाद के लिए उच्चतर कीमत की ओर देखा और आयात कीमतों में भारत में लागत में कमी के अनुरूप कोई कमी नहीं थी। यदि निर्यातक अधिक निर्यात करने के लिए दबाव में थे, तो उन्होंने कीमतें कम की होतीं।
- xxxvi. घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत और बिक्री कीमत की तुलना यह दर्शाती है कि घरेलू उद्योग ने अपने निवेश पर आय अर्जित की है जो प्राधिकारी द्वारा अनुमत 22 प्रतिशत से कहीं अधिक है।

- xxxvii. घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत और आयातों की पहुँच कीमत की तुलना यह दर्शाती है कि घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान आयातों की पहुँच कीमत के बराबर अपने सामानों की बिक्री की।
- xxxviii. घरेलू उद्योग को अब कई वर्षों से क्षति नहीं हो रही है और यह निष्पादन बताता है कि वर्तमान शुल्क समाप्त किए जाने पर क्षति बार-बार होने की संभावना नहीं है। यह शुल्क चिरस्थायी नहीं हो सकता।
- xxxix. घरेलू उद्योग ने याचिका के समय अधिक मात्रा सूचित की।
- xl. घरेलू उद्योग ने अपनी कीमतें काफी बढ़ाई, नियोजित पूंजी पर काफी अधिक आय अर्जित की और किसी भी क्षति मानदंड पर उसको कोई क्षति नहीं हुई। यदि उन पर कीमत कटौती के कुछ प्रभाव पड़ते तो यह प्राप्त नहीं किया जा सकता था।
- xli. अनुबंध-III पहुँच कीमत के परिकलन में बाहरी भाड़े को शामिल करने से संबंधित है। यह तर्क कि उनका मामले उचित प्रतिस्पर्द्धा के संबंध में है जो कि अनुबंध-III के अनुसार भाड़े के व्यवहार से भिन्न है, सारहीन है। घरेलू उद्योग का प्रयास क्षति की बड़ी हुई तस्वीर दर्शाना मात्र है।
- xlii. उत्पाद की जांच की अवधि के दौरान लगभग 3262577 मी. टन की मांग है। घरेलू उद्योग द्वारा लिखित अनुरोध लगभग 155781 मी. टन दर्शाता है जो कुल मांग के 5 प्रतिशत से कम है, जो कि क्षति के स्तर पर आयात किया गया है, यदि पाटनरोधी शुल्क के बिना देखा जाए। यह स्तर नगण्य है और इससे घरेलू उद्योग के निष्पादन पर काफी प्रभाव नहीं पड़ सकता।
- xliii. क्षति मार्जिन और कीमत कटौती जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से कुल आयातों के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए न कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित चुनिंदा लेन-देनों के आधार पर। यह शून्यकरण बनता है जो कि डब्ल्यूटीओ द्वारा प्रतिबंधित है।
- xliv. घरेलू उद्योग के लिखित अनुरोध के भाग के रूप में और याचिका में दिए गए आंकड़े समान नहीं हैं। सही आयात आंकड़ों के अभाव में इन मानदंडों पर विचार-विमर्श असंगत है।
- xlv. आयात बहुत ही न्यूनतम हैं। भारतीय उत्पादकों द्वारा लिया गया बाजार हिस्सा लगभग 80 प्रतिशत है।
- xlvi. आयातों में केवल क्षति रहित कीमत पर मांग आपूर्ति अंतराल शामिल किया जा रहा है।
- xlvii. घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हो रही है और वह क्षमता बढ़ाने की स्थिति में भी रहा है।
- xlviii. निष्पादन अपने उच्च मानक के कारण पूर्णतः आयातों के लिए सुभेद्य नहीं है।
- xlix. आयातों के निष्पादन में प्रतिमान परिवर्तन यह दर्शाता है कि पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- i. भावी निवेश पाटनरोधी शुल्क द्वारा किसी संरक्षण के क्षेत्र से बाहर हैं तथा पाटनरोधी शुल्क जारी रखना इन आधारों पर औचित्यपूर्ण नहीं कहा जा सकता।
- ii. घरेलू उद्योग शुल्क की समाप्ति की स्थिति में पाटन और क्षति के बार-बार होने की संभावना से संबंधित होने का ही दावा करता है।
- iii. घरेलू उद्योग में काफी सुधार हुआ है और इस तरीके से कि वे *** लाख टन की वार्षिक क्षमता में निवेश कर अपनी वार्षिक क्षमताएं बढ़ाने के लिए उत्साहित हैं।
- liii. संबद्ध सामानों के लिए कुल मांग क्षति की अवधि के दौरान बढ़ी। कुल मांग (कैप्टिव खपत सहित) क्षति की अवधि के दौरान 13 प्रतिशत तक बढ़ी। क्षति की अवधि के दौरान कुल मांग (कैप्टिव खपत को छोड़कर) 12 प्रतिशत तक बढ़ी। यह वृद्धि भारत में प्रयोक्ता उद्योग की आवश्यकता के अनुरूप होनी प्रतीत होती है।
- liv. संबद्ध सामानों के आयात क्षति की अवधि में 32 प्रतिशत तक बढ़े, परंतु मांग की प्रतिशतता के रूप में आयात केवल 3 प्रतिशत बढ़े।
- lv. घरेलू उद्योग की संस्थापित क्षमता, उत्पादन और घरेलू बिक्री भारत में संबद्ध सामानों के लिए मांग में वृद्धि के अनुरूप बढ़ी।

- lvi. क्षमता विस्तार केवल सुदृढ़ मूल्यांकन के पीछे ही हो सकता है कि यदि संबद्ध सामानों पर पाटनरोधी शुल्क समाप्त होता है तो पाटन और क्षति की कोई संभावना नहीं है।
- lvii. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का निष्पादन और उनकी भावी योजनाएं क्षति पहुँचाने वाले पाटन के बार-बार होने की कोई संभावना नहीं दर्शाती।
- lviii. संबद्ध देशों से आयातों का समग्र बाजार हिस्सा 2013-14 से जांच की अवधि तक 3 प्रतिशत तक बढ़ा।
- lix. घरेलू उद्योग का लाभ 2013-14 में 100 सूचकांक से बढ़कर जांच की अवधि में 300 सूचकांक हो गया।
- lx. घरेलू उद्योग का लाभ क्षति की अवधि के दौरान 200 सूचकांक तक बढ़ा।
- lxi. घरेलू उद्योग क्षति की अवधि में कुल 30 प्रतिशत बाजार हिस्सा बनाए रखने में सक्षम रहा जबकि अन्य भारतीय उत्पादकों के बाजार हिस्सा जांच की अवधि में 2013-14 में 49 प्रतिशत से घटकर 47 प्रतिशत हो गया। घरेलू उद्योग की स्थिति में स्पष्ट सुधार है।
- lxii. क्षति की अवधि के दौरान क्षमता में तीव्र वृद्धि थी, परंतु जांच की अवधि के दौरान क्षमता उपयोग लगभग आधार वर्ष 2013-14 के क्षमता उपयोग के बराबर है। संबद्ध सामानों के आयातों से घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में कोई गिरावट नहीं आई। घरेलू उद्योग इस वर्ष के दौरान पूर्ण क्षमताओं पर प्रचालन करता रहा है।
- lxiii. स्टॉक 2013-14 में 100 सूचकांक से घटकर 2014-15 में 74 सूचकांक हो गया। 2015-16 में क्षमता और उत्पादन में वृद्धि से स्टॉक 136 सूचकांक तक बढ़ गया। क्षमता और उत्पादन जांच की अवधि में फिर बढ़े, परंतु स्टॉक घटकर 132 सूचकांक हो गया।
- lxiv. घरेलू उद्योग का स्टॉक निर्यात में गिरावट के कारण क्षति की अवधि में बढ़ा।
- lxv. कुल रोजगार 2013-14 में 100 सूचकांक से घटकर जांच की अवधि में 96 सूचकांक हो गया। प्रति कर्मचारी उत्पादकता तथा प्रति दिन उत्पादकता जांच की अवधि के दौरान सबसे अधिक थी। प्रति कर्मचारी उत्पादकता 2013-14 में 18 सूचकांक तक बढ़ी। आयातों से घरेलू उद्योग के रोजगार और उत्पादकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
- lxvi. घरेलू उद्योग द्वारा दी गई मजदूरी उसी अवधि में 100 सूचकांक से बढ़कर 326 हो गई। घरेलू उद्योग की लाभप्रदता भी प्रभावित हुई थी।
- lxvii. घरेलू उद्योग की क्षमता 2013-14 में 100 सूचकांक से बढ़कर जांच की अवधि में 112 सूचकांक हो गई। उसकी नियोजित पूंजी 66 सूचकांक तक बढ़ी। नियोजित पूंजी पर आय 100 सूचकांक से बढ़कर जांच की अवधि 159 सूचकांक हो गई। घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित पूंजी पर आय पर आयातों का कोई प्रभाव नहीं है।
- lxviii. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता क्षति की अवधि के दौरान अधिक सुधरी है।
- lxix. घरेलू उद्योग की बिक्री लागत जांच की अवधि में 6 सूचकांक तक कम हुई, जबकि बिक्री कीमत 7 सूचकांक तक बढ़ी।
- lxx. कोई कीमत न्यूनीकरण अथवा ह्रास नहीं था और वे अच्छा लाभ कमा रहे थे।
- lxxi. कीमत कटौती का घरेलू उद्योग के निष्पादन पर कोई दृश्यमान प्रभाव नहीं था।
- lxxii. घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री संबद्ध सामानों के लिए मांग में वृद्धि के साथ पूरी क्षति की अवधि में बढ़ी। यदि कीमत कटौती का कोई वास्तविक हानिकारक प्रभाव होता तो घरेलू उद्योग अपनी घरेलू बिक्री बनाए रखने और इसे बढ़ाने में सक्षम नहीं होता।
- lxxiii. घरेलू उद्योग का नियोजित पूंजी पर 30 प्रतिशत आय का दावा गैर-कानूनी है क्योंकि मानदंड आय की ऐतिहासिक दर मानने का है। प्राधिकारी को वैश्विक रूप से और भारत में सोडा ऐश उद्योग द्वारा प्राप्त आय के स्तर की जांच करनी चाहिए और तभी इस मामले में नियोजित पूंजी पर उपयुक्त आय लेनी चाहिए।
- lxxiv. प्राधिकारी को यह मूल्यांकन करना अपेक्षित है कि क्या पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन अथवा क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है अथवा नहीं।

- lxxv. याचिकाकर्ताओं को वर्तमान में कोई क्षति नहीं हो रही है जो सार्वजनिक सुनवाई में याचिकाकर्ताओं द्वारा स्वयं स्वीकार किए जाने से सिद्ध है।
- lxxvi. याचिकाकर्ताओं का बाजार हिस्सा आधार वर्ष और 2014-15 की तुलना में जांच की अवधि में बढ़ा है। संबद्ध देशों से आयातों का बाजार हिस्सा अपेक्षाकृत रूप से समान रहा है। संबद्ध आयातों का याचिकाकर्ताओं के बाजार हिस्से पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।
- lxxvii. उत्पादन और बिक्री मात्रा सहित आर्थिक मानदंडों ने क्षति की अवधि में तथा जांच की अवधि में सकारात्मक प्रवृत्ति दर्शाई है और क्षमता उपयोग क्षति की अवधि में स्थिर रहा है।
- lxxviii. घरेलू बिक्री मात्रा और मूल्य के आंकड़े पूरी क्षति की अवधि तथा जांच की अवधि में निरंतर बढ़ते रहे हैं, यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग का बिक्री निष्पादन संबद्ध आयातों को ध्यान में न रखते हुए लाभप्रद रहा है। उत्पादन भी क्षति की अवधि में बढ़ा है।
- lxxix. याचिकाकर्ताओं की लाभप्रदता आधार वर्ष से जांच की अवधि तक 200 अंक तक बढ़ी है।
- lxxx. याचिकाकर्ताओं का ब्याज एवं कर पूर्व लाभ भी आधार वर्ष से जांच की अवधि में 164 सूचकांक तक बढ़ा।
- lxxxi. नियोजित पूंजी पर आय आधार वर्ष से जांच की अवधि में 59 अंक तक बढ़ी।
- lxxxii. याचिकाकर्ताओं ने पूरी क्षति की अवधि में अपने कामगारों को दी गई मजदूरी बढ़ाई। मजदूरी आधार वर्ष से जांच की अवधि में 226 सूचकांक तक बढ़ी।
- lxxxiii. निर्णायक समीक्षा में संभावना का विश्लेषण मौजूदा अधिशेष क्षमताओं और क्षमता अभिवृद्धि के आधार पर किया जाना चाहिए।
- lxxxiv. कीमत आकर्षकता इस संबंध में साक्ष्य के अभाव में वर्तमान वास्तविक मैट्रिक्स में क्षति की संभावना के कारण के रूप में नहीं मानी जा सकती।
- lxxxv. याचिका का अनुबंध 4.3 निम्नलिखित कारणों से कीमत आकर्षकता निर्धारित करने के लिए पर्याप्त नहीं है – (i) दिए गए आंकड़े स्रोत दिए जाने के अभाव में प्राधिकृत साक्ष्य नहीं हैं, (ii) आंकड़े केवल तीन माह से संबंधित हैं अर्थात् जांच की अवधि जनवरी से मार्च, 2017 के हैं, (iii) यह सत्यापनीय नहीं है कि क्या निर्यात संबद्ध देशों से तीसरे देशों को हैं अथवा भारत को।
- lxxxvi. कीमत आकर्षकता के प्रयोजन के लिए भारत को संबद्ध देशों के निर्यात के विरुद्ध अन्य देशों को संबद्ध देशों के निर्यात के बीच उपयुक्त तुलना नहीं की जा सकती।
- lxxxvii. डीसीडब्ल्यू लि. ने 2016-17 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट द्वारा सूचित किया है कि आयातों से खतरा नहीं है तथा कंपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा का सामना करने में सक्षम है।
- lxxxviii. याचिकाकर्ताओं को हुई तथाकथित क्षति उनकी योजनाहीन बंदी का परिणाम है और इसलिए वह संबद्ध आयातों का प्रभाव नहीं है।
- lxxxix. डीसीडब्ल्यू लि. ने अपनी 2016-17 की वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि सोडा ऐश डिब्रीजन के बंद होने के कारण पूर्व वर्ष की तुलना में कारोबार में 11 प्रतिशत तक की हानि थी।

प्राधिकारी द्वारा जांच

- 41. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों और प्रति-तर्कों को ध्यान में रखा है।
- 42. जहां तक क्षति विश्लेषण में एक कारक के रूप में घरेलू उद्योग द्वारा खर्च किए गए भाड़े पर विचार करने के लिए घरेलू उद्योग के तर्क का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति रहित कीमत पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के अनुसार निर्धारित की गई है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि क्षति मार्जिन निर्धारित करने के लिए क्षति रहित कीमत और पहुँच मूल्य के बीच तुलना प्राधिकारी की सतत परिपाटी के अनुसार उसी स्तर पर की गई है।
- 43. प्राधिकारी द्वारा नीचे किया गया क्षति विश्लेषण हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों को हल करता है।

क. संचयी मूल्यांकन

44. पाटनरोधी नियामवली के अनुबंध-II पैरा (iii) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें यह प्रावधान है कि यदि जहां एक से अधिक देश से उत्पाद के आयात पाटनरोधी जांचों के अधीन साथ वहां ,हों रहे जा रखे साथ-कि: है करता निर्धारित वह यदि ,करेंगे से रूप संचयी मूल्यांकन का प्रभाव के आयातों ऐसे प्राधिकारी
- क. प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में सिद्ध पाटन का मार्जिन 2 प्रतिशत से अधिक निर्यात की प्रतिशतता के रूप में व्यक्त है और प्रत्येक देश से आयात की मात्रा समान वस्तु के आयात के 3 प्रतिशत (अथवा अधिक) है अथवा जहां अलग-अलग देशों का निर्यात 3 प्रतिशत से कम है, आयात सार्वजनिक रूप से समान वस्तु के आयात के 7 प्रतिशत से अधिक के लिए होता है, और
- ख. आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन आयातित वस्तु और समान घरेलू वस्तु के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के आलोक में उपयुक्त है।
45. इस संबंध में प्राधिकारी निम्नलिखित नोट करते हैं:
- चीन जन. गण., यूरोपीय संघ, केन्या, पाकिस्तान और यूक्रेन के लिए पाटन मार्जिन ऊपर निर्धारित सीमाओं से कम है। तथापि, पाटन मार्जिन ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए ऊपर निर्धारित सीमाओं से अधिक है।
 - प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों की मात्रा निर्धारित सीमाओं से अधिक है।
 - विभिन्न संबद्ध देशों से और घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए संबद्ध सामान समान बाजार में एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं।
46. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर ध्यान दिया है। पाटनरोधी नियामवली के अनुबंध-II में प्रभाव के आयातों पाटित पर कीमत की औवस्तु समान में बाजार घरेलू और मात्रा की आयातों पाटित (क), एवं (ख) ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव, दोनों की तथ्यपरक जांच का प्रावधान है। जहां तक पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव का संबंध है, प्राधिकारी के लिए यह जांच करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप में या भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में पर्याप्त वृद्धि हुई है। जहां तक कि पाटित के कीमत प्रभाव का संबंध है, प्राधिकारी के लिए यह जांच करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में कीमत में पर्याप्त कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे उत्पादों के प्रभाव से कीमत में काफी अधिक मात्रा में अन्यथा गिरावट आई है अथवा होने वाली इस वृद्धि में रुकावट आई है जो अन्यथा काफी अधिक स्तर तक बढ़ गई होती।
47. जहां तक घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है पाटनरोधी ,नियामवली के अनुबंध-II के पैरा (iv) में निम्नलिखित उल्लेख है:
- "संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और सूचकांकों का मूल्यांकन शामिल है, जिनमें लाभ, आउटपुट, मार्केट शेयर, उत्पादकता, निवेश पर वापिसी या क्षमता का उपयोग, घरेलू कीमतों पर प्रभाव डालने वाले कारक, वास्तविक पाटन मार्जिन की मात्रा और नकदी प्रवाह पर संभावित ऋणात्मक प्रभाव, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, संवृद्धि, पूंजीगत निवेशों को जुटाने की क्षमता सम्मिलित है।"*
48. भारत में घरेलू उद्योग पर आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियामवली के अनुबंध-II(iv) के अनुसार उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता, निवल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा तथा मार्जिन आदि के रूप में घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले ऐसे तत्वों पर विचार किया है।
49. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों तथा तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वस्तुपरक रूप से क्षति मानदंडों की जांच की है।
50. सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9(क)(5) के अनुसार, लगाया गया पाटनरोधी शुल्क, जब तक कि पहले न हटाया गया हो, उसे लगाए जाने की तारीख से पांच वर्षों की समाप्ति पर अप्रभावी हो जाएगा, बशर्ते कि यदि केंद्र सरकार का किसी समीक्षा में यह मत है कि यदि उस शुल्क को बंद करने से पाटन एवं क्षति जारी रहने अथवा बार-

बार होने की संभावना है, वह समय-समय पर अगले पांच वर्षों की अवधि के लिए उसे लगाए जाने की अवधि बढ़ा सकती है और वह अगली अवधि उस अवधि के बढ़ाए जाने के आदेश की तारीख से शुरू होगी।

51. इस संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों पर विचार करते हुए प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से आयातों के कारण पाटन एवं क्षति की संभावनाओं के पहलुओं की जांच करने के लिए कार्रवाई करने से पूर्व घरेलू उद्योग को क्षति, यदि कोई है, की जांच की है।

मांग एवं बाजार हिस्सा

52. संबद्ध सामानों की घरेलू खपत/मांग के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग तथा अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री मात्रा को भारत में कुल आयातों में जोड़ा गया है तथा उसका निम्नलिखित रूप में सार दिया गया है।

विवरण	यूओएम	2013-14	2014-15	2015-16	जांच की अवधि
घरेलू उद्योग की बिक्री (कैप्टिव सहित)	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	99	110	115
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री (कैप्टिव सहित)	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	105	108
आयात - संबद्ध देश	मी. टन	490,567	672,947	603,749	645,298
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	137	123	132
आयात - अन्य देश जिन पर शुल्क लग रहा है	मी. टन	62,355	49,071	25,674	35,469
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	79	41	57
आयात - अन्य देश	मी. टन	16,044	1,202	3,839	14,355
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	7	24	89
कुल मांग (कैप्टिव अंतरण सहित)	मी. टन	2,884,703	3,079,692	3,113,308	3,262,392
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	108	113
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
अन्य भारतीय उत्पादक	%	***	***	***	***
समग्र रूप में भारतीय उत्पादक	%	80.28%	76.52%	79.66%	78.69%
संबद्ध देश	%	17.01%	21.85%	19.39%	19.78%
अन्य देश जिन पर शुल्क लग रहा	%	2.16%	1.59%	0.82%	1.09%
अन्य देश	%	0.56%	0.04%	0.12%	0.44%
भारतीय उत्पादन में संबद्ध देश से आयात का हिस्सा (टाटा केमिकल्स लि. को छोड़कर)	%	30%	40%	34%	34%
भारतीय उत्पादन में संबद्ध	%	21%	28%	24%	25%

विवरण	यूओएम	2013-14	2014-15	2015-16	जांच की अवधि
देश से आयात का हिस्सा (टाटा केमिकल्स लि. को छोड़कर)					

53. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मांग आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान बढ़ी है। आधार वर्ष में जांच की अवधि के दौरान मांग में वृद्धि 13 प्रतिशत थी। घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से और संबद्ध देशों से आयातों में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई।

ख. पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

आयात मात्रा और बाजार हिस्सा

54. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी को यह विचार करने की आवश्यकता होती है कि क्या पूर्ण दृष्टि से अथवा भारत में उत्पादन अथवा खपत की तुलना में पाटित आयातों में काफी वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त आयात आंकड़ों पर विश्वास किया है। संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों की मात्रा का निम्नलिखित रूप में विश्लेषण किया गया है।

विवरण	यूओएम	2013-14	2014-15	2015-16	जांच की अवधि
आयात मात्रा					
चीन जन. गण.	मी. टन	100,052	127,005	89,907	33,769
यूरोपीय संघ	मी. टन	189,191	242,549	242,792	295,525
केन्या	मी. टन	162,392	130,161	101,149	89,516
पाकिस्तान	मी. टन	16,725	37,207	39,910	40,873
ईरान	मी. टन	-	5,427	20,204	32,991
यूक्रेन	मी. टन	196	43,276	29,634	26,714
संयुक्त राज्य अमेरिका	मी. टन	22,010	87,321	80,153	125,911
संबद्ध देश	मी. टन	490,567	672,947	603,749	645,298
अन्य देश जिन पर शुल्क लग रहा है	मी. टन	62,355	49,071	25,674	35,469
अन्य देश	मी. टन	16,044	1,202	3,839	14,355
कुल आयात	मी. टन	568,966	723,220	633,262	695,122
बाजार हिस्सा					
चीन जन. गण.	%	18%	18%	14%	5%
यूरोपीय संघ	%	33%	34%	38%	43%
केन्या	%	29%	18%	16%	13%
पाकिस्तान	%	3%	5%	6%	6%
ईरान	%	0%	1%	3%	5%
यूक्रेन	%	0.03%	6%	5%	4%
संयुक्त राज्य अमेरिका	%	4%	12%	13%	18%

विवरण	यूओएम	2013-14	2014-15	2015-16	जांच की अवधि
संबद्ध देश	%	86%	93%	95%	93%
अन्य देश जिन पर शुल्क लग रहा है	%	11%	7%	4%	5%
अन्य देश	%	3%	0%	1%	2%
कुल	%	100%	100%	100%	100%

55. चीन जन. गण., यूरोपीय संघ, केन्या, पाकिस्तान और यूक्रेन से आयात जांच की अवधि के दौरान अपाटित थे। प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन. गण. और केन्या से आयातों में जांच की अवधि के दौरान गिरावट आई है जबकि यूरोपीय संघ, पाकिस्तान और यूक्रेन से आयातों में जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि चीन जन. गण. और केन्या के बाजार हिस्से में जांच की अवधि में गिरावट आई है जबकि यूरोपीय संघ, पाकिस्तान और यूक्रेन के बाजार हिस्से में जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।
56. ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात जांच की अवधि के दौरान पाटित थे। इन दोनों देशों से आयातों में वृद्धि हुई है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाजार हिस्से में जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।
57. जांच की अवधि के दौरान भारत में संबद्ध सामानों के कुल आयातों में संबद्ध आयात 93 प्रतिशत हैं। इसमें से ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका से पाटित आयातों का हिस्सा 23 प्रतिशत है जबकि चीन जन.गण., यूरोपीय संघ, केन्या, पाकिस्तान और यूक्रेन से अपाटित आयातों का हिस्सा 70 प्रतिशत है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि अपाटित आयातों की मात्रा पाटित आयातों की तुलना में काफी है।

ग. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

58. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी को यह विचार करना अपेक्षित होता है कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा काफी कीमत कटौती की जा रही है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव काफी मात्रा तक कीमतों का ह्रास करने के लिए अथवा कीमत वृद्धि रोकने के लिए अन्यथा है जो कि अन्यथा काफी मात्रा तक हुई होती। संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जांच कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत ह्रास तथा कीमत न्यूनीकरण, यदि कोई है, के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत, निवल बिक्री वसूली और क्षति रहित कीमत (एनआईपी) की तुलना संबद्ध देशों से आयातों की पहुँच कीमत से की गई है।

पाटित आयातों का कीमत ह्रासमान एवं न्यूनीकरण प्रभाव

59. पाटित आयातों के कीमत न्यूनीकरण तथा कीमत ह्रासमान प्रभाव की भी जांच संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत, निवल बिक्री वसूली और पहुँच मूल्य के संदर्भ में जांच की अवधि सहित क्षति अवधि के संबंध में की गई।

विवरण	यूओएम	2013-14	2014-15	2015-16	जांच की अवधि
बिक्री की लागत	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	93	83	84
बिक्री कीमत	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	109	107
चीन जन. गण से संबद्ध आयात की पहुँच कीमत	रु./मी. टन	14,390	17,303	16,653	18,128
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	120	116	126

यूरोपीय संघ से संबद्ध आयात की पहुँच कीमत	रु./मी. टन	16,259	17,366	18,429	16,878
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	113	104
केन्या से संबद्ध आयात की पहुँच कीमत	रु./मी. टन	14,805	15,633	16,457	14,662
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	111	99
पाकिस्तान से संबद्ध आयात की पहुँच कीमत	रु./मी. टन	18,192	19,038	19,665	17,957
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	105	108	99
ईरान से संबद्ध आयात की पहुँच कीमत	रु./मी. टन	उपलब्ध नहीं	16,598	15,813	14,722
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	उपलब्ध नहीं	100	95	89
यूक्रेन से संबद्ध आयात की पहुँच कीमत	रु./मी. टन	17,473	17,086	17,284	15,567
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	99	89
संयुक्त राज्य अमेरिका से संबद्ध आयात की पहुँच कीमत	रु./मी. टन	12,668	15,987	15,901	14,378
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	126	126	113

60. यह नोट करना व्यवहारिक है कि केवल ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका से संबद्ध सामानों के आयात जांच की अवधि के दौरान पाटित किए गए थे। जबकि, अन्य सभी संबद्ध देशों से आयात इस अवधि में अपाटित थे।
61. घरेलू उद्योग की बिक्री लागत आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान कम हुई है। तथापि, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत क्षति की अवधि के दौरान बढ़ी है। चीन जन. गण., यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका से आयातों का पहुँच मूल्य आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान बढ़ा है। जांच की अवधि के दौरान केन्या और पाकिस्तान से आयातों का पहुँच मूल्य कुल मिलाकर समान रहा है। ईरान और यूक्रेन से आयातों के पहुँच मूल्य में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान गिरावट आई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत पूरी क्षति अवधि के दौरान उसकी बिक्री लागत से कहीं अधिक थी। इसके अतिरिक्त याचिकाकर्ताओं की बिक्री कीमत निरंतर और क्षति जांच अवधि के दौरान बढ़ी है। संबद्ध देशों से आयातों से घरेलू उद्योग के लिए कोई कीमत न्यूनीकरण अथवा कीमत हास नहीं हुआ।

कीमत कटौती

62. घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली निकालते समय घरेलू उद्योग द्वारा दी गई छूट, रियायत और कमीशन तथा दिया गया केंद्रीय उत्पाद शुल्क घटा दिया गया है। आयातों के पहुँच मूल्य का परिकलन 1 प्रतिशत पहुँच प्रभार तथा लागू मूल सीमा शुल्क एवं संबद्ध देशों से सीआईएफ कीमतों में शिक्षा उप कर जोड़कर, डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों में सूचित किए गए अनुसार, परिकलित की गई है। घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि कीमत कटौती के निर्धारण के लिए भाड़ा शामिल किया जाना चाहिए। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि कीमत कटौती निर्धारण के लिए निवल बिक्री वसूली और पहुँच मूल्य के बीच तुलना प्राधिकारी की सतत परिपाटी के अनुसार उसी स्तर पर की गई है।

विवरण	यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	जांच की अवधि
चीन					
आयात की पहुँच कीमत	रु./मी. टन	14,390	17,303	16,653	18,128
निवल बिक्री वसूली	रु./मी. टन	***	***	***	***
कीमत कटौती	रु./मी. टन	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
कीमत कटौती	% रेंज	20-30%	10-20%	10-20%	0-10%
यूरोपीय संघ					
आयात की पहुँच कीमत	रु./मी. टन	16,259	17,366	18,429	16,878
निवल बिक्री वसूली	रु./मी. टन	***	***	***	***
कीमत कटौती	रु./मी. टन	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
कीमत कटौती	% रेंज	10-20%	10-20%	0-10%	10-20%
केन्या					
आयात की पहुँच कीमत	रु./मी. टन	14,805	15,633	16,457	14,662
निवल बिक्री वसूली	रु./मी. टन	***	***	***	***
कीमत कटौती	रु./मी. टन	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
कीमत कटौती	% रेंज	20-30%	20-30%	15-25%	30-40%
पाकिस्तान					
आयात की पहुँच कीमत	रु./मी. टन	18,192	19,038	19,665	17,957
निवल बिक्री वसूली	रु./मी. टन	***	***	***	***
कीमत कटौती	रु./मी. टन	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
कीमत कटौती	% रेंज	(5)-5%	0-10%	(5)-5%	0-10%
ईरान					
आयात की पहुँच कीमत	रु./मी. टन	उपलब्ध नहीं	16,598	15,813	14,722
निवल बिक्री वसूली	रु./मी. टन	उपलब्ध नहीं	***	***	***
कीमत कटौती	रु./मी. टन	उपलब्ध नहीं	***	***	***
कीमत कटौती	%	उपलब्ध नहीं	***	***	***
कीमत कटौती	% रेंज	उपलब्ध नहीं	10-20%	20-30%	25-35%
यूक्रेन					

विवरण	यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	जांच की अवधि
आयात की पहुँच कीमत	रु./मी. टन	17,473	17,086	17,284	15,567
निवल बिक्री वसूली	रु./मी. टन	***	***	***	***
कीमत कटौती	रु./मी. टन	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
कीमत कटौती	% रेंज	0-10%	10-20%	10-20%	20-30%
संयुक्त राज्य अमेरिका					
आयात की पहुँच कीमत	रु./मी. टन	12,668	15,987	15,901	14,378
निवल बिक्री वसूली	रु./मी. टन	***	***	***	***
कीमत कटौती	रु./मी. टन	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
कीमत कटौती	% रेंज	40-50%	15-25%	20-30%	30-40%

63. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान आयातों का कीमत कटौती प्रभाव उपर्युक्त प्रत्येक देश के संबंध में सकारात्मक था। तथापि, यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि चीन जन. गण., यूरोपीय संघ, केन्या, पाकिस्तान और यूक्रेन से आयात जांच की अवधि के दौरान अपाटित थे, जबकि ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात जांच की अवधि के दौरान पाटित थे। चूंकि संबद्ध देशों से अधिकतर आयात जांच की अवधि के दौरान अपाटित थे, अतः प्राधिकारी ने स्थिति की अनुकूल समझ के लिए बाद के पैराओं में घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंडों तथा पाटन एवं क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना का विश्लेषण किया है।

घ. घरेलू उद्योग के अन्य आर्थिक मानदंडों की जांच

उत्पादन, क्षमता, बिक्री और क्षमता उपयोग

64. उत्पादन, क्षमता और क्षमता उपयोग के व्यौरे निम्नलिखित हैं:

विवरण	यूओएम	2013-14	2014-15	2015-16	जांच की अवधि
संस्थापित क्षमता	मी. टन	1,111,000	1,111,000	1,236,000	1,246,400
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	111	112
कुल भारतीय उत्पादन	मी. टन	1,611,777	1,693,439	1,786,756	1,886,607
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	105	111	117
याचिकाकर्ताओं का उत्पादन	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	110	113
क्षमता उपयोग	%	83	85	82	84
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	99	101
घरेलू बिक्री (कैप्टिव सहित)	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	99	110	115
मांग	मी. टन	2,884,703	3,079,692	3,113,308	3,262,392

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	108	113
-----------	----------	-----	-----	-----	-----

65. उपर्युक्त सूचना से प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की उत्पादन क्षमता जांच की अवधि सहित क्षति की अवधि के दौरान बढ़ी है। जांच की अवधि के दौरान घरेलू बिक्री में वृद्धि हुई है। क्षमता उपयोग 2015-16 और जांच की अवधि के दौरान क्षमता अभिवृद्धि के बावजूद कुल मिलाकर वही रही है।

मालसूची

66. मालसूची से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित दर्शाते हैं:

विवरण	यूओएम	2013-14	2014-15	2015-16	जांच की अवधि
प्रारंभिक	मी. टन	***	***	***	***
अंतिम	मी. टन	***	***	***	***
औसत	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	74	136	132

67. यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि से पूर्व औसत मालसूची में वृद्धि हुई और फिर जांच की अवधि के दौरान उसमें गिरावट आई।

लाभ तथा नकद प्रवाह पर वास्तविक और संभावित प्रभाव

68. लाभ/हानि तथा नकद प्रवाह के संबंध में यह नोट किया जाता है कि कर पूर्व लाभ तथा ब्याज, नकद लाभ तथा निवेश पर आय के संदर्भ में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में काफी बढ़ी है। प्राधिकारी ने अपनी सतत परिपाटी के आधार पर लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय निर्धारित की है।

विवरण	यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	जांच की अवधि
बिक्री की लागत	र./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	93	83	84
बिक्री कीमत	र./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	109	107
लाभ/हानि	र./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	224	321	300
लाभ/हानि	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	226	359	338
पीबीआईटी	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	177	280	264
नकद लाभ	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	184	288	287
निवेश की आय	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	193	293	160

रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

69. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता से संबंधित निम्नलिखित दर्शाते हैं:

विवरण	यूओएम	2013-14	2014-15	2015-16	जांच की अवधि
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	114	236
रोजगार	सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	99	96	96
मजदूरी	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	110	124	326

70. यह नोट किया जाता है कि आधार वर्ष 2013-14 की तुलना में जांच की अवधि के दौरान कर्मचारियों की संख्या में आंशिक गिरावट थी, तथापि, आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान उत्पादकता में काफी अच्छी वृद्धि हुई। मजदूरी में भी आधार वर्ष 2013-14 की तुलना में जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई।

71. प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ताओं की स्थिति में ऊपर चर्चा किए गए आर्थिक मानदंडों के संबंध में बहुत ही अच्छा सुधार हुआ है। विशेष रूप से क्षमता, उत्पादन, घरेलू बिक्री, नकद प्रवाह, लाभप्रदता, नियोजित पूंजी पर आय और उत्पादकता क्षति की अवधि में काफी सुधार दर्शाते हैं। क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत बढ़ी है और क्षमताओं की अभिवृद्धि से जुड़ी लागत के बावजूद बिक्री लागत से अधिक रही है। बाद के भागों में विश्लेषण यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत भी घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित क्षति रहित कीमत से अधिक थी।

ड. पाटन की मात्रा

72. उपर्युक्त पाटन मार्जिन से संबंधित भाग से यह पाया गया है कि चीन जन. गण., यूरोपीय संघ, केन्या, पाकिस्तान और यूक्रेन से संबद्ध सामानों के आयातों के संबंध में पाटन मार्जिन जांच की अवधि के दौरान नकारात्मक था। पाटन मार्जिन ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए जांच की अवधि के दौरान सकारात्मक था। तथापि, उसका याचिकाकर्ताओं के निष्पादन पर कोई दृश्यमान प्रभाव नहीं है।

वृद्धि

73. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की बिक्री जांच की अवधि के दौरान उत्पादन, बिक्री, कर पूर्व लाभ और ब्याज, नकद लाभ और निवेश पर आय में सुधार के संदर्भ में सकारात्मक थी।

निधियां जुटाने की क्षमता

74. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने वर्ष 2015-16 और जांच की अवधि में संबद्ध सामानों की अपनी उत्पादन क्षमता में वृद्धि की है। घरेलू उद्योग ने वर्तमान में काफी पूंजी निवेश किया है और क्षमता बढ़ाने के लिए निवेश करने की योजना बनाई है। यह दर्शाता है कि पूंजी निवेश बढ़ाने में उनकी क्षमता प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं हुई है।

च. क्षति एवं क्षति मार्जिन की मात्रा

75. प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामानों की क्षति रहित कीमत की तुलना जांच की अवधि के दौरान क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए संबद्ध देशों से निर्यातों के पहुँच मूल्य से की गई है। इस प्रकार, क्षति मार्जिन निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया गया है।

76. प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई सतत परिपाटी के अनुसार, एनआईपी का निर्धारण लागत लेखापरीक्षित रिकार्डों के बजाए घरेलू उद्योग द्वारा रखे गए वित्तीय रिकार्डों के आधार पर पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के तहत निर्धारित सिद्धांत के अनुसार किया जाता है। यह प्राथमिक रूप से इस तथ्य के कारण है कि कुछ लागतों जो

पाटनरोधी जांच में अस्वीकार्य मानी जाती हैं, पर भी लागत लेखा परीक्षा रिपोर्टों में लागतों के भाग के रूप में विचार किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, अनुबंध-III में कच्ची सामग्री, यूटिलिटियों और अन्य नियत लागतों के संबंध में भिन्न सिद्धांत निर्धारित हैं। लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट इन नियमों और प्रविधियों को नहीं अपनाती। तथापि, इस जांच में घरेलू उद्योग लेखापरीक्षित वित्तीय रिकार्डों के अनुसार शीर्ष-वार व्यय की अपेक्षित सूचना देने में सक्षम नहीं रहा है और तदनुसार, प्राधिकारी घरेलू उद्योग द्वारा दी गई लागत लेखापरीक्षा रिपोर्टों में उपलब्ध सूचना के आधार पर एनआईपी निर्धारित करने के लिए विवश थे।

जांच की अवधि

देश	निर्यातक/ उत्पादक	एनआईपी भारतीय रुपए /मी. टन	परिवर्तन दर	एनआईपी अमेरिकी डॉलर/ मी. टन	पहुँच मूल्य अमेरिकी डॉलर/ मी. टन	क्षति मार्जिन अमेरिकी डॉलर/ मी. टन	क्षति मार्जिन %	क्षति मार्जिन % रेंज
चीन जन. गण.	सभी	***	67.95	***	267	***	***	नकारात्मक
यूरोपीय संघ	सभी	***	67.95	***	248	***	***	नकारात्मक
केन्या	सभी	***	67.95	***	216	***	***	नकारात्मक
पाकिस्तान	सभी	***	67.95	***	264	***	***	नकारात्मक
ईरान	सभी	***	67.95	***	217	***	***	नकारात्मक
यूक्रेन	सभी	***	67.95	***	229	***	***	नकारात्मक
संयुक्त राज्य अमेरिका	सभी	***	67.95	***	212	***	***	सकारात्मक
भारत औसत	सभी	***	67.95	***	236	***	***	नकारात्मक

छ. वास्तविक क्षति संबंधी निष्कर्ष

77. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान उत्पादन, बिक्री मात्रा, बाजार हिस्सा, लाभ, नकद लाभ, नियोजित पूंजी पर आय और मालसूची के संदर्भ में सुधार हुआ है। घरेलू उद्योग ने अपने अनुरोधों में भी यह स्वीकार किया है कि उसे क्षति अवधि के दौरान कोई क्षति नहीं हो रही थी। क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत बढ़ी है और क्षमताओं की अभिवृद्धि से जुड़ी लागत के बावजूद बिक्री लागत से अधिक रही है। घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत भी जांच की अवधि के दौरान क्षति रहित कीमत से कहीं अधिक थी।

ठ. अन्य ज्ञात कारक और कारणात्मक संपर्क

याचिकाकर्ताओं के अनुरोध

- संबद्ध देशों से पाटित आयात पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद बढ़े हैं।
- पाटित आयात घरेलू कीमतों से कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। इस प्रकार, यदि पाटनरोधी शुल्क बंद होता है तो पाटित आयातों की मात्रा एक बार फिर बढ़ जाएगी।
- संबद्ध देशों से उत्पादकों के पास उपलब्ध क्षमताएं और उनकी निर्यातोन्मुखता यह दर्शाती है कि यदि पाटनरोधी शुल्क बंद हो जाता है तो पाटित आयातों की मात्रा में उछाल आएगा।
- निर्यातक अत्यधिक निर्यातोन्मुख हैं। संबद्ध निर्यातकों द्वारा उन कीमतों से कम कीमतों पर तीसरे देशों को काफी निर्यात किए जाते हैं जिन पर वे भारत को निर्यात करते हैं और क्षति रहित कीमत पर पाटित किए जाते हैं। आयात शुल्क हटाए जाने की स्थिति में घरेलू कीमतों की काफी कटौती करेंगे। परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को बाजार में कीमत न्यूनीकरण होगा।

- v. घरेलू उद्योग इस तथ्य के मद्देनजर संबंधित उत्पाद की कीमतें काफी घटाने के लिए मजबूर होगा कि संबंधित उत्पाद एक वस्तु उत्पाद है।
- vi. कीमतों में कमी का स्वाभाविक प्रभाव घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पर होगा। लाभ में गिरावट से नकद प्रवाह और निवेश पर आय में गिरावट आएगी।
- vii. यदि घरेलू उद्योग अपने सामान्य कीमत स्तरों को बनाए रखने का विकल्प चुनता है तो उसकी बिक्री मात्रा समाप्त होने की संभावना है। वह एक भारी क्षति होगी क्योंकि इससे मालसूची स्तर, उत्पादन में गिरावट, क्षमता उपयोग और उत्पादकता में गिरावट आएगी।
- viii. क्षति के सकारात्मक जांच परिणाम तभी रिकार्ड किए जाएंगे यदि पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने तथा घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने के बीच कोई संबंध है। पाटनरोधी शुल्क समय पूर्व वापस लिए जाने की स्थिति में क्षति के बार-बार होने की संभावना तथा पाटित आयातों के बीच कारणात्मक संबंध है।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

- i. पाटित आयातों में तथाकथित वृद्धि से याचिकाकर्ताओं के उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री पर प्रभाव नहीं पड़ा।
- ii. हम घरेलू उद्योग के इस दावे पर विवाद करते हैं कि संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों से कम कीमतों पर उपलब्ध थे।
- iii. संबद्ध देशों में उपलब्ध क्षमताओं का इस मामले में कोई प्रभाव नहीं है। भारतीय उद्योग ने 6 लाख टन के आसपास वार्षिक क्षमता बढ़ाई है, जैसा कि मौखिक सुनवाई के दौरान प्रकट किया गया था। वार्षिक क्षमता 20 लाख टन और बढ़ाए जाने की योजना है। घरेलू उद्योग की सशक्त उपस्थिति भारत को संबद्ध देशों में किसी अधिशेष क्षमता के प्रवाह पर बाधा डालेगी।
- iv. यदि घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई कीमत कटौती का कोई वास्तविक हानिकारक प्रभाव था तो घरेलू उद्योग अपनी घरेलू बिक्री बनाए रखने अथवा उसे बढ़ाने में सक्षम नहीं होगा। केवल यह तथ्य कि घरेलू उद्योग ने तथाकथित कीमत कटौती के बावजूद भारत में अपनी बिक्री का विस्तार किया, क्षति की गैर-मौजूदगी तथा क्षति के जारी न रहने अथवा बार-बार न होने की संभावना दर्शाता है।
- v. घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत तथाकथित पाटन के बावजूद क्षति की अवधि के दौरान निरंतर बढ़ी। रिकार्ड में उपलब्ध आंकड़े यह नहीं दर्शाते कि घरेलू उद्योग क्षति की अवधि के दौरान अपनी कीमतें कम करने के लिए मजबूर था।
- vi. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता आधार वर्ष 2013-14 की तुलना में जांच की अवधि के दौरान लगभग तीन गुना बढ़ी है।
- vii. घरेलू उद्योग ने अतिरिक्त क्षमताएं संस्थापित कीं और उस पर बहुत अच्छा आय अर्जित की।
- viii. ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो यह बताए कि यदि पाटनरोधी शुल्क हटाया जाता है तो उपभोक्ता आयातों की ओर जाएंगे।

प्राधिकारी द्वारा जांच

78. कीमत कटौती तथा कीमत न्यूनीकरण एवं ह्रासमान प्रभावों के संदर्भ में घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के क्षति, मात्रात्मक तथा कीमत प्रभावों की जांच करने पर पाटनरोधी नियमावली और पाटनरोधी करार के तहत सूचीबद्ध अन्य संकेतात्मक मानदंडों की प्राधिकारी द्वारा यह देखने के लिए निम्नलिखित रूप में जांच की गई है कि क्या पाटित आयातों को छोड़कर किसी अन्य कारक का घरेलू उद्योग को क्षति में योगदान रहा है।

क. तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमतें

प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों को छोड़कर अन्य देशों तथा पाटनरोधी शुल्क लगने वाले देशों से संबद्ध सामानों के आयात काफी नहीं थे।

ख. मांग में संकुचन तथा खपत पैटर्न में परिवर्तन

प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान मांग में कोई संकुचन नहीं है। इसके विपरीत, संबद्ध सामानों के लिए समग्र मांग में जांच की अवधि के दौरान सुधार हुआ है।

ग. प्रौद्योगिकी में विकास

प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण परिवर्तन दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है जिससे कि घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।

घ. व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां तथा विदेशी एवं घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा

प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध सामान स्वतंत्र रूप से आयात किए जा सकते हैं। घरेलू उद्योग संबद्ध सामानों का प्रमुख उत्पादक है और उसका घरेलू उत्पादन एवं बिक्री में काफी हिस्सा है। इसके अतिरिक्त बाजार अर्थव्यवस्था में जो स्पष्ट है, उसे छोड़कर घरेलू उत्पादकों में कोई अवधारणीय प्रतिस्पर्धा नहीं है।

ङ. घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यात बाजारों में याचिकाकर्ताओं के निष्पादन से घरेलू उद्योग के निष्पादन के संबंध में प्राधिकारी द्वारा किए गए मूल्यांकन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। प्राधिकारी ने अपना मूल्यांकन पूर्णतः घरेलू बिक्री से संबंधित सूचना के आधार पर किया। घरेलू बिक्री के कारण क्षति को अलग रखा गया है और यथासंभव सीमा तक उसकी जांच की गई है।

79. उपर्युक्त विश्लेषण से प्राधिकारी नोट करते हैं कि न तो सूचीबद्ध ज्ञात मापदंड और न ही ऊपर विश्लेषण किए गए अन्य कारक घरेलू उद्योग को निरंतर कोई क्षति दर्शाते हैं। घरेलू उद्योग की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।

ड. क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना**याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए अनुरोध**

- i. जांच की अवधि में घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति की गैर-मौजूदगी पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने के लिए पर्याप्त नहीं है।
- ii. विगत में घरेलू उद्योग को हुई क्षति उत्पाद के पाटन के कारण थी। घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार अथवा वर्तमान अवधि में क्षति का अभाव पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का एक स्वाभाविक परिणाम है।
- iii. सोडा ऐश का देश में निरंतर पाटन करने का इतिहास है। आयात पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बावजूद कम कीमत पर काफी बढ़े हैं।
- iv. विविध देशों से अनुचित कीमत वाले आयात आए हैं। इन कुछ देशों के विरुद्ध समानांतर पाटनरोधी जांच चल रही है।
- v. पूर्व जांच में निर्धारित और वर्तमान जांच में प्रस्तावित पाटन मार्जिन काफी हैं और स्पष्ट रूप से पाटन की संभावना तथा पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में परिणामी क्षति दर्शाते हैं।
- vi. प्रत्येक संबद्ध देश के संबंध में पाटन मार्जिन काफी अधिक हैं।
- vii. संबद्ध देशों से आयात 2015-16 तक कम होने के बाद जांच की अवधि में बढ़े हैं। पाटित कीमतों पर आयातों में वृद्धि यह दर्शाती है कि पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में पाटित कीमतों पर काफी मात्रा में आयात आने की संभावना है।
- viii. क्षति की अवधि में आयातों से इस कारण कि पाटनरोधी शुल्क लागू थे, घरेलू उद्योग की कीमतों पर न्यूनीकरण अथवा हासमान प्रभाव नहीं पड़े।
- ix. तथापि, आयात कीमत काफी कम होनी शुरू हो गई है और घरेलू उद्योग की कीमतों पर न्यूनीकरण प्रभाव होना शुरू हो गया है क्योंकि नई तुर्की क्षमताओं का वाणिज्यिकीकरण हो गया है।
- x. यद्यपि, संबद्ध देशों में उत्पादकों की मालसूची का स्तर सही-सही निर्धारित नहीं किया जा सका, तथापि, यह उचित रूप से माना जा सकता है कि विदेशी उत्पादक छोटी सी अवधि में उत्पादन बढ़ा सकते हैं।

- xi. पाकिस्तान के निर्यातक अपनी क्षमताएं बढ़ा रहे हैं तथा निर्यात बाजारों की पूर्ति करने वाले प्रतीत होते हैं। यह सूचना आईएचएस केमिकल वीक में दिए गए अनुसार पाकिस्तान ने मांग एवं आपूर्ति के अंतराल से ली जा सकती है। विस्तार के पहले चरण में जुलाई, 2017 से *** मी. टन नई क्षमता प्रचालनात्मक होगी। विस्तार के दूसरे चरण में भी जुलाई, 2019 से *** मी. टन नई क्षमता प्रचालनात्मक होगी।
- xii. पाकिस्तान की मैसर्स ओलंपिया की *** मी. टन की वार्षिक क्षमता है। एक चीनी इंजीनियरिंग कंपनी उसके साथ *** मी. टन नई क्षमता जोड़ने के लिए सहयोग कर रही है जो दिसंबर, 2018 तक पूरी हो जाएगी।
- xiii. पाकिस्तान में मांग 4-6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर बढ़ने की उम्मीद है। आईएचएस केमिकल वीक के अनुसार बाजार में अधिक आपूर्ति होना कहा जाता है।
- xiv. चीन की मौजूदा अधिक अधिशेष क्षमताओं के बावजूद प्रस्तावित क्षमता विस्तार अत्यधिक हैं। यह तथ्य कि चीनी उत्पादक भारी अधिशेष होने के बावजूद इतने अधिक क्षमता विस्तार बनाए रख सकते हैं, पहले ही दर्शाता है कि ये क्षमता विस्तार निर्यातों की ओर ले जाने की संभावना है।
- xv. यूरोप के ईटीआई सोडा, जिस पर तर्किश कोंगलोमेरेट का नियंत्रण है, सिनर ग्रुप यूरोप में सोडा ऐश का सबसे बड़ा उत्पादक बनने का लक्ष्य रख रहा है। उसने दो प्रमुख विस्तार परियोजनाएं देखी हैं जिनमें वित्तीय और निर्माण संबंधी कारणों से विलंब हुआ है। तथापि, विस्तार परियोजनाएं अब पुनः प्रचालनात्मक हैं।
- xvi. विश्व में उत्पादकों के पास उनकी घरेलू मांग से अधिक क्षमताएं हैं जिनसे वे अपने उत्पाद विशेष रूप से अपनी जनशक्ति के कारण भारतीय बाजार में बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं।
- xvii. उत्पादक अपनी क्षमताओं का विस्तार करने की ओर अब भी देख रहे हैं। विशेष रूप से तुर्की, जो तुर्की से यूरोपीय संघ को संबद्ध सामानों का और प्रवाह करेगा। यूरोपीय संघ जो पहले ही भारत में पाटन कर रहा है, अपने कार्य को और गहन बनाएगा।
- xviii. संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन व्यापारिक रूप से वैश्विक रूप से संबद्ध सामानों के सबसे बड़े निर्यातक थे। रिपोर्ट दर्शाती है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन में मांग में गिरावट आई है। अत्यधिक आपूर्ति भी भारत जैसे उन देशों को ली जाएगी जिनमें मांग बढ़ रही है।
- xix. पाटित आयातों की मात्रा मानी गई पूरी क्षति अवधि में अत्यधिक थी।
- xx. क्षतिकारक निर्यातों और कीमत आकर्षक निर्यातों की मात्रा पूर्व में बहुत अधिक थी। यह हिस्सा 2015-16 तक कम हुआ और उसके बाद बढ़ रहा है।
- xxi. क्षतिकारक तथा कीमत आकर्षक निर्यातों की मात्रा भारत में खपत की तुलना में वर्तमान जांच की अवधि में काफी अधिक है तथा उसके बाद अनुपात जांच की अवधि के बाद बढ़ा है।
- xxii. भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता निम्नलिखित मानदंडों पर विचार करके निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है: घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत, वर्तमान कीमतें, जिन पर निर्यातक भारत को निर्यात कर रहे हैं, वर्तमान कीमतें, जिन पर निर्यातक कई अन्य देशों को निर्यात कर रहे हैं और अधिशेष उपयोग में न लाई गई क्षमताएं।
- xxiii. भारतीय बाजार अत्यधिक कीमत संवेदनशील है। ग्राहक अपनी खरीद का निर्णय बहुत अच्छी तरह विचार करके कीमत के अनुसार लेते हैं। प्रमुख ग्राहकों के साथ सभी वार्ताएं उद्योग तथा विदेशी उत्पादकों द्वारा उल्लिखित कीमत के आधार पर होती हैं। बाजार में संबद्ध देशों से कम कीमत के आयातों की उपलब्धता निश्चित रूप से घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी।
- xxiv. वर्तमान पाटनरोधी शुल्क वापस लिए जाने की स्थिति में और यदि घरेलू उद्योग आयात कीमतों पर बेचने के लिए बाध्य है तो घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में काफी गिरावट आएगी। निवेश पर आय और नकद लाभ में भी गिरावट आएगी।
- xxv. पूर्व प्राधिकारी की जांचों पर विश्वास किया गया था जिनमें प्राधिकारी ने यह निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित परीक्षण किए कि क्या पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने के बाद पाटन होने की संभावना है अथवा नहीं: जांच की अवधि के दौरान और जांच की अवधि के बाद भारत और अन्य तीसरे देशों को निर्यातों के संबंध में कीमत कटौती एवं क्षति मार्जिन; जांच की अवधि के दौरान और पिछले एक दशक में

तीसरे देशों को निर्यातों की मात्रा जो घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम कीमत पर थी, भारत को निर्यात कीमत, और क्या निर्यातों की यह मात्रा भारतीय मांग को ध्यान में रखते हुए काफी है। इन सभी छः परीक्षणों का उत्तर यह सुनिश्चित करने के लिए नकारात्मक होना चाहिए कि भारतीय बाजार विदेशी उत्पादकों को आकर्षित नहीं कर रहा है।

- xxvi. प्राधिकारी ने विगत में क्षति मार्जिन के सिद्धांत पर विश्वास किया है, परंतु अब ऐसा नहीं कर सकते। यदि क्षति मार्जिन नकारात्मक है तो उसके न होने की संभावना निर्धारित नहीं कर सकते। भारत को वर्तमान निर्यात यह निर्धारित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं कि क्या घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

- i. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा क्षति की तथाकथित संभावना का विश्लेषण नहीं किया जा सकता क्योंकि याचिकाकर्ता ने सभी अपेक्षित जांच की अवधि के बाद के आंकड़े नहीं दिए हैं।
- ii. पूर्व जांचों में पाटन की मौजूदगी मात्र निर्णायक समीक्षा का मूल नहीं है और भारत में पाटित आयातों की वृद्धि का स्पष्ट साक्ष्य होना चाहिए।
- iii. पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति पर पाटन और क्षति की संभावना का निर्धारण पाटित आयातों की वृद्धि की पूर्व प्रभावी दर, स्वतंत्र रूप से निपटान योग्य अथवा संबद्ध देशों में मौजूदा क्षमता में वृद्धि, कीमत न्यूनीकरण/ह्रास, तथा अन्य संगत मानदंडों सहित मालसूची के विश्लेषण पर निर्भर है। यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त आंकड़े हैं।
- iv. तुर्की क्षमताओं के संबंध में किया गया दावा असंगत है और किसी साक्ष्य से सत्यापनीय नहीं है।
- v. याचिकाकर्ताओं की न्यूनीकृत/ह्रास हुई बिक्री कीमत संबद्ध देशों की कीमत के कारण नहीं हो सकती। संबद्ध आयातों की कीमत का तथाकथित प्रभाव काफी होना चाहिए जो कि वर्तमान मामले में मौजूद नहीं है।
- vi. आईएचएस रिपोर्ट का उद्धरण एक सही उद्धरण के रूप में सत्यापनीय नहीं है। इसके अतिरिक्त, यदि पाकिस्तान निर्यातोन्मुख है अथवा पाकिस्तान में मांग-आपूर्ति का अंतराल है तो वह साक्ष्य नहीं है।
- vii. आईएचएस रिपोर्ट का वर्ष सत्यापनीय नहीं है।
- viii. आईएचएस रिपोर्ट के विश्लेषण पर यह सिद्ध है कि घरेलू बाजार में क्षमता का उपयोग काफी मात्रा तक किया जाता है जो यह सिद्ध करता है कि पाकिस्तान में मांग एवं आपूर्ति का कोई अंतराल नहीं है और पाकिस्तान के घरेलू बाजार में पूरी क्षमता का उपयोग किया जाता है।
- ix. चीन में क्षमता विस्तार के लिए दी गई तालिका अधिकृत नहीं है और सत्यापनीय नहीं है।
- x. यूरोप में ईटीआई सोडा से संबंधित सार्वजनिक पटल की सूचना 2015 से है। इसके अतिरिक्त, उनमें विस्तारण की योजना से संबंधित बात है।
- xi. याचिकाकर्ताओं द्वारा दिया गया कोई भी साक्ष्य संबद्ध देशों की निर्यातोन्मुखता नहीं दर्शाता।
- xii. संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन में मांग में गिरावट के संबंध में दावे सिद्ध नहीं हैं।
- xiii. यूरोप में जा रहे तुर्की निर्यातों और फिर यूरोप के भारत में पाटन करने के संबंध में दावे सिद्ध नहीं हैं और केवल अवधारणा है।
- xiv. तीसरे देशों में पाटन कर रहे चीन, यूरोपीय संघ, यूक्रेन और संयुक्त राज्य अमेरिका से काफी निर्यातों के दावे सत्यापनीय स्रोत से सिद्ध नहीं किए गए हैं।
- xv. कीमत आकर्षकता को वर्तमान वास्तविक मैट्रिक्स में उसके लिए साक्ष्य के अभाव में क्षति की संभावना का कारण नहीं माना जा सकता।
- xvi. भारत को संबद्ध देशों द्वारा किए गए निर्यातों के विरुद्ध संबद्ध देशों द्वारा किए गए निर्यातों के बीच उपयुक्त तुलना नहीं की जा सकती।
- xvii. उत्पाद एवं भारतीय बाजार की कीमत संवेदनशीलता के संदर्भ में घरेलू उद्योग की सुभेद्यता से संबंधित दावे सिद्ध नहीं हैं।

- xviii. संभावना का निर्धारण एक अनुकूल निर्धारण है। याचिकाकर्ताओं का पाटनरोधी शुल्क जारी रखने का प्रस्ताव उनके लिखित अनुरोध के पैरा 122-124 में उल्लिखित एक स्थिति होने पर भी सही है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध और पाटनरोधी नियमावली के उल्लंघन में है।
- xix. कारणात्मकता "घरेलू उद्योग को पाटन एवं क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना" भाषा में केंद्रीय है।
- xx. डीसीडब्ल्यू लि. ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 में सूचित किया है कि आयातों से खतरा नहीं है और कंपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सक्षम है।
- xxi. याचिकाकर्ताओं को हुई तथाकथित क्षति उनकी अनियोजित बंदी का परिणाम है और संबद्ध आयातों का प्रभाव नहीं है।
- xxii. यहां परिकलित आयातों की पहुँच कीमत वर्तमान पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बिना है और इस प्रकार पाटनरोधी शुल्क की वापसी से स्थिति बदलेगी नहीं तथा इसीलिए क्षति की संभावना नहीं है।
- xxiii. जांच के अवधि के बाद के आंकड़ों का प्रयोग संभावना की जांच करने के लिए किया जा सकता है न कि ऐतिहासिक आंकड़ों की।
- xxiv. उपर्युक्त पैराओं में उल्लिखित संभावना के दावों से संबंधित आंकड़े याचिका में दिए गए आंकड़ों से भिन्न हैं।
- xxv. घरेलू उद्योग का निष्पादन सभी मापदंडों में असाधारण रूप से अच्छा रहा है और क्षति की संभावना भ्रामक दावों पर आधारित है।
- xxvi. आयात केवल क्षतिरहित कीमत पर मांग और आपूर्ति के बीच अंतराल को पूरा कर रहे हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित मात्रा में वृद्धि से स्वतः ही आयातों के लिए मांग में कमी हो जाएगी।
- xxvii. घरेलू उद्योग के 80 प्रतिशत बाजार हिस्से की तुलना में आयातों का वर्तमान हिस्सा केवल बाजार हिस्से के 20 प्रतिशत है।
- xxviii. आयातों से कीमत कटौती स्तरों पर भी घरेलू उद्योग पर कोई क्षति कारक प्रभाव नहीं बना है।
- xxix. घरेलू उद्योग नियोजित पूंजी पर आय के बहुत ही उच्च स्तर पर प्रचालन कर रहा है और इस अधिक नियोजित पूंजी पर आय को संरक्षण प्रदान करना पाटनरोधी शुल्क का प्रयोजन नहीं है।
- xxx. पाटित आयातों में तथाकथित वृद्धि से घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
- xxxi. तथाकथित कीमत कटौती का घरेलू उद्योग के वित्तीय निष्पादन पर कोई प्रभाव नहीं था।
- xxxii. संबद्ध देशों में उपलब्ध अधिशेष क्षमताओं का इस मामले में कोई प्रभाव नहीं है। भारतीय उद्योग ने मौखिक सुनवाई के दौरान प्रकट किए गए और घरेलू उद्योग के लिखित अनुरोधों में दिए गए अनुसार *** लाख टन के आसपास वार्षिक क्षमता बढ़ाई है। घरेलू उद्योग के लिखित अनुरोधों के अनुसार *** लाख टन वार्षिक क्षमता बढ़ाए जाने की योजना है। भारतीय उद्योग की सशक्त उपस्थिति से संबद्ध देशों में अधिशेष क्षमताओं का भारत में प्रभाव बाधित होगा।
- xxxiii. यदि कीमत कटौती का कोई वास्तविक हानिकारक प्रभाव था तो घरेलू उद्योग अपनी बिक्री बढ़ाने में सक्षम नहीं होता।
- xxxiv. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता बढ़े हुए निर्यातों के बावजूद जांच की अवधि के दौरान लगभग तीन गुना बढ़ी।
- xxxv. संबद्ध सामानों के आयातों में वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग ने अतिरिक्त क्षमताएं संस्थापित कीं और उन पर बहुत अच्छी आय अर्जित की।
- xxxvi. यह बताने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि यदि पाटनरोधी शुल्क हटाया जाता है तो उपभोक्ता आयातों की ओर जाएंगे।
- xxxvii. संबद्ध सामानों के डिटर्जेंट तथा ग्लास उद्योग में प्रयोक्ता हैं जो व्यापक स्तर पर संबद्ध सामानों का प्रयोग करते हैं।

- xxxviii. अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपए का मूल्यहास होने से संबद्ध सामानों का आयात करना अत्यधिक महंगा हुआ है। प्रयोक्ता उद्योग संबंधी सामानों की स्थानीय आपूर्ति पर विश्वास करना जारी रखेंगे और संबद्ध सामानों का आयात केवल तभी करेंगे जब आपूर्ति की कमी हो।
- xxxix. परिवहन लागत एनआईपी के निर्धारण में शामिल नहीं की जा सकती क्योंकि कानून उसका समर्थन नहीं करता। परिवहन लागत मूल जांच में भी एनआईपी के निर्धारण में शामिल नहीं की गई थी। यद्यपि, भारत ने डब्ल्यूटीओ में इसकी वकालत की थी, तथापि, अभी तक डब्ल्यूटीओ सदस्यता द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया है।
- xl. कीमत कटौती और क्षति मार्जिन केवल भारत और उस आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। घरेलू उद्योग का यह दावा कि कीमत कटौती और क्षति मार्जिन का निर्धारण लेन-देन स्तर पर केवल उन लेन-देनों के लिए किया जाना चाहिए जहां कीमत कटौती और क्षति मार्जिन सकारात्मक है, गलत और गैर-कानूनी है। इससे शून्यकरण करने की परिपाटी बनेगी जिसे डब्ल्यूटीओ द्वारा गैर-कानूनी माना गया है।
- xli. कोई भी अन्य भारतीय उत्पादक उनके द्वारा किए गए भारी निवेशों के बावजूद आगे नहीं आया है और पाटनरोधी शुल्क जारी रखने के लिए नहीं कहा है।
- xlili. यह सिद्ध करने के लिए कोई भी विश्वसनीय स्रोत नहीं बताया गया है कि चीन जन. गण. संबद्ध सामानों के लिए और अधिक क्षमताएं बढ़ाएगा।
- xliv. कीमत न्यूनीकरण/हास के संबंध में जांच की अवधि के बाद के कोई आंकड़े नहीं दिए गए हैं, न कि इसके संबंध में कोई महत्वपूर्ण अनुरोध किए गए हैं।
- xlv. संबद्ध आयातों की कीमत का तथाकथित प्रभाव काफी होना चाहिए जो वर्तमान मामले में मौजूद नहीं है, जैसा कि प्रस्तुत किए गए आंकड़ों से सिद्ध है।
- xlv. संबद्ध देशों में मालसूची स्तर के संबंध में जांच की अवधि के बाद के कोई आंकड़े नहीं दिए गए हैं।
- xlvi. पूर्व जांचों में केवल पाटन की मौजूदगी निर्णायक समीक्षा का मूल नहीं है और भारत में पाटित आयातों की वृद्धि का स्पष्ट साक्ष्य होना चाहिए।
- xlvi. पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने पर पाटन और क्षति की संभावना का निर्धारण मुक्त रूप से निपटान योग्य पाटित आयातों की वृद्धि की पूर्व प्रभावी दर अथवा संबद्ध देशों में विद्यमान क्षमता में वृद्धि, कीमत न्यूनीकरण/हास और अन्य संगत मानदंडों सहित मालसूची के विश्लेषण पर निर्भर है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

80. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II(vii) के अनुसार, वास्तविक क्षति के खतरे से संबंधित मानदंडों पर विचार करते हुए क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना की जांच की। पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के खंड (vii) के तहत संभावना के पहलू पर विचार करते हुए प्राधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कारकों पर विचार किया।

1. वर्तमान एवं सतत आयात

81. प्राधिकारी ने जांच की अवधि और जांच की अवधि के बाद की अवधि सहित क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देशों से भारत को संबद्ध सामानों के निर्यातों की मात्रा का विश्लेषण किया है। चीन जन. गण., यूरोपीय संघ, केन्या, पाकिस्तान और यूक्रेन से आयात जांच की अवधि के दौरान अपाटित थे। प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन. गण. और केन्या से आयातों में जांच की अवधि के दौरान गिरावट आई है जबकि यूरोपीय संघ, पाकिस्तान और यूक्रेन से आयातों में जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात जांच की अवधि के दौरान पाटित थे। इन दोनों देशों से आयातों में वृद्धि हुई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि सभी संबद्ध देशों से निर्यातों की मात्रा भारत को साथ लेकर 2013-14 में *** मी. टन से बढ़कर जांच की अवधि के दौरान *** मी. टन हो गई। तथापि, जांच की अवधि के बाद की अवधि 2017-18 में सभी संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों में *** मी. टन की गिरावट आई जो 2.5 प्रतिशत की गिरावट है। पूर्व के भागों में जैसा कि सिद्ध किया गया है, संबद्ध देशों से अधिकतर आयात अपाटित थे, घरेलू उद्योग के निष्पादन में सभी आर्थिक मानदंडों के संबंध में सुधार आया, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत क्षति की अवधि में बढ़ी और बिक्री लागत तथा क्षति रहित कीमत से अधिक रही। वर्तमान में

कोई पाटन तथा क्षति नहीं है और विश्लेषण दर्शाता है कि पाटन एवं क्षति के बार-बार होने अथवा जारी रहने की संभावना सिद्ध नहीं है।

2. अधिशेष क्षमताएं

82. वास्तविक क्षति का खतरा सुनिश्चित करने के लिए मापदंड के लिए भारतीय बाजार में निपटान योग्य मात्रा के परिवर्तन की संभावना का पता लगाने के लिए मौजूदा अधिशेष क्षमताओं और क्षमता अभिवृद्धि, यदि कोई है, का मूल्यांकन करना अपेक्षित है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि संबद्ध देशों में उत्पादकों को पहले ही काफी अधिशेष क्षमताओं का सामना करना पड़ रहा है और ये उत्पादक अधिसंख्य देशों को उत्पाद का निर्यात कर रहे हैं, जिसका काफी बड़ा भाग उस कीमत पर निर्यात किया जा रहा है जो भारत के संबंध में कीमतों से कम है। इस प्रकार, यह पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने की स्थिति में भारत को ये निर्यात भेजे जाने की संभावना दर्शा रहा है।
83. यद्यपि, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने मौजूदा अधिशेष क्षमताओं तथा परिणामस्वरूप भारतीय बाजार में बढ़े हुए पाटन निर्यातों की संभावना के संबंध में कोई सत्यापनीय साक्ष्य तथा सूचना नहीं दी है। तथापि, घरेलू उद्योग ने याचिका में आईएचएस केमिकल जनरल से ली गई सूचना दी है जिसमें संबद्ध देशों ने सोडा ऐश के विनिर्माण से संबंधित सूचना अर्थात् मौजूदा क्षमता, मौजूदा उत्पादन, अनुपयुक्त क्षमता और क्षमता विस्तार आदि से संबंधित सूचना दी गई है। निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट होगा कि लगभग *** मिलियन मी. टन की भारतीय मांग के विरुद्ध संबद्ध देशों में अनुपयुक्त क्षमता लगभग *** मिलियन मी. टन (भारत में मांग का *** प्रतिशत) है और क्षमता विस्तार (पहले ही किया गया तथा आगे होने वाला) *** मिलियन मी. टन (भारत में मांग का *** प्रतिशत) तक है। तथापि, यह सिद्ध नहीं है कि संबद्ध देशों में ऐसी कोई तथाकथित अधिशेष क्षमताएं पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने पर भारत को भेजी जाएंगी।

विवरण	यूओएम	संबद्ध देश					
		चीन	संयुक्त राज्य अमेरिका	यूरोपीय संघ	पाकिस्तान	ईरान	कुल
मौजूदा क्षमता	मी. टन	***	***	***	***	***	***
मौजूदा उत्पादन	मी. टन	***	***	***	***	***	***
अनुपयुक्त क्षमता	मी. टन	***	***	***	***	***	***
क्षमता विस्तार	मी. टन	***	***	***	***	***	***

3. मालसूची स्तर

84. संबद्ध देशों में उत्पादकों के पास उपलब्ध मालसूची स्तर विदेशों उत्पादक (उत्पादकों)/ निर्यातक (निर्यातकों) द्वारा प्रभावला का उत्तर प्रस्तुत न किए जाने के मद्देनजर सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

4. कीमत न्यूनीकरण और कीमत ह्रास

85. घरेलू उद्योग की बिक्री लागत आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान कम हुई। घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत भी क्षति अवधि के दौरान बढ़ी। चीन जन. गण., यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका से आयातों का पहुँच मूल्य आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान बढ़ा है। जांच की अवधि के दौरान केन्या और पाकिस्तान से आयातों का पहुँच मूल्य कुल मिलाकर समान रहा है। ईरान और यूक्रेन से आयातों के पहुँच मूल्य में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान गिरावट आई है। पूर्व के भागों में जैसा कि सिद्ध किया गया है, संबद्ध देशों से आयातों के कारण कोई कीमत न्यूनीकरण तथा कीमत ह्रास नहीं है।

5. वर्तमान पाटन मार्जिन का स्तर

86. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मूल जांच में पाटन मार्जिन सकारात्मक था। तथापि, वर्तमान निर्णायक समीक्षा में चीन जन. गण., यूरोपीय संघ, केन्या, पाकिस्तान और यूक्रेन से आयातों के लिए जांच की अवधि के दौरान नकारात्मक/न्यूनतम है।
87. उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने की स्थिति में पाटन एवं क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की कोई संभावना नहीं है।

ढ. प्रकटन पश्चात विवरण**याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए अनुरोध**

- i. याचिकाकर्ताओं ने प्राधिकारी द्वारा भेजे गए पत्रों की अगोपनीय पाठ की प्रति, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तरों की प्रति, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों, प्रत्युत्तर में किए गए अनुरोधों की प्रति और सामान्य मूल्य के प्रकटन का अनुरोध किया है ताकि वे सार्थक निष्कर्ष पर पहुंचने में सक्षम हो सकें।
- ii. पाटनरोधी जांचों के समाप्त होने पर निश्चयात्मक उपायों को लागू करने के उद्देश्य से, जांच करने वाले प्राधिकारी को निश्चित रूप से पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध का पता लगाना चाहिए।
- iii. जांच परिणाम के निहितार्थ "आवश्यक तथ्यों" और पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध तथा पाटन एवं क्षति की संभावना के निर्धारण के संबंध में निष्कर्ष निश्चयात्मक उपायों को लागू करने के लिए इस निर्णय का आधार बनते हैं और उन्हें अनुच्छेद-6 के अनुसार सभी हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट किया जाना चाहिए ताकि वे उस पर टिप्पणी कर सकें।
- iv. प्राधिकारी ने विभिन्न आर्थिक मापदंडों जैसे उत्पादन, बिक्री और क्षमता का उपयोग आदि पर वर्ष दर वर्ष प्रचलित प्रवृत्ति को ही उपबलध कराया है।
- v. क्षति संबंधी इन मापदंडों के संबंध में प्राधिकारी का निष्कर्ष "आवश्यक तथ्य" होता है।
- vi. इस तथ्य के संबंध में निष्कर्ष जिसे निर्णायक समीक्षा जांच में निश्चयात्मक उपायों को लागू करने के उद्देश्य से हल किया जाना चाहिए (क) पाटन (ख) क्षति (ग) कारणात्मक संबंध (घ) पाटन के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना (च) क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होना हो।
- vii. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पाटन और क्षति के फिर से होने अथवा जारी रहने की संभावना के संबंध में तथ्यों का उल्लेख नहीं किया है। प्रकटन विवरण नियम 16 के अनुसार आवश्यक तथ्यों को पर्याप्त रूप से प्रकट नहीं करता है।
- viii. क्षति के फिर से होने की संभावना के संबंध में, प्रकटन विवरण में केवल वे मानदंड अथवा सूचना अथवा सत्यापित आंकड़े हैं जो इन तथ्यों को सिद्ध किए जाने से संबंधित हैं।
- ix. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत अथवा पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए निर्यातकों द्वारा दी गई सूचना "आंकड़े/सूचना" नहीं हैं जबकि सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन "तथ्य" हैं।
- x. इस प्रकार का कोई प्रकटन विवरण किसी हितबद्ध पक्षकार को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा विचाराधीन उन आवश्यक तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने में सक्षम नहीं बनाएंगे।
- xi. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह प्रकट नहीं किया है कि क्या अथवा पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक नहीं है और यह कि घरेलू उद्योग के सभी मानदंडों में सुधार हुआ है बल्कि उसमें यह स्पष्ट नहीं किया है कि क्या पाटन के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की कोई संभावना है।
- xii. प्राधिकारी ने प्रकटन का अनुरोध करते हुए 27 नवंबर, 2018 से 30 नवंबर, 2018 के बीच प्राधिकारी को घरेलू उद्योग द्वारा किए गए विभिन्न पत्राचारों के बावजूद केवल एनआईपी के निर्धारण और सभी पक्षकारों द्वारा दिए गए लिखित अनुरोधों के बारे में जानकारी दी है।
- xiii. विचाराधीन उत्पाद डायसोटिडियम कार्बोनेट है जिसे सोडा ऐश के रूप में भी जाना जाता है। वर्तमान जांच में उत्पाद का कार्यक्षेत्र वहीं है जिसे संबंधित उत्पाद के मूल जांच में पहले ही परिभाषित किया गया था।
- xiv. प्राधिकारी ने इस तथ्य पर टिप्पणी करने से अपने आप को रोक लिया है कि क्या अथवा नहीं घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद विचाराधीन उत्पाद की एक समान वस्तु है।
- xv. टाटा कैमिकल का कीनियां, यू एस और यूरोप में संबंधित उत्पादक है, कीनियां की और अमेरिका की कंपनियां टाटा कैमिकल की सहायक कंपनियां हैं और इन्होंने भारत में इन वस्तुओं का निर्यात किया है। कीनियां से आयातों की मात्रा बहुत अधिक थी और इसलिए टाटा कैमिकल एक अपात्र घरेलू उद्योग है।
- xvi. मै. डीसीडब्ल्यू ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का न तो आयात किया है और न ही यह संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के किसी आयातकों अथवा निर्यातकों से संबंधित है।

- xvii. मै. निरमा लिमिटेड ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है। हालांकि यूएसए ने उनकी संबंधित कंपनी में भारत में संबद्ध वस्तुओं का निर्यात 2014-15 और 2015-16 के दौरान किया था। यूएसए ने संबंधित कंपनी में जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं का निर्यात नहीं किया।
- xviii. किसी भी अन्य भारतीय उत्पादक ने याचिकाकर्ताओं ने आधार का विरोध नहीं किया है।
- xix. प्राधिकारी ने सही रूप में यह माना है कि याचिकाकर्ता भारतीय पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5(3) के संबंध में आधार की आवश्यकता को पूरा करता है।
- xx. प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और जहां भी संभव हुआ इस प्रकार की सूचना का अगोपनीय पाठ स्वीकार किया है और उसे सार्वजनिक फाइल में रख दिया है।
- xxi. अनेक मुद्दों जिनका उल्लेख नीचे किया गया है, पर विचार पाटन एवं क्षति की संभावना के संबंध में मुद्दों के रूप में और नकि विविध अनुरोधों के भाग के रूप में विचार किया जाना चाहिए।
- क. वर्तमान पाटनरोधी शुल्क को हटाए जाने के सतत पाटन के जारी रहने अथवा उसके बढ़ जाने तथा घरेलू उद्योग को क्षति से फिर से होने की संभावना है।
- ख. सोडा ऐश का आयात वर्तमान में पाटनरोधी शुल्क के अध्यक्षीन है। बावजूद उसके उनका निर्यात भारत में संबद्ध देश से पाटित कीमतों पर किया जा रहा है।
- ग. संबद्ध निर्यातक घरेलू उद्योग के लिए उचित कीमत से कम कीमत पर अनेक अन्य देशों को इस उत्पाद का निर्यात कर रहे हैं।
- घ. अगस्त, 2018 और सितंबर, 2018 के महीनों में आयात में जुलाई, 2018 से 23 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है।
- ङ. चीन ने जुलाई में 54 प्रतिशत की तुलना में अगस्त में 1718 प्रतिशत तक संबद्ध वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि की है।
- च. यूएसए ने आयातों की मात्रा में 796 प्रतिशत तक वृद्धि की है।
- छ. पूर्व की जांच में निर्धारित और वर्तमान जांच में प्रस्तावित पाटन मार्जिन बहुत अधिक हैं और वे स्पष्ट रूप से पाटनरोधी शुल्क के समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन और परिणामी क्षति की संभावना को दर्शाते हैं।
- ज. पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में, इन निर्यातकों को घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से को लेते हुए भारत में विचाराधीन उत्पाद को पाटित करने के लिए अपेक्षाकृत अधिक अवसर प्राप्त होगा।
- झ. आयात की मात्राओं में जांच की अवधि में और पाटित कीमतों पर वृद्धि हुई है। ये आयात संभवतः पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में बहुत अधिक मात्रा में पाटित कीमत पर हो सकते हैं।
- ञ. आयातों का ह्रास/न्यूनीकरण प्रभावों को पाटनरोधी शुल्क के होने के कारण भारतीय बाजार में नहीं देखा गया था। आयात की कीमत में बहुत गिरावट होने लगी है और इसका घरेलू उद्योग की कीमतों पर उस स्थिति में ह्रासकारी प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है। जैसे ही टर्की की नई क्षमताओं का व्यापारीकरण शुरू हुआ, जो वैश्विक मांग आपूर्ति के परिदृश्य को खतरा पहुंचा रहा है।
- ट. घरेलू उद्योग संबद्ध उत्पादकों के पास मालसूची के अवसरों का पता नहीं लगा सका। संबद्ध देशों के पास उपलब्ध भारी मात्रा में क्षमताओं को देखते हुए इसका उचित रूप से उल्लेख किया जा सकता है कि जब कभी बाजार उपलब्ध हो, उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है।
- ठ. यूएसए और चीन संबद्ध वस्तुओं का क्रमशः पहला और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक रहा है।
- ड. टर्की के निर्यातकों के पास *** मी.ट. क्षमताएं हैं जिसमें से उनकी मांग लगभग *** मिलियन मी.ट. है जो *** मी.ट. को निर्यात के लिए उपयुक्त होता है। इन वस्तुओं को यूरोप भेजा जाता है और वहां से उन्हें भारत में भेजा जाता है।
- ढ. चीन, यूरोपीय संघ, यूक्रेन और यूएसए द्वारा तीसरे देशों में ही पाटन किया जा रहा है। लेनदेनवार विश्लेषण पिछले एक दशक के दौरान किए गए आयातों के लिए किया गया है।
- ण. कीमत आकर्षक निर्यातों की मात्रा भारत में खपत की तुलना में जांच की वर्तमान अवधि में बहुत अधिक है और उसके बाद इस मात्रा में जांच की अवधि के बाद की अवधि में वृद्धि हुई।

- xxii. घरेलू उद्योग के अनुरोधों को उपयुक्त तरीके से नहीं रखने के फलस्वरूप इन अनुरोधों की उपयुक्त जांच नहीं हो सकती है।
- xxiii. प्राधिकारी ने केवल विभिन्न उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के आदेशों का उल्लेख किया है परंतु वर्तमान जांचों के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी की टिप्पणियों का कोई उल्लेख नहीं किया है।
- xxiv. घरेलू उद्योग की चिंता इस तथ्य के बारे में है कि घरेलू उद्योग द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों पर उचित विचार किया जाना चाहिए।
- xxv. प्रकटन विवरण में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनेक अनुरोध किए गए हैं जिन्हें लिखित अनुरोधों पर सुनवाई अथवा सुनवाई के बाद के चरण तक अवगत नहीं कराया गया था।
- xxvi. हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया था कि किसी गैर निर्यातक औद्योगिक प्रयोक्ता के लिए, प्रश्नावली का प्रपत्र लागू नहीं है। यह केवल उन सीमाओं तक लागू होता है जो फरवरी, 2018 के बाद हुआ है। कानून के अंतर्गत अपेक्षाएं इस व्यापार सूचना के जारी किए जाने के पूर्व अथवा उसके बाद शुरू की गई जांच के लिए अलग-अलग नहीं हो सकती है।
- xxvii. सही रूप में इस कारण से ऐसा हुआ है कि इस मुद्दे को जैसे ही व्यापार सूचना जारी की गई थी, पूर्व में निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष उठाया गया था। प्राधिकारी को हितबद्ध पक्षकारों को व्यापार सूचना के अनुसार चालू मामलों में संगत सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश देने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था।
- xxviii. ऐसी प्रतीत होता है कि न तो हितबद्ध पक्षकारों को चालू मामलों में सूचना उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है और न ही हितबद्ध पक्षकारों ने व्यापार सूचना का ध्यान रखा है।
- xxix. निर्दिष्ट प्राधिकारी के रिकॉर्ड पर सूचना अनेक जांचों में व्यापार सूचनाओं के अनुरूप नहीं हैं।
- xxx. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि वर्तमान मामले का जटिल इतिहास में इस जांच में किसी समय सीमा के बारे में अस्पष्टता बढ़ा दी है।
- xxxi. याचिकाकर्ताओं ने दिनांक 22.7.2017 से अंतिम जांच परिणामों और दिनांक 22.7.2017 के निरस्तीकरण आदेश को याचिका और संबद्ध मामलों के रूप में चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने दिनांक 31.7.2017 के आदेश के द्वारा केन्द्र सरकार को दिनांक 22.7.2017 से अंतिम जांच परिणामों और दिनांक 22.7.2017 के निरस्तीकरण आदेश पर कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है।
- xxxii. दिनांक 31.7.2017 के आदेश के बल पर, वर्तमान मामले के वापस लिए जाने संबंधी आदेश "अब लागू नहीं" की और वास्तव में इस जांच को पूर्व स्थिति में ला दिया गया था।
- xxxiii. निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह अपेक्षित था कि वे निर्णायक समीक्षा को पूरा करने के लिए यह जांच करें।
- xxxiv. उच्च न्यायालय ने दिनांक 11.6.2018 के निर्णय और आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर किए गए संबद्ध रिट याचिका को मध्यावधि समीक्षा में दिनांक 22.7.2017 के अंतिम जांच परिणामों को रद्द करने और निर्णायक समीक्षा को रद्द करते हुए दिनांक 22.7.2017 के आदेश के द्वारा इन जांच परिणामों को रद्द करने की अनुमति दी और प्राधिकारी को निर्णायक समीक्षा को कानून के अनुसार इसके सार्थक परिणाम तक लाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया।
- xxxv. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि इस जांच को कानून की किसी प्रक्रिया का पालन करने के बाद किया जाना था और इसके बारे में निष्कर्ष निकाला जाना था।
- xxxvi. हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया कि कोई भी शुल्क लागू नहीं है क्योंकि प्राधिकारी ने केन्द्र सरकार पर शुल्कों की अवधि बढ़ाए जाने के लिए कोई आदेश लागू नहीं किया। प्राधिकारी के लिए ऐसा कोई अवसर नहीं है जिससे कि वह केन्द्र सरकार को अपनी सिफारिशें दे सकें।
- xxxvii. इसके अलावा, उन्होंने यह दावा किया कि राजस्व विभाग फोरेच इंडिया लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी एवं अन्य के फैसले के संबंध में शुल्कों को नहीं बढ़ा सकता है क्योंकि कोई शुल्क मौजूद नहीं है। यदि नियम 18(1) के अंतर्गत अवधि में कोई रूकावट हो तो कोई भी प्राधिकारी शुल्क नहीं बढ़ा सकता है। उक्त निर्णय को रोक दिया गया है और इस कारण से यह प्राधिकारी पर बाध्यकारी नहीं है।

- xxxviii. वर्तमान जांच उच्च न्यायालय के दिनांक 15.6.2018 के निर्णय और आदेश के अनुसार दिए गए निदेश के अनुसार की जा रही है जिसमें इस नियमावली के नियम 17(1)(क) के प्रथम परंतुक के संबंध में 6 महीने तक निर्णायक समीक्षा जांच को समाप्त करने के लिए अवधि में विस्तार किया। हितबद्ध पक्षकारों के तर्क का आशय यह है कि उच्च न्यायालय का आदेश गैर कानूनी है।
- xxxix. दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती दी जा रही है। उक्त आदेश के विरुद्ध स्थगन आवेदन भी दायर किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने मौखिक रूप से यह टिप्पणी करते समय दिनांक 9 जुलाई, 2018 के अंतरिम आदेश के द्वारा सूचना जारी की कि चूंकि सरकार इस अधिसूचना को वापस नहीं ले रही है अतः इस पर रोक आवश्यक नहीं है। केन्द्र सरकार ने आज की तारीख तक पाटनरोधी शुल्क को वापस नहीं लिया है।
- xl. उच्च न्यायालय के दिनांक 11.6.2018 के आदेश में इसे बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि इस जांच को कानून के अनुसार समाप्त किया जाना था जिसका स्पष्ट अर्थ यह है कि इसमें शामिल सभी हितबद्ध पक्षकारों को इस जांच में भाग लेना चाहिए था और संबंधित सूचना प्रस्तुत करनी चाहिए थी। हितबद्ध पक्षकार यह दावा नहीं कर सकते कि उन्हें जांच के अधीन अपने दायित्वों की जानकारी नहीं थी।
- xli. घरेलू उद्योग द्वारा निर्धारित पाटन मार्जिन और प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाटन मार्जिन के बीच बहुत बड़ा अंतर है।
- xlili. प्राधिकारी ने यह माना है कि चीन को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा नहीं दिया जा सकता है क्योंकि जांच की अवधि का एक हिस्सा दिसंबर, 2016 से पूर्व आता है। किसी भी उत्तरदायी उत्पादक द्वारा दायर की जा रही किसी बाजार प्रश्नावली/उत्तर के अभाव में, चीन को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। किसी भी संबद्ध देश से किसी उत्तर देने वाले निर्यातक/उत्पादक के न होने की स्थिति में प्राधिकारी ने उसे गैर सहयोगी के रूप में माना है।
- xlvi. यूएसए, यूरोपीय संघ और ईरान में सामान्य मूल्य के निर्धारण के उद्देश्य से, घरेलू उद्योग ने आईएसएस कैमिकल रिपोर्टों से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत किए जिसका उपयोग जिसे अपनाया जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अनेक मामलों में स्वीकार किया गया है क्योंकि वे संबंधित क्षेत्रों में प्रचलित कीमतों की एक सही तसवीर प्रस्तुत करते हैं।
- xlii. इन नियमों में घरेलू कीमत और उत्पाद की लागत के बीच एक स्पष्ट क्रम प्रस्तुत किया है। इस अधिनियम की धारा 9 क(1)(ग) में इस प्रकार के क्रम का स्पष्ट प्रावधान है। इसे वाणिज्य मंत्रालय बनाने में, हलडोर टोपसा के मामले में भी सिद्ध किया गया था।
- xliii. उच्चतम न्यायालय ने इसे स्पष्ट और अनिवार्य बनाया है कि यदि संबद्ध देश में कीमत के संबंध में सूचना उपलब्ध हो, तब प्राधिकारी सामान्य मूल्य के निर्धारण के एक आधार के रूप में उत्पादन की लागत का विकल्प नहीं चुन सकते हैं।
- xliiii. आईएसएस कैमिकल वीकली में वैश्विक आधार पर ऐतिहासिक और पूर्वानुमान लगाई गई कीमत का प्रावधान है। प्रत्येक महीना यह बाजार का सारांश और बाजार के आंकड़ों के पूरक को प्रकाशित करता है। बाजार के सारांश में वर्तमान बाजार स्थिति तथा कीमत और मार्जिन इतिहास एवं पूर्वानुमानों का विश्लेषण शामिल होता है।
- xliii. आईएसएस कैमिकल की रिपोर्ट को अधिकांशतः अत्यधिक अनुभव वाले शोधकर्ताओं द्वारा पढ़ा जाता है। यह प्रमाणिक है और इसकी मान्यता है तथा इसमें प्रकाशित आंकड़ों और सूचना की विश्वसनीयता एवं उपयोगिता है।
- xliiii. यह सूचना जांच को आरंभ किए जाने पर की गई थी और इसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया गया था। इस सूचना पर किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा किसी प्रकार का संदेह व्यक्त नहीं किया गया है अतः इन व्यापार पत्रिका की कीमतों को नहीं मानना और उत्पादन की लागत को मान लेना उपयुक्त नहीं है।
- xliii. कीनिया और पाकिस्तान में सामान्य मूल्य के निर्धारण के उद्देश्य से, नकदी, कीनिया में टाटा कैमिकल्स प्लांट की वार्षिक रिपोर्टों से संबंधित साक्ष्यों को आईसीएल, पाकिस्तान की वार्षिक रिपोर्ट पर याचिकाकर्ताओं द्वारा विचार किया गया था क्योंकि वे उन संबंध बाजारों में सामान्य मूल्य के संबंध में सबसे अधिक प्रतीक तसवीर उपलब्ध कराएंगे।

- I. सामान्य मूल्य का निर्धारण इस तथ्य की उपेक्षा करते हुए किया गया है कि सूचना और कम उपयुक्त सूचना का उपयोग करना और वह भी उसे पूर्ण रूप से प्रकट किए बिना की गई है। इस सूचना को अस्वीकार करने और याचिकाकर्ताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्य को न मानने के लिए प्रकटन विवरण में कोई कारण दर्ज नहीं किया गया है।
- ii. ऐसी स्थिति में हां निर्यातकों में असहयोग को अपनाया है और किसी हितबद्ध पक्षकारों से इस पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई है, निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए अपेक्षित है कि वे नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना के रूप में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए दावे के साथ आगे की कार्रवाई करें
- iii. प्राधिकारी ने केवल “सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना” का ही संदर्भ लिया है। हालांकि इस उन पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है कि वर्तमान मामले में “सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना” का आधार क्या है।
- iiii. चीन जन गण के लिए निर्यात कीमत की गणना के मामले में मूल्यवर्धित कर के समायोजनों पर अवश्य ही विचार किया जाना चाहिए।
- liv. संबद्ध देशों में वास्तविक रूप से प्रचलित कीमतें सकारात्मक पाटन मार्जिन को दर्शाती हैं। चुनौती के अधीन मध्यावधि समीक्षा अंतिम जांच परिणाम (जिसके बारे में सहयोगी उत्पादकों द्वारा उत्तर प्रस्तुत किए गए थे) में निर्धारित पाटन मार्जिन में न्यूनतम से काफी अधिक स्तर पर सकारात्मक मार्जिन को दर्शाया। सामान्य मूल्य का निर्धारण गलत तरीके से किया गया है।
- lv. उक्त जांच में जांच की अवधि 2014-15 थी। प्राधिकारी ने जांच की अवधि के बाद की अवधि के लिए पाटन मार्जिन का भी निर्धारण किया था जो अप्रैल, 2015 से सितंबर, 2015 थी और वह भी सकारात्मक थी।
- lvi. यूएस के उत्पादकों को विशाल प्राकृतिक संसाधनों के कारण लाभ मिलता है और इसलिए उत्पादन की उनकी लागत भारत में उपयोग किए जाने वाले सिंथेटिक सामग्रियों की तुलना में कम होगी। यू एस के निर्यातक पाटन प्रथाओं का सहारा ले रहे हैं क्योंकि वे भारत में उनके सामान्य मूल्य के बहुत कम कीमत पर निर्यात कर रहे हैं जिसके कारण आयातों में अचानक वृद्धि हो रही है।
- lvii. कम लागत के लाभ का आशय यह नहीं हो सकता है कि पाटन का सहारा लिया गया है और कम लागत का अभिप्राय “पाटन के नहीं होने” से नहीं हो सकता।
- lviii. पूर्व में दायर किए गए अनुरोध यह दर्शाते हैं कि याचिकाकर्ताओं ने यह स्वीकार किया है कि घरेलू उद्योग का के कार्य निष्पादन में वर्तमान अवधि में गिरावट नहीं आई है बल्कि लागू पाटनरोधी शुल्क के कारण इसमें सुधार हुआ है।
- lix. दुलाई लागत संबद्ध वस्तुओं के मामलों में उत्पादन की लागत का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है क्योंकि सोडा ऐश के भारतीय उत्पादक गुजरात राज्य में स्थिति हैं (कच्चे माल की उपलब्धता के कारण) और यह बिक्री पूरे भारत में की जानी होती है।
- lx. संबद्ध वस्तु तुलनात्मक रूप से कम कीमत के उत्पाद हैं। इस उत्पाद की प्रति मी.ट. दुलाई लागत का आपतन बहुत अधिक होता है जब इसकी तुलना इस उत्पाद की बिक्री कीमत से की जाती है।
- lxi. घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत की तुलना आयातों की पहुंच कीमत से दुलाई लागतों को जोड़ने के बाद ही की जानी चाहिए।
- lxii. इस नियमावली में घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के निर्धारण का एक निर्धारित पद्धति का प्रावधान नहीं है। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि कोई प्रथा कानून बन गया है और यह कि हरेक स्थिति में यह उपयुक्त माना जाएगा।
- lxiii. सोडा ऐश के उपभोक्ता घरेलू उद्योग की कीमतों का समझौता करते समय घरेलू उद्योग की कारखानागत कीमत और आयातों की पत्तनगत कीमत से नहीं करते हैं। वे अपने कारखाने पर विभिन्न स्रोतों से इस उत्पाद की पहुंच कीमत का निर्धारण और तुलना करते हैं।
- lxiv. डब्ल्यू टी ओ में भारत सरकार की स्थिति उचित तुलना किए जाने पर इस पद्धति का समर्थन करते हैं।

- lxv. कारखाने से भंडार तक भाड़े संबंधी तथ्य को अलग करने का कोई कारण नहीं हो सकता है क्योंकि ये खर्च के भाग के अलावा कुछ भी नहीं होते हैं जिनका सत्यापन लेखा बुक से किया जा सकता है और ये बढ़ाए गए कारखाना द्वार तक वस्तुओं की दुलाई के लिए किया गया खर्च मात्र है। यदि इन वस्तुओं को कारखाने से भंडार तक ले जाया जाता है तब इन वस्तुओं को मालसूची के भाग के रूप में माना जा सकता है।
- lxvi. लेखांकन मानदंडों के अनुसार भी कारखाना से भंडार तक दुलाई पर विचार उत्पादन की लागत के भाग के रूप में किया जाता है और यदि ऐसा मामला हो तब भंडार केवल एक बढ़ाई गई कारखाना वेयर हाउस है और उस पर ही कारखानागत एनआईपी और बिक्री कीमत के आधार के रूप में विचार किया जाना चाहिए।
- lxvii. जीएसटी और लगाए गए अन्य प्रभारों की गणना तभी की जाती है जब इन वस्तुओं को भंडार से बाहर ले जाया जाता है क्योंकि उन पर विचार कारखानागत लागतों के रूप में किया जाता है। भंडार की कीमतों पर विचार एनआईपी और बिक्री की कीमत की गणना के उद्देश्य से कारखानागत कीमतों के रूप में किया जाना चाहिए।
- lxviii. केवल विगत प्रथा घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए तर्कों और किए गए अनुरोधों पर विचार न किए जाने के लिए कोई औचित्य नहीं हो सकता है, विशेषकर तब जब इस प्रकार के अनुरोध इस विशेष मामले में मूल जांच के समय से किया गया हो।
- lix. कीमत में कटौती और क्षति कारक आयातों/क्षति मार्जिन का निर्धारण केवल उन लेनदेनों पर निरंतर विचार करते हुए किया जाना चाहिए जो घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे थे और उसे क्षति पहुंचा रहे थे।
- lxx. भारत में भारित औसत निर्यात कीमत इस तथ्य का निर्धारण करने के लिए पूर्ण रूप से पर्याप्त नहीं है कि क्या घरेलू उद्योग को पुनः क्षति होने की संभावना है।
- lxxi. प्रमुख संबद्ध देशों में उत्पादक के पास बहुत अधिक मात्रा में अप्रयुक्त क्षमताएं हैं और वे (क) भारत में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों से कम और (ख) भारत में इन देशों से निर्यात कीमत से कम कीमतों पर तीसरे देशों में विचाराधीन उत्पाद की पर्याप्त मात्रा में कर रहे हैं।
- lxxii. शुल्कों को समाप्त किए जाने की स्थिति में, इन उत्पादकों को संभवतः भारत में अच्छा बाजार अवसर प्राप्त होगा और वे संभवतः घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों से कम कीमत पर बहुत अधिक मात्रा में निर्यात करकेंगे।
- lxxiii. अलग-अलग निर्यातकों का व्यवहार जिसे अलग-अलग निर्यात लेनदेन के माध्यम से दर्शाया गया है, संगत और उपयुक्त है तथा इसकी जांच की जानी आवश्यक है क्योंकि यह अपने आप में क्षति पहुंचाने वाले इस प्रकार के उत्पादकों/निर्यातकों के पाटन की प्रवृत्ति को दर्शाते हैं।
- lxxiv. हालांकि यह देखा गया है कि प्रकटन विवरण में केवल ये अनुरोध शामिल किए गए हैं और न कि भविष्य में उत्पन्न होने वाले आवश्यक तथ्य जिन पर प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया है।
- lxxv. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध विचाराधीन आवश्यक तथ्य नहीं होता है।
- lxxvi. निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना और साक्ष्य के आधार पर सिद्ध किया गया तथ्य निर्दिष्ट प्राधिकारी के विचाराधीन आवश्यक तथ्य नहीं होते हैं।
- lxxvii. वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच के मामले के संदर्भ में और कानून के अंतर्गत निर्धारित क्षति संबंधी मानदंडों पर विचार करते हुए, निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे नियम 11 द्वारा निर्धारित तरीके से उपर्युक्त कानूनी प्रावधानों पर विचार करें।
- lxxviii. संबंधित उत्पाद की मांग में भारत में क्षति की अवधि की तुलना में वृद्धि हुई है।
- lxxix. शुल्कों के मौजूद रहने के बावजूद, भारतीय मांग में आयात का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और आयात की मात्राओं में क्षति की अवधि की तुलना में वृद्धि हुई है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि आयात पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में कम से कम बढ़ने (और न कि गिरने) जा रही है।
- lxxx. चूंकि शुल्कों को वर्तमान अधिसूचना के अनुसार जुलाई, 2018 से वसूला नहीं जा रहा है और तब जब वर्तमान जांच का निष्कर्ष नहीं निकाला गया है और इसके संबंध में निर्णय नहीं लिया गया है कि क्या पाटनरोधी शुल्क को और आगे बढ़ाया जाना अपेक्षित है, आयातों में पहले ही बहुत अधिक वृद्धि दर्शाना शुरू कर दिया है।

- lxxxi. प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों की पहुंच कीमतों के कारण बहुत अधिक मार्जिन में घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमतों में कटौती हो रही है। इसके फलस्वरूप बहुत अधिक सकारात्मक कटौती स्तर प्राप्त हो रहा है।
- lxxxii. कीमत में कटौती का निर्धारण घरेलू उत्पाद दर दुलाई पर विचार किए बिना की गई है जबकि आयात किए गए उत्पाद पर दुलाई पर विचार पत्तन के स्तरों तक किया गया है (जो आयात किए गए उत्पाद पर अधिकांश भाड़ा होता है) अतः यह तुलना उसी स्तर पर नहीं है।
- lxxxiii. प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत में क्षति की अवधि के दौरान गिरावट आई है जबकि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों में उसी अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।
- lxxxiv. चीन जन गण, यूरोपीय संघ और यू.एस.ए. से आयातों की पहुंच कीमत में क्षति अवधि की तुलना में वृद्धि हुई है। जांच की अवधि के दौरान कीनिया और पाकिस्तान से आयातों का पहुंच मूल्य लगभग एक समान रहा है। ईरान और यूक्रेन से आयातों की पहुंच कीमतों में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान गिरावट आई है।
- lxxxv. ऐसा प्रतीत होता है कि इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया है कि (क) वर्तमान स्थिति ऐसी है जब पाटनरोधी शुल्क लागू है और इस कारण से वर्तमान पाटनरोधी शुल्क को नहीं बढ़ाए जाने की स्थिति में क्षति को दर्शाने के लिए बिल्कुल संगत नहीं है। (ख) चीन जन गण को छोड़कर सभी संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमत में बिक्री की लागत में समान अवधि में गिरावट के बिना 2015-16 की तुलना में जांच की अवधि में गिरावट आई है।
- lxxxvi. यह (क) उत्पाद की लागतों की तुलना पर ध्यान दिए बिना कीमतों में कटौती करने के लिए निर्यातकों के व्यवहार और (ख) वर्तमान पाटनरोधी शुल्क को और आगे नहीं बढ़ाए जाने की स्थिति में कीमतों में कटौती की संभावना को दर्शाता है।
- lxxxvii. इन आयातों के कारण पाटनरोधी शुल्क के लागू रहने पर कोई ह्रासकारी अथवा न्यूनकारी प्रभाव कीमत पर नहीं पड़ रहा था।
- lxxxviii. प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि क्षति की अवधि की तुलना में घरेलू उद्योग की क्षमता में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री कीमतों में उसी अवधि की तुलना में वृद्धि हुई है। क्षमताओं को बढ़ाए जाने के बावजूद घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग क्षति की अवधि की तुलना में लगभग वहीं रहा है।
- lxxxix. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा क्षमता का उपयोग 80 प्रतिशत से अधिक हुआ है जो एक सही उपयोगिता स्तर है।
- xc. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह विचार किया है कि संयंत्र का क्षमता से कम उपयोग हुआ है और घरेलू उद्योग उसकी तुलना में अधिक उत्पादन कर सकता था जितना इसमें उस अवधि के दौरान किया था।
- xci. निरमा संयंत्र को 95 प्रतिशत तक चला रहा था जो अपने आप में यह दर्शाता है कि 80 प्रतिशत उच्चतम क्षमता उपयोग नहीं है। इस प्रकार से घरेलू उद्योग अपनी क्षमता का कम से कम 96 प्रतिशत तक उत्पादन कर सकता है।
- xcii. यह निष्कर्ष निकालना उपयुक्त नहीं होगा कि घरेलू उद्योग उच्चतम स्तर पर उत्पादन कर रहा था बल्कि वैकल्पिक रूप में एनआईपी का निर्धारण सभी तीन कंपनियों के लिए 80 प्रतिशत की दर से किया जाना चाहिए।
- xciii. पाटनरोधी शुल्क 2012 में लगाया गया था। उद्योग को 2011-12 में घाटा उठाना पड़ रहा था और यह 2013-14 तक कम स्तर पर लाभ और निवेश पर लाभ प्राप्त कर रहा था।
- xciv. 2012 में पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद घरेलू उद्योग की स्थिति में धीरे-धीरे सुधार आया और इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के संघटक और अन्य उत्पादकों ने यह महसूस किया कि यह बाजार क्षमता में विस्तार में निवेश करने के लिए अर्थक्षम नहीं है और इसमें विस्तार की योजना बनाई है।
- xcv. घरेलू उद्योग और अन्य नए उत्पादकों द्वारा क्षमताओं में बहुत अधिक वृद्धि की गई है। पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद, 10 लाख मीटर की नई क्षमता या तो पहले ही चालू की जा चुकी है (निरमा और जीएचसीएल द्वारा) अथवा चालू किए जाने के कगार पर है (गरही) द्वारा।

- xcvi. 20 लाख मी.ट. क्षमता में वृद्धि की योजना इस चरण में बनाई जा रही है। हालांकि ये केवल इस कारण से है कि इस उत्पाद के लिए भारतीय बाजार अर्थक्षम रहा है।
- xcvii. पहले ही 3225 करोड़ रूपए का निवेश किया गया है, 10,000 करोड़ रूपए का और आगे निवेश किए जाने की योजना बनाई जा रही है। अन्य उत्पादकों द्वारा भी क्षमता में बहुत अधिक वृद्धि की गई है। मै. घारही ने 2200 करोड़ रूपए के निवेश से 5 लाख मी.ट. की उत्पादन क्षमता का एक नया ग्रीनफील्ड संयंत्र शुरू किया है। हालांकि प्रकटन विवरण में इसकी उपेक्षा की गई है। इन निवेशों पर पाटनरोधी शुल्क का संभावित रूप से विस्तार न किए जाने के प्रभाव पर भी विचार क्षति का विश्लेषण करते समय नहीं किया गया है।
- xcviii. पाटित और बड़े हुए आयातों का घरेलू उद्योग द्वारा किए गए इस प्रकार के भारी निवेशों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। नए निवेशों के लिए तार्किक रूप से अक्षम बनने के उद्देश्य से 7000/मी.ट. का न्यूनतम उचित लाभ की आवश्यकता है। क्षति की अवधि की तुलना में घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित औसत लाभ बहुत कम था।
- xcix. कीमत में वृद्धि का कारक औद्योगिक उत्पादन के लिए अपेक्षित उद्यम संबंधी क्रियाकलाप को जारी रखने के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा है। घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित किए जा रहे लाभ की क्षमता सृजन में में फिर से निवेश किया जा रहा है और इसे उद्योग द्वारा वापस नहीं लिया जा रहा है।
- c. अगर घरेलू उद्योग इन लाभों को अर्जित करना जारी रखे तब नए निवेशों की वसूली उस अवधि में की जाएगी जो इन परिसंपत्तियों के जीवनकाल से ही अधिक होगी।
- ci. शुल्कों को आगे न बढ़ाने से संभवतः घरेलू उद्योग की नई क्षमता वृद्धि के लिए निवेश समाप्त हो जाएंगे बल्कि इसके पूर्व के मौजूदा क्षमताओं पर भी प्रभाव पड़ेगा।
- cii. घरेलू उद्योग के लाभ में सुधार को घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना के न होने के संबंध में निष्कर्ष निकालने के लिए प्रयास के रूप में नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि इस लाभ को पूंजी पर धन के आधिक्य के रूप में ही समझा जाए।
- ciii. यह भी नोट करना महत्वपूर्ण होगा कि यह एक ऐसा मामला है जहां याचिकाकर्ता का घरेलू उद्योग उपभोक्ता उद्योग की लागत पर लाभ अर्जित कर रहा है। न केवल घरेलू उद्योग अपेक्षाकृत अधिक लाभ अर्जित कर रहा है बल्कि उन्होंने क्षति की वर्तमान अवधि की तुलना में बहुत अधिक सुधार दर्शाया है।
- civ. निर्णायक समीक्षा जांचों में प्राधिकारी से इस पर विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने के बाद इस उत्पाद के पाटन से नई क्षमता विस्तारों पर जो इस देश में पहले ही हो चुके हैं, तथा इन क्षमता विस्तारों जो देश में होंगे, पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।
- cv. कनाडा की प्रथा का संदर्भ लिया गया है जिसमें इस तथ्य पर समुचित रूप से विचार किया जाता है कि भावी उत्पादन में घरेलू उद्योग द्वारा बहुत अधिक निवेश किया गया है।
- cvi. घरेलू उद्योग ने उत्पादन की लागत और नव स्थापित क्षमताओं की एनआईपी के संबंध में पूर्व में दायर किए गए अनुरोधों के रूप में सूचना उपलब्ध कराई है।
- cvii. यह दर्शाता है कि नए संयंत्र में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पहले से ही बहुत कम है और घरेलू उद्योग को यदि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क को और आगे नहीं बढ़ाया जाता है तब इस प्रकार की नई क्षमताओं के संबंध में लाभों में बहुत अधिक गिरावट का सामना करना पड़ेगा और घरेलू उद्योग ऐसी कामतों पर बिक्री करने के लिए बाध्य होगा।
- cviii. प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण में मांग में बाजार हिस्से की जांच नहीं की है। आयातों के बाजार हिस्से में क्षति की अवधि की तुलना में वृद्धि हुई है और घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा कमोवेश एक जैसा रहा है। कुल मिलाकर घरेलू उत्पादकों के बाजार हिस्से में गिरावट आई है।
- cix. रिकॉर्ड पर आंकड़े यह दर्शाते हैं कि मालसूची में वृद्धि जांच के आधार वर्ष और 2015-16 के बीच लगभग 36 अंक रही है और 2015-16 तथा जांच की अवधि के बीच गिरावट केवल 4 अंक अर्थात् 136 से 132 हुई है।
- cx. प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि घरेलू उद्योग के लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय में क्षति की अवधि के दौरान सुधार आया है। इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया है कि (क) जांच की अवधि में लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय पिछले वर्ष की तुलना में कुछ गिरावट दर्शाता है, (ख) नए निवेश पर आय, लाभ और नकद लाभ

बहुत कम रहा है (ग) लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय में सुधार पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के परिणामस्वरूप हुआ है और इसका आशय यह नहीं है कि क्षति के फिर से होने की कोई संभावना नहीं है, (घ) क्षति की अवधि के मानदंड केवल सतत क्षति की जांच के लिए और न कि क्षति की संभावना के लिए संगत हैं।

- cx i. पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में मालसूची के स्तर में 4 अंक की गिरावट विशेष रूप से प्रकटन विवरण में देखी गई है, जांच की अवधि में लाभप्रदता में 21 अंक की गिरावट को पूर्ण रूप से नजरअंदाज कर दिया गया है।
- cx ii. घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन की वस्तुपरक जांच का अभिप्राय यह है कि बिना किसी भेदभाव के उसी मानदंड पर सभी मापदंडों पर विचार किया जाना चाहिए।
- cx iii. जबकि वर्तमान जांच की अवधि पाटन के जारी रहने को सिद्ध करने के लिए संगत है, ऐतिहासिक आंकड़े पाटन की संभावना को सिद्ध करने के लिए संगत हैं क्योंकि यह संबद्ध देश के पाटन प्रथाओं में आदतन संलग्न रहने के रूप में सिद्ध करता है।
- cx iv. इन गणनाओं ने यह दर्शाया है कि पाटन पूरे 10 वर्षों की अवधि के दौरान होता रहा है। भारित औसत आधार पर जांच की अवधि के लिए आंकड़े अपने आप में यह दर्शाते हैं कि पाटन जारी रहा है और वह पर्याप्त हो सकता है।
- cx v. यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारित औसत पाटन मार्जिन न्यूनतम है तब आयात संबंधी प्रत्येक लेनदेन के लिए पृथक् रूप से पाटन मार्जिन की जांच करने की आवश्यकता है।
- cx vi. संबद्ध वस्तुओं का सतत पाटन हुआ है। सामान्य मूल्य का निर्धारण संबद्ध देशों में प्रचलित कीमतों के अनुसार किया जाना चाहिए और इसे संरक्षित नहीं किया जाना चाहिए।
- cx vii. घरेलू बाजार में पाटनरोधी शुल्क के लगाए जाने के बावजूद पाटित कीमतों पर आयात किया गया है। 2015-16 तक गिरावट के बाद आयातों में जांच की अवधि में बहुत अधिक वृद्धि हुई है जो जांच की अवधि के बाद फिर से और अधिक बढ़ गई है।
- cx viii. घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में कुछ गिरावट के साथ लागू पाटनरोधी शुल्क को देखते हुए सुधार हुआ है। हालांकि पाटनरोधी शुल्क को आगे न बढ़ाने के कारण वास्तविक क्षति के पुनः होने की संभावना है। इसके अलावा, जहां तक घरेलू उद्योग की इस लाभप्रदता का प्रश्न है, यह अनुरोध किया जाता है कि सोडा ऐश एक बहुत अधिक पूंजी गहन, निम्न कच्चा माल लागत और अत्यधिक तैयार उत्पाद भाड़ा उद्योग है। भाड़े संबंधी लागत उत्पादन की लागत का बहुत अधिक प्रतिशत होता है। इस कारण से इस मामले को विचाराधीन उत्पाद की विलक्षणता के आलोक में देखा जाना चाहिए।
- cx ix. नियोजित पूंजी पर आय के संबंध में उद्योग द्वारा चलाए जा रहे संयंत्र में हास हुआ है। चूंकि निवल स्थायी परिसंपत्ति घरेलू उत्पादकों के लिए उचित नहीं है और वह घरेलू उत्पादकों की परिसंपत्तियों के मूल्य का सही मूल्य नहीं दर्शाता है अतः घरेलू उद्योग निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह अनुरोध करता है कि वे नियोजित पूंजी पर आय की गणना करने के लिए निवेश के वर्तमान मूल्य पर विचार करें।
- cx x. घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में सुधार मात्र यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है कि शुल्कों को बढ़ाया जाना उचित नहीं है। नियम 23 में प्राधिकारी को यह अधिदेश दिया गया है कि वे घरेलू उद्योग की वर्तमान स्थिति पर केवल ध्यान केन्द्रित करने के बजाए घरेलू उद्योग पर शुल्क को समाप्त किए जाने के प्रभाव की जांच करें। यदि प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि घरेलू उद्योग को सतत क्षति उठानी नहीं पड़ी है तब प्राधिकारी को इस तथ्य की जांच करने की आवश्यकता है कि क्या घरेलू उद्योग को पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में क्षति होने की संभावना है। यदि ऐसा नहीं है तब प्राधिकारी को निश्चित रूप से इस तथ्य की जांच करनी चाहिए कि क्या विचाराधीन उत्पाद के सतत पाटन के कारण क्षति फिर से उत्पन्न होगी।
- cx xi. संबद्ध देशों से उत्पादकों के पास बहुत अधिक क्षमता है। इसका आशय यह है कि उनके पास घरेलू मांग से बहुत अधिक क्षमताएं हैं जो यह सिद्ध करता है कि शुल्कों को समाप्त किए जाने की स्थिति में भारत में निर्यात में और अधिक वृद्धि होगी।
- cx xii. प्रचलित पाटनरोधी शुल्कों के बिना कीमत में कटौती सकारात्मक है।

- cxxiii. ऐतिहासिक रूप से (10 वर्ष की अवधि के लिए आंकड़ों के अनुसार) पाटित और क्षतिकारक आयातों का हिस्सा बहुत अधिक रहा है।
- cxxiv. संबद्ध देशों द्वारा तीसरे देशों में किए गए निर्यातों की बहुत ज्यादा मात्रा उन कीमतों पर हुई है तो भारत में किए गए निर्यातों की कीमत से कम है।
- cxxv. संबद्ध देशों द्वारा तीसरे देशों में किए गए निर्यातों की बहुत ज्यादा मात्रा उन कीमतों पर हुई है तो घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों से कम है।
- cxxvi. पाटनरोधी शुल्क को आगे न बढ़ाए जाने के फलस्वरूप ऐसी स्थिति पैदा होगी जहां आयात कीमतें वास्तविक रूप से घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम होगी। इस कारण से उपभोक्ता आयात की किए गए वस्तुओं को लेना चाहेंगे जिसके फलस्वरूप इस उत्पाद के आयातों में बहुत अधिक वृद्धि होगी।
- cxxvii. यह जांच विधिसम्मत है और यह उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में किया जा रहा है। जैसे ही प्राधिकारी उस सीमा तक सिफारिश देंगे इन शुल्कों को वाद की तिथि से लगाया जा सकता है।
- cxxviii. शुल्क की मात्रा को संशोधित किया जाना अपेक्षित नहीं है और मौजूदा शुल्कों को केवल बढ़ाया जाना चाहिए।
- cxxix. पाटनरोधी शुल्क अमरीकी डॉलर/मी.ट. में शुल्क के रूप में व्यक्त किए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्धारित मात्रा (शुल्क का निर्धारित रूप) के रूप में ही लगाया जा सकता है। रूप का बहुत अधिक अवमूल्यन हुआ है और इस कारण से निश्चात्मक शुल्कों को अमरीकी डॉलर में ही व्यक्त किया जाना चाहिए। भारतीय रूप के अवमूल्यन का प्रभाव कच्चे मालों की लागतों, उपयोगिताओं और अन्य लागतों पर पड़ा है।
- cxxx. इस उत्पाद पर पहले से ही वर्तमान में पाटनरोधी शुल्क की निर्धारित मात्रा लग रही है।
- cxxxii. पाटनरोधी कानून पाटनरोधी संबंधी डब्ल्यू टी ओ करार के अनुरूप बनाया गया है जो स्पष्ट रूप से प्राधिकारियों को अनुरोध किए गए रूप में और तरीके से पाटनरोधी शुल्कों को लगाने के लिए अनुमति देता है।
- cxxxiii. काफी अधिक संख्या में की गई जांचों (15 वर्षों से अधिक की अवधि के दौरान अब तब 300 से अधिक जांच की गई हैं) से प्राप्त अनुभव से यह पता चलता है कि लगाए गए पाटनरोधी शुल्क से बचने के लिए प्रयास किए गए हैं। पाटनरोधी शुल्क से बचने के संबंध में काफी लंबे समय से विभिन्न उद्योग समूहों द्वारा काफी संख्या में की गई शिकायतें इस संबंध में संगत हैं।
- cxxxiii. सीमाशुल्क पत्तन प्राधिकारियों के पास किसी आयातक द्वारा सूचित की गई आयात कीमत की सत्यता सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र नहीं है। पत्तन प्राधिकारियों के लिए आयात कीमत का सत्यापन करने हेतु न तो यह संभव है और न ही यह व्यवहार्य है।
- cxxxiv. इस शुल्क को उस तरीके से लगाया जाना चाहिए, जहां यह व्यर्थ न हो जाए।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

- i. इस मामले की पृष्ठभूमि के संबंध में, एच यू एल माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी के ध्यान में यह लाता है कि डब्ल्यू. पी. 14202 और 14204, 2017 में माननीय गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय जो वर्तमान समीक्षा जांच की कार्यवाहियों को जारी रखने के लिए इसमें प्राधिकारी के लिए आधार था, एस एल पी (सिविल) डायरी सं. 36509/2018 में उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।
- ii. प्रक्रिया के संबंध में, माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रकटन विवरण के पैरा सं. 7 (v) और 7(vii) में यह टिप्पणी की है कि “संबद्ध देश से किसी आयातक/ प्रयोक्ता अथवा उत्पादक/ निर्यातक ने प्रश्नावली को कोई उत्तर अथवा कोई अनुरोध नहीं प्रस्तुत किया है। इसके उत्तर में एच यू एल का यह अनुरोध है कि उक्त टिप्पणी त्रुटिपूर्ण है। कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने अपने अनुरोध दायर किए हैं और वह सार्वजनिक फाइल में रखे गए अभिलेखों का हिस्सा है। इस कारण से निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उस पर विचार किया जाना चाहिए।
- iii. इसके अलावा, माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पैरा सं. 7(xi) में यह भी टिप्पणी की है कि “निर्यातकों, उत्पादकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों जिन्होंने प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है और न ही इस जांच से संगत सूचना उपलब्ध कराई है, को गैर सहयोगी हितबद्ध पक्षकारों के रूप में माना गया है।” एच यू एल का यह अनुरोध है कि उक्त टिप्पणी त्रुटिपूर्ण है।

- iv. एच यू एल संबद्ध वस्तुओं की सबसे बड़े औद्योगिकी प्रयोक्ताओं में से एक है और इसने प्रश्नगत उत्पाद का आयात नहीं किया है। इस कारण से, जांच आरंभन के समय लागू निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार, आयातक की प्रश्नावली को इस प्रकार के औद्योगिक प्रयोक्ता द्वारा दायर किए जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा एच यू एल यह अनुरोध करता है कि वर्तमान जांच की अवधि के दौरान, इसने कुछ आंकड़े और सूचना उपलब्ध कराई है जो इसके खयाल से अंतिम जांच परिणाम को जारी करने के लिए किसी निष्कर्ष पर पहुंचने हेतु निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए संगत है। चूंकि, निर्दिष्ट प्राधिकारी एक अर्द्ध न्यायिक प्राधिकार है अतः इसे अंतिम जांच परिणाम की सिफारिश करने के पूर्व हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अभिलेख में रखे गए आंकड़ों एवं सूचना के साथ साथ सभी कानूनी अनुरोधों का समाधान करना है।
- v. माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी ने उत्पादन के कार्यक्षेत्र और समान वस्तु के संबंध में टिप्पणियां की हैं। एच यू एल का यह अनुरोध है कि इसे उसके संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करनी है। उस स्थिति में कि नई अथवा अतिरिक्त सूचना उपलब्ध कराई जाती हो, एच यू एल उसके संबंध में टिप्पणी करने के अपने अधिकार को सुरक्षित रखता है।
- vi. एच यू एल का यह अनुरोध है कि माननीय निर्दिष्ट प्राधिकार के विवरण ने घरेलू उद्योग के रूप में याचिकाकर्ता की पात्रता के संबंध में टिप्पणियां की हैं। हालांकि, इसने भारत में विशेष रूप से विचाराधीन के उत्पाद के जी एच सी एल, अन्य घरेलू उत्पादकों की पात्रता के संबंध में किसी टिप्पणी को दर्ज नहीं करने में भूल की है।
- vii. इसके अलावा, यद्यपि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं की पिछली पाटनरोधी कार्यवाहियों में जी एच सी एल को विशेष रूप से घरेलू उद्योग के रूप में माना है अतः यह स्पष्ट नहीं है कि क्यों निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इसमें याचिकाकर्ताओं के अनुरोध पर विचार नहीं किया है और इसमें एच यू एल को घरेलू उद्योग के रूप में जी एच सी एल की पात्रता पर विचार करने/ उसकी जांच करने के अनुरोध पर विचार नहीं किया है। वर्ष 2017-18 के लिए जी एच सी एल की वार्षिक रिपोर्ट यह दर्शाती है कि उनका डोसा एश प्रभाग का कार्य निष्पादन बहुत ही अच्छा रहा है। उनकी बिक्री में उनका क्षमता उपयोग 95 प्रतिशत से अधिक होने के साथ साथ बहुत अधिक बढ़ गया है।
- viii. उपर्युक्त को देखते हुए, इस पर अवश्य ही विचार किया जाना चाहिए कि क्या याचिकाकर्ता हाल के वर्षों में जी एच सी एल के सकारात्मक कार्य निष्पादन के कारण ही घरेलू उद्योग के रूप में जी एच सी एल की पात्रता पर फिर से विचार करने के लिए अनुरोध कर रहा है। चूंकि इस मुद्दे का समाधान प्रकटन विवरण में नहीं किया गया है अतः यदि याचिकाकर्ता को जानबूझकर घरेलू उद्योग से प्रथम दृष्टि में जी एच सी एल को बाहर कर दिया गया है, ताकि जी एच सी एल के विशिष्ट कार्य निष्पादन के कारण न कि जी एच सी एल के आयातों के मौजूद रहने के तथ्य की पुष्टि न किए जाने के कारण उनके लिए प्रतिकूल क्षति की संभावना अथवा क्षति के निर्धारण से बचा जा सके, माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी विशेष रूप से इसका निर्धारण कर सकते हैं।
- ix. माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इस तथ्य के संबंध में एक सामान्य टिप्पणी की है कि इसने जहां भी आवश्यक हुआ गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और गोपनीय सूचना को हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया है। एच यू एल का अनुरोध है कि इसे उसके संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करनी है। हालांकि, एच यू एल नई अथवा अतिरिक्त सूचना उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में टिप्पणी करने के अपने अधिकार को सुरक्षित रखता है।
- x. एच यू एल अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा ऊपर में दिए गए स्व-कथनों से सहमत है। मूल जांच के अनुसरण में शुल्कों को लगाये जाने में विच्छेद अथवा शुल्कों के समाप्त होने पर पूर्व में समाप्त शुल्कों को उसके पश्चात निर्णायक समीक्षा जांच के रूप में नहीं लगाया जा सकता है। माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी को फोरेच इण्डिया लिमि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में दिल्ली उच्च न्यायालय के सबसे हाल के निर्णय पर ध्यान देना चाहिए।
- xi. माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि हितबद्ध पक्षकारों के पास प्रश्नावली का उत्तर देने और जांच में भाग लेने के लिए पर्याप्त समय था। इस प्रकार की टिप्पणी करने के पूर्व एच यू एल का यह अनुरोध है कि माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी को निश्चित रूप से वर्तमान मामले के जटिल इतिहास (विशेष रूप से रिट याचिका और उसके बाद के आदेश) पर विशेष रूप से विचार करना चाहिए जिसके कारण वर्तमान जांच में किसी समय सीमा के बारे में संदेह बढ़ गया है और इस कारण से प्रश्नावली के उत्तरों को दायर करने के लिए अधिकांश हितबद्ध पक्षकारों के साथ समय सीमाओं के पालन किए जाने के मामले में हस्तक्षेप किया। हालांकि, प्राधिकारी से यह अनुरोध है कि वे अपने जांच परिणाम को जारी किए जाने के पूर्व विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराये गये सभी कानूनी अनुरोधों और अन्य सूचना/ साक्ष्य पर विचार करें।

- xii. चीन से सामान्य मूल्य पर, एच यू एल के पास उसके संबंध में कोई विशिष्ट टिप्पणियां नहीं हैं। हालांकि, एच यू एल माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह अनुरोध करता है कि वे चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य का निश्चरण करने के उद्देश्य से संगत पाटनरोधी नियमावली पर विचार करें।
- xiii. संबद्ध देशों के लिए सामान्य मूल्य की गणना पर, प्राधिकारी ने उस पद्धति को प्रकट नहीं किया है जिसे इसने संगठित सामान्य मूल्य की गणना के लिए अपनाया है। प्राधिकारी को प्रकटन विवरण के माध्यम से इस प्रकार की सूचना सभी हितबद्ध पक्षकारों को देनी चाहिए थी। माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी को संगत धारा/ नियमों के अनुसार सामान्य मूल्य की गणना करनी चाहिए और इसके साथ ही भाग लेने वाले निर्यातकों/ उत्पादकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना पर विचार करना चाहिए।
- xiv. निर्यात कीमत पर निर्दिष्ट प्राधिकारी ने समायोजनों के लिए किसी पद्धति अथवा स्रोत को प्रकट नहीं किया है जिसे इसमें संबद्ध देशों के लिए निर्यात कीमत तय करने के लिए बनाया है। माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी को संगत धारा/ नियमों के अनुसार निर्यात कीमत की गणना करनी चाहिए और इसके साथ ही उन समायोजनों का साक्ष्य उपलब्ध कराना चाहिए जिन्हें निर्यात कीमत के लिए किया गया है।
- xv. माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह टिप्पणी की है कि पाटन मार्जिन चीन जन. गण., यूरोपीय यूनियन, पाकिस्तान और यूक्रेन के लिए नकारात्मक है और केन्या के लिए पाटन मार्जिन न्यूनतम से कम है। यह एक महत्वपूर्ण निश्चरण है क्योंकि यह स्पष्ट रूप से इन संबद्ध देशों के लिए पाटन को जारी रखने के मौजूद न होने को सिद्ध करता है।
- xvi. इस कारण से शुल्कों को जारी रखने के उद्देश्य से, अब यह सिद्ध करना आवश्यक होगा कि वर्तमान जांच में पाटन के फिर से होने की संभावना है। यह देखते हुए कि अधिकांश संबद्ध देशों से वर्तमान में कोई पाटन नहीं हुआ है और याचिकाकर्त्ताओं को कोई क्षति नहीं हुई है (अथवा उसकी कोई संभावना नहीं है), माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे चुनौती दिए गए शुल्कों को समाप्त रहने देने की अनुमति दें।
- xvii. जैसा कि स्पष्ट रूप से अनुबंध ॥ में बल दिया गया है, घरेलू उद्योग को क्षति की जांच केवल पाटित आयातों के संबंध में किया जाना अपेक्षित है। माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अपने प्रकटन विवरण में जिस प्रकार से निश्चरण किया गया है, चीन जन. गण., यूरोपीय यूनियन, केन्या, पाकिस्तान और यूक्रेन से जांच की अवधि में कोई पाटन/ न्यूनतम पाटन नहीं हो रहा है। चूंकि, इन देशों से कोई पाटन नहीं हो रहा है अतः इन देशों के लिए क्षति का विश्लेषण उपर्युक्त प्रावधानों के अंतर्गत अत्यधिक और अवांछित है। क्षति के संबंध में, माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह केवल यह अपेक्षित है कि वे इस तथ्य का आकलन करें कि क्या संबद्ध देशों जिसमें सकारात्मक पाटन मार्जिन है अर्थात् ईरान और यू एस ए से आयातों के कारण याचिकाकर्त्ताओं को क्षति हुई है।
- xviii. माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह टिप्पणी की है कि संबद्ध आयातों और याचिकाकर्त्ताओं के बाजार हिस्से में वृद्धि के साथ साथ क्षति की अवधि में मांग में वृद्धि हुई है। हालांकि, उसी अनुच्छेद में प्राधिकारी ने सही रूप में यह नोट किया है कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई। एच यू एल यह अनुरोध करता है कि यद्यपि प्राधिकारी ने ऊपर में किए गए उल्लेख के अनुसार टिप्पणी की है फिर भी इसने कुल मांग में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से के लिए प्रवृत्ति उपलब्ध नहीं कराई है। बिना किसी पूर्वाग्रह के, याचिकाकर्त्ताओं की बिक्री में देश की कुल मांग की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक दर से वृद्धि हुई है, जो बाजार हिस्से में वृद्धि को दर्शाता है। इस प्रकार से, संबद्ध आयातों का याचिकाकर्त्ताओं के बाजार हिस्से पर नकारात्मक रूप से प्रभाव नहीं पड़ा है।
- xix. जबकि यूरोपीय यूनियन, पाकिस्तान, यूक्रेन, ईरान और यू एस ए से आयातों में कथित रूप से वृद्धि हुई है, फिर भी घरेलू उद्योग की बिक्री में वृद्धि हुई है जो इस बात का साक्ष्य है कि घरेलू उद्योग घरेलू बिक्री पर संबद्ध आयातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।
- xx. याचिकाकर्त्ताओं की बिक्री कीमत बिक्री की लागत के अनुरूप सतत रूप से बने रहने में सक्षम हुई है। संबद्ध आयातों ने याचिकाकर्त्ताओं को लागत में किसी परिवर्तन के साथ अपनी कीमत को उपयुक्त रूप से समायोजित करने से नहीं रोका है और इस प्रकार से यह दर्शा रहा है कि याचिकाकर्त्ताओं को कीमत ह्रास अथवा न्यूनीकरण के कारण क्षति नहीं हो रही है।
- xxi. प्रकटन विवरण में उपलब्ध कीमत में कटौती संबंधी आंकड़े केवल जांच की अवधि के संबद्ध में हैं। इसके अलावा, माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी ने निवल बिक्री कीमत अथवा निवल बिक्री प्राप्ति (जो सूचीबद्ध भी हो) संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं कराये हैं कि यह जांच की अवधि के लिए कीमत में कटौती के विश्लेषण के उद्देश्य से विचार कर रहा है। कीमत में कटौती के आंकड़ों को प्रकट नहीं किए जाने की स्थिति में उस पर विचार माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी

द्वारा संपूर्ण रूप में क्षति की अवधि के लिए किया जा रहा है, एच यू एल को उसके संबद्ध में कोई सार्थक टिप्पणियां करने के लिए अवसर दिए जाने से वंचित किया जा रहा है। प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे उन सभी सूचनाओं को कृपया प्रकट करें जिन पर यह कीमत में कटौती के विश्लेषण के उद्देश्य से विचार कर रहा है।

- xxii. यह नोट किया जाता है कि माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी ने "प्राधिकारी की सतत् प्रथा" के आधार पर कीमत में कटौती का आकलन किया है जिसे तार्किक रूप से यह समझने के लिए माना जा सकता है कि भाड़े को शामिल नहीं किया गया है। हालांकि, यह देखते हुए कि यहां गोपनीयता के संबंध में कोई चिंता नहीं है, माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे स्पष्ट रूप से इस बात को स्पष्ट करें कि भाड़े पर विचार किया गया है अथवा नहीं।
- xxiii. घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग अपनी संस्थापित क्षमता का उपयोग करने में सक्षम रहा है।
- xxiv. माल सूची में पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में गिरावट आई है जो इस बात का साक्ष्य है कि घरेलू उद्योग जांच की अवधि में बढ़ी हुई बिक्री करने में सक्षम रहा है।
- xxv. यह मान लिया जाये कि आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की कर और ब्याज पूर्व लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय, लाभ में बहुत अधिक वृद्धि हुई है (जैसा कि प्राधिकारी द्वारा टिप्पणी भी की गई है)।
- xxvi. प्रति कर्मचारी उत्पादकता और मजदूरी में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में बहुत अधिक मात्रा में वृद्धि हुई है।
- xxvii. एच यू एल के पास पाटन के आकार के संबंध में कोई टिप्पणी करने के लिए नहीं है और यह याचिकाकर्त्ताओं द्वारा नई अथवा अतिरिक्त सूचना उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में जांच की अवधि के दौरान टिप्पणी करने के अपने अधिकार को सुरक्षित रखता है।
- xxviii. एच यू एल निर्दिष्ट प्राधिकारी की याचिकाकर्त्ताओं की निधियां उगाहने की क्षमता और विकास के संबंध में जांच परिणाम से सहमत है जिसकी जांच प्रकटन विवरण के पैरा सं. 70 और 71 में की गई है।
- xxix. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह स्पष्ट किया है कि क्षति रहित कीमत की गणना उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना के आधार पर की गई है। यदि सहयोग करने वाले उत्पादक के अलग अलग बर्ताव के आंकड़ों को उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण अस्वीकार किया होता तब माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी उत्पादक को इस प्रकार के अंतिम चरण में अतिरिक्त आंकड़े उपलब्ध कराने की अनुमति नहीं दी होती। उसी कठोर मानदंड का पालन याचिकाकर्त्ताओं पर भी लागू किया जाना चाहिए और क्षति रहित कीमत के संबंध में किसी अतिरिक्त सूचना (अथवा विचाराधीन कोई अन्य मुद्दे) स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। यदि वास्तव में इस प्रकार की सूचना को स्वीकार किया जाता है तब माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी को फिर से प्रकटन विवरण जारी करना चाहिए और एक उचित समय अवधि के भीतर अपनी टिप्पणियों को प्रस्तुत करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को अनुमति देनी चाहिए।
- xxx. बिना किसी पूर्वाग्रह के प्राधिकारी ने सही रूप में यह नोट किया है कि चीन जन. गण., यूरोपीय यूनियन, केन्या, पाकिस्तान, ईरान, यूक्रेन के लिए क्षति मार्जिन नकारात्मक है। अधिकांश संबद्ध देशों से पाटन के न किए जाने के साथ साथ, घरेलू उद्योग को स्पष्ट रूप से क्षति नहीं हुई है और क्षति का मार्जिन यू एस ए को छोड़कर सभी संबद्ध देशों के लिए नकारात्मक है।
- xxxi. यदि अधिकांश संबद्ध देशों से कोई पाटन नहीं हुआ है अथवा याचिकाकर्त्ताओं को क्षति नहीं हुई है तब कारणात्मक संबंध का कोई प्रश्न नहीं हो सकता।
- xxxii. याचिकाकर्त्ताओं ने यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य अथवा ठोस साक्ष्य (जिसमें जांच की अवधि के बाद की अवधि के लिए आंकड़े शामिल हैं) उपलब्ध नहीं कराये हैं कि शुल्क को जारी न रखने की फलस्वरूप पाटन और क्षति फिर से होगी।
- xxxiii. जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों का विश्लेषण करना संगत है जो याचिकाकर्त्ता ने उपलब्ध कराये हैं। इसके अलावा, यद्यपि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि इसने जांच की अवधि के बाद की अवधि के आंकड़ों पर विचार किया है फिर भी एच यू एल सहित हितबद्ध पक्षकारों को इस प्रकार का कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं कराया

गया है। बिना किसी पूर्वाग्रह के, प्रकटन विवरण के पैरा 78 में माने गए अनुसार जांच की अवधि के बाद की अवधि में आयात संबंधी आंकड़ों में गिरावट आई है।

- xxxiv. प्रकटन विवरण से यह स्पष्ट नहीं है और न ही यह सत्यापन के योग्य है कि आई एच एस की रिपोर्ट किस वर्ष से संबंधित है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने बिना किसी तार्किक आधार के इस सूचना को गोपनीय रखा है। माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी से विनम्रतापूर्वक यह अनुरोध है कि वे सार बनाये गये श्रेणियों में इन आंकड़ों को उपलब्ध करायें ताकि हितबद्ध पक्षकार भी इसमें विचारित आवश्यक तथ्यों पर टिप्पणी कर सकें। चूंकि एच यू एल प्रकटन विवरण की गोपनीय सूचना का सत्यापन नहीं कर सकता है अथवा उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता है। अतः यह उन अनुरोधों पर विश्वास करता है जिन्हें इसमें प्रतिउत्तर प्रस्तुत करने के पैरा 84 से 90 में किया है जबकि यह याचिकाकर्त्ताओं द्वारा विश्वास किए गए आई एच एस रिपोर्ट का उत्तर दे रहा था। उस पर प्राधिकारी द्वारा किसी निर्णायक जांच परिणाम किए जाने के पूर्व फिर से विचार किया जा सकता है।
- xxxv. संबद्ध देशों के बाजारों के संबंध में उपलब्ध सूचना के आधार पर यह स्पष्ट है कि स्थानीय क्षमताओं, विशेष चीन और पश्चिमी यूरोप में का प्रमुख रूप से उपयोग घरेलू बिक्री के लिए किया जाता है। वास्तव में, इन बाजारों में निर्यात बिक्री कुल उत्पादन का एक बहुत छोटा हिस्सा होता है (पिछले वर्ष के लिए तथा आने वाले वर्षों के लिए पूर्वानुमान के रूप में)।
- xxxvi. पाटन अथवा क्षति की संभावना को सिद्ध करने की जिम्मेदारी याचिकाकर्त्ताओं की होती है। प्राधिकारी ने यह उल्लेख करते हुए किए निर्यातकों/ उत्पादकों ने माल सूची के संबंध में आंकड़े उपलब्ध नहीं कराये, याचिकाकर्त्ताओं से निर्यातकों/ उत्पादकों पर यह भार डाल देते हैं। याचिकाकर्त्ताओं के उनके लिखित अनुरोधों के पैरा सं. 104 में विवरण को देखते हुए प्राधिकारी से इसमें यह नोट करने का अनुरोध किया जाता है कि याचिकाकर्त्ता पर्याप्त साक्ष्य के साथ पाटन अथवा क्षति की संभावना को सिद्ध करने में सक्षम नहीं हुए हैं।
- xxxvii. याचिकाकर्त्ताओं ने कीमत ह्रास/ न्यूनीकरण के संबंध में जांच की अवधि के बाद की अवधि से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं कराये हैं और न ही उसके संबंध में कोई सिद्ध किया हुआ अनुरोध किया है। इस पहलू पर विस्तृत अनुरोध ऊपर में दिए गए संगत भाग में किया गया है। प्राधिकारी ने सही रूप में यह नोट किया है (अप्रत्यक्ष रूप से) की प्रकटन विवरण के पैरा सं. 82 पर कोई कीमत न्यूनीकरण अथवा ह्रास नहीं दिया गया है।
- xxxviii. यह स्पष्ट है कि संबद्ध देशों में से दो को छोड़कर सभी के लिए पाटन मार्जिन नकारात्मक है।
- xxxix. माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी प्राधिकारी उस पद्धति का उल्लेख किया है जिसका उपयोग क्षति रहित कीमत को तय करने के लिए किया गया है और एच यू एल के पास उसके संबंध में कोई टिप्पणियां नहीं हैं।
- xl. सार्वजनिक सुनवाई के दौरान सेंट गोबिंद इण्डिया प्रा. लिमि. उठाये गये मुद्दों, लिखित अनुरोधों और प्रतिउत्तर में दिए गए विवरण जिनका उल्लेख प्रकटन विवरण में नहीं किया गया है अथवा जिनका निपटारा उपयुक्त रूप से नहीं किया गया है, पर विचार प्रकटन विवरण में इसकी टिप्पणियों के भाग के रूप में किया जाना है।
- xli. दिनांक 22.07.2017 के निर्णायक समीक्षा जांच को रद्द करने के बाद, एस जी आई पी एल के लिए अपनी प्रश्नावली का उत्तर उपलब्ध कराने के वास्ते कोई अवसर नहीं है।
- xlii. वर्तमान जांच बिना किसी क्षेत्राधिकार के है और पाटनरोधी शुल्कों को अब माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में नहीं बढ़ाया जा सकता है।
- xliii. स्पष्टगामी अथवा उत्तरगामी प्रभाव के साथ कोई अधिसूचना अब केंद्र सरकार द्वारा उस स्थिति में भी जारी नहीं किया जा सकता है यदि निर्णायक समीक्षा का फैसला फोरच इण्डिया लिमि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी एवं अन्य के मामले में स्थापित कानूनी स्थिति के संबंध में आवेदक घरेलू उत्पादकों के पक्ष में नहीं दिया जा सकता है कि मूल शुल्कों के समाप्त होने अथवा एक वर्ष के विस्तार के बीच कोई अंतर नहीं हो सकता है।
- xliv. एक वर्ष के लिए शुल्कों का विस्तार 02.07.2018 को समाप्त हो गया है जो लगभग 4 महीने के अंतर के बराबर होता है।
- xliv. केंद्र सरकार शुल्कों में अंतराल के बाद पाटनरोधी शुल्कों की वसूली करने के लिए सीमा शुल्क अधिसूचना भी जारी नहीं कर सकता है।

- xlvi. माननीय प्राधिकारी द्वारा दी गई कोई बिना किसी अधिकार के होगी और यह धारा 9क (5) के अंतर्गत उन्हें उपलब्ध अधिदेश के प्रतिकूल होगा। उक्त जांच को निश्चित रूप से समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
- xlvi. घरेलू उद्योग माननीय न्यायालय को भ्रमित करने का प्रयास कर रहा था जब उन्होंने इस मामले के संबंध में न्यायिक छानबीन के लिए इस न्यायालय से संपर्क किया। परंतु हमें आशा है कि माननीय न्यायालय को भ्रमित करने के इस प्रकार के प्रयास न्यायिक छानबीन की प्रक्रिया के अंत में घरेलू उद्योग के लिए निष्फल साबित होगी और अंततः इन शुल्कों को समाप्त होने की अनुमति दी जायेगी।
- xlvi. भारतीय उत्पादकों ने बहुत चयनित रूप से प्राधिकारी को क्षति के पूर्व में विचारित तस्वीर को दर्शाने के लिए क्षति संबंधी आंकड़े उपलब्ध कराये हैं और तदनुसार, बहुत बड़ा लाभ कमाने वाले उत्पादक जैसे जी एच सी एल ने इस जांच के उद्देश्य से क्षति संबंधी आंकड़े साझा नहीं किये।
- xlix. यदि जी एच सी एल ने वर्तमान मामले में अपने आयात के कारण भाग नहीं लेने का निर्णय लिया है तब यह माना जाना चाहिए जी एच सी एल ने अपना ध्यान निर्माण से व्यापार पर कर दिया है जो यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग ने बार बार विशेष कार्यसूची के साथ प्राधिकारी से संपर्क किया है।
- i. यू एस ए को छोड़कर संबद्ध देशों से पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन या तो नकारात्मक है अथवा न्यूनतम स्तरों से कम है। हालांकि, यह नोट किया जाना संगत है कि घरेलू उद्योग द्वारा जैसा कि प्रस्ताव किया गया है प्राधिकारी ने वर्तमान मामले में संचयी आकलन किया है और संचय करने के अंतर्गत जो संगत है वह घरेलू उद्योग पर संबद्ध देशों से आयातों और न कि किसी विशेष देश से आयातों का समग्र प्रभाव है। घरेलू उद्योग की स्थिति बहुत मजबूत है और संबद्ध देशों पर वर्तमान शुल्कों के समाप्त होने की स्थिति में वहां कोई पाटन अथवा क्षति नहीं हो सकती है।
 - ii. संबद्ध देशों से आयातों में घरेलू उद्योग पर मात्रा संबंधी कोई प्रभाव नहीं डाला जो प्रमुख मात्रा संबंधी मानदंडों जैसे उत्पादन, बिक्री आदि में वृद्धि से स्पष्ट है। घरेलू उद्योग की एन एस आर में कुछ वर्षों के दौरान वृद्धि हुई जबकि सी ओ पी में गिरावट आई। यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग के पास मजबूत कीमत निर्धारण संबंधी शक्ति है और वास्तव में कीमत निर्धारण संबंधी व्यवहार अत्यधिक एकाधिकारवादी है। इस प्रकार से इन आयातों के कारण कीमत तथा घरेलू उद्योग को कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है। कीमत में सकारात्मक कटौती केवल पेपर पर है और इस प्रकार की कीमत पर सकारात्मक कटौती घरेलू उद्योग द्वारा वसूले जाने वाले बहुत अधिक कीमत का परिणाम है।
 - iii. यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता आधार वर्ष में 100 अंकों से बढ़कर जांच की अवधि में 300 अंकों तक पहुंच गई और नियोजित पूंजी पर आय आधार वर्ष में 100 अंकों से बढ़कर जांच की अवधि में 160 अंक तक पहुंच गई। इस प्रकार की वृद्धि को उल्लेखनीय वृद्धि के रूप में देखा जाना चाहिए। वास्तव में, डी एम एफ से संबंधित हाल के एक नये मामले में प्राधिकारी ने यह पाया कि जब लाभप्रदता आधार वर्ष में 100 अंकों से गिरकर जांच की अवधि में 15 अंकों तक पहुंच गई जिसमें जांच की अवधि में नियोजित पूंजी पर आय 6 प्रतिशत से कम थी, कोई शुल्क लगाये जाने की आवश्यकता नहीं है।
 - iiii. घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित नियोजित पूंजी पर आय में यद्यपि प्रवृत्ति के अनुसार पिछले 2 वर्षों की तुलना में गिरावट आई, नियोजित पूंजी पर वास्तविक आय का प्रतिशत अभी भी बहुत अधिक रहता है जिसके कारण प्रवृत्ति में गिरावट कपटपूर्ण और निर्थक हो जाती है। प्राधिकारी क्षति रहित कीमत के उद्देश्य से नियोजित पूंजी पर 22 प्रतिशत आय की अनुमति देते हैं और हमारी समझ यह है कि घरेलू उद्योग 25 से 35 प्रतिशत तक नियोजित पूंजी पर औसत आय अर्जित कर रहा है। रूस और टर्की से सोडा एश के मामले के संबंध में दिनांक 05.07.2018 के प्राधिकारी के आदेश जिसमें प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा 16 अप्रैल, सितंबर, 2017 के दौरान नियोजित पूंजी पर वसूला गया 29 प्रतिशत को देखा है, में यह स्पष्ट है। लाभ का मार्जिन 41 प्रतिशत था और निरमा जैसी कंपनी ने 58 प्रतिशत लाभ मार्जिन अर्जित किया। नियोजित पूंजी पर आय और लाभ के मार्जिन के ये स्तर सामान्य स्थिति नहीं है और स्पष्ट रूप से घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित लाभों के अत्यधिक स्तर को दर्शाते हैं।
 - iv. वास्तव में घरेलू उद्योग उपभोक्ताओं से अधिक वसूली करने के लिए लागू पाटनरोधी शुल्क का दुरुपयोग करते हुए नियोजित पूंजी पर अर्जित इस प्रकार के अत्यधिक लाभ के लिए संरक्षण प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है और इस प्रकार के लाभ स्तर को बनाये रखने के लिए सतत संरक्षण पाटनरोधी शुल्क का अभिष्ट उद्देश्य नहीं है। यह तोड़-मरोड़ जिसे पूर्व में पाया गया था अब पूर्ण रूप से गायब है और घरेलू उद्योग आयातों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है।

- iv. संबद्ध देशों से आयातों में जांच की अवधि के बाद की अवधि में गिरावट आई जिसे हमारे पूर्व के अनुरोध के साथ साथ पढ़ा जाना चाहिए कि जांच की अवधि में आयात मांग आपूर्ति के अंतर के कारण भी आवश्यक हो गया था। यह आयात की मात्रा में संभावित वृद्धि के न होने को दर्शाता है।
- lvi. मैसर्स निरमा लिमि. की यू एस ए में संबद्ध कंपनी भारत में संबद्ध वस्तुओं के निर्माण और निर्यात में शामिल है। निरमा की संबंधित अमरीकी कंपनी ने 2014-15 और 2015-16 के दौरान संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया था।
- lvii. निरमा की संबंधित कंपनी ने भारत में 2014-15 और 2015-16 के दौरान बहुत अधिक मात्रा में निर्यात किया था।
- lviii. नियम 2(ख) की सावधिक व्याख्या को लागू करते हुए, निरमा को पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के साथ पठित नियम 2(ख) के अंतर्गत आधार की जांच के लिए बाहर किया जाना चाहिए।
- lix. आधार विश्लेषण से मैसर्स टाटा केमिकल्स लिमि. को बाहर किए जाने का कारण यह प्रतीत होता है कि टाटा की केन्या में एक संबंधित कंपनी है जिसने क्षति के अवधि के दौरान भारत में संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया था। उसी मानदंड को निरमा पर भी लागू किया जाना चाहिए क्योंकि इसकी एक संबंधित कंपनी यू एस ए में है जिसने क्षति की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया था।
- lx. जब निरमा को आधार विश्लेषण से बाहर किया जायेगा, तब शेष याचिकाकर्ता मैसर्स डी सी डब्ल्यू लिमि. के पास कोई आधार नहीं रहेगा क्योंकि कुल भारतीय उत्पादन में इसका हिस्सा 25 प्रतिशत से नीचे चला जायेगा।
- lxi. चीन जन. गण., यूरोपीय यूनियन, पाकिस्तान, ईरान और यूक्रेन से आयातों के कारण पाटन मार्जिन क्षति की अवधि के दौरान नकारात्मक था। इसके साथ ही जांच की अवधि के दौरान केन्या से आयातों के कारण पाटन मार्जिन न्यूनतम था। क्षति मार्जिन भी यू एस ए को छोड़कर सभी संबद्ध देशों के लिए नकारात्मक था।
- lxii. यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि ईरान और यू एस ए से आयातों के लिए पाटन मार्जिन सकारात्मक है, फिर भी संबद्ध देशों के लिए भारित औसत पाटन मार्जिन इस मामले में नकारात्मक है क्योंकि सात संबद्ध देशों में से पांच के लिए पाटन मार्जिन या तो नकारात्मक है अथवा न्यूनतम है।
- lxiii. वैसा ही तर्क क्षति मार्जिन के लिए दिया जाता है। यद्यपि क्षति मार्जिन यू एस ए के लिए सकारात्मक था, फिर भी सभी संबद्ध देशों के लिए भारित औसत क्षति मार्जिन जांच की अवधि के दौरान नकारात्मक था।
- lxiv. घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत उनकी क्षति रहित कीमत की तुलना में बहुत अधिक है।
- lxv. यह स्पष्ट है कि संबद्ध वस्तुओं से आयातों को पाटित नहीं किया गया था और इसके परिणामस्वरूप जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई।
- lxvi. इस बात का ठोस संकेत है कि यदि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किया गया होता तब पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पाटन और क्षति के फिर से होने की कोई संभावना नहीं है।
- lxvii. इस कारण से, यद्यपि क्षति की अवधि के दौरान यूरोपीय यूनियन, पाकिस्तान, यूक्रेन, ईरान और यू एस ए से आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई फिर भी घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन पर कोई समग्र प्रभाव नहीं पड़ा।
- lxviii. चीन जन. गण., यूरोपीय यूनियन, केन्या, पाकिस्तान और यूक्रेन से आयातों को जांच की अवधि के दौरान पाटित नहीं किया गया था। इस प्रकार की पाटित न किए गए आयातों के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हो सकी। यह इस तथ्य से सिद्ध होता है कि क्षति मार्जिन चीन जन. गण., यूरोपीय यूनियन, केन्या, पाकिस्तान, ईरान और यूक्रेन के लिए नकारात्मक थी।
- lxix. घरेलू उद्योग की संस्थापित क्षमता, उत्पादन, घरेलू बिक्री और क्षमता के उपयोग में क्षति की अवधि की तुलना में पूर्ण रूप से सुधार हुआ है।
- lxx. औसत माल सूची में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई और यह क्षति के अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की संस्थापित क्षमता और उत्पादन में वृद्धि के अनुरूप थी।
- lxxi. कर और ब्याज पूर्व लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय के मामले में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

- lxxii. आधार वर्ष 2013-14 की तुलना में जांच की अवधि के दौरान कर्मचारियों की संख्या में कमी आई थी और आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। आधार वर्ष 2013-14 की तुलना में जांच की अवधि के दौरान मजदूरी में भी वृद्धि हुई।
- lxxiii. घरेलू उद्योग का विकास क्षति के अवधि के दौरान उत्पादन, बिक्री, कर और ब्याज पूर्व लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय में सुधार के मामले में सकारात्मक थी।
- lxxiv. घरेलू उद्योग ने वर्ष 2015-16 और जांच की अवधि में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की अपनी क्षमता में वृद्धि की है।
- lxxv. घरेलू उद्योग ने वर्तमान में बहुत अधिक पूंजी निवेश किया है और आगे क्षमताओं में वृद्धि करने के लिए निवेश की योजना बनाई है। यह इस तथ्य को इंगित करता है कि पूंजी निवेश उगाहने की उसकी क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।
- lxxvi. आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत में कमी आई है। घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में क्षति के अवधि के दौरान भी वृद्धि हुई और यह आयातों की पहुंच कीमत पर विचार किए बिना हुई है।
- lxxvii. चीन जन. गण., यूरोपीय यूनियन और यू एस एस से आयातों की पहुंच मूल्य में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। जांच की अवधि के दौरान केन्या और पाकिस्तान से आयातों का पहुंच मूल्य एक जैसा रहा है। ईरान और यूक्रेन से आयातों की पहुंच मूल्य आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान गिरावट आई है।
- lxxviii. संबद्ध वस्तुओं के आयातों में भारत में संबद्ध वस्तुओं की मांग और आपूर्ति में बहुत अधिक अंतर के कारण वृद्धि हुई। इस वृद्धि का घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत पर प्रभाव नहीं पड़ा।
- lxxix. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में आधार वर्ष 2013-14 से तुलना किये जाने पर जांच की अवधि के दौरान लगभग 3 गुणा वृद्धि हुई है और बिक्री कीमत उनकी क्षति रहित कीमत की तुलना में अधिक है।
- lxxx. आयातों में वृद्धि और आयात किये गए वस्तुओं के प्रति उपभोक्ता की पसंदीगी में परिवर्तन के बीच सह-संबंध का कोई साक्ष्य नहीं है।
- lxxxi. संबद्ध वस्तुओं का डिटेजेंट एवं कांच उद्योग में उपभोक्ता हैं जो व्यापक स्तर पर इन संबद्ध वस्तुओं का उपयोग करते हैं।
- lxxxii. जांच की अवधि और जांच की अवधि के बाद की अवधि अर्थात् 2017-18 के दौरान यू एस डालर की तुलना में भारतीय रुपए के लगातार गिरने के साथ यह संबद्ध वस्तुओं का आयात करने के लिए अधिक से अधिक महंगा हो गया था।
- lxxxiii. भारत में प्रयोक्ता उद्योग संबद्ध वस्तुओं के स्थानीय आपूर्ति पर विश्वास करना जारी रखेगा और तभी संबद्ध वस्तुओं का आयात करेगा जब आपूर्ति में गिरावट हो।
- lxxxiv. जांच की अवधि के बाद की अवधि तथा 2017-18 में, संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा में जांच की अवधि की तुलना में 2.5 प्रतिशत तक गिरावट आई।
- lxxxv. व्यापार पत्रिकाओं पर सचिव (राजस्व), भारत सरकार बनाम भारतीय डायस्टफ्स निर्माण संघ, 2015 (322) ई एल टी 3 (एस सी) के अनुसार पाटनरोधी जांचों में विश्वास नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्त्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए आई एच एस कैमिकल्स पत्रिका के आंकड़ों पर ध्यान निश्चित रूप से नहीं किया जाना चाहिए।
- lxxxvi. घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में क्षति की अवधि की तुलना में 115 अंकों की वृद्धि हुई।
- lxxxvii. यदि कीमत में कटौती जिसका दावा किया गया है, का कोई वास्तविक हानिकारक प्रभाव होता, तब याचिकाकर्त्ता अपनी घरेलू बिक्री को बनाये रखने अथवा उनमें वृद्धि करने में सक्षम नहीं हुए होते।
- lxxxviii. यह तथ्य कि याचिकाकर्त्ताओं ने कीमत में कथित कटौती के बावजूद भारत में इनकी बिक्री का विस्तार करने का प्रबंध किया क्षति के अभाव को दर्शाता है।

- lxxxix. इस प्रकार के तर्क को टूट और बस टायर मामले द्वारा समर्थन दिया गया है जहां पाटनरोधी शुल्क को लगाये जाने को माननीय सेसटेट द्वारा इस आधार पर रद्द किया गया था कि निर्दिष्ट प्राधिकारी के क्षति संबंधी जांच परिणाम में त्रुटि थी और यह कि यदि कीमत में कटौती और कम कीमत पर बिक्री हुई होती, तब बिक्री की मात्रा का अनुरक्षण बहुत मुश्किल हुआ होता।
- xc. सोडा एश के आयातों पर अब पाटनरोधी शुल्क नहीं लगता है क्योंकि पाटनरोधी शुल्क दिनांक 2 जुलाई, 2018 को समाप्त हो गया।
- xc. चूंकि संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क पहले ही दिनांक 2 जुलाई, 2018 को समाप्त हो गया है और निर्णायक समीक्षा अभी भी समाप्त नहीं हुई है, पाटनरोधी शुल्क को बाद की तिथि से लगाना फोरच इण्डिया लिमि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी एवं अन्य, डब्ल्यू. पी. (सी) सं. 2014 का 4810 में दिए गए निर्णय का उल्लंघन हुआ होता और इस प्रकार से यह गैर कानूनी होता।

प्राधिकारी द्वारा जांच

88. प्रकटन पश्चात टिप्पणियों की जांच नीचे दिए गए अनुसार की गई है :

- i. इस अनुरोध के संबंध में की प्राधिकारी को उन आवश्यक तथ्यों जो इसके जांच परिणाम और निष्कर्ष का आधार बनते हैं, को प्रकट नहीं करना चाहिए। यह देखा गया है कि प्राधिकारी ने सभी संबद्ध पक्षकारों को पाटनरोधी नियमावली के नियम 16 के संबंध में विचाराधीन सभी आवश्यक आवश्यक तथ्यों को प्रकट किया था।
- ii. इस अनुरोध के संबंध में कि प्राधिकारी को क्षति रहित कीमत और इसके आधार को प्रकट नहीं करना चाहिए यह देखा गया है कि अधिकारी ने उसे घरेलू उद्योग को पाटनरोधी नियमावली के नियम 16 के संबंध में प्रकट किया था।
- iii. इस अनुरोध के संबंध में कि कीमत पर कोई ह्रास अथवा कीमत न्यूनीकरण नहीं हुआ था क्योंकि पाटनरोधी शुल्क क्षति के अवधि के दौरान लागू थी, यह देखा गया है कि प्राधिकारी ने आयातों के पहुंच मूल्य में पाटनरोधी शुल्क की वृद्धि की बिना इस प्रकार का विश्लेषण किया था और फिर भी कीमत पर कोई ह्रास अथवा कीमत न्यूनीकरण नहीं देखा गया।
- iv. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग के अनुरोधों पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए था। यह देखा गया है कि प्राधिकारी ने वर्तमान जांच परिणाम में उपयुक्त स्थानों पर घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों की जांच की है।
- v. इस अनुरोध के संबंध में कि याचिका में और प्रकटन विवरण में निर्धारित पाटन मार्जिन में बहुत अधिक अंतर है। यह देखा गया है कि प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के अनुसार पाटन मार्जिन विश्लेषण किया है और उसे सभी हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट किया गया है। किसी भी पक्षकार ने यह सिद्ध नहीं किया गया है कि किस प्रकार से प्राधिकारी के क्षति मार्जिन का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुरूप नहीं है। इस अनुरोध के संबंध में की मूल्यवर्धित कर का समायोजन चीन जन. गण. के लिए कारखानागत निर्यात कीमत में किया जाना चाहिए। यह देखा गया है कि प्राधिकारी ने चीन जन. गण. के लिए कारखानागत निर्यात कीमत का निर्धारण करने में मूल्यवर्धित कर के समायोजन का लागू किया है।
- vi. इस अनुरोध के संबंध में कि दुलाई संबंधी लागत क्षति रहित कीमत का हिस्सा होना चाहिए, यह देखा गया है कि वर्तमान जांच परिणामों में उपयुक्त स्थानों पर किये गये उल्लेख के अनुसार, प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध III के अनुसार क्षति रहित कीमत का निर्धारण किया है। प्राधिकारी ने क्षति रहित कीमत और पहुंच मूल्य की तुलना व्यापार के उसी स्तर पर किया है।
- vii. इस अनुरोध के संबंध में कि संबद्ध वस्तुओं के आयातों में पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में वृद्धि होगी, जांच की अवधि के बाद की अवधि अर्थात् 2017-18 के लिए आयात संबंधी आंकड़ों के विश्लेषण से यह देखा गया है कि संबद्ध वस्तुओं के आयातों में 2016-17 की तुलना में 2.5 प्रतिशत तक गिरावट आई। अन्य आर्थिक मानदंडों का विश्लेषण यह नहीं दर्शाता है कि पाटन और क्षति के उस स्थिति में जारी रहने अथवा फिर से होने की संभावना है यदि संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया गया होता।
- viii. इस अनुरोध के संबंध में कि कीमत में कटौती संबद्ध देशों के लिए सकारात्मक और बहुत अधिक है, यह देखा गया है कि एक निर्णायक समीक्षा में, कीमत में कटौती एकमात्र निर्धारक कारक नहीं है। प्राधिकारी ने ऐतिहासिक रूप से घरेलू उद्योग के मात्रा संबंधी प्रभावों और कीमत संबंधी प्रभावों के लिए सभी संगत आर्थिक मानदंडों की सुव्यवस्थित

तरीके से जांच की है तथा इस मामले में पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन की भी जांच की है। यह विश्लेषण इस सत्य हो दर्शाता है कि याचिकाकर्त्ताओं का कार्य निष्पादन लाभ, नियोजित पूंजी पर आय, क्षमता का विस्तार, उत्पादन और बिक्री के मामले में जांच की अवधि सहित क्षति की अवधि के दौरान अच्छा रहा है। याचिकाकर्त्ताओं की बिक्री कीमत याचिकाकर्त्ताओं की क्षति रहित कीमत की तुलना में बहुत अधिक पाई गई थी। कीमत पर कोई ह्रास और कीमत न्यूनीकरण नहीं हुआ है। पाटन मार्जिन को चीन जन. गण., यूरोपीय यूनियन, केन्या, पाकिस्तान और यूक्रेन के लिए न्यूनतम अथवा नकारात्मक पाया गया था। क्षति के मार्जिन को चीन जन. गण., यूरोपीय यूनियन, केन्या, पाकिस्तान, ईरान और यूक्रेन के लिए नकारात्मक पाया गया था। भारत और क्षति मार्जिन सभी संबद्ध देशों के लिए नकारात्मक पाया गया था। संबद्ध वस्तुओं के आयातों में क्षति की अवधि के बाद की अवधि के दौरान 2.5 प्रतिशत तक गिरावट हुई। याचिकाकर्त्ता यह सिद्ध करने में सक्षम नहीं हो पाये हैं कि क्षति पहुंचाने वाले पाटन के संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में जारी रहने अथवा फिर से होने की संभावना है। याचिकाकर्त्ताओं के कार्य निष्पादन में बहुत अधिक सुधार से उत्साहित होकर, 10 लाख मी. ट. नई क्षमताओं को या तो पहले ही शुरू कर दिया गया है (निरमा और जी एच सी एल द्वारा) अथवा अन्य भारतीय उत्पादकों द्वारा शुरू किए जाने के करार पर है जैसा की याचिकाकर्त्ताओं द्वारा मान लिया गया है। याचिकाकर्त्ताओं ने आगे यह माना है कि 20 लाख मी. ट. की क्षमता में वृद्धि की योजना इस चरण में बनाई जा रही है क्योंकि इस उत्पाद के लिए भारतीय बाजार अक्षम रहा है। याचिकाकर्त्ताओं की नियोजित पूंजी पर आय क्षमता विस्तार की बहुत अधिक लागत होने के बावजूद बहुत अधिक रहती है।

- ix. इस अनुरोध के संबंध में कि प्राधिकारी ने पाटन और क्षति की संभावना अथवा उसके फिर से होने के संबंध में पर्याप्त विश्लेषण नहीं किया है, यह देखा गया है कि प्राधिकारी ने वर्तमान जांच परिणाम के उपयुक्त स्थानों पर इस संबंध में विस्तृत विश्लेषण किया है।
- x. इस अनुरोध के संबंध में कि प्राधिकारी को विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुरोधों पर विचार करना चाहिए यह देखा गया है कि प्राधिकारी ने इस प्रकार के अनुरोधों को दर्ज किया है और उसकी जांच वर्तमान जांच परिणाम में उपयुक्त स्थानों पर किया है।
- xi. इस अनुरोध के संबंध में कि हितबद्ध पक्षकारों को जांच की अवधि के बाद की अवधि से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। यह देखा गया है कि प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार हितबद्ध पक्षकार जांच की अवधि के बाद की अवधि से संबंधित आयात आंकड़ों के लिए अनुरोध कर सकते हैं। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जांच की अवधि के बाद की अवधि से संबंधित आयात आंकड़ों को प्राप्त करने के संबंध में प्राधिकारी से संपर्क नहीं किया है। किसी भी मामले में जांच की अवधि के बाद की अवधि से संबंधित आयात आंकड़े सार्वजनिक फाइल में रखे गये थे और सभी हितबद्ध पक्षकार उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद इसे प्राप्त कर सकते थे।
- xii. इस अनुरोध के संबंध में कि प्राधिकारी संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी को कानूनी रूप से जारी रखने की सिफारिश नहीं कर सकते हैं और स्पष्टगामी अथवा बाद की स्थिति के प्रभाव से कोई भी अधिसूचना जारी नहीं की जा सकती है। यह देखा गया है कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 और पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत, पाटनरोधी शुल्क लगाने अथवा नहीं लगाने का अंतिम निर्णय केंद्र सरकार के पास है।

ण. निष्कर्ष एवं सिफारिशें

89. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों की जांच करने के बाद और उपर्युक्त तथ्यों, परिस्थितियों और विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी का निष्कर्ष नीचे दिए गए अनुसार है :
 - i. घरेलू उद्योग के वित्तीय और आर्थिक मानदंड (मात्रा और कीमत दोनों) स्थिर हैं और पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता के साथ गिरावट का कोई साक्ष्य नहीं है।
 - ii. याचिकाकर्त्ताओं ने लाभ, नियोजित पूंजी पर आय, क्षमता का विस्तार, उत्पादन और बिक्री के मामले में जांच की अवधि सहित क्षति की अवधि के दौरान भी बहुत अच्छा कार्य किया है।
 - iii. याचिकाकर्त्ताओं की बिक्री कीमत याचिकाकर्त्ताओं की क्षति रहित कीमत की तुलना में बहुत अधिक पाई गई थी।
 - iv. कीमत पर कोई ह्रास और कीमत न्यूनीकरण नहीं था।

- v. पाटन मार्जिन चीन जन. गण., यूरोपीय यूनियन, केन्या, पाकिस्तान और यूक्रेन के लिए न्यूनतम अथवा नकारात्मक पाया गया था।
- vi. क्षति मार्जिन चीन जन. गण., यूरोपीय यूनियन, केन्या, पाकिस्तान, ईरान और यूक्रेन के लिए नकारात्मक पाया गया था। भारत और सत क्षति मार्जिन सभी संबद्ध देशों के लिए नकारात्मक पाया गया था।
- vii. याचिकाकर्ता यह सिद्ध करने में सक्षम नहीं हो पाये हैं कि क्षति पहुंचाने वाले पाटन संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना है।
- viii. उद्योग की क्षमता, उत्पादन, घरेलू बिक्री और समग्र लाभप्रदता क्षति के मौजूद होने अथवा खराब आर्थिक स्थिति होने का संकेत नहीं देता है।
- ix. याचिकाकर्ताओं द्वारा पाटनरोधी शुल्क के वापस लिये जाने पर क्षति के फिर से होने की संभावना के संबंध में प्रस्तुत किये गये कारकों को कीमत प्राप्ति तथा जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की कीमत की प्रवृत्ति से समर्थन नहीं दिया गया है।
- x. याचिकाकर्ताओं के कार्य निष्पादन में पर्याप्त सुधार के कारण 10 लाख मी. ट. की नई क्षमताएं या तो पहले ही शुरू की जा चुकी हैं (निरमा और जी एच सी एल द्वारा) अथवा अन्य भारतीय उत्पादकों द्वारा आरंभ किए जाने के करार पर है, जैसा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा मान लिया गया है।
- xi. 20 लाख मी. ट. की क्षमता की वृद्धि की योजना इस चरण में बनाई जा रही है क्योंकि इस उत्पाद के लिए भारतीय बाजार अक्षम रहा है।
- xii. याचिकाकर्ताओं की नियोजित पूंजी पर क्षमता विस्तार में बहुत अधिक लागत लगने के बावजूद बहुत अधिक रही है।
90. प्राधिकारी उपयुक्त कारणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि पाटनरोधी शुल्क को जारी रखना आवश्यक नहीं है और तदनुसार, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क को आगे बढ़ाने की सिफारिश नहीं करते हैं।
- त. आगे की प्रक्रिया**
91. इस अधिसूचना के विरुद्ध कोई भी अपील सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 और मैसर्स जिंदल पोली फिल्म लिमि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी डब्ल्यू. पी. (सिविल) सं. 8202/2017 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद और सेवा कर अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष किया जायेगा।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं महानिदेशक

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th December, 2018

FINAL FINDINGS

Sub: Anti-dumping Sunset Review Investigation concerning imports of “Soda Ash”, originating in or exported from China PR, European Union, Kenya, Pakistan, Iran, Ukraine and USA.

F. No. 7/5/2017-DGAD.—A. BACKGROUND OF THE CASE

- Whereas, having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as “AD Rules”), the Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”) had notified its final findings vide Notification No.14/17/2010-DGAD dated 17th February, 2012, recommending imposition of definitive anti-dumping duties on the imports of “Soda Ash” (hereinafter referred to as the “subject goods” or “product under

consideration”), originating in or exported from China PR, the European Union, Kenya, Pakistan, Iran, Ukraine and USA (hereinafter referred to as the subject countries). The definitive anti-dumping duties were imposed by the Central Government vide Notification No. 34/2012- Customs (ADD) dated 3rd July, 2012.

2. And whereas, the Authority having completed a mid-term review recommended withdrawal of anti-dumping duty on the subject goods vide Final Findings No. 15/28/2014-DGAD dated 22 July 2017, and accordingly annulled the sunset review *vide* Notification No. 7/5/2017-DGAD dated 22 July 2017 too simultaneously.
3. And whereas, the Petitioners challenged the aforesaid mid-term review Final Findings and sunset review annulment order before the Hon’ble High Court of Gujarat at Ahmedabad. In pursuance of order dated 11 June 2018 in Special Civil Application Nos. 14202 to 14207 of 2017 and Misc. Civil Application No. 2 of 2018 in Special Application No. 14202 of 2018; and final order dated 15 June 2018 in Misc. Civil Application No. 3 of 2018 in Special Civil Application No. 14204 of 2018, the Hon’ble High Court of Gujarat set aside the aforementioned mid-term review Final Findings and the sunset review annulment order. The Hon’ble High Court also extended the timeline to complete the sunset review by six months and directed the Authority to complete the sunset review as per procedure.
4. Whereas in terms of Section 9A(5) of the Customs Tariff Act 1995 as amended, the anti-dumping duty imposed shall unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review, whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In accordance with the above, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.
5. Whereas, M/s Nirma Ltd. and M/s DCW Ltd. (hereinafter referred to as Petitioners) had jointly filed a petition in accordance with the Act and the Rules, seeking initiation of a sunset review of anti-dumping duty in force on import of “Soda Ash” for extending the duties for a further period of five years, alleging likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury of the subject goods originating in or exported from China PR, the European Union, Kenya, Pakistan, Iran, Ukraine and USA.
6. The Designated Authority initiated sunset review vide Notification No. 7/5/2017-DGAD dated 16 June 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, to examine whether the expiry of anti-dumping duty would lead to continuation or recurrence of dumping or injury. The initiation of sunset review however was subject to the final outcome of the mid-term review which was underway.

B. PROCEDURE

7. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:
 - i. The Authority sent copies of the initiation notification dated 16 June 2017 to the embassies of the subject countries in India, known exporters from the subject countries, known importers and other interested parties, and the domestic producers, as per available information. The known interested parties were requested to file the questionnaire responses and make their views known in writing within the prescribed time limit.
 - ii. Copies of the letter and questionnaires sent to the exporters were also sent to embassies of the subject countries along with a list of known exporters/producers, with a request to advise the exporters/producers from the subject countries to respond within the prescribed time.
 - iii. Copy of the non-confidential version of the petition filed on behalf of the Petitioners was made available to the known exporters, domestic producers and the embassies of the subject countries in accordance with Rule 6(3) of the AD Rules.
 - iv. The Authority forwarded a copy of the public notice initiating the sunset review to the following known producers/exporters in the subject countries and gave them opportunity to make their views known in writing within forty days from the date of the letter in accordance with the Rules 6(2) & 6(4) of the AD Rules:

Shandong Haihua Group, Shandong Haihua Group Co., Ltd. Develop Zone of Haihua Weifang City, Shandong, China
Qinghai Alkali Plant (Zhejiang Glass Chaina's Qingtai Alkali Plant (Zhejiang Glass China's Qinghai Delingha Industrial Park Zip:817000 – China
Jinshan chemical co. China's Zhengzhou City in Henan Province, Zhengzhou City Fushoushan Street 87,China
Hebei Tangshan Sanyou Al kali Industry Company Nanpu Development Area,TangShan,Hebei,China
Tianjin Soda Ash Plant No. 87Xinhua Road Tangg u District Tianjin China
SIMAN LTD Pob 29 Kazanlak SL Zagora Bulgaria 6103
Solvay Sodi AD Zip Code: 9160 Bosnia and Herzegovina Brunner Monday Winnington Lane Mond House, Northwich, Cheshire, UK, CW8 4DT
SPIN INTERNATIONAL 13 RUE DE PASSY Paris 75016
BELVEDERE SRL ROMANIA Cetatianu Ioan GALATI, Romania 800198
Asha Trade Import Export Mangaliei Nr 71 BL PIS SC D Apt 36 Constanta 900116Romania
GHCL Romania Ghcl Upsom Ocna Mures Alba County Romania 515700
Sisccam Sode Lukavac, The first street 1 75300, Lukava Bosnia and Herzegovina
Magadi Soda Company P O Box 1 - 00205, Magadi, Kenya.
ALLIED NETWORKX COMPANY LTD Asili Co-Op House Moi Avenue Nairobi Kenya 72964 00200
FMC Industrial Chemicals 1735 Market Street Philadelphia, PA 19103 USA
OCI Chemical Corporation 1800 West Oak Commons Court Suite 100

Marietta, GA 30062
SOLVAY SODA ASH Headquarters 5333 Richmond Ave., Houston, TX 77098 Mailing address: P.O. Box 27328, Houston, TX 77227
General Chemicals Industrial Products 120 Eagle Rock Avenue East Hanover, New Jersey, USA.
ANSAC 15 Riverside Avenue 2nd Floor Westport, CT 06880 USA
FMC Corporation Wells Fargo Bank N.A. Shareowner Services P.O. Box 64854 St. Paul, MN 55164-0854 Or 161 N. Concord Exchange South St. Paul, MN
Soda Ash Soda Ash Business ICI Pakistan Limited 63-Mozang Road Lahore, Pakistan
Olympia Chemicals Ltd. 23-Davis Road, Lahore, Pakistan
Syrina Trade Co., Arum s.88 office 251a Donetsk, Ukraine

- v. In response to the initiation of the sunset review, no producer/exporter from the subject countries filed any response to the questionnaire or made any submission.
- vi. Questionnaires were sent to the following known importers/users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules:

Gujarat Guardian Ltd, Village- Kondh, Valia Road, Plant Sate Highway No.13, Ankleshwar, Bharuch 393001
Float Glass India Ltd., T-7, Midc, Industrial Area, Taloja, Maharashtra
Hindustan National Glass & Ind. Ltd., Rishra, West Bengal
Procter & Gamble Hygiene & HealthCare, Mandideep Plnt L&C-MFG, Plot No.182, Mandideep, Madhya Pradesh
Advatecg Industries Pvt Ltd, Dhanali, Village –Dhanali, Al-Kadi Distrcit, Mahesana, Gujarat
U.P. Glass Manufacturer, Syndicate, 14-Monapuram, Near Ganesh Nagar, Firozabad-283203, U.P.
Fena (P) Ltd, A-237, Okhla Industrial Area, Phase I, New Delhi-20
Pollachi Chamber of Commerce & Industry, RP Complex, IInd floor, 14, Balagopalapuram Street, Pollachi-642001

Power Soap ltd, 62-B, North Boag Road, T.Nagar Chennai – 600017
Alembic Glass Industries Ltd, Alembic Road, Baroda (Vadodara) Gujarat
Deepak Nitrite Ltd, 4/12, Chemical Complex, GIDC, Nanfessari, Baroda (Vadodara) Gujarat
Hindustan Unilive Ltd., Party Address Dakshina Building, 8th Floor, Plot No-2 Sector-11, CBD Belapur, Navi Mumbai
Albright Morarji & Pandit Ltd, Ambernath, Dist. Thane, Maharashtra
Saint-Gobain Glass India, Head Office and Plant: A-1 SIPCOT Industrial Park, Sriperumbudur-602105, Kanchipuram District – Tamil Nadu
Asahi India Glass Ltd., 5th Floor, Tower-B, Global Business Park, Mehrauli-Gurgaon Road, Gurgaon-122002(India)
Shree Union Organics P Ltd, BS-3, Apeejay. 130, Bombay Samachar Marg, Mumbai-23
Vasundhara Rasayan Ltd, C-104, MIDC Industrial Area, Mahed, Dist. Raigad, Maharashtra
Shantinath Detergents Pvt Ltd, P-15, Kalakar Street, Kolkata-700007
Advance Home & Personal Care Ltd, Advance Surfactants India Ltd, 511/2/1, Village Rajokri, New Delhi-38
S. Kumar Detergent P. Ltd, Plot No.34, Sector-2, Industrial Area, Pithampur-454775 Distt Dhar, M.P.
Hind Silicates Pvt Ltd., 3A, Auckland Place, 5th floor, Kolkata-17
P & J Cretechem (P) Ltd, 318, Swapnalok, 92/93, SD Road, Secunderabad-500003, AP, India
J.J. Patel Industries, Gondal Road, B/H Rajkamal Petrol Pump, Vavdi, Rajkot-360004
Modern Glass Industries, Coal Siding Road, S.N. Road, Firozabad-283203
Sandeep Organics Pvt Ltd., 104, Nain Krupa, 118/122, Kazi Syeed, Street, Masjid Bunder (West), Vadgadi, Mumbai -400003
Alembic Glass Industries Ltd., Alembic Road, Baroda(Vadodara) Gujarat
Rohit Surfactants(P) Ltd., 117/H-2/202, Pandu Nagar, Kanpur-05
BDJ Glass Industries Pvt. Ltd, 1 Kyd Street, Place Court, 1 st Floor, Suite-14-A, Kolkata-700016
Jagatjit Industries Ltd., Plot No.78, Sector-18, Institutional Area, Gurgaon-122001
Haldyn Glass Gujarat Ltd., 9, Gayatri Commercial Complex, Behind Mittal Industrial Estate No.5, Andheri Kurla Road, Marol Naka, Andheri(E), Mumbai-400059
Hipolin Limited, Madhuban”, 4 th Floor, Ellisbridge, Ahmedabad-380006
Modern Glass Industries, Coal Siding Road, S.N. Road, Firozabad-283203
Detergent Manufacturers, Association (Delhi Region) 148, New Okhla Industrial Complex-1, New Delhi-110020

Mauli Exports, Plot No.97-98, Sector – 25, Part-II, Industrial Area, HUDA, Panipat – 132 104, Haryana
M/s Chempex International, 393/III/6 Bazer, Bikanerian, Katra, Ahluwalia, Amritsar, Punjab
Tata Chemicals Ltd., Leela Business Park, Andheri Kurla Road, Andheri (E), Mumbai -59
M/s Tuticorin Alkali Chemicals and Fertilizers Ltd., 534, Anna Salai, Teynampet, Chennai -18
AGI Glasspac, Glass factory Road, Moti Nagar, Post Box. 1930,Shanth Nagar, Hyderabad – 500 018
Power Soaps Ltd., A-8, 1st Main Road, Ambattur Industrial Estate Chennai – 600 058
Hindcon Chemicals (P) Ltd., 62/B, Braunfled Row, 1st floor, Calcutta – 700 027
Empire Industries Ltd., Empire House, 414, Senapati Bapat, Lower Parel, Mumbai – 13

- vii. In response to the above notification, no importer/user filed any response to the questionnaire or made any submission.
- viii. Questionnaires were also sent to the known domestic producers of the subject goods in India for necessary information and response.

S.NO.	Name of domestic producer
i.	M/s GHCL Ltd.
ii.	M/s Tata Chemicals Ltd.
iii.	M/s Saurashtra Chemicals Ltd.

- ix. Initiation notification was also sent to the following associations:

S.NO.	Name of association
i.	Detergent Manufacturers Association (Delhi Region)
ii.	Indian Chemical Merchants & Manufacturers Association
iii.	Bulk Drug Manufacturers Association(India)
iv.	Indian Glass Manufacturers' Association
v.	The Dyers & Chemical Merchants Association
vi.	All India Glass Manufacturer's Federation
vii.	Alkali Manufacturers Association of India
viii.	Indian Soap & Toiletries Maker's Association

- x. The following parties made submissions during the course of this investigation:
- Embassy of Ukraine
 - Detergent Manufacturers Association of India
 - All India Glass Manufacturers Federation
 - Saint Gobain India Pvt. Ltd.
 - Hindustan Unilever Ltd.
 - Olympia Chemicals Ltd., Pakistan
- xi. Exporters, producers and other interested parties who have not responded to the Authority, nor supplied information relevant to this investigation, have been treated as non-cooperating interested

parties.

- xii. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to arrange for details of imports of subject goods for the past three years, including the period of investigation. The Authority has, therefore, relied upon the DGCI&S data for computation of the volume of imports and analysis of other parameters.
- xiii. Optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) was worked out so as to ascertain if anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to Domestic Industry. The NIP has been determined by the Authority in terms of the principles laid down under Annexure III to the AD Rules.
- xiv. Investigation was carried out for the period starting from April 2016 – March 2017 (hereinafter referred to as the “POI”). However, injury examination covered the periods 2013-14, 2014-15, 2015-16 and the POI.
- xv. In accordance with Rule 6(6) of the AD Rules, the Authority also provided opportunity to the interested parties to present their views orally in the oral hearing held on 5 November 2018. The parties, which presented their views in the oral hearing, were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions.
- xvi. The submissions made by the interested parties during the course of the investigation have been considered by the Authority, wherever found relevant, in the present findings. Verification to the extent deemed necessary was carried out in respect of the information and data submitted by the domestic industry.
- xvii. Information provided by interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- xviii. Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has recorded the present findings on the basis of available facts.
- xix. The Authority disclosed essential facts under consideration to all parties vide disclosure statement dated 27.11.2018. Adequate time was given to all parties to submit their comments on the disclosure statement. Submissions of all parties on the disclosure statement have been recorded and examined at appropriate places in the present findings.
- xx. *** represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- xxi. The average exchange rate of 1US\$ = Rs. 67.95 prevailing during the POI has been adopted by the Authority.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

Submissions made by the Petitioners

- i. The product under consideration is Disodium Carbonate, also known as Soda Ash, having chemical formula Na_2CO_3 in all its form and produced through any process.
- ii. Soda Ash is produced in two forms- Light Soda Ash and Dense Soda Ash.
- iii. It is produced through synthetic process as also extracted from natural sources.
- iv. The scope of investigation is the same as the original investigation.
- v. Soda Ash is classified under customs sub-heading No. 2836.20 under the Customs Tariff Act, 1975 and includes the tariff headings 28362010, 28362020, 28362090.

- vi. There is no known difference in subject goods produced by the domestic industry and subject goods exported from subject countries.
- vii. Subject goods produced by the domestic industry and imported from subject countries are having comparable characteristics in terms of parameters such as physical and chemical characteristics, manufacturing process, technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing and tariff classification of the goods. Soda Ash produced by the domestic industry and that imported from the subject countries are thus treated as Like Articles.

Examination by the Authority

8. The product under consideration in the original investigation as well as in the present sunset review is 'Soda Ash'. In the original investigation, the product scope was defined as under:

"i. The product under consideration in the present investigation is Disodium Carbonate, also known as Soda Ash having chemical formula Na_2CO_3 . Soda Ash is produced in two forms - Light Soda Ash and Dense Soda Ash. The difference in the two types is bulk density. It can be produced through synthetic route and natural route, known as dissolution process. The present investigation includes all types and forms of Soda Ash.

ii. Soda Ash is an essential ingredient in the manufacture of detergents, soaps, cleaning compounds, sodium-based chemicals, float glass, container and specialty glasses, silicates and other industrial chemicals. It is also widely used in textiles, paper, metallurgical industries and desalination plants. Soda Ash is classified under Chapter 28 of the Customs Tariff Act under subheading No. 2836.20. The customs classification is, however, indicative only and is not binding on the scope of the present investigation."

- 9. No interested party has raised any issue regarding the scope of product under consideration and like articles.
- 10. The authority confirms that the product under consideration in this sunset review investigation is the same as defined in the original investigation. The authority also holds that the product produced by the domestic industry is a like article to the product under consideration.

D. Scope of Domestic Industry and Standing

Submissions made by the Petitioners

- i. Barring GHCL and Tata Chemicals, none of the companies have themselves imported the subject goods during the POI.
- ii. Tata Chemicals has related producers in Kenya, US and Europe. The Kenyan and US Companies are subsidiaries of Tata Chemicals which has exported goods to India. In view of the decision of the Authority in the original investigation, the petitioners have treated Tata Chemical as ineligible domestic industry.
- iii. GHCL has imported the product under consideration from amongst subject countries. However, the details of this are publicly unavailable to the petitioners. GHCL may be considered as ineligible domestic industry if it is deemed fit.
- iv. M/s Nirma has a related producer in USA, which has exported Soda Ash to India upto March 2016. No exports have been made by this company in the POI.
- v. It has been submitted that standing is not a mandatory requirement in a sunset review investigation. Rule 23 specifically excludes Rule 5.
- vi. The request for extension of ADD is based on likelihood of recurrence of injury.
- vii. Since no injury has been claimed, there is no reason to require analysis of data for all domestic producers.
- viii. The production of the petitioning companies constitutes a major proportion in Indian production.
- ix. The petitioners cannot be denied relief just because other Indian producers have not produced relevant information.

Submissions made by other interested parties

- i. M/s Nirma Ltd. has a related producer in subject country i.e. USA and that there were no exports made by the said related producer to India during the POI.
- ii. Mere existence of imports does not automatically render a domestic producer ineligible under Rule 2(b) of the AD Rules. The Authority has the discretion to determine the scope of Domestic Industry.
- iii. It is submitted that the domestic industry may be excluding GHCL merely because of its positive performance in the past few years.
- iv. M/s Nirma Ltd. has a related company in USA that is involved in manufacturing and export of the subject goods to India. This related company has exported the subject goods during the entire injury period. As per Rule 2(b) of the AD Rules, the domestic industry should not compromise of producers that are related to exporters of the subject goods.
- v. The production of the Petitioners does not constitute a major proportion in the total Indian production in terms of Rule 2(b) of the AD Rules.
- vi. On comparison of the production data with the sales data of the Petitioners and Other Indian Producers, there is a gross mismatch in the annual production of Other Indian Producers and their domestic sales.
- vii. While the domestic industry's production is more than its domestic sales, on the other hand, annual production of other Indian producers seems almost half of their annual domestic sales.
- viii. There is gross mismatch on the annual production data of other Indian Producers and annual domestic sales' data of other Indian Producers.
- ix. The data produced has been skewed by the domestic industry solely for the purpose of falsely establishing standing in this case under Rule 2(b) of the AD Rules.
- x. If the correct production data of other Indian Producers is used, the Petitioners will no longer have major proportion in the total Indian production, thus failing to qualify as domestic industry in terms of Rule 2(b).
- xi. M/s Tata Chemicals Ltd. has a related company in Kenya and M/s GHCL had imported the subject goods and have been claimed to be excluded from the domestic industry by the Petitioners. Applying the same logic, M/s Nirma Ltd. should also be excluded since it has a related company in USA.
- xii. Tata Chemicals Ltd and M/s GHCL Ltd. have not been mentioned in the List of Importers, in Annexure 1.4 of the Petition.

Examination by the Authority

11. The Authority notes that Rule 2(b) of the AD Rules read as follows:

“domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”.

12. Rule 2(b) of the AD Rules provides that domestic producers which are related to the exporters or importers or which are themselves importers of the allegedly dumped articles may be excluded when determining the domestic industry.

13. The Authority notes that in the original investigation, the domestic industry constituents were involved in imports of subject goods from the subject countries or were related to the exporters/importers of subject goods from the subject countries. In the final findings of the original investigation, the Authority in the final findings no. 14/17/2010-DGAD dated 17.02.2012 had noted as below:

“49. The Authority considers that the domestic producers who import an insignificant quantum of the dumped goods or whose related exporter exports the dumped goods or whose related importer imports the dumped goods do not unduly benefit from dumping practices, if these imports do not

represent a significant part of their sales or market size. Indeed, no advantage occurs to such domestic producers because of the competition from other suppliers in the market. The Authority also notes that another distinction drawn by the Investigating authorities of other countries, while deciding whether a domestic producer should be excluded is: Is the domestic producer merely supplementing its domestic production with some dumped imports or whether it is primarily an importer with relatively limited production? The Authority considers that in the latter case, such company should be excluded from the scope of domestic industry. Another element which can be considered is whether or not the domestic producer in question is committed to production in the country of imports.

50. In view of the above, the Authority holds that the only relevant issue for determination is whether or not GHCL, Nirma, SCL and Tata Chemicals should be treated as eligible domestic industry. In the instant case, there is no allegation that any of the domestic producers is related to an importer. The arguments of the interested parties are that SCL, Nirma and GHCL should be treated as ineligible domestic industry in view of their relationship with foreign producers/exporters in subject countries or, in case of Nirma, additionally because of imports made by Nirma.

51. The Authority has examined the issue of eligibility of the applicant companies by applying the aforesaid principles to the facts and circumstances of the present case. The facts of the instant case are as follows in so far as the issue of relationship and eligibility of the applicant companies is concerned.

- i. The application was filed by Alkali Manufacturers' Association of India (AMAI). AMAI is an association of producers of caustic soda (including chlorine) and soda ash.
- ii. DCW, GHCL, Nirma and Saukem have provided information relevant to injury to the domestic industry and have requested to be considered as "domestic industry" for the purpose of the present investigation. These companies are being treated as "participating companies". The petition has express support of all Indian Producers of soda ash during POI, except Tata Chemicals. Tata Chemicals has neither supported nor opposed the imposition of anti-dumping duties. It is however noted that Magadi Soda Company, Kenya (renamed as Tata Chemicals Magadi Ltd) is a 100% subsidiary of Tata Chemicals and the company is participating in the present investigations by filing exporters' questionnaire response.
- iii. Post initiation and after holding of 1st oral hearing, Tuticorin Alkali Chemicals (TAC) has filed its written submissions vide their letter dated 23rd May, 2011 supporting the application and requesting the Designated Authority to impose anti-dumping duties. It is noted that TAC has not participated in the proceedings by way of filing response to the initiation notification. It is also noted that they were not producing the subject goods during POI. The Authority has, therefore, not considered the submissions of TAC at this belated stage.
- iv. None of the petitioner companies are related to any of the importers of the product under consideration in India;
- v. DCW Ltd. does not have any related producer-exporter outside India. The company has not imported the product under consideration, nor is the company related to any exporter or importer. There is no dispute that DCW is an eligible domestic producer constituting 'domestic industry'. Petitioner has strongly contended that in the event the Authority holds that GHCL, Nirma and SCL are ineligible domestic industry, DCW alone shall constitute domestic industry, as the production of the company in that event shall constitute 100% of the "production by the domestic industry".
- vi. SCL and Nirma are undisputedly related companies.
- vii. Nirma has imported soda ash from its related supplier in USA. Barring Nirma, none of the petitioner companies have themselves imported the material from any of the subject countries during the entire injury period.
- viii. GHCL has a related company in Romania, namely S.C. GHCL Upsom. The related exporter of GHCL has exported Soda Ash to India over the current injury period. GHCL has also

provided details of their related company in Romania regarding production and exports to India (volume information only). Details of exports made by related exporter over the injury period show that (a) these exports have been directly made by the Romanian company to unrelated Indian customers during the POI, and (b) the volume of exports by the company steeply declined over the injury period. Table below shows the volume of exports from Romania, exports by GHCL Upsom and other relevant details.

S. No.	Particulars	Unit	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
A	(a) Exports by S.C. GHCL Upsom	MT	17,356	51,353	6,489	4,101
B	Exports to related parties	MT	11,082	-	-	-
C	Exports to unrelated Indian parties	MT	6,274	51,353	6,489	4,101
D	(b) Total imports from Romania	MT	46,594	67,121	7,652	47,148
2	Exports made by S.C. GHCL Upsom in relation to	MT	17,356	51,353	6,489	4,101
A	Indian production		0.85%	2.54%	0.32%	0.20%
B	Indian Consumption		0.80%	2.33%	0.29%	0.17%
C	Production of GHCL		3.31%	8.68%	1.05%	0.61%
D	Imports made by GHCL in relation to					
A	GHCL's production		2.11%	0.00%	0.00%	0.00%
B	Indian production		0.54%	0.00%	0.00%	0.00%
C	Indian consumption		0.51%	0.00%	0.00%	0.00%
3	Gross imports from Romania	MT	46,594	67,121	7,652	47,148
A	• Exports by GHCL Upsom	MT	17,356	51,353	6,489	4,101
B	• Exports by Other exporters	MT	29,238	15,768	1,163	43,047
C	Share of GHCL Upsom in total exports from Romania		37.25%	76.51%	84.80%	8.70%

52. The Authority holds that:

- (i) GHCL Upsom is not the majority exporter of soda ash from Romania. Other exporters from Romania constitute majority exports from Romania.
- (ii) Exports by GHCL Upsom declined significantly in absolute terms as also in relation to imports from Romania.
- (iii) Exports by GHCL Upsom are quite insignificant when compared with total imports of soda ash in India, production of soda ash by GHCL and consumption of soda ash in India.
- (iv) The imports were not made by GHCL, India. The imports were made directly by unrelated consumers.
- (v) The volume of exports by GHCL Upsom is not so significant as to have caused or provoked injury to the domestic industry.

(vi) *Focus of GHCL continues to be on production. The company has not turned trader. Nor the company has unduly benefited from dumping. In fact, imposition of anti-dumping duty would imply imposition of anti-dumping duty on exports made by GHCL Upsom as well. The injury determination shall not get distorted by including GHCL within the scope of the domestic industry.*

(vii) *None of the opposing interested parties have advanced any justification for exclusion of GHCL from the scope of the domestic industry, barring the fact of relationship itself.*

53. *SCL & Nirma have related producer in USA, namely Searles Valley Minerals. Details of exports made by related exporter over the injury period show that (a) these exports have been made only during the POI, (b) the exports have been made to Nirma, (c) Nirma has used this material for self-consumption. Table below shows the volume of exports from US, exports by Searles Valley Minerals (related producer of Nirma and SCL in USA) and other relevant details:*

S. No.		Unit	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1	(a) Exports by Searles Valley Minerals	MT	-	-	-	2,700
	Exports to Nirma	MT	-	-	-	2,700
	Exports to unrelated Indian parties	MT	-	-	-	-
	(b) Total imports from USA	MT	123	629	830	32,679
	Direct	MT	123	629	830	17,852
	Transshipments	MT	-	-	-	14,827
2	Exports made by SearlesValley Minerals (USA) in relation to					
	Indian production		0.00%	0.00%	0.00%	0.13%
	Indian Consumption		0.00%	0.00%	0.00%	0.11%
	Production of Nirma		0.00%	0.00%	0.00%	0.58%
	Imports made by Nirma in relation to					
	Nirma's production		0.00%	0.00%	0.00%	0.58%
	Indian production		0.00%	0.00%	0.00%	0.13%
	Indian consumption		0.00%	0.00%	0.00%	0.11%
3	Imports from USA in India	MT	123	629	830	32,679
	Exports by affiliated parties of Nirma/ Saukem	MT	-	-	-	2,700
	Exports by Other Parties from USA	MT	123	629	830	29,979
	Share of exports by Nirma's affiliated producer in total exports from USA		0.00%	0.00%	0.00%	8.26%

54. The Authority notes that –

- (i) Searles Valley Minerals (related company of Nirma and SCL in USA) is not the majority exporter of soda ash from USA during the POI. Other exporters (non-related) from USA have a majority and much larger share in exports from USA.
- (ii) Exports by Searles Valley Minerals are insignificant when compared with total imports of soda ash in India, production of soda ash by Nirma and Saukem and consumption of soda ash in India.
- (iii) The volume of exports by Searles Valley Minerals is not so significant as to have caused or provoked injury to the domestic industry.
- (iv) The imports from the related company in USA by Nirma have not been used for trading in the domestic market. The same has been used for captive consumption by Nirma and the volume thereof is insignificant compared to the total production of Nirma.
- (v) Focus of Nirma (or Saukem) continues to be on production. It can be reasonably stated that the company has not shifted to trading in imported goods. Nor the company can be said to have unduly benefited from dumping. In fact, imposition of anti-dumping duty would imply imposition of anti-dumping duty on exports made by Searles Valley Minerals as well. The injury determination shall not get distorted by including Searles Valley Minerals within the scope of the domestic industry.
- (vi) None of the opposing interested parties have advanced any justification for exclusion of Searles Valley Minerals from the scope of the domestic industry, barring the fact of relationship itself.

55. Tata Chemicals (one of the domestic producers of subject goods) has a related producer in Kenya as per information available on record and the Authority notes that there are significant imports from Kenya during POI. The present investigation includes Kenya as one of the subject countries. Details of exports made by related exporter in Kenya over the injury period show that (a) the Kenyan company is a subsidiary of Tata Chemicals, (b) records do not show any other producer of soda ash in Kenya, (c) these exports have been made throughout the injury period (d) petitioner claimed and other interested parties have not disputed with cogent reasons that Tata Chemicals should be treated ineligible domestic producer under Rule 2(b) to qualify as a domestic industry. Table below shows the volume of exports from Kenya, exports by Magadi Soda Ash (renamed as Tata Chemicals Magadi Ltd) and other relevant details

S. No.		Unit	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1	(a) Exports by Magadi Soda	MT	85,797	1,15,520	1,17,572	1,06,585
	Exports to related parties	MT	-	-	-	2,005
	Exports to unrelated Indian parties	MT	85,797	1,15,520	1,17,572	1,04,580
	(b) Total imports from Kenya	MT	85,797	1,15,520	1,17,572	1,06,585
2	Exports made by Magadi Soda (Kenya) in relation to	MT	85,797	1,15,520	1,17,572	1,06,585
	Indian production		4.19%	5.72%	5.79%	5.13%
	Indian consumption		3.97%	5.24%	5.33%	4.32%
	Production of TCL		11.33%	16.57%	16.91%	15.32%

56. From the above, the Authority notes that-

- (i) Magadi Soda, Kenya (renamed as Tata Chemicals Magadi Ltd) is the sole exporter of soda ash from Kenya.

- (ii) *Exports by Magadi Soda (Kenya) are quite significant when compared with total imports of soda ash in India, production of soda ash by Tata Chemicals and consumption of soda ash in India.*
 - (iii) *The volume of exports by Magadi Soda (Kenya) is significant so as to have caused or provoked injury to the domestic industry.*
 - (iv) *Focus of Tata Chemicals continues to be on production. The company has not turned trader. However, the undue benefit to the company from dumping by related company cannot be ruled out, given the volume of exports by the related company from Kenya during POI.*
 - (v) *While the petitioner has argued that Tata Chemicals should be treated ineligible domestic industry, none of the opposing interested parties have sought inclusion of Tata Chemicals within the scope of domestic industry.*
57. *It is, thus, seen that –*
- (i) *85% of exports from USA and 93% of exports from Romania are by producers unrelated to Indian producers. However, 100% of exports from Magadi are by the producer related to one of the Indian producers.*
 - (ii) *As regards Tata Chemicals, the exports made by Magadi Soda are quite significant. Magadi Soda is the sole producer of soda ash in Kenya, the volume of exports has not declined. Magadi Soda has low domestic demand and the focus of the company is on exports (exports by the company are almost 90% of its total sales). The Authority holds that even though Tata Chemicals is a domestic producer, the company must be considered ineligible to be treated as “domestic industry” for the purpose of the present investigations.*
 - (iii) *As regards GHCL, the Authority notes that the exports made by related exporter have significantly declined over the injury period, 93% of the exports from Romania are by unrelated producers in Romania, focus of GHCL has not shifted from manufacturing to trading, nor any undue benefit can be said to have accrued either to related exporter or to GHCL. The Authority holds GHCL as eligible to be treated as “domestic industry” for the purpose of the present investigations.*
 - (iv) *As regards Nirma and Saukem, the Authority notes that the exports made by related exporter were only in the investigation period. 85% of the exports from USA are by unrelated producers in USA. Focus of Nirma has not shifted from manufacturing to trading, as the relevant figures would indicate. Exports made by the related producer in USA cannot be said to have resulted in undue benefit to the domestic producer in India, namely, Nirma or Saukem. Rather, the insignificant quantity of the material has been imported for internal consumption. In view of the above position, the Authority holds Nirma and Saukem as eligible to be treated as “domestic industry” for the purpose of the present investigations.*
58. *Thus, the Authority is of the view that it is appropriate to consider GHCL, Nirma, Saukem and DCW Limited as the domestic industry under Rule 2(b) of the Anti-dumping Rules. Accordingly, the Authority considers GHCL, Nirma, Saukem and DCW Limited, the constituent applicants as “domestic industry”, satisfying the requirements of Rule 2(b) read with Rule 5(3) of the Anti-dumping Rules.”*
14. In the present investigation, M/s DCW Ltd. has neither imported subject goods from the subject countries nor is related to either importers or exporters of subject goods from the subject countries. M/s Nirma Ltd. also has not imported the subject goods from the subject countries. Their related company in USA however has exported the subject goods to India during 2014-15 (***% of total imports of PUC from subject countries and *** % of production of PUC by Nirma Ltd.) and 2015-16 (***% of total imports of PUC from subject countries and *** % of production of PUC by Nirma Ltd.). M/s Nirma Ltd’s related company in USA though has not exported the subject goods during the POI. None of other Indian producers has opposed the standing of the petitioners. The Authority notes that the focus of M/s Nirma Ltd. remains on domestic production of the subject goods.
15. The production position of the constituents of the domestic industry in the present investigation is as given below:

Particular	UOM	2013- 14	2014- 15	2015-16	POI
Production of Petitioners	MT	925,479	940,319	1,017,741	1,042,246
Other Indian Producers (comprising of GHCL, Tata Chemicals Ltd. and Tuticorin Alkalies)	MT	1,410,117	1,477,012	1,492,907	1,568,253
Total Indian Production	MT	2,335,596	2,417,331	2,510,649	2,610,499
Total Indian Production (excluding Tata Chemicals Ltd.)	MT	1,611,777	1,693,439	1,786,756	1,886,607
Share of Petitioners	%	40%	39%	41%	40%
Share of Other Indian Producers	%	60%	61%	59%	60%
Share of Petitioners (if Tata Chemicals Ltd. is not considered is part of Indian producers)	%	57%	56%	57%	55%

16. The Authority holds that the petitioners satisfy the requirement of standing in terms of Rule 2(b) and Rule 5(3) of the Indian AD rules.

E. Confidentiality

Submissions made by other interested parties

- i. The Petitioner has claimed confidentiality on several information and data in the Petition which impairs the ability of the Respondents to defend their interests since essential facts are not known to them.
- ii. The Petitioners have failed to provide good cause for claiming confidentiality on certain essential facts as required under Rule 7 of the AD Rules and Article 6.5 of the AD Agreement.
- iii. The confidential treatment of export sales volume, exports of the subject goods to India during the injury period by the related company of M/s Nirma Ltd. in USA, captive consumption, inventory and employment is in violation of Rule 7(1) of the AD Rules and Article 6(5) of the AD Agreement.
- iv. The aforementioned information would not give a significant competitive advantage to the Respondent, nor have any significantly adverse effect upon the Petitioners, and therefore this information cannot be regarded as 'confidential in nature'.
- v. The Petitioners have shown no good cause to treat the above information and data in confidence.
- vi. There is an absence of non-confidential summaries of the information made confidential, especially for costing information. This is in violation of Rule 7 of the AD Rules and Article 6.5 of the AD Agreement.
- vii. As per Trade Notice 1/2013 dated 9 December 2013, the non-confidential version of the Petition is required to contain an indexation and/or a summary of the confidential data.
- viii. The non-confidential summary must be in sufficient detail so as to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis.
- ix. As per the Trade Notice, no submission made without a meaningful non-confidential version on confidentiality shall be taken on record by the Authority.
- x. In Argentia-Ceramic Tiles, it was seen that the purpose of the non-confidential summaries is to inform the interested parties so as to enable them to defend their interests.
- xi. The Petitioners have failed to provide sources of the information relied on by them.

Examination by the Authority

17. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of the AD Rules provides as follows:

Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules and (7) of rule 6, sub-rule (2),(3) (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.

18. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis was directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidences submitted by various interested parties in the form of public file.

F. Miscellaneous Submissions**Submissions made by the Petitioners**

- i. The cessation of present ADD is likely to lead to continuation or aggravation of the continued dumping and likelihood of recurrence of injury to the domestic industry.
- ii. Imports of Soda Ash are at present subject to ADD despite which they are being exported to India from the subject country at dumping prices.
- iii. The subject exporters are exporting the product to a number of other countries at a price below fair price for the domestic industry.
- iv. By way of a Notification dated 3.7.2012, the Central Govt. earlier imposed ADD on imports of Soda Ash from the Subject Countries. Upon an application filed by an interested party, a review (Mid Term Review) was initiated on 21.7.2015. This Mid Term Review resulted in the issuance of Customs Notification dated 21.12.2016 withdrawing the duty. The Mid Term Review was kept in abeyance on account of pendency of Special Civil Application No. 16426 of 2016 filed by the domestic industry challenging the said Customs Notification along with the preceding Disclosure Statement dated 14.9.2016 and Final Findings dated 23.9.2016. They were quashed and set aside by way of Judgement and Order dated 23.2.2017 passed by the Hon'ble High Court of Ahmedabad.
- v. A fresh Disclosure Statement was ordered to be issued within 60 days. The Authority issued the said Disclosure Statement on 7.6.2017, while the expiration of the 60 day period was on 30.5.2017. The Authority initiated a Sunset Review with respect to imports of Soda Ash from present Subject Countries vide Notification dated 16.6.2017. It has been submitted that while disclosing essential facts, which are nothing but final set of facts on which the Authority would make final determination, showing continued dumping and position likelihood of recurrence of dumping and injury and initiating Sunset Review to consider further imposition for five years, the Authority vide Final Findings dated 22.7.2017 recommended withdrawal of ADD in Mid Term Review. On the same day, the Authority also issued an order withdrawing the Sunset Review.

- vi. Since the 5-year period of the Notification dated 3.7.2012 was ending on 2.7.2017, and since the Mid Term Review was not completed by the Authority while Sunset Review was already initiated, the period of ADD was extended by one year i.e. upto 2.7.2018 under Section 9A(5) of the Customs Tariff Act, 1975 by way of Notification dated 30.6.2017 issued pursuant to Order dated 30.6.2017 passed by the High Court in Special Civil Application No. 12249 of 2017.
- vii. The Petitioners challenged the Final Findings dated 22.7.2017 and Annulment Order dated 22.7.2017 by way of Petition and allied matters. The High Court vide Order dated 31.7.2017 restrained the Central Govt. from acting upon the Final Findings dated 22.7.2017 and Annulment Order dated 22.7.2017. Thus, by virtue of the Order dated 31.7.2017, the withdrawal order of the present case was “no longer in operation” and the investigation was de facto restored.
- viii. The Authority was required to undertake the investigation for completing the Sunset Review.
- ix. The domestic industry requested for completing investigation vide letters 26.4.2018 and 2.5.2018.
- x. Since the subject writ petitions were pending and the Authority did not take further steps for completion of investigation before 22.7.2018, i.e. the day on which extended period of duty was to expire, the domestic industry filed I.A. No. 1 of 2018 in the subject Petition.
- xi. The High Court vide Judgement and Order dated 11.6.2018 allowed the subject writ petition quashing and setting aside the Final Findings dated 22.7.2017 in Mid Term Review and Order dated 22.7.2017 annulling Sunset Review.
- xii. In order to comply with the directions of the Court it was necessary for the Authority to seek an extension under First Proviso to Rule 17(1)(a) of the Rules.
- xiii. Alkali Manufacturers’ Association of India, vide letter dated 12.6.2018 informed the Authority about the Judgement and order dated 11.6.2018 and requested the Authority to complete the Sunset Review.
- xiv. The Petitioners, vide email dated 13.6.2018 drew the kind attention of the Authority to this fact with a request to seek extension.
- xv. On seeing that there was no compliance, the domestic industry approached the High Court by way of Misc Civil Application No. 3 of 2018 for appropriate orders. This was allowed by Judgement and Order dated 15.6.2018 and the High Court extended the period for concluding the Sunset Review Investigation by 6 months in terms of the first proviso to Rule 17(1)(a) of the Rules.
- xvi. A Review Investigation must be completed within a period not exceeding 12 months, but can be extended by 6 months, as per Rule 23.
- xvii. After the expiration of the said months, there is no further period mandated in law for completion of the Sunset Review. Such period is expiring on 15.12.2018.
- xviii. The same was informed to the Authority by Alkali Manufacturers’ Association vide letter dated 17.7.2018.
- xix. The domestic industry further drew the attention of the Authority vide letter dated 19.10.2018.
- xx. After the cessation of duty on 2.7.2018, imports of Soda Ash in India from the subject countries have increased significantly.
- xxi. The import in the months of August 2018 and September 2018 have seen an increase of 23% from July 2018.
- xxii. China has increased the exports of the subject goods by 1718% in August, as compared to 54% in July.
- xxiii. USA has increased the volume of imports by 796%.
- xxiv. The alleged findings of the mid-term review were found incorrect, and the Hon’ble High Court intervened.
- xxv. Interested parties’ submissions shows disrespect towards the orders of the Hon’ble High Court.
- xxvi. The soda ash industry has had a history of dumping in the country.

- xxvii. Dumping Margins determined in previous investigation and previous investigation and proposed in the present investigation are significant and clearly show likelihood of dumping and consequent injury in the event of cessation of ADD.
- xxviii. In the event of cessation of ADD, these exporters will get a greater opportunity to dump the product under consideration into India, taking away the domestic industry's market share.
- xxix. The import volumes have increased in the POI and at dumped prices. The imports are likely to enter in significant volumes at dumped price in the event of cessation of ADD.
- xxx. Suppression/depression effects of the imports were not seen in the Indian market because of the existence of the ADD. Import price have started declining significantly and have started having a suppressing effect on the prices of the domestic industry as soon as new Turkish capacities have commercialized which is threatening the global demand supply scenario.
- xxxi. The domestic industry could not ascertain the levels of inventories with the subject producers. In view of the immense capacities available with the subject countries, it can be fairly stated that production can be ramped up as and when market is available.
- xxxii. USA and China have remained the first and second biggest exporters of the subject good respectively.
- xxxiii. The Turkish exporters have capacities to the tune of *** million metric tonnes of which their demand is around *** million metric tonnes, which leaves *** metric tonnes fit for exports. These goods are sent to Europe, and then are pushed to India.
- xxxiv. There is an existence of dumping even in third countries by China, EU, Ukraine and the USA. Transaction wise analysis has been undertaken for last one-decade imports.
- xxxv. The volume of dumped exports was very high throughout.
- xxxvi. The volume of injurious exports was very high earlier. The share declined till 2015-16 and increased thereafter.
- xxxvii. The volume of price attractive exports is quite high in the present POI in comparison to the consumption in India and the proportion increased thereafter in the post POI.

Submissions made by other interested parties

- i. For a non-importing industrial user, there are no questionnaire formats applicable. It is only applicable to initiations that took place after February 2018.
- ii. The complex history of the present case has added ambiguity to any timelines in the investigation.
- iii. There are no duties in existence, as the Authority did not apply to the Central Government to extend the period of duties. There is no occasion for the Authority to give its recommendation to the Central Government.
- iv. The Department of Revenue cannot extend the duties in terms of the judgement of Forech India Ltd.
- v. The Designated Authority & Ors since there are no existing duties. No Authority can extend the duties if there is a break in the period under Rule 18(1). The said judgement has not been stayed, and is therefore binding on the Authority
- v. The Designated Authority has annulled the sunset review investigation after 36 days of the investigation.
- vi. No interested party has opportunity to even participate or provide its submissions as the Designated Authority had closed the investigation before expiry of 40 days from the initiation.
- vii. The Authority has after expiry of more than 16 months conducted hearing without giving opportunity to any interested party to provide its responses or submission.
- viii. No interested party has got any time to respond nor has the Authority intimated interested parties about the revised timeline for submitting responses or their submissions.
- ix. The domestic industry, by seeking excessive judicial scrutiny, was able to extend the duties in an uninterrupted manner though the factual findings by the competent authority showed that that there are no ADD warranted the present case.

- x. The Soda Ash industry is a well-organized sector which has been enjoying the benefits of ADD for a very long period of time.
- xi. GHCL and Tata Chemicals have been excluded to hide the factual position of soda ash industry.
- xii. The soda ash industry has been performing in an outstanding manner for the past several years which shows that the domestic industry is not vulnerable to any material injury.
- xiii. Over the past 8 financial years it can be seen that the domestic industry was able to maintain robust capacity utilization above 80% (avg about 83%). This shows fundamentally strong position of the domestic industry and the domestic industry does not face any threat.
- xiv. The domestic industry shows consistent production and sales situation with reasonable increases.
- xv. The Indian producers have been holding 80% share in the Indian market and what has been getting imported to India was only to the tune of 20%. That's a huge gap in market share. Continuation of ADD may block out all imports, which appears to be the intention of the domestic industry such that they can enjoy absolute monopoly.
- xvi. The profitability of the domestic industry has been high in terms of profits and ROCE and has been growing, unaffected by imports.
- xvii. The landed prices of imports were not creating any price suppression or depression effect including price underselling to the domestic industry for quite some time. Such price behaviour clearly shows that expiry of duty is not going to create any adverse effect on prices of the domestic industry.
- xviii. Positive price undercutting is only the result of very high price charged by the domestic industry and does not suggest any adverse price situation per se.
- xix. There are large number of user industries and segments in India for whom soda ash is the major raw material and the unrealistically high prices charged by the domestic industries using the ADD in force have rendered such industries uncompetitive against its global players and are suffering heavily.
- xx. Profiteering by soda ash industry with the help of ADD has killed competition in the trade of soda ash in India which was not the intended purpose of ADD.
- xxi. The domestic industry is trying to propagate that the performance is good because of ADD in force. This connotes the demand for perpetual continuation of duties by citing likelihood.
- xxii. Import volumes into India have been at a level to fulfil the demand supply gap. The landed prices of imports were not creating any price effects on the domestic industry.
- xxiii. Any continuation of ADD on imports of soda ash from subject countries shall be a gross misuse of ADD scheme. It has become a tool for profiteering. The ADD is in force due to the technicalities involved in the judicial proceedings and there is no merit in the continuation of the present duties.
- xxiv. As per the legal position established by the Hon'ble Delhi High Court in WP 4886/2014, even if the Authority completes the present sunset review as per the directions and recommends continuation of duty, duty cannot be extended further as the same has already lapsed on 2.7.2018.
- xxv. The domestic industry did not make any foreign party respondents in their petition in the Hon'ble Gujarat HC which has prevented such parties from making its views known, making them non-cooperative.
- xxvi. GHCL has been excluded from the domestic industry with a purpose since it makes huge profits. The injury data from GHCL should also be examined. The inclusion and exclusion of a producer is at the discretion of the Authority.
- xxvii. Imports of Soda Ash are no longer subject to ADD, as the duty lapsed on 2nd July 2018.
- xxviii. The Hon'ble High Court of Delhi in *Forech India Limited v. Designated Authority & Ors.* has held that- i) the gap between one year ADD extension pending the sunset review and the five-year duty imposed pursuant to sunset review is illegal; and ii) the five year extension of ADD pursuant to the sunset review that is imposed after the gap is also illegal.
- xxix. Any prospective levy of ADD would run afoul of the aforesaid judgement and thus, would be illegal.

- xxx. Petitioners have not provided concrete or sufficient evidence for proving that discontinuation of duty would lead to recurrence or continuation of injury on account of dumped imports.
- xxxi. In order to establish recurrence or continuation of injury, it is pertinent to analyse the post-POI data which has not been provided. In the absence of this data, likelihood of substantially increased importation cannot be determined.
- xxxii. There is no causal link between the alleged injury suffered by the Petitioners and the subject imports. Even if there is continued dumping, there is an absence of continued injury, which implies that there is no longer a causal link between dumping and injury.
- xxxiii. The year of the IHS Report is unclear and is not verifiable if it is indeed an IHS Report.
- xxxiv. Petitioner's reference to Turkey, which is not a subject country, is unnecessary. The averment that excess capacity in Turkey would lead to outflow of subject goods from Turkey to EU, which in turn would lead to outflow to India, is mere conjecture and not duly substantiated.
- xxxv. No verifiable evidence has been produced by the Petitioners to establish the expanding capacities of the subject countries. The evidence provided at Annexure 4.3 of the Petition is also not verifiable.

Examination by the Authority

19. Rule 23 of the AD Rules states as follows:

(1) Any anti-dumping duty imposed under the provision of section 9A of the Act, shall remain in force, so long as and to the extent necessary, to counteract dumping, which is causing injury.

(1A) The Designated Authority shall review the need for the continued imposition of any anti-dumping duty, where warranted, on its own initiative or upon request by any interested party who submits positive information substantiating the need for such review, and a reasonable period of time has elapsed since the imposition of the definitive anti-dumping duty and upon such review, the Designated Authority shall recommend to the Central Government for its withdrawal, where it comes to a conclusion that the injury to the domestic industry is not likely to continue or recur, if the said anti-dumping duty is removed or varied and is therefore no longer warranted.

(1B) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) or (1A), any definitive anti-dumping duty levied under the Act, shall be effective for a period not exceeding five years from the date of its imposition, unless the Designated Authority comes to a conclusion, on a review initiated before that period on its own initiative or upon a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, within a reasonable period of time prior to the expiry of that period, that the expiry of the said anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

(2) Any review initiated under sub-rule (1) shall be concluded within a period not exceeding twelve months from the date of initiation of such review.

(3) The provisions of rules 6, 7, 8, 9/10, 11, 16, 17, 18, 19, and 20 shall be mutatis mutandis applicable in the case of review.

20. The Authority has recorded the issues raised by the interested parties and domestic industry and notes that Rule 23 of the AD Rules obligates the Authority to review the need for the continued imposition of an anti-dumping duty.

21. The Authority notes that the interested parties have raised the following relevant issues:

- a. Hon'ble High Court of Delhi in WP(C) No. 4886/2014 has held that there should be no gap in 5-year extension of anti-dumping duty pursuant to the sunset review and the 1-year extension of anti-dumping duty while the sunset review is pending completion.
- b. The aforesaid judgment has been challenged before the Hon'ble Supreme Court in SLP(C) No. 15859-15861/2018. The Hon'ble Supreme Court issued notice in the aforesaid SLP by order dated 9 July 2018 but did not grant any stay on the judgment of the Hon'ble High Court of Delhi in WP 4886/2014.

- c. The Hon'ble High Court of Gujarat extended the timeline to complete the sunset review by six months vide order dated 15 June 2018 in Misc. Civil Application No. 3 of 2018 in R/Special Civil Application No. 14204 of 2017.
 - d. The anti-dumping duty on the subject goods lapsed on 2 July 2018. Interested parties now argue that the Authority does not have any jurisdiction to recommend further extension of anti-dumping duty for five years pursuant to this sunset review. They argue that any prospective levy of anti-dumping duty would run afoul of the Hon'ble High Court of Delhi's judgment in WP(C) No. 4886/2014.
 - e. User industry in India will suffer if anti-dumping duty is continued.
22. As regards the submission that the Authority cannot legally recommend continuation of anti-dumping on the subject goods, it is observed that under the Customs Tariff Act, 1975 and AD Rules, the final decision to impose or not to impose anti-dumping duty lies with the Central Government. As regards the submission on interest of user industry, the Authority notes that the purpose of anti-dumping duty is to create a level-playing field. It is in the interest of user industry that the domestic industry is given adequate protection from dumped imports that cause injury to the domestic industry.
23. The Authority further notes that the interested parties had sufficient time to respond to the questionnaire and participate in the investigation by making submissions.
24. Issues regarding dumping, injury, causal link and likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury shall be addressed in appropriate places of this final findings.

G. Determination of Dumping Margin

Market Economy Claims, Normal Value, Export Price and Dumping Margin

Submissions made by the Petitioners

- i. The dumping margin has been determined by considering individual import transactions for the last 10 years.
- ii. While the current POI is relevant for establishing continuation of dumping, the historical data is relevant for establishing likelihood of dumping. It has been submitted that if the POI itself shows that the dumping continued, the same may be sufficient. However, if dumping can be shown throughout the past decade, it is likely to continue on the cessation of ADD.
- iii. The weighted average may be an appropriate yardstick for considering weighted average dumping margin for the current POI.
- iv. Behaviour of individual exporters, as shown through different export transactions, is relevant, appropriate and necessary to be examined for establishing likelihood of dumping.
- v. If the Authority concludes that the weighted average dumping margin is de-minimis, then there arises a need to examine dumping margin separately for each import transaction. In case of significant exports at dumped prices, it is evident that exports are likely to happen at dumped prices in the event of cessation of ADD.
- vi. Article 15 shall be applicable to the present POI, in the case of China PR, since a part of the POI is within the period of December 2016. China should be treated as non-market economy. The normal value in China should be determined on the basis of Para-7 of Annexure-I.
- vii. The normal value in China should be determined on the basis of price payable in India, since petitioners could not determine normal value in China on the basis of price or constructed value in a market economy third country for the reason that the relevant, complete and exhaustive verifiable information is not publicly available and could not be procured. The normal value can be determined on the basis of selling price of domestic industry itself, as this price is unsuppressed and constitutes price payable in India.
- viii. Domestic industry has considered prices for USA and EU as per prices reported in IHS Chemical Global Soda Ash. Since the journal mentions high and low prices, domestic industry has adopted average price. Normal value and dumping margin have also been determined considering the average price.

- ix. Normal value for Pakistan has been calculated on the basis of an Annual Report of ICI Pakistan Ltd., a listed company in Pakistan.
- x. Normal value for Kenya has been constructed on the basis of the details given in the Annual Report for the plant in Magadi, Kenya, owned by Tata Chemicals Ltd.
- xi. Normal value for Iran has been determined on the basis of the prices published in IHS Chemical Soda Ash for Middle East/North Africa considering it a comparable representative price. No other information/evidence of price of subject goods in the domestic market of Iran were available.
- xii. Export price has been determined as the weighted average import price of soda ash from respective subject countries. It has been calculated at CIF level.
- xiii. Export price has been adjusted for ocean freight, marine insurance, port expenses, commission, inland freight and indirect taxes (VAT difference only in case of China) which may have been incurred by the exporter for exporting material to India, in order to put normal value and export price at the same level of trade.
- xiv. Export price has been determined in US\$ considering average exchange rate for the proposed investigation period.
- xv. The normal value and export price for the product have been determined at ex-factory level, pertain to the same period, with no known difference in the terms and conditions of sale, and free of taxes. Thus, the comparison made is a fair comparison.
- xvi. Dumping margins are not de-minimis, but substantial.
- xvii. All exporters and foreign producers must be considered as non-cooperative. None of them filed the questionnaire response in the present case. The Authority should not let the non-cooperation adversely impact the case of the domestic industry. It has been submitted that the Authority should draw adverse inference against exporters, holding that the exporters have preferred non-cooperation.
- xviii. Transaction wise details of exports to third countries is a mandatory requirement for sunset review cases and the purpose is to undertake an analysis for the purpose of examining recurrence of injury.
- xix. The aforementioned is the single most important information at the stage of sunset review and particularly in a case where the request for extension is based on recurrence of injury.

Submissions made by other interested parties

- i. The dumping margin must be calculated on the basis of the information filed by the cooperating producers/exporters in the present investigation.
- ii. Dumping margin should be determined based on total exports during the POI and not based on selective transactions.
- iii. The determination of dumping margin on weighted average basis alone is legal.
- iv. The domestic industry has tried to present an inflated NV and squeezed EP to show a higher dumping margin, which is baseless.
- v. The case of Secretary (Revenue), GOI v. Dyestuffs Manufacturers Association of India confirmed that trade journals cannot be relied upon as facts available for the purpose of determining normal value on best judgement assessment principle.
- vi. The Petitioners have relied on IHS Chemical, which is a trade journal, to determine normal value. This normal value should be disregarded.
- vii. The normal values for Pakistan and Kenya have also been determined by looking at Company Annual Reports, which is not the correct approach.
- viii. The Petitioners have not provided any source for the adjustments made with regard to ocean freight, marine insurance, port expenses, commission, bank charges, inland freight, indirect taxes to the compare the export price and the normal price at the same level of trade.
- ix. No information has been provided pertaining to how the adjustments were computed for the purposes of the Petition.

- x. The import data presented in the Petition by the Petitioners is also questionable. Multiple sources have been relied on by the Petitioner for import data. Up to March 2015, the Petition relies on DGCI&S import data for all subject countries. For April 2015-March 2016, the Petition relies on the secondary source IBIS for import data for China, the EU, Kenya, Iran, Ukraine and USA, but for Pakistan, the Petition relies on DGCI&S import data.
- xi. The multiplicity of data sources in the Petition leads one to believe that the data is skewed and has produced incorrect dumping and injury analysis results in this case.
- xii. The producers/exporters may not have known of the developments pertaining to the review and investigation, which is why they could not participate in the review.
- xiii. Authority may consider intimating to the producers/exporters in the subject countries about this ongoing review and direct them to submit relevant information in their defense.
- xiv. Turkey is not a subject country and its capacity is not relevant.
- xv. The domestic industry has made no determination for normal value for Ukraine in their written submissions, and therefore it has no legal basis to claim injury from imports of the subject goods from Ukraine.
- xvi. The domestic industry's claim that producers in the subject countries are dumping in third countries is without any evidence.
- xvii. Domestic industry's condition has improved substantially, and it does not need any protection now.
- xviii. Ukraine has only one producer of Soda Ash, the PJSC "Crimean Soda Plant" which is out of Ukrainian control due to the occupation of Crimea by the Russian Federation. The producer has illegal Russian registration now. There is no export of Ukrainian Soda Ash to the world, including India.
- xix. Reference has been made to the United Nations Comtrade Database and State Statistics Service of Ukraine, which show no export of the product under investigation to India from Ukraine since 2014 till date. Ukraine stopped to export its product to other countries as well. The ADD Sunset Review Investigation concerning imports of Soda Ash was initiated on 16 June 2017. On 22 July 2017, it was annulled, following a Court decision.

Examination of Market Economy Claims by the Authority

China PR

25. The Authority sent copies of the MET questionnaire to all the known producers/exporters in China PR for rebutting presumption of non-market economy in accordance with criteria laid down in para 8(3) of Annexure-I to the AD Rules. The Authority also requested embassies of respective countries in India to advise the producers/exporters in their country to provide the required information. As per Paragraph 8, Annexure I to the AD Rules as amended, the presumption of a non-market economy can be rebutted if the exporter(s) provide information and sufficient evidence on the basis of the criteria specified in subparagraph (3) in Paragraph 8 and establish to the contrary. However, none of the producers/exporters in China PR have cooperated and filed response to the exporter's questionnaire and MET questionnaire in the present review. In view of the above position and in absence of rebuttal of non-market economy presumption, the Authority considers it appropriate to proceed with para-7 of Annexure-I to the AD Rules for determination of normal value for China PR.

H. DETERMINATION OF NORMAL VALUE

26. In respect of producers/exporters from the respective subject countries, the Authority has determined normal value on the basis of best available information as per the AD Rules.

China PR

27. Article 15 of China's Accession Protocol provides as follows:

"Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;

(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."

28. Article 15 implies that provisions of one of the sub-paragraph shall expire 15 years from the date of China's Accession. The provisions of this paragraph expired in 11 December 2016. Since the factum of dumping causing injury to the Domestic Industry is based on the investigation period, the conditions prevalent during the investigation period alone are relevant, appropriate and necessary for the purpose of the present review. The POI for the purpose of the present review is April 2016 – March 2017. Since the subparagraph of Article 15 was in existence during the major part of the POI, the Authority may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China PR if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.
29. The Authority notes that in the past three years, China PR has been treated as non-market economy country in anti-dumping investigations by India and other WTO Members. China PR has been treated as a non-market economy country subject to rebuttal of the presumption by the exporting country or its individual exporters in terms of the AD Rules.
30. However, none of the exporters/producers from China PR has filed market economy questionnaire response. In view of the above position and in the absence of rebuttal of non-market economy presumption by any Chinese exporting company, the Authority considers it appropriate to treat China PR as a non-market economy country in the present investigation and proceed with para-7 of Annexure-I to the AD Rules for determination of normal value in case of China PR
31. Further, in view of non-cooperation by the Chinese producers/exporters, the Authority considers it appropriate to proceed with the provisions of para-7 of Annexure-I to the AD Rules for determination of normal value. Para 7 of Annexure I of the AD Rules provides that:

“In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the Designated Authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.”

32. Accordingly, in the absence of any reliable price and cost details for the subject goods in any market economy third country, the Authority constructed the normal value for China PR in terms of para-7 of Annexure I to the AD Rules. Accordingly, the normal value for exports from China PR has been constructed for the subject goods and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

European Union (EU)

33. The Authority notes that none of the producers/exporters from the EU have submitted exporter's questionnaire response. Therefore, the Authority has relied upon the best available information in terms of Rule 6(8) of the AD Rules for the determination of normal value in respect of the EU. The normal value so determined for the EU has been mentioned in the dumping margin table given below.

USA

34. The Authority notes that none of the producers/exporters from USA have submitted exporter's questionnaire response. Therefore, the Authority has relied upon the best available information in terms of Rule 6(8) of the AD Rules for the determination of normal value in respect of USA. The normal value so determined for USA has been mentioned in the dumping margin table given below.

Iran

35. The Authority notes that none of the producers/exporters from Iran have submitted exporter's questionnaire response. Therefore, the Authority has relied upon the best available information in terms of Rule 6(8) of the AD Rules for the determination of normal value in respect of Iran. The normal value so determined for Iran has been mentioned in the dumping margin table given below.

Pakistan

36. The Authority notes that none of the producers/exporters from Pakistan have submitted exporter's questionnaire response. Therefore, the Authority has relied upon the best available information in terms of Rule 6(8) of the AD Rules for the determination of normal value in respect of Pakistan. The normal value so determined for Pakistan has been mentioned in the dumping margin table given below.

Kenya

37. The Authority notes that none of the producers/exporters from Kenya have submitted exporter's questionnaire response. Therefore, the Authority has relied upon the best available information in terms of Rule 6(8) of the AD Rules for the determination of normal value in respect of Kenya. The normal value so determined for Kenya has been mentioned in the dumping margin table given below.

Ukraine

38. The Authority notes that none of the producers/exporters from Ukraine have submitted exporter's questionnaire response. Therefore, the Authority has relied upon the best available information in terms of Rule 6(8) of the AD Rules for the determination of normal value in respect of Ukraine. The normal value so determined for Ukraine has been mentioned in the dumping margin table given below.

I. EXPORT PRICE

China PR, the EU, USA, Iran, Pakistan, Kenya, Ukraine

39. The Authority notes that none of the exporters/producers of the subject goods from China PR, Ukraine, the EU, USA, Iran, Pakistan and Kenya have responded to the Authority in the form and manner prescribed. In the absence of exporter's questionnaire response from the producers/exporters from the aforesaid countries, the Authority has determined the export price in respect of these countries on the

basis of best available information in terms of Rule 6(8) of the AD Rules. The Authority has relied upon DGCI&S import data for the purpose of arriving at the weighted average CIF value of imports from the aforesaid countries during the POI. Appropriate adjustments on account of ocean freight, insurance, commission, port expenses, inland freight and bank charges have been considered to arrive at the net export price in respect of each of these countries. Accordingly, the proposed export price at ex-factory level for all exporters of China PR, Ukraine, the EU, USA, Iran, Pakistan and Kenya has been respectively determined as given in the dumping margin table given below.

J. DUMPING MARGIN

40. Comparing the aforesaid normal values and export prices as determined, the dumping margin determined for the subject countries during the POI are as follows:

POI

Country	Exporter/ Producer	Normal Value US\$/MT	Net Export Price US\$/MT	Dumping Margin US\$/MT	Dumping Margin %	Dumping Margin % Range
China PR	All	***	181.64	***	***	Negative
EU	All	***	183.08	***	***	Negative
Kenya	All	***	162.68	***	***	De- minimis
Pakistan	All	***	212.01	***	***	Negative
Iran	All	***	149.75	***	***	Positive
Ukraine	All	***	167.75	***	***	Negative
USA	All	***	150.11	***	***	Positive

K. Methodology for Injury Determination and Examination of Injury and Causal link

Submissions made by the Petitioners

- The improvement in the performance of the Domestic Industry is largely due to the ADD in force and injury is likely in the event of cessation of ADD.
- Individual import transactions for the past 10 years have been considered to determine likelihood of injury.
- The net sales realization has been determined by considering the selling price of the entire domestic sales volume, excluding taxes and duties, rebates, discounts and commissions. Landed price of imports has been determined considering weighted average CIF import price, with 1% landing charges and applicable basic customs duty. On comparison of the net sales realization and landed price of imports, it was observed that price undercutting is significantly positive in the event of cessation of ADD.
- The selling price of the domestic industry should be compared with the landed price of imports only after adding transportation costs, since they form a substantial portion of the cost of production in case of the subject goods.
- The Rules do not provide the methodology of how the Authority must determine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of like product in India. It has been submitted that there is no fixed methodology for determining price undercutting.
- For fair comparison, the domestic price is compared with import price at the same level of trade. The price of the like product cannot be ex-factory price when the objective is to compare it with the import

price. Price undercutting should be determined after adding freight. India's position at the WTO also states that the comparison of the prices must be at a point closest to consumption.

- vii. The adoption of the Product type wise and month or quarter-wise determination of price undercutting and the adjustment of post sales expenses- warranty, guarantees, mandatory square parts, Indian office expenses, by the Authority in a couple of dozen cases clearly establish recognition and acceptance of the principles of fair comparison.
- viii. Price undercutting and injury margins should be determined by considering only those transactions that were undercutting or injuring the prices of the domestic industry. Reliance is made on the WTO Report in the matter of EC-Anti Dumping Duties on Malleable Cast Iron Tube, where it is established:
 - a. There is no requirement under Article 3.2 to establish one single margin of undercutting on the basis of an examination of every transaction involving the product concerned and the like product;
 - b. A requirement that an investigating authority must base its price undercutting analysis on a methodology that offset undercutting prices with overcutting prices would have the result of requiring the investigating authority to conclude that no price undercutting existed, when, in fact, there might be a considerable number of sales at undercutting prices which might have had an adverse effect on the domestic industry;
 - c. The extent to which price undercutting would have an impact on a domestic industry would be a function of two variables- (i) the number of sales at undercutting prices, and (ii) the extent of the undercutting of such sales. The former is particularly important since it provides an indicator of the likely number of sales lost by the domestic industry.
 - d. The calculation of an average margin of undercutting for all sales, whether or not at undercutting prices, might not be the most effective manner to assess the impact of price undercutting on a domestic industry, as it limited the ability of the investigating authority independently to examine these two variables.
- ix. The weighted average export prices to India are grossly insufficient to determine whether injury to the domestic industry is likely to recur.
- x. Non-Injurious Price and injury margin is not required to be determined in a sunset review case where extension request is based on likelihood of recurrence of injury to domestic industry. These can be determined in order to examine the behaviour of the exporters in different export transactions. For this purpose, the Authority is only required to ascertain whether particular export transaction occurred at a price below or above NIP.
- xi. In a sunset review case, Rule 11 does not get extended, and the Authority is required to examine only the likelihood of continuation or recurrence.
- xii. Annexure-II cannot be applied to the present case on 'as it is basis' since these rules are inconsistent with the Act and the WTO ADA. These rules must be imposed 'after necessary modifications' to the fact that these rules are being considered in a case where ADD is in place and where the petition is for the extension of ADD on the grounds of likelihood of recurrence of injury to the domestic industry.
- xiii. It is submitted that the legal provisions must be applied to the following effect:
 - a. The element of present injury to the domestic industry must be translated to a probable future injury;
 - b. The effect of the imports must be determined; and
 - c. A significant rate of increase of dumped imports from third countries must also be taken into consideration.
- xiv. A list of parameters adopted by various countries to determine likelihood has been submitted, and they all differ in nature. It is therefore submitted that the parameters listed in the Rules cannot be strictly applied either as the 'upper limit' or as 'strict prescription' and are merely indicative.
- xv. The demand for the product under consideration has increased throughout the injury investigation period, be it with inclusion of captive consumption or not.

- xvi. The imports occupy a significant volume in the Indian market and have increased significantly throughout the injury period. The imports started showing a significant rise when the ADD ceased in July 2018 as per current notification.
- xvii. Imports in relation to production and the consumption in the country increased in 2014-15 as compared to 2013-14 levels. It declined in 2015-16 but increased again in the POI. The import in relation to production and consumption have increased over the injury investigation period despite existing ADD being in force.
- xviii. The landed price of the dumped imports is significantly below the selling price of the domestic industry and the same implies high levels of price undercutting from the subject countries in the event of cessation of ADD.
- xix. Comparison of cost of production, selling price and landed price of imports shows that while cost of production and selling price of the domestic industry has shown positive trend and the imports were not causing any price suppression or depression effect with the ADD in force, should the present ADD cease, the dumping would cause significant depressing effect on the prices of the domestic industry in the market.
- xx. After the imposition of ADD in 2012, the domestic industry gradually improved and soon the market became viable to invest in capacity extensions and have planned expansion. Post-imposition of ADD, a fresh capacity to the tune of *** lac MT has been commissioned, with another *** lac MT being planned. M/s Gharhi has commissioned a new green field plant of a production capacity of *** lac MT at an investment of Rs. *** crores. Viability of these fresh investments is at stake.
- xxi. The profitability of the domestic industry has improved by and large but has declined over the POI. Cash flow and return on capital employed increased over the injury period, and price parameter have shown improvement due to the imposition of ADD. Cessation of ADD will create price pressure on the domestic industry and will lead to a decline in these parameters of the domestic industry.
- xxii. The demand for the product under consideration is increasing at a reasonable rate, which creates a justification for expansion of capacities further. The expansion of the capacity, as stated before, required huge amounts of investment, which are at stake.
- xxiii. The market share of the subject countries in the domestic demand of the product under consideration has increased whereas market share of the domestic industry has declined over the injury period. Imports from subject countries will further capture the market in India, in case the ADD in force is not extended further.
- xxiv. The inventories with the domestic industry have increased over the injury period.
- xxv. Wages, productivity and employment level has increased over the injury period.
- xxvi. The growth of the petitioning domestic industry in terms of various parameters was positive.
- xxvii. Domestic industry has not claimed continued injury.
- xxviii. The visible increase in performance of the domestic industry is only a result of the remedial effects of the ADD.
- xxix. Even though absolute performance levels do not show material injury, the situation of the domestic industry is clearly fragile, which is evident by the deterioration of profits post-POI.
- xxx. The performance has further declined post-POI.
- xxxi. No evidence has been provided showing that the downstream industries have been rendered uncompetitive because of the alleged high prices.
- xxxii. Performance of consumers has improved instead of deterioration during the period of ADD, as is established by the profits achieved by HUL.
- xxxiii. Detergent manufacturers, which are major users of subject goods, have increased their selling price far more than the costs. Thus the claim of downstream industries becoming uncompetitive is baseless.
- xxxiv. Domestic industry's performance has improved largely because of the existence of ADD.

- xxxv. There is no basis to say that there is a fair demand and supply balance. There is a clear demand supply gap in the world.
- xxxvi. No evidence has been produced by the interested parties to rebut the high likelihood of continuation/recurrence of dumping.
- xxxvii. Significant imports are being made to India at a significantly dumped price.
- xxxviii. Turkey is becoming a threat to every country, and Indian market has become even more vulnerable.
- xxxix. The existence of ADD has led to increase in production and sales by the domestic industry.
- xl. The import volumes increased significantly from 2013-14 to 2014-15 and showed decline in 2015-16, only to increase back to the levels they occupied in 2014-15.
- xli. Despite the existence of ADD for the duration of the entire injury period, the import volumes have shown an exponential increase.
- xl. Imports have already started showing significant increase since July 2018.
- xl. The import in the months from July 2018 to September 2018 itself shows an increase of 37%.
- xl. The volume of imports has increased to 796% as compared to previous month.
- xl. The excessive ROI is because of the fact that the Authority is determining return on capital employed by considering investments made by the domestic industry which are largely depreciated.
- xl. The ROI should be determined considering the net present value of the investigations and not net depreciated book value of the investment. It is grossly inappropriate and even unfair to the domestic industry that the ROI is determined considering depreciated value of the investments.
- xl. The ROI of the new investments at the current level of prices would be only 14%. This is not a good return.
- xl. The inventories of the domestic industry too have almost doubled over the period. The market share of the subject countries, as the additional capacities in the countries attracting ADD became effective, shows an increasing trend while that of the domestic industry remained about the same. The market share of the other Indian producers declined over the period.
- xl. The fresh investments made by the domestic industry as a result of the imposition of the ADD require a minimum reasonable return in order to be reasonably viable. The average return earned by the domestic industry over the injury period was much lower. At this rate, the cost of investment will be recovered only after the life of the assets.
- l. Imports were not causing any price suppression or depression effect with the ADD in force. If the present ADD ceases, the dumping would cause significant depressing effect on the prices of the domestic industry in the market. The likelihood of price suppression/depression must be examined, and not price suppression/depression itself.
- li. Increased ROC and profitability can be no grounds for products to be dumped by the subject countries.
- lii. The profits being earned are being reinvested in capacity creation.
- lii. The analysis has been undertaken to examine the likely effect of cessation of duties and clearly establishes that significant exports were made in this period at prices below normal value, selling price and NIP of the domestic industry.
- liv. No evidence has been brought forward to show that customs are clearing goods without collection of ADD. There are several cases in the past wherein the sunset review findings were issued after completion of 18 months. This argument raised by other interested parties renders all these findings and duties illegal. Investigation is being undertaken as per the High Court's direction vide Judgement and Order dated 15.6.2018. Petitioners are not seeking retrospective duty. Further, the decision of the Delhi High Court is under challenge, and a stay application has also been filed against the order. The Central Govt. has not withdrawn the ADD till date.

- iv. There is de facto only one investigation conducted after original investigations. MTR findings were not based on adequate analysis of likelihood of injury.
- lvi. Responding exporters must also show that there will be no continued dumping or is unlikely to continue.
- lvii. The Authority has prescribed SSR Questionnaire Part II which seeks information from the exporter on their capacities, capacity expansion, transaction wise third country exports, domestic sales, etc. for examination of likelihood of recurrence of dumping and injury.
- lviii. The responding parties have produced no evidence to prove otherwise.
- lix. The domestic industry has filed details regarding import volumes from subject countries. The data filed pertains not only to injury investigation period but is also an analysis of import volumes from 2006-07 till 2018-19.
- lx. Imports have seen significant surge in the post-POI with decline in import price.
- lxi. Injurious transactions have risen significantly and represent close to 90% of total volumes.
- lxii. Further detailed and concrete evidence have been provided by the domestic industry.
- lxiii. Imports are at present undercutting the prices of the domestic industry. Imports are likely to undercut the prices of the domestic industry even when duties will not be in place.
- lxiv. All necessary evidences substantiating price attractiveness of Indian market in terms of export by subject countries to other countries at dumped and injurious price have been elaborated on.

Submissions made by other interested parties

- i. The Petitioners have not suffered continued injury and the performance of the domestic industry has improved in the current period due to ADD in force.
- ii. The Authority has given due weightage to the fact that the domestic industry therein had grown significantly and performed well and that the ADD had served its intended purpose.
- iii. The Petitioners have been able to perform well in a market that is fair, on account of ADD achieving its intended objective of providing/restoring fair market situation for domestic products in India.
- iv. Considering that there is no continued injury and the performance of the Petitioners is satisfactory, there is no likelihood of recurrence of injury.
- v. There is no legal obligation to consider any other data except the injury period including POI and post-POI when determining any form of likelihood of recurrence of dumping/injury.
- vi. The Petitioners have submitted that the selling price should be compared to the landed price after adding transportation costs. HUL submits that such a claim is erroneous and is contrary to the Authority's practice of comparing selling price and landed price at ex-factory level.
- vii. NIP is determined based on the principles laid down in Annexure III of the AD Rules.
- viii. The Authority allows a 22% rate of return on the capital employed.
- ix. NIP is also calculated at ex-factory level, i.e. without giving the effects of post factory expenses, since landed price is considered at the place of importation. Net Sales Realisation follows the same principle. It is unreasonable for the Petitioner to ask for a deviation in the established methodology. The fair comparison aspect of this lies in the fact that both prices are calculated after making the necessary adjustments from both prices.
- x. The subjective methodology of price undercutting demanded by the Petitioners is untenable in light of the fact that there must be set precedent over which future participants in such investigation may rely and formulate their submissions.
- xi. As long as the prices are compared after making adjustments to both prices, there is no need for subjective methodology for any consideration of freight and other transport costs being added to the determination.

- xii. The request to reassess price underselling after including freight and transportation costs is a ruse by the Petitioners to manipulate the determination of price underselling to their benefit and not in interest of fairness and equity.
- xiii. The WTO proposal regarding transport costs is a mere proposal and has not been accepted or crystallised into law in the WTO. The proposal does not indicate inclusion of freight/transportation costs. It reaffirms the need to compare prices at the same level of trade and does not call for any particular change.
- xiv. The transaction-based approach to determining undercutting is akin to zeroing which has been held to be unreasonable and in violation of the AD Agreement.
- xv. While the parameters of likelihood are not explicitly defined in the AD Rules, Para (vii) of Annexure II of the AD Rules has been interpreted as the governing provision on factors for likelihood.
- xvi. The parameters analysed by the Authority in the past are: (a) Increase of subject imports indicating a likelihood of increased importation; (b) Evidence to demonstrate spare capacities in a subject country which are likely to be diverted to India if duties are removed; (c) Evidence that proves the existence of depressing/suppressing effect; (d) Evidence on inventories of the article being investigated; (e) Dumping margin in previous investigation; (f) Price attractiveness of the Indian Market; (g) The vulnerability of the domestic industry in terms of price sensitivity of the product and Indian market.
- xvii. To establish whether there is an increase in dumped imports, it is pertinent to analyse the post POI data which the Petitioners have not provided. Without Post-POI data, the likelihood of substantially increased importation cannot be determined. The Petitioners have not provided any evidence of likely undercutting of prices in the event of cessation of ADD.
- xviii. It is not the purpose of ADD to protect the investments/prospective investments of the domestic industry.
- xix. Domestic industry is performing at an adequate level and the subject imports are not affecting their performance in the least.
- xx. If the Petitioners were suffering alleged injury due to the subject imports, the Petitioners should have experienced a decline in its market share and a similar increase in the market share for the subject countries. However, that is not the case in the present factual matrix.
- xxi. The market share of the Petitioners has increased in the POI, while the market share of the imports has remained the same.
- xxii. The claim that inventories with the domestic industries have increased over the injury period is inconsistent with the data provided by them in the Petition as their sales volume have been steadily growing throughout the injury period as well as the POI.
- xxiii. Petitioners have been able to perform well to significantly increase the wages, productivity and employment throughout the injury period.
- xxiv. The dumping margin must be based upon the normal value and export price as provided by the participating exporters/producers from Subject Countries.
- xxv. Positive economic parameters should be sufficient to determine lack of recurrence of injury and the present investigation must therefore be terminated.
- xxvi. The domestic industry has not suffered any continued injury. The performance of the domestic industry has been extraordinary on all parameters and such outstanding performance clearly shows that the expiry of the present duties will not lead to any recurrence of injury.
- xxvii. There was no consistent increase in imports and the movement in imports can be linked to the demand supply situation for the product in the country.
- xxviii. The Indian producers continued to hold 80% of the market share as a whole, which is a substantial market share.
- xxix. The Petitioners are trying to eliminate fair competition by banning imports.

- xxx. The domestic industry has not suffered any volume or price injury. Their absolute sale figure and production has gone up significantly. Capacity utilization also increased during the POI, despite increased capacity.
- xxxi. There has been no injury on price front since imports have not forced them to reduce the prices. The domestic industry has continued to increase the price much more compared to increase in cost of sales resulting into exponential growth in their profits.
- xxxii. The price increases achieved by the domestic industry clearly show that there is no price suppression/depression effect in the present case.
- xxxiii. The domestic industry could increase its wages and every parameter was significantly positive in terms of growth as well.
- xxxiv. The import price from subject countries showed an increase of about 6% by the POI over the base year. The NSR of the domestic industry also increased by about 7% in this period but the cost was reduced by about 17%. The domestic industry was able to increase its prices significantly which shows no price effects from imports and also the pricing behaviour of the domestic industry.
- xxxv. The fact that the import prices increased when there was a significant reduction in cost signifies the exporters also looked at a higher price for the product and there was no reduction in import prices in line with reduction in cost to India. If the exporters were under pressure to export more, they would have reduced the prices.
- xxxvi. The comparison of cost of production of domestic industry and sales price shows that the domestic industry has earned a return on their investment which is much higher than 22% allowed by the Authority.
- xxxvii. The comparison of cost of production of domestic industry and landed price of imports shows that domestic industry sold its goods at par with landed price of imports during the POI.
- xxxviii. The domestic industry has not been suffering injury for years now and such performance suggests that injury is not likely to recur in case of expiry of present duties. The duty cannot be perpetual.
- xxxix. The domestic industry reported a higher volume at the time of petition.
- xl. The domestic industry increased their prices significantly, earned very high ROCE and also suffered no injury on any injury parameters. This could not have been achieved if the price undercutting was having some consequences on them.
- xli. Annexure III deals with the inclusion of outward freight in the calculation of landed price. The argument that their case is about fair comparison which is different from treatment of freight as per Annexure III is frivolous. The attempt of the domestic industry is only to show an inflated picture of injury.
- xl.ii. The product has a demand of about 3262577 MT during the POI. The written submission by the domestic industry shows about 155781 MT, which is less than 5% of the total demand, which has been imported at an injurious level, if seen without ADD. This level is negligible and cannot make any significant impact on the performance of the domestic industry.
- xl.iii. Injury margin and price undercutting should be determined on the basis of total imports from subject countries during the POI and not based on selective transactions as proposed by the domestic industry. This amounts to zeroing, which is banned by WTO.
- xl.iv. The import data provided as part of the domestic industry's written submission and in the petition are not the same. In the absence of a correct import data, discussions on these parameters are irrelevant.
- xl.v. Imports are very minimal. The market share enjoyed by the Indian producers is about 80%.
- xl.vi. The imports are merely covering the demand supply gap at non-injurious price.
- xl.vii. The domestic industry has not been suffering any injury and has also been in a position to increase the capacity.
- xl.viii. The performance is not vulnerable to imports at all, owing to its high standard.

- xlix. The paradigm shift in the performance of imports shows that there is no requirement for continuation of ADD at all.
- l. Future investments are beyond the scope of any protection by way of ADD, and the continuation of ADD cannot be justified on these grounds.
- li. The domestic industry claims to be only concerned with the likelihood of recurrence of dumping and injury in the event of cessation of duty.
- lii. The domestic industry has improved significantly and in such manner that they are encouraged to expand their annual capacities by investing in *** lacs tons of annual capacity.
- liii. The total demand for subject goods increased during the injury period. Total demand (including captive consumption) increased by 13% during the injury period. Total demand (excluding captive consumption) increased by 12% during the injury period. This increase seems to be in line with the requirement of the user industry in India.
- liv. Imports of subject goods increased by 32% over the injury period, but imports as a percentage of demand increased merely 3%.
- lv. Domestic industry's installed capacity, production and domestic sales increased in line with the increase in demand for the subject goods in India.
- lvi. A capacity expansion could only be at the back of robust assessment that there is no likelihood of dumping and injury if anti-dumping duty on subject good lapses.
- lvii. The domestic industry's performance during the injury period and their future plans demonstrate no likelihood of recurrence of dumping causing injury.
- lviii. Overall market share of imports from subject countries increased by 3% from 2013-14 to the POI.
- lix. Profits of the domestic industry increased from 100 indexed points in 2013-14 to 300 indexed points in the POI.
- lx. Profits of the domestic industry increased by 200 indexed points during the injury period.
- lxi. The domestic industry was able to maintain overall 30% market share during the injury period, while market share of other Indian producers slightly declined from 49% in 2013-14 to 47% in the POI. There is clear improvement in the status of the domestic industry.
- lxii. There was a sharp increase in capacity during the injury period, but the capacity utilisation during the POI was almost equal to that of the base year 2013-14. Imports of subject goods did not cause any decline in the domestic industry's capacity utilisation. Domestic industry has been operating at full capacities during this year.
- lxiii. Stocks declined from 100 indexed points in 2013-14 to 74 indexed points in 2014-15. With increase in capacity and production in 2015-16, stocks increased to 136 indexed points. Capacity and production further increased in the POI, but the stocks declined to 132 indexed points.
- lxiv. The domestic industry's stocks increased in the injury period due to the decline in exports.
- lxv. Overall employment slightly decreased from 100 indexed points in 2013-14 to 96 indexed points in the POI, productivity per employee and productivity per day were at an all-time high during POI. Productivity per employee increased by 18 indexed points in 2013-14. Imports did not affect the employment and productivity of the domestic industry.
- lxvi. The wages paid out by the domestic industry increased sharply over the same period from 100 indexed points to 326. The profitability of the domestic industry was still not affected.
- lxvii. Domestic industry's capacity increased from 100 indexed points in 2013-14 to 112 indexed points in the POI. Its capital employed increased by 66 indexed points. RoCE increased from 100 indexed points to 159 points in the POI. Imports have no impact on the return on capital earned by the domestic industry.
- lxviii. Domestic industry's profitability improved remarkably during injury period.

- lxi. The cost of sales of the domestic industry declined by 6 indexed points in the POI, while the selling price increased by 7 indexed points.
- lxx. There was no price suppression or depression and they were making healthy profit.
- lxxi. Price undercutting has had no visible impact on the performance of the domestic industry.
- lxxii. Domestic sales of the domestic industry increased over the entire injury period with increase in demand for subject goods. If the price undercutting had any actual detrimental effect, the domestic industry would not have been able to maintain its domestic sales or increase them.
- lxxiii. Domestic industry's claim of 30% return on capital employed is illegal as the norm is to consider the historical rate of return. The Authority should examine the level of return enjoyed by the soda ash industry globally and in India, and only then adopt an appropriate return on capital employed in this case.
- lxxiv. The Authority is required to assess whether or not the expiry of ADD is likely to lead to continuation or recurrence of dumping or injury.
- lxxv. The Petitioners are not suffering present injury, which can be evidenced by the Petitioner's own admission at the public hearing.
- lxxvi. The market share of the Petitioners has increased in the POI in comparison to the base year and 2014-15. The market share of the imports from the Subject Countries has remained relatively the same. The subject imports have not impacted the market share of the Petitioners.
- lxxvii. Economic parameters including production and sales volume have shown a positive trend in the injury period as well as the POI and the capacity utilization has been constant over the injury period.
- lxxviii. The domestic sales volume and value figures have been steadily growing throughout the injury period as well as the POI- This shows that the domestic industry's sales performance has been profitable irrespective of the subject imports. The production has also increased over the injury period.
- lxxix. The profitability of the Petitioners has risen by 200 points from the base year to the POI.
- lxxx. The Petitioner's profit before interest and tax has also risen by 164 index points in the POI from the base year.
- lxxxi. The return on capital employed has risen by 59 points from the base year to the POI.
- lxxxii. The Petitioners increased the wages paid to their workers throughout the injury period. The wages increased by 226 index points in POI from base year.
- lxxxiii. Likelihood analysis in a sunset review ought to be made on the basis of existing surplus capacities and capacity addition.
- lxxxiv. Price attractiveness cannot be considered as a reason for likelihood of injury in the present factual matrix for lack of evidence on the same.
- lxxxv. Annexure 4.3 of the Petition is not sufficient for determining price attractiveness for reasons as follows: (i) the data as provided is not authenticated evidence for lack of providing the source; (ii) the data only pertains to three months, i.e. January to March 2017 of the POI; (iii) it is not verifiable if it is exports from the subject countries to third countries or India.
- lxxxvi. Reasonable comparison cannot be made between subject country exports to other countries against subject country exports to India for the purpose of price attractiveness.
- lxxxvii. DCW Ltd. have reported vide its Annual Report of 2016-17 that the imports are not a threat and the company is capable of facing international competition.
- lxxxviii. The alleged injury suffered by the Petitioners is an outcome of their unplanned shut down and therefore, is not an effect of the subject imports.
- lxxxix. The DCW Ltd. in their Annual Report 2016-17 have stated that there was loss in turnover of up to 11% in comparison to the previous year due to shut down of soda ash division.

Examination by the Authority

41. The Authority has taken note of the arguments and counter-arguments of the interested parties on injury to the domestic industry.
42. As regards the contention of the domestic industry for consideration of freight incurred by domestic industry as a factor in injury analysis, the Authority notes that NIP has been determined in terms of Annexure III of the AD Rules. The Authority further notes that the comparison between NIP and Landed Value for injury margin determination has been done at the same level as per the consistent practice of the Authority.
43. The injury analysis made by the Authority hereunder addresses the various submissions made by the interested parties.

A. Cumulative assessment

44. Attention is invited to Annexure II para (iii) of the AD Rules which provides that in case imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to an anti-dumping investigation, the Designated Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that:
 - i. the margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two per cent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three per cent of the import of like article or where the export of individual countries is less than three per cent, the imports collectively accounts for more than seven per cent of the import of like article; and
 - ii. Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in the light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.
45. In this regard, the Authority notes the following:
 - i. the margins of dumping for China PR, the EU, Kenya, Pakistan and Ukraine are less than the limits prescribed above. However, the margins of dumping are more than the limits prescribe above for Iran and USA;
 - ii. the volume of imports from each of the subject countries is more than the limits prescribed;
 - iii. The subject goods supplied from various subject countries and by the domestic industry compete with each other in the same market.
46. The Authority has taken note of the submissions made by the interested parties. Annexure II of the AD Rules provides for objective examination of both (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for the like articles; and (b) the consequent impact on domestic producers of such products. While examining the volume effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in dumped imports either in absolute terms or relative to production or consumption in India. With regard to price effect of dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree or prevent price increase which would have otherwise occurred to a significant degree.
47. As regards the impact of dumped imports on the domestic industry, para (iv) of Annexure-II of the AD Rules states as follows:

“The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.”
48. For the examination of the impact of imports on the domestic industry in India, the Authority has considered such further indices having a bearing on the state of the industry as production, capacity utilization, sales quantum, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of

dumping etc. in accordance with Annexure II(iv) of the Rules supra.

49. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account the facts and arguments of the interested parties.
50. According to Section 9(A)(5) of the Customs Tariff Act, 1975, anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition, provided that if the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may, from time-to-time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of the order of such extension.
51. In consideration of the various submissions made by the interested parties in this regard, the Authority has examined the current injury, if any, to the domestic industry before proceeding to examine the likelihood aspects of dumping and injury on account of imports from the subject countries.

Demand and market share

52. For the purpose of assessment of the domestic consumption/demand of the subject goods, the sales volume of the domestic industry and other Indian producers have been added to the total imports into India and the same have been summarized below:

Particulars	UOM	2013-14	2014-15	2015-16	POI
Sales of Domestic Industry (including captive)	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>99</i>	<i>110</i>	<i>115</i>
Sales of Other Indian producers (including captive)	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>103</i>	<i>105</i>	<i>108</i>
Imports - Subject Countries	MT	490,567	672,947	603,749	645,298
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>137</i>	<i>123</i>	<i>132</i>
Imports - Other Countries attracting duties	MT	62,355	49,071	25,674	35,469
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>79</i>	<i>41</i>	<i>57</i>
Imports - Other Countries	MT	16,044	1,202	3,839	14,355
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>7</i>	<i>24</i>	<i>89</i>
Total Demand (With captive transfer)	MT	2,884,703	3,079,692	3,113,308	3,262,392
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>107</i>	<i>108</i>	<i>113</i>
Domestic Industry	%	***	***	***	***
Other Indian Producers	%	***	***	***	***
Indian Producers as a whole	%	80.28%	76.52%	79.66%	78.69%
Subject Countries	%	17.01%	21.85%	19.39%	19.78%
Other Countries attracting duties	%	2.16%	1.59%	0.82%	1.09%
Other Countries	%	0.56%	0.04%	0.12%	0.44%
Share of imports from subject countries in Indian production (excluding Tata Chemicals Ltd.)	%	30%	40%	34%	34%
Share of imports from subject countries in Indian production (including Tata Chemicals Ltd.)	%	21%	28%	24%	25%

53. The Authority notes that demand has increased during the POI as compared to the base year. The growth in demand during the POI over base year was 13%. Market share of domestic industry and imports from subject countries increased during the injury period.

B. Volume Effects of Dumped Imports

Import Volume and Market Share

54. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the import data procured from DGCI&S. The volume of imports of the subject goods from the subject countries have been analyzed as under:

Particulars	UOM	2013-14	2014-15	2015-16	POI
Import Volume					
China PR	MT	100,052	127,005	89,907	33,769
EU	MT	189,191	242,549	242,792	295,525
Kenya	MT	162,392	130,161	101,149	89,516
Pakistan	MT	16,725	37,207	39,910	40,873
Iran	MT	-	5,427	20,204	32,991
Ukraine	MT	196	43,276	29,634	26,714
USA	MT	22,010	87,321	80,153	125,911
Subject Countries	MT	490,567	672,947	603,749	645,298
Other Countries attracting duties	MT	62,355	49,071	25,674	35,469
Other Countries	MT	16,044	1,202	3,839	14,355
Total Imports	MT	568,966	723,220	633,262	695,122
Market Share					
China PR	%	18%	18%	14%	5%
EU	%	33%	34%	38%	43%
Kenya	%	29%	18%	16%	13%
Pakistan	%	3%	5%	6%	6%
Iran	%	0%	1%	3%	5%
Ukraine	%	0.03%	6%	5%	4%
USA	%	4%	12%	13%	18%
Subject Countries	%	86%	93%	95%	93%
Other Countries attracting duties	%	11%	7%	4%	5%
Other Countries	%	3%	0%	1%	2%
Total	%	100%	100%	100%	100%

55. Imports from China PR, the EU, Kenya, Pakistan and Ukraine were un-dumped during the POI. The Authority notes that imports from China PR and Kenya have declined during the POI whereas imports from EU, Pakistan and Ukraine have increased during the POI. The Authority further notes that market share of China PR and Kenya have declined during the POI, whereas market share of EU, Pakistan and Ukraine have increased during the POI.
56. Imports from Iran and USA were dumped during the POI. Imports from both of these countries have increased. The Authority further notes that market share of Iran and USA have increased during the

POI.

57. Subject imports comprise 93% in total imports of the subject goods into India during the POI. Out of this, share of dumped imports from Iran and USA is 23%, while share of un-dumped imports from China PR, the EU, Kenya, Pakistan and Ukraine is 70%. The Authority notes that the quantum of un-dumped imports is significant in comparison to dumped imports.

C. Price Effect of the Dumped imports on the Domestic Industry

58. With regard to the effect of the dumped imports on prices, the Designated Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. The impact on the prices of the domestic industry on account of the dumped imports from the subject countries has been examined with reference to the price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis, the cost of production, Net Sales Realization (NSR) and the Non-injurious Price (NIP) of the domestic industry have been compared with the landed price of imports from the subject countries.

Price suppression and depression effects of the dumped imports

59. The price suppression and price depression effect of the dumped imports has also been examined with reference to the cost of production, net sales realization and the landed values of the subject goods from the subject countries in relation to the injury period including the POI.

Particulars	UOM	2013-14	2014-15	2015-16	POI
Cost of Sales	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	93	83	84
Selling Price	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	107	109	107
Landed price of Subject Imports from China PR	Rs./MT	14,390	17,303	16,653	18,128
Trend	Indexed	100	120	116	126
Landed price of Subject Imports from EU	Rs./MT	16,259	17,366	18,429	16,878
Trend	Indexed	100	107	113	104
Landed price of Subject Imports from Kenya	Rs./MT	14,805	15,633	16,457	14,662
Trend	Indexed	100	106	111	99
Landed price of Subject Imports from Pakistan	Rs./MT	18,192	19,038	19,665	17,957
Trend	Indexed	100	105	108	99
Landed price of Subject Imports from Iran	Rs./MT	NA	16,598	15,813	14,722
Trend	Indexed	NA	100	95	89
Landed price of Subject Imports from Ukraine	Rs./MT	17,473	17,086	17,284	15,567
Trend	Indexed	100	98	99	89
Landed price of Subject Imports from USA	Rs./MT	12,668	15,987	15,901	14,378
Trend	Indexed	100	126	126	113

60. It is pertinent to note that imports of the subject goods only from Iran and USA were dumped during the POI, while imports from all the other subject countries were un-dumped in that period.
61. The cost of sales of the domestic industry decreased during the POI as compared to the base year. Selling price of the domestic industry however increased during the injury period. The landed value of imports from China PR, EU and USA has increased during the POI as compared to the base year. The landed value of imports from Kenya and Pakistan during the POI has more or less remained the same. The landed value of imports from Iran and Ukraine has declined during the POI as compared to the base year. The Authority notes that the selling price of the domestic industry was much higher than its cost of sales during the entire injury period. Further, selling price of the Petitioners has consistently increased and during the injury investigation period. The imports from subject countries did not cause any price suppression or price depression for the domestic industry.

Price Undercutting

62. While working out the net sales realization of the domestic industry, the rebates, discounts and commissions offered by the domestic industry and the central excise duty paid have been deducted. The landed value of imports has been calculated by adding 1% landing charges and applicable basic customs duty and education cess to the CIF prices from the subject countries, as reported in DGCI&S data. The domestic industry contended that freight should be included for determination of price undercutting. The Authority further notes that the comparison between Net Sales realization and Landed Value for price undercutting determination has been done at the same level as per the consistent practice of the Authority .

Particulars	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	POI
China					
Landed price of imports	Rs./MT	14,390	17,303	16,653	18,128
Net Sales Realisation	Rs./MT	***	***	***	***
Price Undercutting	Rs./MT	***	***	***	***
Price Undercutting	%	***	***	***	***
Price Undercutting	% Range	20-30%	10-20%	10-20%	0-10%
EU					
Landed price of imports	Rs./MT	16,259	17,366	18,429	16,878
Net Sales Realisation	Rs./MT	***	***	***	***
Price Undercutting	Rs./MT	***	***	***	***
Price Undercutting	%	***	***	***	***
Price Undercutting	% Range	10-20%	10-20%	0-10%	10-20%
Kenya					
Landed price of imports	Rs./MT	14,805	15,633	16,457	14,662
Net Sales Realisation	Rs./MT	***	***	***	***
Price Undercutting	Rs./MT	***	***	***	***
Price Undercutting	%	***	***	***	***
Price Undercutting	% Range	20-30%	20-30%	15-25%	30-40%
Pakistan					
Landed price of imports	Rs./MT	18,192	19,038	19,665	17,957
Net Sales Realisation	Rs./MT	***	***	***	***
Price Undercutting	Rs./MT	***	***	***	***
Price Undercutting	%	***	***	***	***

Particulars	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	POI
Price Undercutting	% Range	(5)-5%	0-10%	(5)-5%	0-10%
Iran					
Landed price of imports	Rs./MT	NA	16,598	15,813	14,722
Net Sales Realisation	Rs./MT	NA	***	***	***
Price Undercutting	Rs./MT	NA	***	***	***
Price Undercutting	%	NA	***	***	***
Price Undercutting	% Range	NA	10-20%	20-30%	25-35%
Ukraine					
Landed price of imports	Rs./MT	17,473	17,086	17,284	15,567
Net Sales Realisation	Rs./MT	***	***	***	***
Price Undercutting	Rs./MT	***	***	***	***
Price Undercutting	%	***	***	***	***
Price Undercutting	% Range	0-10%	10-20%	10-20%	20-30%
USA					
Landed price of imports	Rs./MT	12,668	15,987	15,901	14,378
Net Sales Realisation	Rs./MT	***	***	***	***
Price Undercutting	Rs./MT	***	***	***	***
Price Undercutting	%	***	***	***	***
Price Undercutting	% Range	40-50%	15-25%	20-30%	30-40%

63. The Authority notes that during the POI, the price undercutting effect of imports was positive in respect of each of the above referred countries. However, it is important to note that imports from China PR, the EU, Kenya, Pakistan and Ukraine were un-dumped during the POI whereas imports from Iran and USA were dumped during the POI. Since majority of imports from the subject countries were un-dumped during the POI, the Authority has carried out further analyses on economic parameters of the domestic industry and likelihood or recurrence of dumping and injury in subsequent paragraphs for a holistic understanding of the situation.

D. Examination of other Economic Parameters of Domestic Industry

Production, Capacity, Sales and Capacity Utilization

64. The Production, Capacity and Capacity Utilization details are as follows:

Particulars	UOM	2013-14	2014-15	2015-16	POI
Installed capacity	MT	1,111,000	1,111,000	1,236,000	1,246,400
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>111</i>	<i>112</i>
Total Indian Production	MT	1,611,777	1,693,439	1,786,756	1,886,607
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>105</i>	<i>111</i>	<i>117</i>
Production of Petitioners	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>102</i>	<i>110</i>	<i>113</i>
Capacity Utilization	%	83	85	82	84
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>102</i>	<i>99</i>	<i>101</i>
Domestic Sales (including captive)	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>99</i>	<i>110</i>	<i>115</i>
Demand	MT	2,884,703	3,079,692	3,113,308	3,262,392
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>107</i>	<i>108</i>	<i>113</i>

65. From the above information, the Authority notes that the capacity of production of the domestic industry has increased during the injury period including the POI. The domestic sales have increased during the POI. The capacity utilization has more or less remained the same despite capacity addition during 2015-16 and the POI.

Inventories

66. Data relating to inventories shows as follows:

Particulars	UOM	2013-14	2014-15	2015-16	POI
Opening	MT	***	***	***	***
Closing	MT	***	***	***	***
Average	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	74	136	132

67. It is noted that average inventories increased prior to the POI and then witnessed decline during the POI.

Profits and actual and potential effects on the cash flow

68. With regard to Profit/Loss and cash flow, it is noted that the profitability of domestic industry in terms of profit before tax and interest, cash profit and return on investment have remarkably increased in the POI as compared to base year. The Authority has determined profit, cash profit and ROI on the basis of its consistent practice.

Particulars	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	POI
Cost of Sales	Rs/MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	93	83	84
Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	107	109	107
Profit/Loss	Rs/MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	224	321	300
Profit/Loss	Rs.Lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	226	359	338
PBIT	Rs.Lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	177	280	264
Cash Profit	Rs.Lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	184	288	287
Return of investment	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	193	293	160

Employment, wages and productivity

69. The data relating to employment, wages and productivity show as follows:

Particulars	UOM	2013-14	2014-15	2015-16	POI
Productivity per employee	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>103</i>	<i>114</i>	<i>236</i>
Employment	Nos.	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>99</i>	<i>96</i>	<i>96</i>
Wages	Rs. Lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>110</i>	<i>124</i>	<i>326</i>

70. It is noted that there was marginal decline in the number of employees during the POI as compared to the base year 2013-14, however, productivity remarkably increased during the POI as compared to the base year. Wages also increased during the POI in comparison to the base year 2013-14.

71. The Authority notes that situation of the Petitioners has remarkably improved in respect of economic parameters discussed above. Particularly, capacity, production, domestic sales, cash flow, profitability, ROCE and productivity show significant improvement over the injury period. Selling price of the domestic industry has increased over the injury period and remains higher than the cost of sales despite cost associated with addition of capacities. Analysis in later sections demonstrate that the selling price of the domestic industry was also higher than the non-injurious price determined for the domestic industry.

E. Magnitude of dumping

72. It is observed from the section pertaining to Dumping Margin above that dumping margins in respect of the imports of the subject goods from China PR, the EU, Kenya, Pakistan and Ukraine was negative during the POI. Dumping margin was positive during the POI for Iran and USA. . However, the same has had no visible impact on the performance of the Petitioners.

Growth

73. The Authority notes that the growth of the domestic industry was positive in terms of improvement in production, sales, profit before tax and interest, cash profit and return on investment during the POI.

Ability to raise funds

74. It is noted that the domestic industry has enhanced its capacity of production of the subject goods in the year 2015-16 and the POI. The domestic industry has made significant capital investment at present and has further planned investments for enhancing capacities. This signifies that their ability to raise capital investment has not been affected adversely.

F. Magnitude of Injury and Injury Margin

75. The non-injurious price of the subject goods produced by the domestic industry as determined by the Authority has been compared with the landed value of the exports from the subject countries for determination of injury margin during POI. The injury margin thus determined is as under:

76. As per the consistent practice followed by the authority, the NIP is worked out as per the methodology prescribed under Annexure-III of the AD Rules on the basis of financial records maintained by the domestic industry rather than the cost audited records. This is primarily on account of the fact that certain costs which are treated as inadmissible in the anti-dumping investigation may be considered as part of costs in the cost audit reports. Further annexure- III prescribes different methodology in respect of raw materials, utilities and other fixed costs. Cost audit report do not follow these rules and procedures. In this investigation however, the domestic industry have not been able to furnish the required information expense head wise as per the audited financial records and accordingly the

authority was constrained to determine NIP on the basis of information available in the cost audit reports provided by the domestic industry.

POI

Country	Exporter/ Producer	NIP INR/MT	Exchange Rate	NIP US\$/MT	Landed Value US\$/MT	Injury Margin US\$/MT	Injury Margin %	Injury Margin % Range
China PR	All	***	67.95	***	267	***	***	Negative
EU	All	***	67.95	***	248	***	***	Negative
Kenya	All	***	67.95	***	216	***	***	Negative
Pakistan	All	***	67.95	***	264	***	***	Negative
Iran	All	***	67.95	***	217	***	***	Negative
Ukraine	All	***	67.95	***	229	***	***	Negative
USA	All	***	67.95	***	212	***	***	Positive
Weighted average	All	***	67.95	***	236	***	***	Negative

G. Conclusions on material injury

77. The Authority notes that the performance of the domestic industry improved in terms of production, sales volumes, market share, profit, cash profit, return on capital employed and inventory during the POI as compared to the base year. The domestic industry has also admitted in its submissions that it was not suffering injury during the injury period. Selling price of the domestic industry has increased over the injury period and remains much higher than the cost of sales despite cost associated with addition of capacities. The selling price of the domestic industry was also much higher than the non-injurious price during the POI.

L. Other known factors and causal link

Submissions of Petitioners

- i. The dumped imports from the subject countries have increased despite ADD in force.
- ii. Subject imports are available at prices lower than domestic prices. Thus, if the ADD ceases, the dumped imports volumes shall increase once again.
- iii. The capacities available with the producers from the subject countries and their export orientation show that in case ADD ceases to exist, the volume of dumped imports would surge.
- iv. The exporters are highly export oriented. Significant exports are made by the subject exporters to third countries at prices below which they are exported to India and are dumped at an injurious price. The imports would significantly undercut the domestic prices in the event of cessation of duties. Resultantly, the domestic industry will be faced with price depression in the market.
- v. Domestic industry would be forced to reduce the prices of the product concerned significantly given the fact that the product concerned is a commodity product.
- vi. The natural impact of the reduction of prices would be on the profitability of the domestic industry. Decline in profits would lead to decline in cash flow and return on investment.
- vii. If the domestic industry chooses to maintain its normal price levels, it is likely to lose its sales volume. That would be a bigger injury since it would lead to a use in inventories level, decline in production, capacity utilization, and productivity.
- viii. A positive finding of injury would be recorded only in case there is a relationship between cessation of ADD and recurrence or continuation of injury to the domestic industry. There exists a causal

relationship between the likelihood of recurrence or injury and dumped imports in the event of premature withdrawal of ADD.

Submissions made by other interested parties

- i. The alleged increase in dumped imports did not impact the production, capacity utilisation and domestic sales of the Petitioners.
- ii. We dispute the domestic industry's claim that subject imports were available at prices lower than the domestic industry's prices.
- iii. Capacities available in the subject countries have no bearing in this case. The Indian industry has added close to 6 Lac tons of annual capacity as was disclosed during the public hearing. There are further plans to add 20 lac tons of annual capacity. The domestic industry's strong presence would impede the flow of any surplus capacities in the subject countries to India.
- iv. In case the price undercutting claimed by the domestic industry had an actual detrimental impact, the domestic industry would not have been able to maintain its domestic sales or to increase them. The mere fact that the domestic industry managed to expand its sales in India despite the alleged price undercutting demonstrates the absence of injury and no likelihood of continuation or recurrence of injury.
- v. Selling price of the domestic industry continuously increased during the injury period despite the alleged dumping. The data on record does not show that the domestic industry was forced to lower its prices during the injury period.
- vi. Profitability of the domestic industry has increased almost 3 times during the POI as compared with the base year 2013-14.
- vii. Domestic industry installed additional capacities and earned very good return on the same.
- viii. There is no evidence that suggests that if ADD is revoked, consumers would switch to imports.

Examination by the Authority

78. Having examined injury, volume and price effects of dumped imports on the prices of the domestic industry, in terms of its price undercutting and price suppression and depression effects, other indicative parameters listed under the AD Rules and AD Agreement have been examined by the Authority to see whether any other factor, other than the dumped imports could have contributed to injury to the domestic industry, as follows:

a. Volume and prices of imports from third countries

The Authority notes that during the POI, imports of the subject goods from countries other than the subject countries and countries attracting anti-dumping duty were not so significant.

b. Contraction of demand and changes in the pattern of consumption.

The Authority notes that there is no contraction in the demand during the POI. On the contrary, overall demand for subject goods has shown improvement during the POI.

c. Developments in technology:

The Authority notes that none of the interested parties have furnished any evidence to demonstrate significant changes in technology that could have caused injury to the domestic industry.

d. Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers

The Authority notes that the subject goods are freely importable. The domestic industry is the major producer of the subject goods and account for significant domestic production and sales. Further there is no perceptible competition among the domestic producers, except that is obvious of a market economy.

e. Export performance of the domestic industry:

The Authority notes that the performance of the Petitioners in the export markets has not affected the assessment made by the Authority of the domestic industry's performance. The Authority conducted its assessment based solely on information pertaining to the domestic sales. Injury on account of domestic

sales has been isolated and examined, to the extent possible.

79. From the above analysis, the Authority notes that neither of the listed known parameters nor the other factors analysed above show any continued injury to the domestic industry. The economic health of the domestic industry has improved.

M. Likelihood of continuation or recurrence of injury

Submissions made by the Petitioners

- i. Absence of continued injury to the domestic industry in the investigation period is not sufficient to warrant cessation of ADD.
- ii. The injury suffered by the domestic industry in the past was due to dumping of the product. Improvement in the performance of the domestic industry or absence in the injury in the current period is a natural result of imposition of ADD.
- iii. Soda ash has a history of continued dumping in the country. The imports have increased significantly at low price, despite the imposition of ADD.
- iv. There has been an influx of unfairly priced imports from multiple countries. Against some of these countries there is a parallel anti-dumping investigation ongoing.
- v. Dumping margins determined in previous investigation and proposed in the present investigation are significant and clearly show likelihood of dumping and consequent injury in the event of cessation of ADD.
- vi. The dumping margin with respect to each of the subject countries is substantially high.
- vii. Imports from subject countries have increased in the POI after declining till 2015-16. Increase in imports at dumped prices indicates that imports are likely to enter in significant volume at dumped price in the event of cessation of ADD.
- viii. The imports over the injury period did not have suppressing or depressing effects on price of the domestic industry for the reason that ADD was in place.
- ix. However, import price have started declining significantly and have started having suppressing effect on the prices of the domestic industry since the new Turkish capacities have commercialized.
- x. While the level of inventories of the producers in the subject countries could not be accurately determined, it can be fairly assumed that the foreign producers can scale up production in a short period of time.
- xi. Exporters from Pakistan are expanding their capacities and appears to cater to export markets. This information can be gathered from the demand and supply gap in Pakistan as provided in the IHS Chemical Week. The first phase of expansion shall add *** MT of new capacity operational from July 2017. The second phase of the expansion will also add *** MT of new capacity operational from July 2019.
- xii. M/s Olympia from Pakistan has an annual capacity of *** MT. A Chinese Engineering company is cooperating with it to add *** MT of new capacity, which shall be completed by December 2018.
- xiii. The demand in Pakistan is expected to grow in the range of 4-6% per year. The market is said to be oversupplied, as per the IHS Chemical Week.
- xiv. Despite existing significant surplus capacities of China, the proposed capacity expansions are extremely large. The fact that Chinese producers can afford such massive capacity expansions in spite of having huge surplus already show that the capacity expansions are likely to be directed towards exports.
- xv. ETI Soda from Europe, which is controlled by the Turkish conglomerate, Ciner Group is aiming to become the biggest producer of Soda Ash in Europe. It has seen two major expansion projects which have been delayed for financial and construction reasons. However, the expansion projects are now operational again.

- xvi. Producers around the world have capacities more than their domestic demand which forces them to sell their products, especially to Indian market owing to its strength.
- xvii. Producers are still looking to expand their capacities, especially Turkey, which will lead to further outflow of subject goods from Turkey to EU. EU, which is already dumping in India will intensify the act.
- xviii. US and China were traditionally the largest exporters of subject goods globally. Reports show that demand in US and China has declined. The excessive supply would also be diverted to countries with growing demand, such as India.
- xix. The volume of dumped exports was extremely high throughout the period considered.
- xx. The volume of injurious exports and price attractive exports was very high earlier. The share declined till 2015-16 and increasing thereafter.
- xxi. The volume of injurious and price attractive exports is quite high in the present POI in comparison to the consumption in India and the proportion increased thereafter in the post POI.
- xxii. Price attractiveness of Indian market is required to be decided considering the following parameters: selling price of domestic industry, current prices at which exporters are exporting to India, current prices at which exporters are exporting to a number of other countries, and surplus unutilized capacities.
- xxiii. The Indian market is highly price sensitive. The customers decide their procurement, with the price being the foremost consideration. All negotiations with major consumers happen on the basis of the price quoted by the industry and foreign producers. Availability of such low-priced imports from subject countries in the market will definitely cause an adverse impact on the domestic industry.
- xxiv. In the event of withdrawal of current ADD, and if domestic industry is constrained to sell at import prices, the profitability of the domestic industry would significantly decline. The return on investment and cash profit would also decline.
- xxv. Reliance was placed on previous authority investigations wherein authority undertook the following tests to determine whether dumping after ADD cessation is likely or not: price undercutting and injury margin in respect of exports to India and other third countries during and post-POI; the volume of exports to third countries during POI and over the past one decade which was at a price below the selling price of the domestic industry, export price to India, and whether such volume of exports is significant having regard to Indian demand. The answer to all six tests must be negative in order to ascertain that the Indian market is not attracting foreign producers.
- xxvi. The Authority has relied on the injury margin principle in the past but cannot do so anymore. It cannot determine likelihood to not exist if the injury margin is negative. The present exports to India are not sufficient to determine whether injury to domestic industry is likely to occur.

Submissions made by other interested parties

- i. Alleged likelihood of injury cannot be analysed by any interested party since the Petitioner has not provided all requisite post-POI data.
- ii. The mere existence of dumping in previous investigations is not the crux of a sunset review and there must be explicit evidence of an increase of dumped imports into India.
- iii. The determination of likelihood of dumping and injury upon expiration of ADD is dependent on the analysis of the prospective rate of increase of dumped imports, freely disposable or increase in existing capacity in Subject Countries, price suppression/depression, and inventories along with other relevant criteria. There is insufficient data to establish this.
- iv. The claim made regarding Turkish capacities is irrelevant and not verifiable with any evidence.
- v. Depressed or suppressed selling price of the Petitioners cannot be attributed to the price of the subject imports. The alleged effect of the price of subject imports must be significant, which in the present case is non-existent.

- vi. The extract of the IHS report is not verifiable as a true extract. Further, it does not evidence if Pakistan is export-oriented or that there is demand-supply gap in Pakistan.
- vii. The year of the IHS Report is not verifiable.
- viii. On analysis of the IHS Report, it is evident that the capacity is utilized to a great extent in the domestic market, evidencing that there is no demand-supply gap in Pakistan and all the capacity is utilized in the domestic market of Pakistan.
- ix. The table provided for capacity expansion in China is not authenticated and is not verifiable.
- x. The public domain information pertaining to ETI Soda in Europe are from 2015. Moreover, they talk about plans of expansions.
- xi. None of the evidences provided by the Petitioners show export orientation of the subject countries.
- xii. Claims about decline in demand in US and China are unsubstantiated.
- xiii. Claims about Turkish exports flowing into Europe, and in turn Europe dumping in India are unsubstantiated and are mere conjecture.
- xiv. Claims of significant exports from China, EU, Ukraine and USA dumping in third countries have not been substantiated with a verifiable source.
- xv. Price attractiveness cannot be considered as a reason for likelihood of injury in the present factual matrix for lack of evidence for the same.
- xvi. A reasonable comparison cannot be made between exports made by subject countries to other countries against exports made by subject countries to India.
- xvii. Claims regarding vulnerability of domestic industry in terms of price sensitivity of the product and the Indian market are unsubstantiated.
- xviii. The determination of likelihood is a holistic determination. The Petitioners' proposal to let ADD continue even if one of the situations mentioned in Para 122-124 of their written submission is true is against the principles of natural justice and is in violation of AD Rules.
- xix. Causation is central to the language "likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry."
- xx. DCW Ltd. has reported in its Annual Report 2016-17 that the imports are not a threat and the company is capable of facing international competition.
- xxi. The alleged injury suffered by the petitioners is an outcome of their unplanned shut down and is not an effect of subject imports.
- xxii. Landed price of imports calculated here is without loading the current ADD and thus withdrawal of ADD will not change the situation, and therefore this is no likelihood of injury.
- xxiii. Post-POI data may be used to examine the likelihood, not the historical data.
- xxiv. The data pertaining to the claims of likelihood mentioned in the said paragraphs is different from the data presented in the petition.
- xxv. The domestic industry's performance has been extraordinarily good on all parameters and likelihood of injury is based on illusionary claims.
- xxvi. The imports are merely filling the gap between demand and supply at a non-injurious price. The increase in volume produced by the domestic industry would automatically lead to a drop in demand for imports.
- xxvii. The current shares of imports only constitute 20% of the market share, as compared to the domestic industry's 80% of market share.
- xxviii. The imports have not created any injurious effect on the domestic industry even at price undercutting levels.

- xxix. The domestic industry is operating at a very high level of ROCE and providing protection to such high ROCE is not the purpose of ADD.
- xxx. The alleged increase in dumped imports did not impact the production, capacity utilization and domestic sales of the domestic industry.
- xxxi. Any alleged price undercutting had no impact on the financial performance of the domestic industry.
- xxxii. Surplus capacities available in the subject countries have no bearing in this case. The Indian industry has added close to *** lac tons of annual capacity as was disclosed during the public hearing and in the domestic industry's written submissions. There are further plans to add *** lac tons of annual capacity as per the domestic industry's written submissions. The strong presence of the Indian industry would impede the flow of any surplus capacities in the subject countries to India.
- xxxiii. If price undercutting had any actual detrimental impact, the domestic industry would not have been able to expand its sales.
- xxxiv. Profitability of the domestic industry increased almost three times during the POI despite increased exports.
- xxxv. Despite increase in imports of the subject goods, the domestic industry installed additional capacities and earned very good return on the same.
- xxxvi. There is no evidence to suggest that if ADD is revoked, consumers would switch to imports.
- xxxvii. The subject goods have users in detergent as well as glass industry, which use the subject goods on a large scale.
- xxxviii. With Indian Rupee depreciating against the US Dollar, it has been becoming more and more expensive to import the subject goods. The user industry will continue to rely on local supplies of the subject goods and import the subject goods only when there is a shortfall of supply.
- xxxix. The transportation cost cannot be included in the determination of NIP since it is not supported by law. Transportation cost was not included in determining NIP in the original investigation as well. While India has advocated for this in the WTO, this proposal has not been accepted by the WTO membership yet.
- xl. The price undercutting and injury margin should be determined only on weighted average basis. The domestic industry's claim that price undercutting and injury margin should be determined on transaction level only for those transactions where undercutting and injury margin are positive is erroneous and illegal. This would amount to applying zeroing practice, which has been held illegal by the WTO.
- xli. No other Indian producer, despite large investments made by them, has come ahead and asked for continuation of ADD.
- xlii. No credible source has been provided to prove that China PR will be adding more capacities for the subject goods.
- xliii. No post-POI data has been provided with respect to price suppression/depression, nor has any substantiated submissions been made with respect to the same.
- xliv. The alleged effect of the price of subject imports must be significant which in the present case is non-existent as evidenced by the data produced.
- xlv. No post-POI data has been provided with respect to inventory level in the Subject Countries.
- xlvi. The mere existence of dumping in previous investigations is not the crux of a Sunset review and there must be explicit evidence of an increase of dumped imports into India.
- xlvi. The determination of likelihood of dumping and injury upon expiration of ADD is dependent on the analysis of the prospective rate of increase of dumped imports, freely disposable or increase in existing capacity in the Subject Countries, price suppression/depression, and inventories along with other relevant criteria.

Examination by the Authority

80. The Authority examined the likelihood of continuation or recurrence of injury considering the parameters relating to the threat of material injury in terms of Annexure II(vii) of the AD Rules. While considering the likelihood aspect under clause (vii) of Annexure II to the AD Rules the Authority considered, inter alia, the following factors as:

1. Present and continued imports

81. The Authority has undertaken analysis of the volume of exports of the subject goods to India from the subject countries during the injury period including the POI and post-POI period as well. Imports from China PR, the EU, Kenya, Pakistan and Ukraine were un-dumped during the POI. The Authority notes that imports from China PR and Kenya have declined during the POI whereas imports from EU, Pakistan and Ukraine have increased during the POI. Imports from Iran and USA were dumped during the POI. Imports from both of these countries have increased. The Authority notes that the volume of the exports from all the subject countries taken together to India increased from *** MT in 2013-14 to *** MT during the POI. However, in the post POI period 2017-18, imports of the subject goods from all the subject countries taken together declined to *** MT, a decline of 2.5%. As established in earlier sections, majority of imports from the subject countries were un-dumped, performance of the domestic industry improved on all economic parameters, selling price of the domestic industry increased over the injury period and remained higher than the cost of sales and non-injurious price. There is no present dumping and injury, and the analysis shows that the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury is not established.

2. Surplus Capacities

82. This parameter for ascertaining the threat of material injury requires evaluation of existing surplus capacities and capacity addition, if any, to explore the possibility of diversion of disposable quantity to Indian market. Domestic industry has claimed that the producers in subject countries are already faced with significant surplus capacities and that these producers are exporting the product to a large number of countries, a very significant proportion of which is being exported at a price below the prices in respect of India, thus showing likelihood of diversion of these exports to India in the event of withdrawal of anti-dumping duty.

83. While none of the interested parties have provided any verifiable evidence and information with regard to existing surplus capacities, and consequent likelihood /possibility of increased dumped exports to the Indian market, the domestic industry has furnished information in the petition taken from IHS Chemical journal, which provides information regarding Soda Ash manufacturing in the subject countries viz. existing capacity, existing production, unutilized capacity and capacity expansion etc. As would be obvious from the table below that against Indian demand of approx. *** million MT, the unutilized capacity in the subject countries is approx. *** million MT (***% of demand in India) and capacity expansion (undertaken already as well as upcoming) is to the extent of *** million MT (***% of demand in India). However, it is not established that any such alleged surplus capacities in subject countries shall be diverted to India if anti-dumping duty were to be revoked.

Particulars	UOM	Subject Countries					
		China	USA	EU	Pakistan	Iran	Total
Existing Capacity	MT	***	***	***	***	***	***
Existing Production	MT	***	***	***	***	***	***
Unutilized Capacity	MT	***	***	***	***	***	***
Capacity Expansion	MT	***	***	***	***	***	***

3. Level of inventories

84. The level of inventories available with the producers in subject countries could not be ascertained in view of non-submission of questionnaire response by foreign producer(s)/exporter(s).

4. Price suppression and Price depression

85. The cost of sales of the domestic industry decreased during the POI as compared to the base year. Selling price of the domestic industry also increased during the injury period. The landed value of imports from China PR, EU and USA has increased during the POI as compared to the base year. The landed value of imports from Kenya and Pakistan during the POI has more or less remained the same. The landed value of imports from Iran and Ukraine has declined during the POI as compared to the base year. As established in earlier sections, there is no price suppression and price depression due to imports from subject countries.

5. Level of current dumping margin

86. The Authority notes that dumping margin in the original investigation was positive. However, in the present sunset review, dumping margin is negative/de minimis during the POI for imports from China PR, the EU, Kenya, Pakistan and Ukraine.
87. Based on the above analyses, the Authority holds that there is no likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury in case of revocation of anti-dumping duty.

N. Post-disclosure comments

Submissions made by the Petitioners

- i. The petitioners have requested disclosure of a non-confidential version copy of the communications sent by the Authority, copy of the replies filed by the Interested Parties, submissions by Interested Parties, copy of the rejoinder submissions, and the Normal Value in order to enable them to come to a meaningful conclusion.
- ii. In order to apply definitive measures at the conclusion of anti-dumping investigations, an investigating Authority must find dumping, injury and causal link.
- iii. The “essential facts” underlying the findings and conclusions pertaining to the determination of dumping, injury and causal link and likelihood of dumping and injury form the basis of the decision to apply definitive measures and should be disclosed to all interested parties as per Article 6, in order for them to comment.
- iv. The Authority has merely provided the trend prevalent from year to year on various economic parameters such as production, sales and capacity utilisation, etc.
- v. The Authority’s conclusion on these injury parameters constitute “essential fact”.
- vi. The conclusions on fact that must be resolved in order to apply definitive measures in a sunset review investigation are (a) dumping (b) injury (c) causal link (d) likelihood of continuation or recurrence of dumping (e) continuation or recurrence of injury.
- vii. The Designated Authority has not stated facts with regard to likelihood of recurrence or continuation of dumping and injury. The disclosure statement does not constitute sufficient disclosure of essential facts as per Rule 16.
- viii. With regard to likelihood of recurrence of injury, the disclosure statement merely contains parameters or information or verified data that are relevant to establishment of facts.
- ix. The information given by the exporters for determination of normal value, export price or dumping margin constitutes “data/information”, while the normal value, export price & dumping margin constitutes “facts”.
- x. Any such disclosure statement would not enable any Interested Party in knowing what the essential facts under consideration by the Designated Authority are.
- xi. The Designated Authority disclosed whether or not dumping margin is more than de-minimis and that there is improvement in all the parameters of the Domestic Industry but has not disclosed whether there is likelihood of continuation or recurrence of dumping.
- xii. The Authority only shared the determination of NIP and the written submissions of all the parties, despite various communications by the Domestic Industry to the Authority between November 27, 2018- November 30, 2018 requesting disclosure.

- xiii. The product under consideration is Disodium Carbonate, also known as Soda Ash. The product scope in the present investigation is the same as what was already defined in the original investigation of the product concerned.
- xiv. The Authority has refrained from making an observation on whether or not the product produced by the Domestic Industry is a like article to the product under consideration.
- xv. Tata Chemicals has related producers in Kenya, US and Europe. The Kenyan and American companies are subsidiaries of Tata Chemicals and have exported goods to India. The volumes of imports from Kenya were quite significant and therefore Tata Chemicals is an ineligible Domestic Industry.
- xvi. M/s DCW Ltd. has neither imported subject goods from the subject countries nor is related to either importers or exporters of subject goods from the subject countries.
- xvii. M/s Nirma Ltd. has not imported the subject goods from the subject countries. Their related company in USA however exported the subject goods to India during 2014-15 and 2015-16. The related company in USA did not export the subject goods during the POI.
- xviii. None of other Indian producers has opposed the standing of the petitioners.
- xix. The Authority has rightly held that the petitioners satisfy the requirement of standing in terms of Rule 2 (b) and Rule 5 (3) of the Indian AD rules.
- xx. The Authority accepted the confidentiality claims and has accepted non-confidential versions, wherever possible, of such information and placed the same in the public file.
- xxi. Several issues, as listed below, should be considered as issues concerning likelihood of dumping & injury and not part of miscellaneous submissions:
 - a. The cessation of present ADD is likely to lead to continuation or aggravation of the continued dumping and likelihood of recurrence of injury to the Domestic Industry.
 - b. Imports of Soda Ash are at present subject to ADD despite which they are being exported to India from the subject country at dumping prices.
 - c. The subject exporters are exporting the product to a number of other countries at a price below fair price for the Domestic Industry.
 - d. The import in the months of August 2018 and September 2018 have seen an increase of 23% from July 2018.
 - e. China has increased the exports of the subject goods by 1718% in August, as compared to 54% in July.
 - f. USA has increased the volume of imports by 796%.
 - g. Dumping Margins determined in previous investigation and proposed in the present investigation are significant and clearly show likelihood of dumping and consequent injury in the event of cessation of ADD.
 - h. In the event of cessation of ADD, these exporters will get a greater opportunity to dump the product under consideration into India, taking away the Domestic Industry's market share.
 - i. The import volumes have increased in the POI and at dumped prices. The imports are likely to enter in significant volumes at dumped price in the event of cessation of ADD.
 - j. Suppression/depression effects of the imports were not seen in the Indian market because of the existence of the ADD. Import price have started declining significantly and have started having a suppressing effect on the prices of the Domestic Industry as soon as new Turkish capacities have commercialized which is threatening the global demand supply scenario.
 - k. The Domestic Industry could not ascertain the levels of inventories with the subject producers. In view of the immense capacities available with the subject countries, it can be fairly stated that production can be ramped up as and when market is available.

- l. USA and China have remained the first and second biggest exporters of the subject good respectively.
 - m. The Turkish exporters have capacities to the tune of *** million metric tonnes of which their demand is around *** million metric tonnes, which leaves *** metric tonnes fit for exports. These goods are sent to Europe, and then are pushed to India.
 - n. There is an existence of dumping even in third countries by China, EU, Ukraine and the USA. Transaction wise analysis has been undertaken for last one-decade imports.
 - o. The volume of price attractive exports is quite high in the present POI in comparison to the consumption in India and the proportion increased thereafter in the post POI.
- xxii. The inappropriate placement of the submissions of the Domestic Industry may result in inappropriate examination of these submissions.
 - xxiii. The Authority has only referred to various High Court and Supreme Court orders without stating the observations of the Designated Authority on the present investigations.
 - xxiv. The Domestic Industry's concern is with regard to the fact that due consideration must be given to various submissions raised by the Domestic Industry.
 - xxv. The disclosure statement contains various submissions by other Interested Parties which were not made known till the stage of hearing or post hearing written submissions.
 - xxvi. The Interested Parties claimed that for a non-importing industrial user, there are no questionnaire formats applicable. It is only applicable to initiations that took place after February 2018. The requirements under the law cannot be different for an investigation initiated before or after issuance of this trade notice.
 - xxvii. It is precisely for this reason that the issue was raised before the Designated Authority earlier as soon the trade notice was issued. Enough time was given to the Authority to direct the Interested Parties to provide relevant information in the ongoing cases as per the trade notice.
 - xxviii. It appears that neither the Interested Parties have been asked to provide information in on-going cases, nor have the Interested Parties taken cognizance of the trade notice.
 - xxix. The information on record of the Designated Authority is not consistent with the trade notices in a large number of investigations.
 - xxx. The Interested Parties have argued that the complex history of the present case has added ambiguity to any timelines in the investigation.
 - xxxi. The Petitioners had challenged the Final Findings dated 22.7.2017 and Annulment Order dated 22.7.2017 by way of Petition and allied matters. The High Court vide Order dated 31.7.2017 restrained the Central Govt. from acting upon the Final Findings dated 22.7.2017 and Annulment Order dated 22.7.2017.
 - xxxii. By virtue of the Order dated 31.7.2017, the withdrawal order of the present case was "no longer in operation" and the investigation was de-facto restored.
 - xxxiii. The Designated Authority was required to undertake the investigation for completing the Sunset Review.
 - xxxiv. The High Court vide Judgment and Order dated 11.6.2018 allowed the subject writ petition filed by the petitioners for quashing and setting aside the Final Findings dated 22.7.2017 in Mid Term Review and Order dated 22.7.2017 annulling Sunset Review and directed the Authority to do the needful for bringing the Sunset Review to its logical end strictly in accordance with law.
 - xxxv. There can be no ambiguity that the investigation had to be conducted and concluded after following the due process of law.
 - xxxvi. The Interested Parties claimed that there are no duties in existence, as the Authority did not apply to the Central Government to extend the period of duties. There is no occasion for the Authority to give its recommendation to the Central Government.

- xxxvii. They further claimed that the Department of Revenue cannot extend the duties in terms of the judgement of *Forech India Ltd. v. The Designated Authority & Ors* since there are no existing duties. No Authority can extend the duties if there is a break in the period under Rule 18(1). The said judgement has not been stayed, and is therefore binding on the Authority
- xxxviii. The present investigation is being undertaken as per the High Court's direction vide Judgment and Order dated 15.06.2018 which extended the period for concluding the Sunset Review Investigation by 6 months in terms of the first proviso to Rule 17(1)(a) of the Rules. The argument of the Interested Parties implies that the High Court order is illegal.
- xxxix. The decision of the Delhi High Court is under challenge. Stay application has also been filed against the said order. The Supreme Court issued notice vide interim order 9th July 2018 while orally observing that since the Government is not withdrawing the notification, stay is not necessary. The Central Govt. has not withdrawn the ADD till date.
- xl. The High Court order dated 11.06.2018 had made it very clear that the investigation had to be concluded as per law, which in unambiguous terms meant that all the Interested Parties involved ought to have participated and submitted information relevant for the investigation. Interested Parties cannot make a claim that they were not aware of their obligation under an investigation.
- xli. There is stark difference between the dumping margin determined by the Domestic Industry and that determined by the Authority.
- xl.ii. The Authority has held that China cannot be given market economy treatment since a part of the POI falls prior to December 2016. In the absence of any market questionnaire/responses being filed by any of the responding producer, China cannot be granted market economy treatment. In the absence of any responding exporters/producers from any of the subject countries, the Authority has held the same as non-cooperative.
- xl.iii. For the purpose of determination of Normal value in USA, EU and Iran, the Domestic Industry submitted evidences relating to IHS chemical reports, which has been used/adopted/accepted by the Designated Authority in several cases, since they provide a true picture of the prices prevailing in the respective regions.
- xl.iv. The rules have placed a clear hierarchy between domestic price and cost of production. Section 9A(1)(c) of the Act clearly provides for a hierarchy. This was also established in the case of *Ministry of Commerce vs M/s.Haldor Topsoe*.
- xl.v. The Supreme Court has made it clear and mandatory that if information with regard to price in subject country is available, the Authority cannot choose cost of production as a basis of determination of normal value.
- xl.vi. IHS Chemical Weekly provides historical and forecasted pricing on a worldwide basis. Each month, it publishes a market summary and market statistics supplement. The market summary includes an analysis of the current market situation as well as price and margin history and forecasts.
- xl.vii. IHS Chemical's Report is mostly accessed by highly experienced researchers. It is authentic, has recognition, reliability and usefulness of the data and information published in it.
- xl.viii. Information was provided upon initiation of investigations and was made available to other Interested Parties. The information has not been disputed by any Interested Party, it is not appropriate to discard these trade journal prices and adopt cost of production.
- xl.ix. For the purpose of determination of normal value in Kenya and Pakistan, evidences relating to the annual reports of Tata Chemicals plant in Magadi, Kenya and the Annual report of ICL, Pakistan was considered by the petitioners, as they would provide the most accurate picture with regard to normal value in those subject countries.
- l. The normal value has been determined, disregarding that information and using less appropriate information, that too without full disclosure of the same. There is no reason recorded in the disclosure statement for rejecting the information and evidence provided by the petitioners.

- li. In a situation where exporters have preferred non-cooperation and there is no objection from any Interested Party, the Designated Authority is required to proceed with the claims made by the Domestic Industry as the best information available as per Rule 6(8).
- lii. The Authority has only laid reference on 'best available information' however, it has not been disclosed to the parties as to what forms the basis of 'best available information' in the present case.
- liii. The consideration of VAT adjustments in case of calculation of export price for China PR must be made.
- liv. Prices actually prevailing in the subject countries shows positive dumping margin. The dumping margin determined in the MTR Final Finding under challenge (which had responses filed by cooperating producers) also showed positive margin much above the de minimis level. Normal value has been wrongly determined.
- lv. The POI in the said investigation was 2014-15. The Authority had also determined dumping margin for post POI which was April 2015-Sep 2015, which was also positive.
- lvi. US producers have the advantage of immense natural resources and so their cost of production will be less as compared to the synthetic materials used in India. US exporters are resorting to dumping practices as they are exporting to India at prices much below their normal value which is leading to surge in imports.
- lvii. An advantage of low cost cannot imply resorting to dumping, and low cost does not mean "absence of dumping".
- lviii. Submissions filed earlier show that petitioners have admitted that the performance of the Domestic Industry has not deteriorated in the current period but has improved largely due to ADD in force.
- lix. Transportation cost forms a very substantial portion of the cost of production in case of subject goods as the Indian Producers of soda ash are located in the State of Gujarat (due to availability of raw material), and the sales have to be made throughout India.
- lx. The subject goods are a comparatively lower price product. The incidence of transportation cost per MT of the product works out to be very substantial when compared with the selling price of the product.
- lxi. The selling price of the Domestic Industry should be compared with the landed price of imports only after adding the transportation costs.
- lxii. The rules do not provide for one set methodology of determination of the effect of the dumped imports on the prices of the Domestic Industry. It cannot be said that a practice has become the law or that it will stand appropriate in every situation.
- lxiii. Consumers of soda ash do not compare ex-factory price of the Domestic Industry and ex-port price of imports while negotiating the prices with the Domestic Industry. They determine and compare landed price of the product from different sources at their factory.
- lxiv. The position of the Government of India at the WTO on fair comparisons favour this methodology.
- lxv. There can be no reason for excluding freight expense from the factory to the depot, as these are nothing but part of expenses, verifiable from the books of accounts and are merely an expense incurred for transportation of goods to an extended factory gate. If the goods are transferred from the factory to the depot then the goods are to be considered as a part of the inventory.
- lxvi. Even as per the accounting standards, the freight from the factory to depot is considered as a part of the cost of production and if that is the case then the depot is only an extended factory warehouse and that alone should be considered as the basis of the ex-factory NIP and selling price.
- lxvii. GST and other charges incurred are calculated only when the goods are moved from depot as those are considered as the ex-factory costs. The depot prices must be considered as ex-factory prices for the purpose of calculation of the NIP and selling price.

- lxviii. Past practice alone cannot be a justification for non-consideration of the arguments and submissions made by the Domestic Industry, particularly when such submissions have been made since the time of original investigation in this particular case.
- lxix. Undercutting and injurious imports/injury margins should be determined considering only those transactions that were undercutting or injuring the prices of the Domestic Industry.
- lxx. The weighted average export prices to India are grossly insufficient to determine whether injury to the Domestic Industry is likely to recur.
- lxxi. The producers in major subject countries are holding huge unutilized capacities, are exporting significant volumes of the product under consideration to third countries at prices (a) below selling price of the Domestic Industry in India, and (b) below export price from these countries to India.
- lxxii. In the event of cessation of duties, these producers are likely to find good market opportunities in India and are likely to export significant volumes at a price below the selling price of the Domestic Industry.
- lxxiii. Behaviour of individual exporters, as shown through different export transactions is relevant, appropriate and necessary to be examined as this in itself signifies the tendency of dumping of such producers/exporters causing injury.
- lxxiv. It is however seen that the disclosure statement merely contains these submissions and not emerging essential facts which have been considered by the Authority.
- lxxv. Submissions by Interested Parties do not constitute essential facts under consideration.
- lxxvi. The facts established by the Designated Authority on the basis of information and evidence on record constitute essential facts under consideration of the Designated Authority.
- lxxvii. In the context of present SSR case and considering the injury parameters laid down under the law, the Designated Authority is required to consider the above legal provisions in the manner prescribed by Rule 11.
- lxxviii. The demand for the product concerned has increased in India over the injury period.
- lxxix. Despite the existence of duties, the imports occupy a significant share in the Indian demand and import volumes have increased over the injury period. This clearly shows that the imports are going to at least increase (and not decline) in case of cessation of ADD.
- lxxx. As the duties are not being collected from July 2018 as per current notification, and even when the present investigation is not concluded and not decided whether ADD is required to be extended further, imports have already started showing significant increase.
- lxxxi. The Authority has noted that the landed prices of the subject imports from the subject countries are undercutting the net selling prices of the Domestic Industry by a significant margin resulting in significantly positive undercutting levels.
- lxxxii. Price undercutting has been determined without considering freight on the domestic product, whereas freight on the imported product has been considered up to the port levels (which constitutes majority of the freight on the imported product). The comparison is therefore not at the same level.
- lxxxiii. The Authority has noted that the cost of sales of the Domestic Industry have declined during the injury period while the selling prices of the Domestic Industry have increased during the same period.
- lxxxiv. The landed prices of the imports from China PR, EU and USA have increased over the injury period. The landed value of imports from Kenya and Pakistan during the POI has remained about the same. The landed prices of imports from Iran and Ukraine have declined during the POI as compared to the base year.
- lxxxv. It seems to have been ignored that (a) the present situation is when the ADD is in place and therefore is not at all relevant to show the likelihood of injury in case the present ADD is not extended, (b) landed price of imports from all the subject countries, except China PR has declined in the POI as compared to 2015-16 without corresponding decline in cost of sales.

- lxxxvi. This shows (a) the behaviour of the exporters to reduce prices irrespective of any relation to costs of the product and (b) likelihood of reduction in prices in the event the present ADD are not extended further.
- lxxxvii. The imports were not causing any price suppression or depression effect because of the ADD in force.
- lxxxviii. The Authority has noted the enhancement of capacity of the Domestic Industry over the injury period. The production and the domestic sales of the Domestic Industry have also increased over the same period. The capacity utilization of the Domestic Industry, despite addition of capacities, has remained about the same over the injury period.
- lxxxix. Various Interested Parties have claimed that the capacity utilisation by the Domestic Industry is over 80%, which is a good utilisation level.
- xc. The Designated Authority has considered that the plant was underutilised, and the Domestic Industry could have produced more than what it produced during the period.
- xc. Nirma was running the plant at 95%, which itself shows that 80% is not the optimum capacity utilisation. Thus, the Domestic Industry can at least produce up to 96% of its capacity.
- xcii. It would not be appropriate to conclude that the Domestic Industry was producing optimally. Or, in the alternate, the NIP should be determined at 80% for all the three companies.
- xciii. The anti-dumping duties were levied in 2012. The industry was incurring losses in 2011-12 and was making low level of profits and ROI until 2013-14.
- xciv. After imposition of ADD in 2012 the situation of the Domestic Industry gradually improved and consequently constituents of Domestic Industry and other producers felt that that the market is viable to invest in capacity expansions and have planned expansion.
- xcv. Significant capacities have been added by the Domestic Industry and other new producers. Post imposition of ADD, a fresh capacity to the tune of 10 Lac MT are either already commissioned (by Nirma and GHCL) or are at the verge of getting commissioned (by Garhi).
- xcvi. 20 lacs MT capacity enhancements are being planned at this stage. These are however only because the Indian market for the product has remained viable.
- xcvii. While an investment of Rs. 3,225 crores have already been made, further investments of Rs. 10,000 crores are being planned. Significant capacity addition has been made by other producers as well. M/s Gharhi has commissioned a new green field plant of a production capacity of 5 lac MT at an investment of Rs. 2200 crores. This has however been ignored in the disclosure statement. The impact of possible non-extension of ADD on these investments has also not been considered while undertaking injury analysis.
- xcviii. Dumped and increased imports will have an adverse impact on such huge investments made by the Domestic Industry. Fresh investments require a minimum reasonable return of Rs. 7,000/MT in order to be reasonably viable. The average return earned by the Domestic Industry over the injury period was much lower.
- xcix. The profit element in price is an important life line for continuance of entrepreneurial activity required for industrial production. Profits being earned by the Domestic Industry are being reinvested in capacity creation and are not being withdrawn by the industry.
- c. Should the Domestic Industry continue to earn these profits, the fresh investments will be recovered over a period that exceeds even the life of the assets.
- ci. The non-extension of the duties would likely decimate not only the Indian industry's investments for fresh capacity additions but will also impact the earlier existing capacities.
- cii. Improvement in profits of the Domestic Industry should not be regarded as sufficient to conclude absence of likelihood of injury to the Domestic Industry, since profit is understood merely as the excess of money over the capital.

- ciii. It would also be relevant to note that it is not a case where the petitioner's Domestic Industry is earning profits at the cost of consumer industry. Not only that the consumer industry is earning higher profits, but also, that they have improved significantly over the present injury period.
- civ. In sunset review investigations, the Authority is required to consider whether dumping of the product post cessation of ADD is likely to adversely affect the new capacity expansions that have already taken place in the country and for the capacity expansions that will take place in the country.
- cv. Reference is made to the Canadian practice wherein adequate consideration is given to the fact that significant investment has been made by the Domestic Industry in future production.
- cvi. The Domestic Industry has already provided information, by way of the submissions filed earlier, with regard to the cost of production and NIP of the newly installed capacities.
- cvi. It shows that the profitability of Domestic Industry in the new plant is already quite low and the Domestic Industry would suffer severe decline in profits in respect of such new capacities, if the present ADD is not extended further and Domestic Industry is forced to sell at such prices.
- cvi. The Authority has not examined market share in demand in the Disclosure Statement. The market share of the imports has increased over the injury period and market share of the Domestic Industry has remained more or less the same. Market share of the domestic producers as a whole has declined.
- cix. The data on record shows that the increase in inventories is about 36 basis points between the base year of the investigation and 2015-16, and the decline between 2015-16 and the POI is only by 4 basis points, i.e., from 136 to 132.
- cx. The Authority has noted that profits, cash profits and ROI of the Domestic Industry has improved over the injury period. It has been ignored that (a) the profits, cash profits and ROI in the POI shows some decline as compared to the preceding year, (b) profits, cash profits and ROI of the new investment is quite low, (c) the improvement in profits, cash profits and ROI are a result of imposition of ADD and does not imply absence of likelihood of recurrence of injury, (d) injury period parameters are relevant only for examination of continued injury and not likelihood of injury.
- cxi. The 4-basis point decline in inventory level in the POI as compared to the previous year has been specifically observed in the disclosure statement, a 21-basis point decline in profitability in the POI has been completely ignored.
- cxii. An objective examination of the performance of the Domestic Industry implies that all parameters should be considered with the same yardstick on a non-discriminatory basis.
- cxiii. While the current POI is relevant for establishing continuation of dumping, the historical data is relevant for establishing likelihood of dumping as it establishes the subject country(ies) as habitually indulging in dumping practices.
- cxiv. Calculations have shown that dumping has prevailed throughout the 10 years period. The data for the POI on weighted average basis itself shows that the dumping has continued, the same may be sufficient.
- cxv. If the Designated Authority comes to a conclusion that the weighted average dumping margin is de-minimis, then there is a need to examine dumping margin separately for each import transaction.
- cxvi. There is continued dumping of subject goods. Normal value should be determined as per the prices prevailing in the subject countries and should not be constructed.
- cxvii. Imports made into the domestic market at dumped prices despite imposition of antidumping duty. Imports after declining till 2015-16 increased significantly in the POI which further again intensified in Post POI.
- cxviii. Performance of the Domestic Industry has improved in view of antidumping duty in place with some decline in the POI as compared to the previous year. However non-extension of anti-dumping duty is likely to lead to recurrence of material injury. Further, as regards high profitability of Domestic Industry, it is submitted that soda ash is a highly capital intensive, low raw material cost and high finished product freight industry. The freight costs constitute very high percentage of cost of

production. Therefore, this case should be seen in the light of peculiarities of the product under consideration.

- cxix. As regards ROCE, the plants are being operated by industry are depreciated. Since net fixed assets are unfair to domestic producers and don't represent true value the domestic producers' assets value, the Domestic Industry requests the Designated Authority to consider present value of investment for calculating ROCE.
- cxx. Mere improvement in performance of the Domestic Industry is insufficient to conclude that extension of duties is not justified. Rule 23 mandates the Authority to examine the effect of the revocation of duty on Domestic Industry, instead of merely focusing on the present situation of Domestic Industry. If the Authority comes to a conclusion that the Domestic Industry has not suffered continued injury, the Authority needs to examine whether the Domestic Industry is likely to suffer injury in the event of cessation of antidumping duty. If not so, the Authority must examine whether continued dumping of the product under consideration is likely to lead to recurrence of injury.
- cxxi. Producers from subject countries have significant capacity, much more than the domestic demand, which establishes that in the event of cessation of duties, exports to India will intensify.
- cxxii. The price undercutting without prevailing antidumping duties is positive.
- cxxiii. Historically (as per data for the 10-year period) the share of dumped and injurious imports has been significant.
- cxxiv. Significant volume of third country exports by subject countries are at prices below the prices at which exports have been made to India.
- cxxv. Significant volume of third country exports by subject countries are at prices below the selling prices of the Domestic Industry.
- cxxvi. Non-extension of antidumping duty would lead to a situation where import prices would materially be below selling price of the Domestic Industry. The consumers would therefore switch to imported goods which will lead to significant increase in imports of the product.
- cxxvii. The investigation is legal and is being undertaken pursuant to the High Court Order. The duties can be levied prospectively once the Authority gives recommendation to that extent.
- cxxviii. The quantum of duty is not required to be modified and the existing duties should only be extended.
- cxxix. Anti-dumping duty may be imposed only as fixed quantum of anti-dumping duty (fixed form of duty), expressed as duty in US\$/MT. Rupee has depreciated significantly and therefore the definitive duties must be expressed in US\$. The depreciation INR has impacted the costs of the raw materials, utilities and other costs.
- cxix. The product is already attracting fixed quantum of anti-dumping duty at present.
- cxixi. The Anti-dumping legislation has been created in consonance and in conformity with the WTO Agreement on Anti-Dumping, which explicitly permit authorities to impose anti-dumping duties in the form and manner requested.
- cxixii. Experience generated out of fairly large number of investigations (more than 300 investigations have been conducted so far spread over more than 15 years) that attempts are made to evade anti-dumping duty imposed. A large number of complaints made by spectrum of industries over a long period with regard to circumvention of anti-dumping duties are relevant in this regard.
- cxixiii. Customs port authorities lack a mechanism to ensure correctness of import price reported by an importer. It is neither feasible nor practicable for the port authorities to verify the import price.
- cxixiv. The duty should be imposed in a manner where it does not become futile.

Submissions made by other interested parties

- i. In respect of background of the case, HUL brings to the notice of Hon'ble Designated Authority that the decision rendered by the Hon'ble High Court of Gujarat in W.P. 14202 and 14204 of 2017, which

was the basis for the Authority herein to continue with the current sunset review proceedings, is under consideration before the Apex Court in S.L.P. (Civil) Dairy No. 36509/2018.

- ii. In respect of procedure, the Hon'ble Designated Authority has observed at paragraph no. 7(v) and 7(vii) of the Disclosure Statement that "no importer/user or no producer/exporter from subject countries filed any response to questionnaire or made any submission". In response, HUL submits that said observation is erroneous. Some interested parties have filed their submissions and the same are part of the public file records. Therefore, the same ought to be considered by the Designated Authority.
- iii. Further, the Hon'ble Designated Authority has also observed at paragraph no. 7(xi) that "exporters, producers and other interested parties who have not responded to the Authority, nor supplied information relevant to this investigation, have been treated as non-cooperating interested parties". HUL submits that said observation is erroneous.
- iv. HUL is one of the largest industrial users of the subject goods and have not imported the product in question. Therefore, as per the prescribed rules and procedures in existence at the time of initiation, the importer questionnaire is not required to be filed by such industrial user. HUL further submits that, during the course of the present investigation, it has provided certain pieces of data and information which it thinks is relevant for the Designated Authority to come to a conclusion for issuance of final findings. Since the Designated Authority is a quasi-judicial authority, it has to address all the legal submissions along with the data/information placed on record by interested parties prior to recommending the final findings.
- v. The Hon'ble Designated Authority has made observations with respect to the product scope and like article. HUL submits that it does not have any comments on the same. In the event that new or additional information is made available, HUL reserves its right to comment on the same.
- vi. HUL submits that the Hon'ble Designated Authority Statement has made observations with respect to the eligibility of the Petitioners as domestic industry. However, it has erred in not recording any observation on the eligibility of other domestic producers, specifically GHCL of the PUC in India.
- vii. Further, though the Designated Authority in the past anti-dumping proceedings of the subject goods has specifically considered GHCL as domestic industry, it is not clear as to why the Designated Authority herein has not considered the request of the Petitioners and HUL herein to consider/examine the eligibility of GHCL as domestic industry. GHCL's Annual Report for the year 2017-18 shows that their Soda Ash division is performing exceptionally. Their sales value has risen exceptionally along with their capacity utilization being above 95%.
- viii. In view of the above, it must be considered whether the Petitioners are requesting for a reconsideration of GHCL's eligibility to be domestic industry merely because of GHCL's positive performance in recent years. Since this issue remains unaddressed in the Disclosure Statement, the Hon'ble Designated Authority may specifically determine if the Petitioners have impliedly excluded GHCL, at first instance, from the domestic industry so as to avoid the determination of injury or likelihood of injury being unfavorable to them due to GHCL's exceptional performance and not because of GHCL's unsubstantiated existence of imports.
- ix. The Hon'ble Designated Authority has made a general observation with respect to the fact that it has accepted the confidentiality claims wherever warranted and not disclosed confidential information to interested parties. HUL submits that it does not have any comments on the same. However, HUL reserves its right to comment in the event new or additional information is made available.
- x. HUL agrees with the averment made above by other interested parties. Once there has been a lapse of duties or break in levy of duties pursuant to original investigation, the already expired duties cannot thereafter be levied by way of a sunset review investigation. The Hon'ble Designated Authority ought to take cognizance of the most recent decision of the High Court of Delhi in *Forech India Ltd vs Designated Authority*.
- xi. The Hon'ble Designated Authority has noted that the interested parties had sufficient time to respond to the questionnaire and participate in investigation. Before making such an observation, HUL submits that the Hon'ble Designated Authority must specifically take into consideration the complex history of the present case (particularly with the writ petition and orders thereafter) has added ambiguity to any

timelines in the present investigation, and therefore interfered with most of the interested parties' adherence to the timelines for filing questionnaire responses. However, the Authority is requested to take into consideration all the legal submissions and other information/evidence provided by the opposing interested parties prior to issuance of its final findings.

- xii. On normal value from China, HUL does not have any specific comments on the same. However, HUL requests the Hon'ble Designated Authority to take into consideration the relevant AD Rules for the purpose of determining the normal value for China PR.
- xiii. On computation of normal value for subject countries, Authority has not disclosed the methodology it has adopted for computation of constructed normal value. The Authority ought to have given such information to all interested parties vide Disclosure Statement. The Hon'ble Designated Authority should calculate the normal value in accordance with the relevant section/rules and also take into consideration the information provided by participating exporters/producers.
- xiv. On export price, the Designated Authority has not disclosed the methodology or source for adjustments it has made to arrive at the export price for subject countries. The Hon'ble Designated Authority should calculate the export price in accordance with the relevant section/rules and also provide evidence of the adjustments that have been made to the export price.
- xv. The Hon'ble Designated Authority has observed that the dumping margin is negative for China PR, EU, Pakistan and Ukraine and dumping margin is de-minimis for Kenya. This is a crucial determination since it clearly establishes an absence of continuation of dumping for these subject countries.
- xvi. Therefore, in order for any continuation of duties, it would be mandatory to now establish a likelihood of recurrence of dumping in the present investigation. Given that there is presently no dumping from a majority of the subject countries, and no injury to the Petitioners (or likelihood thereof), the Hon'ble Designated Authority is requested to allow the impugned duties to stay expired.
- xvii. As emphasized clearly in Annexure II, the examination of injury to the domestic industry is only required to be conducted with regard to dumped imports. As determined by the Hon'ble Designated Authority in its Disclosure Statement, there is no / de minimis dumping taking place in the period of investigation from China PR, EU, Kenya, Pakistan and Ukraine. Since there is no dumping from these countries, the analysis of injury for these countries is excessive and unwarranted under the above provisions. With regard to injury, the Hon'ble Designated Authority is only required to assess whether the Petitioners are injured on account of imports from the subject countries which have positive dumping margins i.e. Iran and USA.
- xviii. The Hon'ble Designated Authority has observed that the demand has increased in the injury period, along with an increase in the market share of the subject imports and the Petitioners. However, in the same paragraph, the Authority has rightly noted that the market share of domestic industry increased during the injury period. HUL submits that, though the Authority has observed as aforesaid, it has not provided the trend for the market share of the domestic industry in the total demand. Without prejudice, the sales of the Petitioners have increased at a greater rate than the total demand of the country, indicating an increase in market share. Thus, subject imports have not negatively impacted the market share of the Petitioners.
- xix. While there has been an alleged increase in imports from EU, Pakistan, Ukraine, Iran and USA, there has been an increase in sales of the domestic industry, evidencing that there has been no impact of the subject imports on the domestic sales of the domestic industry.
- xx. The selling price of the Petitioners has consistently been able to keep up with the cost of sales. The subject imports have not prevented the Petitioners from appropriately adjusting their price with any change in cost, thus demonstrating that the Petitioners are suffering no price suppression or depression.
- xxi. The price undercutting data available in Disclosure Statement is only in respect of the POI. Also, the Hon'ble Designated Authority has not provided the net selling price or net sales realization (even indexed) figures that it is considering for the purpose of price undercutting analysis for the POI. In the absence of disclosure of the price undercutting figures that are being considered by the Hon'ble

Designed Authority for the injury period as a whole, HUL is being deprived of the opportunity to make meaningful comments on the same. The Authority is requested to kindly disclose all the information it is considering in respect of price undercutting analysis.

- xxii. It is noted that the Hon'ble Designated Authority has assessed price undercutting based on the "consistent practice of the Authority", which can be reasonably presumed to mean that freight has not been included. However, given that there is no concern on confidentiality here, the Hon'ble Designated Authority is requested to explicitly clarify whether or not freight has been considered.
- xxiii. There is an increase in production and sales of the domestic industry. Further, it can be seen that the domestic industry has been able to utilize its installed capacity.
- xxiv. The inventories have decreased in the POI in comparison to the previous year, which evidences that the domestic industry has been able to make increased sales in the POI.
- xxv. Admittedly there has been a remarkable increase (as also observed by the Authority) in the profit before tax and interest, cash profit and return on investment, profits of the domestic industry in the POI in comparison to the base year.
- xxvi. The productivity per employee and the wages have increased immensely in the POI in comparison to the base year.
- xxvii. HUL does not have any comments on magnitude of dumping and reserves its right to comment during the course of investigation in the event new or additional information is made available by the Petitioners.
- xxviii. HUL agrees with the finding of the Designated Authority with regard to growth and the Petitioners' ability to raise funds, as examined at paragraphs no. 70 and 71 of the Disclosure Statement.
- xxix. The Hon'ble Designated has clarified that the NIP has been calculated on the basis of the best information available. If a cooperating producer's individual treatment had been rejected on account of non-provision of data, the Hon'ble Designated Authority would not allow the producer to provide additional data at such a late stage. The same strict standard must also be applied to the Petitioners and no further information concerning NIP (or any other issues under consideration) must be accepted. If indeed such information is accepted, the Hon'ble Designated Authority must issue the disclosure statement again and allow the interested parties to file their comments within a reasonable period of time.
- xxx. Without prejudice, the Authority has rightly noted that the injury margin for China PR, EU, Kenya, Pakistan, Iran, Ukraine is negative. Along with an absence of dumping from most of the subject countries, there is clearly an absence of injury to the domestic industry and the margin of injury is also negative for all subject countries except USA.
- xxxi. If there is no dumping from most of the subject countries or injury to the Petitioners, there can be no question of a causal link.
- xxxii. The Petitioners have not provided concrete or sufficient evidence (including post POI data) for proving that discontinuation of duty would lead to recurrence of dumping and injury.
- xxxiii. It is pertinent to analyse the post-POI data which the Petitioner has not provided. Furthermore, though the Designated Authority has noted that it has taken into consideration the post POI data, the interested parties including HUL have not been provided with any such data. Without prejudice, there is a decline in import volumes in the post-POI period as acknowledged at paragraph no. 78 of the Disclosure Statement.
- xxxiv. It is not evident/verifiable from the Disclosure Statement as to which year the IHS report pertains to. Moreover, the Authority has kept the information confidential without any reasonable basis. The Hon'ble Designated Authority is humbly requested to make available the figures in summarized ranges so that the interested parties can also comment on the essential facts considered herein. Since HUL cannot verify or comment on the confidential information of the Disclosure Statement, it relies on the submissions it has made at paragraph no. 84 to 90 of the Rejoinder submissions while it was responding to the IHS Report relied upon by the Petitioners. The same may be reconsidered by the Authority before making any conclusive findings.

- xxxv. Based on information available on subject countries' markets, it is clear that the local capacities, particularly in China and Western Europe, are predominantly utilized for domestic sales. Indeed, export sales in these markets are a very small portion of the total production (for the past year as well as forecasts for the coming years).
- xxxvi. The onus to prove likelihood of dumping or injury lies with the Petitioners. The Authority by stating that the exporters/producers did not provide the data on inventories shifts the burden on the exporters/producers from the Petitioners. In view of the Petitioners statement at paragraph no. 104 of their written submissions, the Authority herein is requested to note that the Petitioners have not been able to prove likelihood of dumping or injury with sufficient evidence.
- xxxvii. Petitioners have not provided any post POI data with respect to price suppression/depression, nor has it made any substantiated submissions with respect to the same. The detailed submissions on this aspect is made in the relevant section hereinabove. The Authority has rightly noted (indirectly) that there is no price suppression or depression at paragraph no. 82 of the Disclosure Statement.
- xxxviii. It is evident that the dumping margin is negative for all but two of the subject countries.
- xxxix. The Hon'ble Designated Authority has explained the methodology that have been used to arrive at the non-injurious price and HUL do not have any comments in respect of the same.
- xl. Issues raised by Saint Gobain India Pvt. Ltd. during the public hearing, written submissions and the rejoinder statement which have not been mentioned or have not been dealt with appropriately in the Disclosure Statement are to be considered as part of its comments to the disclosure statement.
- xli. After the annulment of the sunset review investigation dated 22.7.2017, there is no opportunity for the SGIPL to provide its questionnaire response.
- xlvi. The present investigation is without jurisdiction and anti-dumping duties now cannot be extended in the light of the judgement of Hon'ble Supreme Court and Hon'ble Delhi High Court.
- xlvi. No notification with retrospective or prospective effect can now be issued by the Central Government even if the sunset review is decided in favour of the applicant domestic producers in terms of the settled legal position in the case of Forech India Ltd. v. The Designated Authority & Ors that there cannot be a gap between expiry of original duties or extension of one year.
- xli. The extension of duties for one year has lapsed on 2.7.2018, amounting to a gap of over 4 months.
- xli. The Central Government also cannot issue Custom Notification to collect the anti-dumping duties after there is a break in duties.
- xli. Any recommendation given by the Hon'ble Authority would be without authority of law and contrary to the mandate available to them under Section 9A(5). The said investigation must be terminated.
- xlii. DI was attempting to misguide the Hon'ble Court when they approached the Court for judicial scrutiny in connection with this matter. But we are hopeful that such attempts to misguide the Hon'ble Court will be proved futile for the DI at the end of the process of judicial scrutiny and the duties shall be ultimately allowed to expire
- xliii. Indian producers have very selectively provided injury data to the Authority to show only a premeditated picture of injury and accordingly large profit-making producers like GHCL did not share injury data for the purpose of this investigation.
- xli. If GHCL has decided not to participate in the present matter on account of their import, then it has to be construed that GHCL has shifted its focus from manufacturing to trading which shows the DI has time and again approached the Authority with particular agenda.
- l. The dumping margin and injury margin from subject countries other than USA is either negative or below de-minimis levels. However, it is relevant to be noted that as proposed by the DI, the Authority has conducted cumulative assessment in the present matter and what is relevant under cumulating is the overall impact of imports from subject countries on domestic industry and not imports from a particular country. The situation of the DI is extremely strong that they are not vulnerable to any dumping and injury in the event of expiry of present duties on subject countries.

- li. The imports from subject countries did not create any volume effect on the DI which is evident in the increases in key volume parameters such as production, sales etc. The NSR of the DI increased over the years whereas the COP declined. This shows the DI is enjoying strong pricing power and in fact the pricing behavior is highly monopolistic. The imports are, thus, not creating any adverse effect on the price as well of the DI. The positive price undercutting is only on paper and such positive price undercutting is the result of very high price charged by the DI.
- lii. It can be seen that profitability of the DI moved from 100 basis points in the base year to 300 points in the POI and ROCE moved from 100 basis points in the base year to 160 points in the POI. Such increases should be seen as a commendable growth. In fact in a recent fresh matter concerning DMF, the Authority found no duty is warranted to be imposed when the profitability moved from (100) points in the base year to 15 points in the POI with less than 6% ROCE in the POI.
- liii. The ROCE earned by the DI though declined over the 2 previous years on the trend line, the actual ROCE percentage still remain exorbitantly high rendering the fall in trend deceptive and meaningless. The Authority permits 22% ROCE for the purpose of NIP and our understanding is that the DI is earning an average ROCE in the range of 25% to 35%. This is evident in the order of the Authority dated 5.4.2018 concerning Soda Ash from Russia and Turkey matter wherein the Authority found ROCE of 29% realized by the DI during April 16 to Sep 2017. The profit margin was 41% and company like Nirma earned 58% of profit margin. These levels of ROCE and profit margin are not a normal situation and clearly show extreme level of profits earned by the DI.
- liv. The DI is in fact seeking protection for such extra ordinarily high ROCE earned by misusing the ADD in force to overcharge the users and continued protection to maintain such profit level is not the intended purpose of ADD. The distortion which that was found earlier is totally absent now and the DI is well placed to compete with imports.
- lv. The imports from subject countries declined in the post POI which should be read along with our previous submission that imports in POI were necessitated due to demand supply gap as well. This shows absence of likely increase in import volume.
- lvi. M/s Nirma Ltd.'s related company in USA is involved in manufacturing and export of the subject goods to India. Nirma's related US company had exported the subject goods during 2014-15 and 2015-16.
- lvii. Nirma's related company had exported significant quantities of the subject goods to India during 2014-15 and 2015-16.
- lviii. Applying literal interpretation of Rule 2(b), Nirma should be excluded for standing examination under Rule 2(b) read with Rule 5(3) of the AD Rules.
- lix. The reason for excluding M/s Tata Chemicals Ltd. from the standing analysis seems to be that Tata has a related company in Kenya which had exported the subject goods to India during the injury period. The same standard should also be applied to Nirma, as it has a related company in USA that had exported the subject goods during the injury period.
- lx. When Nirma is excluded from standing analysis, the remaining Petitioner M/s DCW Ltd. will no longer have standing as its share in total Indian production will fall way below 25%.
- lxi. Dumping margin due to imports from China PR, the EU, Pakistan, Iran and Ukraine was negative during the POI. Also, dumping margin due to imports from Kenya during the POI was de-minimis. Injury margins were also negative for all subject countries except USA.
- lxii. Even though dumping margins seems to be positive for imports from Iran and USA, the weighted average dumping margin for the subject countries is negative in this case because dumping margin for five out of seven subject countries is either negative or de-minimis.
- lxiii. Similar logic is extended to injury margins. Even though injury margin was positive for USA, the weighted average injury margin for all the subject countries was negative during the POI.
- lxiv. The selling price of the domestic industry is much higher than their non-injurious price.
- lxv. It is evident that imports of the subject goods were not dumped and consequently did not cause any injury to the domestic industry during the POI.

- lxvi. This is a strong indicator that there is no likelihood of continuation of dumping and injury or likelihood of recurrence of dumping and injury if anti-dumping duty were to be revoked.
- lxvii. Therefore, even though market share of imports from the EU, Pakistan, Ukraine, Iran and USA increased during the injury period, there was no overall impact on the performance of the domestic industry.
- lxviii. Imports from China PR, the EU, Kenya, Pakistan and Ukraine were un-dumped during the POI. Such un-dumped imports could not cause any injury to the domestic industry. This is established from the fact that injury margins were negative for China PR, the EU, Kenya, Pakistan, Iran and Ukraine.
- lxix. Domestic industry's installed capacity, production, domestic sales and capacity utilisation have all improved over the injury period.
- lxx. Average inventories increased during the injury period in line with the increase in installed capacity and production of the domestic industry and decreased during the POI.
- lxxi. The profitability of domestic industry in terms of profit before tax and interest, cash profit and return on investment have remarkably increased in the POI as compared to the base year.
- lxxii. There was decline in the number of employees during the POI as compared to the base year 2013-14 and productivity remarkably increased during the POI as compared to the base year. Wages also increased during the POI in comparison to the base year 2013-14.
- lxxiii. Growth of the domestic industry was positive in terms of improvement in production, sales, profit before tax and interest, cash profit and return on investment during the POI.
- lxxiv. Domestic industry has enhanced its capacity of production of the subject goods in the year 2015-16 and the POI.
- lxxv. The domestic industry has made significant capital investment at present and has further planned investments for enhancing capacities. This signifies that their ability to raise capital investment has not been affected adversely.
- lxxvi. Cost of sales of the domestic industry decreased during the POI as compared to the base year. The selling price of the domestic industry also increased during the injury period and has been independent of the landed prices of imports.
- lxxvii. The landed values of imports from China PR, the EU and USA have increased during the POI as compared to the base year. The landed values of imports from Kenya and Pakistan during the POI have remained the same. The landed values of imports from Iran and Ukraine have declined during the POI as compared to the base year.
- lxxviii. Imports of the subject goods increased because of sharp gap in demand and supply of the subject goods in India. This increase did not impact the selling price of the domestic industry.
- lxxix. Profitability of the domestic industry increased almost three-times during the POI when compared with the base year 2013-14, and the selling price is higher than their non-injurious price.
- lxxx. No evidence of correlation between increase in imports and shift in consumer preference to imported goods.
- lxxxi. The subject goods have users in detergent as well as glass industry, which use the subject goods on a large scale.
- lxxxii. With Indian Rupee continuously depreciating against the US Dollar during the POI and post POI period 2017-18, it had become more and more expensive to import the subject goods.
- lxxxiii. The user industry in India will continue to rely on local supplies of the subject goods and import the subject goods only when there is a shortfall in supply.
- lxxxiv. In the post POI period 2017-18, the volume of imports of the subject goods declined by 2.5% in comparison to the POI.

- lxxxv. Trade journals cannot be relied upon in anti-dumping investigations, as per Secretary (Revenue), GOI v. Dyestuffs Manufacturers Association of India, 2015 (322) ELT 3 (SC). IHS Chemical journal data submitted by the Petitioners must be disregarded.
- lxxxvi. The domestic sales of the domestic industry increased to 115 indexed points over the injury period.
- lxxxvii. In case the price undercutting claimed had any actual detrimental impact, the Petitioners would not have been able to maintain their domestic sales or increase them.
- lxxxviii. The mere fact that the Petitioners managed to expand their sales in India despite the alleged price undercutting demonstrates the absence of injury.
- lxxxix. Such reasoning is supported by the the Truck and Bus Tires Case, where the imposition of anti-dumping duty was annulled by Hon'ble CESTAT on the basis that the injury findings of the Designated Authority were flawed, and that maintenance of sales volume would have been hard if there was price undercutting and underselling.
- xc. Imports of Soda Ash are no longer subject to anti-dumping duty, as the anti-dumping duty lapsed on 2 July 2018.
- xc. Since the anti-dumping duty on the subject goods has already lapsed on 2 July 2018 and the sunset review is not yet over, any prospective levy of anti-dumping duty would run afoul of the judgment in Forech India Limited v. The Designated Authority & Others, W.P.(C) No. 4810 of 2014 and thus, would be illegal.

Examination by the Authority

88. The examination of post-disclosure comments is as under:

- i. As regards the submission that the Authority should disclose essential facts that form the basis of its findings and conclusion, it is observed that the Authority had disclosed all essential facts under consideration in terms of Rule 16 of the AD Rules to all the parties concerned.
- ii. As regards the submission that the Authority should disclose the non-injurious price and its basis, it is observed that the Authority had disclosed the same to the domestic industry in terms of Rule 16 of the AD Rules.
- iii. As regards the submission that there was no price suppression and price depression because anti-dumping duty was in force during the injury period, it is observed that the Authority had conducted such analysis without addition of anti-dumping duty in the landed value of imports and still found no price suppression and price depression.
- iv. As regards the submission that due concern should be given to the submissions of the domestic industry, it is observed that the Authority has examined the submissions of the domestic industry and other interested parties at appropriate places in the present findings.
- v. As regards the submission that there are stark differences in the dumping margins determined in the petition and disclosure statement, it is observed that the Authority has conducted dumping margin analyses as per the AD Rules and the same have been disclosed to all interested parties. No party has established how the Authority's dumping margin determination is inconsistent with the AD Rules. As regards the submission that VAT adjustment should be made in the ex-factory export price for China PR, it is observed that the Authority has made the applicable VAT adjustment in determining ex-factory export price for China PR.
- vi. As regards the submission that transportation cost should form part of the NIP, it is observed that as explained at appropriate places in the present findings, the Authority has determined NIP as per Annexure-III to the AD Rules. The Authority has compared NIP and landed value at the same level of trade.
- vii. As regards the submission that imports of the subject goods shall increase in the event of cessation of anti-dumping duty, it is observed from the analysis of import volume for post-POI period 2017-18 that imports of the subject goods declined by 2.5% in comparison to 2016-17. Analysis of other economic parameters do not show that dumping and injury are likely to continue or recur if the anti-dumping duty on the subject goods were to be revoked.

- viii. As regards the submission that price undercutting is positive and significant for subject countries, it is observed that in a sunset review, price undercutting is not the only determinative factor. The Authority has holistically examined all the relevant economic parameters of the domestic industry for volume effects and price effects, as well as examined the dumping margin and injury margin in this case. The analysis indicates that the Petitioners have performed well during the injury period including the POI in terms of profit, ROCE, capacity expansion, production and sales. The selling price of the Petitioners was found to be much higher than the NIP of the Petitioners. There is no price suppression and price depression. Dumping margin was found to be de-minimis or negative for China PR, the EU, Kenya, Pakistan and Ukraine. Injury margin was found to be negative for China PR, the EU, Kenya, Pakistan, Iran and Ukraine. Weighted average injury margin was negative for all the subject countries. Imports of the subject goods declined by 2.5% during the post-POI period. The Petitioners have not been able to establish that dumping causing injury is likely to continue or recur in the event anti-dumping duty were to be revoked on the subject goods. Buoyed by the significant improvement in the performance of the Petitioners, fresh capacities to the tune of 10 Lac MT are either already commissioned (by Nirma and GHCL) or are at the verge of getting commissioned by other Indian producers, as has been conceded by the Petitioners. Petitioners have further conceded that 20 lacs MT capacity enhancements are being planned at this stage because the Indian market for the product has remained viable. ROCE of the Petitioners has remained high despite incurring significant cost in capacity expansion.
- ix. As regards the submission that the Authority has not carried out sufficient analysis on likelihood or recurrence of dumping and injury, it is observed that the Authority has carried out detailed analysis in this regard at appropriate places of the present findings.
- x. As regards the submission that the Authority should consider the submissions filed by various interested parties, it is observed that the Authority has recorded such submissions and examined the same at appropriate places in the present findings.
- xi. As regards the submission that interested parties have not been provided with post-POI data, it is observed that as per the procedure prescribed by the Authority, interested parties can request for post-POI import data. No interested party has approached the Authority with regard to procurement of post-POI import data as per the prescribed procedure. In any case, the post POI import data was placed in the public file and all the interested parties could have accessed it after following the due procedure.
- xii. As regards the submission that the Authority cannot legally recommend continuation of anti-dumping on the subject goods and no notification can be issued with retrospective or prospective effect, it is observed that under the Customs Tariff Act, 1975 and AD Rules, the final decision to impose or not to impose anti-dumping duty lies with the Central Government.

O. Conclusions and Recommendations

- 89. Having examined the contentions of various interested parties and on the basis of the above facts, circumstances, and analysis, the Authority concludes as under:
 - i. The financial and economic parameters of Domestic Industry (both volume and price) are stable and not evidencing deterioration requiring continuation of anti-dumping duty.
 - ii. The Petitioners have performed well during the injury period including the POI in terms of profit, ROCE, capacity expansion, production and sales.
 - iii. The selling price of the Petitioners was found to be much higher than the NIP of the Petitioners.
 - iv. There was no price suppression and price depression.
 - v. Dumping margin was found to be de-minimis or negative for China PR, the EU, Kenya, Pakistan and Ukraine.
 - vi. Injury margin was found to be negative for China PR, the EU, Kenya, Pakistan, Iran and Ukraine. Weighted average injury margin was negative for all the subject countries.
 - vii. The Petitioners have not been able to establish that dumping causing injury is likely to continue or recur in the event anti-dumping duty were to be revoked on the subject goods.

- viii. Capacity, production, domestic sales and overall profitability of the industry do not indicate existence of injury or a deteriorated economic condition.
 - ix. The factors submitted by the Petitioners on likelihood of recurrence of injury on withdrawal of ADD are not supported by the price realisations and price trends of the subject goods during the POI.
 - x. Due to significant improvement in the performance of the Petitioners, fresh capacities to the tune of 10 Lac MT are either already commissioned (by Nirma and GHCL) or are at the verge of getting commissioned by other Indian producers, as has been conceded by the Petitioners.
 - xi. Capacity enhancements of 20 lacs MT are being planned at this stage because the Indian market for the product has remained viable.
 - xii. ROCE of the Petitioners has remained very high despite incurring significant cost in capacity expansion.
90. The Authority on account of the aforesaid reasons concludes that continuation of anti-dumping duty is not warranted and accordingly does not recommend extension of anti-dumping duty on the imports of subject goods from the subject countries.

P. FURTHER PROCEDURE

91. An appeal against this notification shall lie before the Customs, Excise, and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 and the decision of the Hon'ble High Court of Delhi in M/s Jindal Poly Film Ltd. v. Designated Authority W.P. (Civil) No. 8202/2017.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. and Director General